"शीत युद्धोत्तर भारत—ईरान सम्बन्धः ऊर्जा सुरक्षा के विशेष संदर्भ में"

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय
लखनऊ से राजनीति विज्ञान विषय में
पी०एच०डी० की उपाधि
हेतु प्रस्तुत

शोध प्रबन्ध

BABASAHEB
BHIMRAO
AMBEDKAR
UNIVERSITY
LUCKNOW
प्रज्ञा शील करुणा
ESTABLISHED 1996

शोध निर्देशक
प्रो० रिपु सूदन सिंह
(संकायाध्यक्ष एंव विभागाध्यक्ष)
राजनीति विज्ञान विभाग
अम्बेडकर अध्ययन विद्यापीठ
बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर
विश्वविद्यालय, लखनऊ

शोधार्थी
इन्दु
नामांकन संख्याः 910/13
राजनीति विज्ञान विभाग
अम्बेडकर अध्ययन विद्यापीठ
बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर
विश्वविद्यालय, लखनऊ

अम्बेडकर अध्ययन विद्यापीठ
बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
लखनऊ—226025

CERTIFICATE

This is to certify that the thesis titled "**शीत युद्धोत्तर भारत–ईरान सम्बन्ध: ऊर्जा सुरक्षा के विशेष संदर्भ में**" Submitted by Ms. **Indu** is an original research work and has not been previously submitted in part or full for the award of any other degree or diploma to this or any other university.

The thesis submitted to Babasaheb Bhimrao Ambedkar University satisfies all the requirements as stipulated in the *Doctor of Philosophy (Ph.D.) regulations-1999 as amended in 2008/2010/2013* and it is fit for submission and evaluation for the award of the degree of Doctor of Philosophy of the University.

Date: 12-05-2019

Supervisor

Prof. Rpit Sudam Singh
Research Supervisor
DPS/SAS/BBAU

Head of the Department

विभागाध्यक्ष
राजनीति विज्ञान विभाग
बी०बी०ए०यू०
Head
Deptt. of Political Science
B.B.A.U

घोषणा–पत्र

मैं, इन्दु यह घोषणा करती हूँ कि मैंने "**शीत युद्धोत्तर भारत–ईरान सम्बन्धः ऊर्जा सुरक्षा के विशेष संदर्भ में**" विषय पर शोध कार्य प्रो० रिपु सूदन सिंह राजनीति विज्ञान विभाग, अम्बेडकर अध्ययन विद्यापीठ, बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ के निर्देशन में पूर्ण किया है। पी०एच०डी० की उपाधि हेतु प्रस्तुत यह शोध प्रबन्ध मेरा मौलिक कार्य है। प्रस्तुत शोध प्रबन्ध इससे पहले इस विश्वविद्यालय अथवा किसी अन्य विश्वविद्यालय में पी०एच०डी० उपाधि हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है।

मैं, इस बात की भी घोषणा करती हूँ कि प्रस्तुत शोध किसी भी प्रकार के साहित्यक चोरी (प्लैजिरिज्म) से मुक्त हैं।

दिनांक 12.05.2019

Indu

इन्दु

(शोधार्थी)
नामांकन संख्याः 910/13
राजनीति विज्ञान विभाग
अम्बेडकर अध्ययन विद्यापीठ
बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर
विश्वविद्यालय, लखनऊ

आभार

ऊर्जा आर्थिक विकास के साथ–साथ मानव विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है जिसके बिना मानव जीवन का सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, और राजनीतिक, विकास नगण्य है। इसलिए प्रत्येक राष्ट्र सस्ती ऊर्जा तक अपनी पहुँच स्थापित करना चाहतें हैं। 21वीं सदी में बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था ने समूचे विश्व की ऊर्जा सुरक्षा पर अपना ध्यान केन्द्रित किया हैं जिसकी वजह से विश्व जगत में प्राकृतिक संसाधनों की प्राप्ति के लिए प्रतिस्पर्धा का माहौल बन गया हैं। जिससे प्रत्येक राष्ट्र तेल व गैस के क्षेत्र पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते हैं।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध *''शीत युद्धोत्तर भारत–ईरान सम्बन्धः ऊर्जा सुरक्षा के विशेष संदर्भ में''* विषय पर शोध करने का मेरा उद्देश्य भारत और ईरान के वास्तविक सम्बन्धों को जानना विशेष रुप से ऊर्जा के सन्दर्भ में। मेरे इस शोध कार्य व विषय चयन के लिए प्रेरित व निर्देशित करने वाले परम श्रद्धेय शोध निर्देशक प्रोफेसर रिपु सूदन सिंह की मैं आजीवन ऋणी रहूंगी, जिनके ज्ञानपूर्ण कुशल मार्गदर्शन में शोध कार्य बिना किसी व्यवधान के गतिशील रहा और गुरूवर के वात्सल्यपूर्ण प्रेम और कुशल मार्गदर्शन से शोध प्रबन्ध ने अपनी सम्पूर्णता को प्राप्त किया है।

इसी क्रम में मैं अपने विभाग के प्रो० सार्तिक बाग, प्रो० शशिकान्त पाण्डेय, डॉ० सिद्धार्थ मुखर्जी, डॉ० प्रीति चौधरी एवं अन्य गुरूजनों की सदा आभारी रहूँगी, जिनके दिशा–निर्देश से शोध प्रबन्ध कार्य को पूरा करने में सहायता प्राप्त हुई। मैं राजनीति विज्ञान विभाग के सभी कर्मचारियों की सहृदय से आभारी हूँ, जिनका समय–समय पर सहयोग प्राप्त होता रहा।

शोध अध्ययन के क्रम में बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ, और आई0डी०एस०ए० के पुस्तकालयाध्यक्षों के प्रति विशेष रूप से आभार व्यक्त करती हूँ जिनके सहयोग के बिना शोध कार्य पूर्ण करने में कठिनाई होती।

इसी क्रम में मैं अपनी माता श्रीमती गीता देवी व पिता श्री मनमोहन जी को धन्यवाद व्यक्त करती हूँ जिन्होंने मुझे हमेशा शोध प्रबन्ध के लेखन हेतु प्रेरित एवं उत्साहित किया।

इसी क्रम में, परिवार के अन्य सदस्य मेरे बड़े भाई–प्रसेनजीत मित्र, रतनसेन, पुण्डरीक व बहन–बिन्दु दी, जीजा–दुश्यन्त, भाभी–शान्ति देवी, अर्चना धर, प्रतीक, दीपिका, निशान्त, दिव्येश की भी सदैव आभारी एवं ऋणी रहूंगी, जिनका हमेशा सहयोग एवं आशीर्वाद प्राप्त होता रहा है। व प्रिय मित्र इन्दु, अराधना, प्रतीक्षा, दीपादी,नीतू, आकाश, रविन्द्र, ईरा, प्रदीप, रीचा दीक्षित, माया भारती, रंजना, दीप्ति, डॉ० अनील कुमार, डॉ० आनंद प्रताप सिंह, डॉ० राजीव प्रजापति, राघवेन्द्र प्रताप, देवेन्द्र प्रताप, डॉ० उपेन्द्र कुमार, सीमा भारती, दिनेश, सन्दीप, प्रेम, राजीव सागर, डॉ० रामबचन कुमार, अजय पाठक, डॉ० शैफाली सिंह, एवं सभी मित्रों की आभारी हूँ।

Indu

इन्दु

शब्द–संक्षेप सूची

क्र.सं.	शब्द संक्षेप	पूर्ण विवरण
1.	डब्लू0टी0ओ0	विश्व व्यापार संगठन
2.	जी0डी0पी0	सकल घरेलू उत्पाद
3.	यू0एन0ओ0	संयुक्त राष्ट्र संगठन
4.	आई0पी0आई0	ईरान–पाकिस्तान–भारत (गैस पाइप लाइन समझौता)
5.	यू०एस०ए०	संयुक्त राज्य अमेरिका
6.	ओपके	पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन
7.	टी0सी0एफ0	ट्रिलियन क्यूबिक फीट
8.	आई0बी0ई0फ0	इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन
9.	आई0ई0ए0	अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी
10.	एम0एम0टी0	मिलियन मीट्रि टन
11.	ई0आई0ए0	अमेरिकी ऊर्जा सूचना
12.	यू0एन0	संयुक्त राष्ट्र
13.	ओ0एन0जी0सी0	तेल और प्राकृतिक गैस निगम
14.	ई0यू0	यूरोपीय संघ
15.	एल0एन0जी0	तरलीकृत प्राकृतिक गैस
16.	यू0एस0एस0 आर0	सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक का संघ।
17.	सी0 ई0 एन0 टी0 ओ0	केंद्रीय संधि संगठन
18.	एन0 ए0 एम0	गुट–निरपेक्ष आंदोलन
19.	जे0 सी0 एम0	संयुक्त आयोग बैठक
20.	जी0ए0आई0ल0	गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

21.	एम0 आर0 पी0 एल0	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड
22.	यू0 ए0 ई0	संयुक्त अरब अमीरात
23.	ओ0 आई0 सी0	इस्लामिक सहयोग संगठन
24.	यू0 एस0	संयुक्त राज्य अमेरिका
25.	सी0टी0बी0टी0	व्यापक परमाणु–परीक्षण–प्रतिबंध संधि
26.	आई0ए0ई0ए0	अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी
27.	आई0 एल0 एस0 ए0	ईरान और लीबिया प्रतिबंध अधिनियम
28.	सी0 ए0 ए0टी0 एस0 ए0	प्रतिबंध अधिनियम के माध्यम से अमेरिका के सलाहकारों का मुकाबला करना
29.	सी0ए0ए0आर0के0	दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ
30.	सी0 पी0ई0सी0	चीन–पाकिस्तान आर्थिक गलियारा
31.	यू0 एन0 एस0 सी0ओ0 पी0	फिलिस्तीन पर संयुक्त राष्ट्र की विशेष समिति
32.	ओ0ई0सी0डी0	आर्थिक सहयोग और विकास संगठन
33.	जी0 सी0 सी0	गल्फ़ कोपरेशन काउंसिल
34.	एम0 आर0 पी0 एल0	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड
35.	आई0 ओ0 सी0 एल0	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
36.	आई0 बी0 ई0 एफ0	इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन

प्रकाशित लेख

1. ″भारत– अमेरिकी सम्बन्धों में ईरान एक मुद्दे के रूप में″ Review of Research, Vol.8, No. 07, ISSUE: 2249-894X.

2. ‘‘वैश्वीकरण के दौर में भारत–ईरान सम्बंधों में चाबहार बन्दरगाह का महत्व’’ Review of Research, Vol.8, No. 06, ISSUE: 2249-894X.

अनुक्रमणिका

अध्याय	शीर्षक	पृष्ठ संख्या
	आभार	
प्रथम अध्याय	**: प्रस्तावना**	**1–27**
	1. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि	
	1.1 भारत–ईरान सम्बन्ध	
	1.2 अध्ययन की प्रासंगिकता	
	1.3 साहित्य की समीक्षा	
	1.4 शोध प्रश्न	
	1.5 शोध के उद्देश्य	
	1.6 शोध परिकल्पना	
	1.7 शोध की विधि	
	1.8 अध्यायीकरण	
	1.9 अध्यायों का संक्षिप्त परिचय	
द्वितीय अध्याय	**: ऐतिहासिक संदर्भ में भारत–ईरान सम्बन्ध**	**28–42**
	2.1 भारत–ईरान संबंध का ऐतिहासिक परिपेक्ष्य	
	2.1.1 व्यापार	
	2.1.2 कला एवं शैली	
	2.2 भारत पर ईरानी तथा यूनानी हमले	
	2.2.1 ईरानी आक्रमण	
	2.2.2 दारा प्रथम	
	2.3 ईरानी प्रभुत्व का प्रभाव	
	2.3.1 लिपि एवं भाषा	
	2.3.2 सांस्कृतिक प्रभाव	
	2.4 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में ईरान	
	2.4.1 ईरान की भौगोलिक स्थिति	
	2.4.2 धर्म	
	2.4.3 जाति	
	2.4.4 नाम	
	2.4.5 कला एवं संस्कृति	

2.5 राजनीतिक व्यवस्था
2.5.1 हखामनी वंश
2.5.2 सासानी वंश
2.6 अर्थव्यवस्था
2.7 ईरान की इस्लामिक क्रांति

तृतीय अध्याय : भारत–ईरान सम्बन्ध में ऊर्जा सुरक्षा 43–62

3.1 ऊर्जा सुरक्षा
3.2 भारत में ऊर्जा सुरक्षा की रूपरेखा
3.3 ईरान में ऊर्जा की रूपरेखा
3.3.1 तेल भंडारः
3.3.2 ईरान के सबसे बड़े तेल क्षेत्र
3.3.3 प्राकृतिक गैस का भंडार
3.4 भारत में ऊर्जा मांग
3.5 भारत में उपलब्ध ऊर्जा भण्डारः
3.6 ईरान से ऊर्जा आयातः एक तुलनात्मक अध्ययन

चतुर्थ अध्याय : भारत–ईरान संबन्धों के विविध आयाम 63–85

4.1 सांस्कृतिक सम्बन्ध
4.2 राजनीतिक संबंध
4.3 आर्थिक सम्बन्ध
4.4 क्षेत्रीय सहभागिता
4.5 भू–राजनीति व सामरिक आयाम
4.6 विभिन्न क्षेत्रों में भारत–ईरान गठबंधन

पंचम अध्याय : भारत–ईरान संबंधों में अमेरिका की भूमिका का परीक्षण 86–110

5.1 शीत युद्ध के दौरान भारत–ईरान संबंध और अमेरिका
5.2 1971 का भारत–पाकिस्तान युद्ध और अमेरिकाः
5.3 18 मई 1974 परमाणु परीक्षण और अमेरिकी प्रतिबंध
5.4 1998 में भारत का परमाणु परीक्षण और अमेरिकी प्रतिबंध
5.5 भारत–अमेरिकी संबंध–एक घटनाक्रम
5.5.1 वर्तमान में भारत–अमेरिका संबंध
5.5.2 भारत और अमेरिका के बीच 123 असैन्य परमाणु सहयोग समझौता और ईरान
5.6 शीत युद्ध के बाद भारत–ईरान संबंध और अमेरिका की

भूमिका

5.7 शीत युद्ध के बाद भारत–ईरान संबंध

5.8 भारत–अमेरिका संबंध में ईरान एक मुद्दे के रुप में

5.8.1 भारत–अमेरिका संबंध

5.8.2 अमेरिका–ईरान संबंध

5.8.3 ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध नवंबर 2018

5.8.3.1 ईरान परमाणु समझौता P5 + 1

5.8.3.2 ईरान परमाणु समझौता–मुख्य बिंदु

5.8.4 भारत ईरान संबंधों, में भारत–अमेरिका 2+2 वार्ता का प्रभाव

5.9 भारत–ईरान संबंधों में अमेरिका की भूमिका का परीक्षण

5.10 भारत–ईरान संबंध से अमेरिका का टकराता हित

षष्टम् अध्याय : भारत–ईरान सम्बन्ध का पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया पर प्रभाव 111–13

6.1 दक्षिण एशिया में भारत

6.1.1 दक्षिण एशियाई देशों के साथ भारत के आर्थिक संबंध

6.2 दक्षिण एशिया में ईरान

6.3 पश्चिम एशिया में भारत

6.4 पश्चिम एशिया में ईरान

सप्तम् अध्याय : वैश्विक राजनीति में भारत ईरान सम्बन्ध 132–153

7.1 वैश्विक राजनीतिः

7.2 भारत–ईरान संबंध आतंकवाद (सीरिया, फिलिस्तीन, इजरायल) की समीक्षा

7.3 वैश्विक दौर में भारत–चीन प्रतिस्पर्धा

7.4 वैश्विक परिदृश्य में भारत

7.5 आधुनिक युग में भारत ईरान के दृष्टिकोण की समीक्षा

अष्टम अध्यायः निष्कर्ष एवं सुझाव 154–161

सन्दर्भ ग्रन्थ–सूची 162–172

तालिका एवं चित्र की सूची

क्र. सं.	तलिका एवं चित्र सं.	तलिका एवं रेखाचित्र विषय
1.	चित्र 3.1	विश्व के बड़े कच्चे तेल उत्पादक देश
3.	चित्र 3.2	ईरान के सबसे बड़े तेल क्षेत्र
4.	तालिका 3.1	ईरान के पांच सबसे बड़े तेल क्षेत्र
5.	चित्र 3.3	प्राकृतिक गैस के सबसे बड़े आरक्षित धारक वर्ष 2017
6.	तालिका 3.2	भारत में ऊर्जा स्रोतों का उपभोग
7.	तालिका 3.3	भारत में ऊर्जा उपलब्धता
8.	चित्र 3.4	भारत के तेल आयात के स्त्रोत वर्ष 2013–2017
9.	तालिका 4.1	भारत–ईरान के आर्थिक संबंध
10.	चित्र 4.1	क्षेत्रीय संपर्क मार्ग
11.	तालिका 6.1	दक्षिण एशिया में भारत का निर्यात (2007–2009)
12.	तालिका 6.2	दक्षिण एशिया में भारत का निर्यात (2016–2018)
13.	तालिका 6.3	भारत का दक्षिण एशिया से आयात (2007–2009)
14.	तालिका 6.4	भारत का दक्षिण एशिया से आयात (2016–2018)
15.	चित्र 6.1	ईरान की भौगोलिक स्थित
16.	चित्र 7.1	वैश्विक राजनीति के विभिन्न आयाम

अध्याय–प्रथम

प्रस्तावना

द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों को जिस एक मात्र कारक ने सर्वाधिक प्रभावित किया, निःसंदेह वह शीत युद्ध ही था। वास्तव में यह शीत युद्ध कोई सैन्य या प्रतिपक्ष युद्ध नहीं था अपितु यह एक वैचारिक संघर्ष था जो इन दो महाशक्तियों (संयुक्त राज्य अमेरिका व सोवियत संघ) के मध्य इस तनावपूर्ण स्थिति को व्यक्त करने के लिए सामने आया जिसे शीत युद्ध का नाम दिया गया। जिसने एक लंबे समय 1945–1991 के कालखंड को अपनी गिरफ्त में रखा। वस्तुतः यह दो विचारधाराओं के बीच एक प्रकार का वाक् युद्ध, मनोवैज्ञानिक युद्ध, कूटनीतिक युद्ध, या प्रचार युद्ध था। इसका प्रभाव विश्व के अनेक देशों पर दिखाई देता है।

कोहेन और नाई के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में वस्तुतः ऐसे अनेक माध्यम होते हैं जो राज्यों की वेस्टफेलियन व्यवस्था को पीछे छोड़ देते हैं। विभिन्न राज्य अपने हितों को ध्यान में रखते हुए एक दूसरे से जुड़ते हैं यह निम्न रूपों से स्पष्ट होता है–औपचारिक व अनौपचारिक। इस माध्यम के जरिए न केवल राजनीति का आदान–प्रदान होता हैं बल्कि प्राकृतिक स्रोतों का भी दोहन होता हैं। 1990 के बाद विश्व में परिवर्तन की दौड़ शुरू हुई जिसमें पश्चिम के विकसित व पूर्व एशियाई क्षेत्रों के विकासशील देश आर्थिक उन्नति की दिशा में प्रगतिशील प्रयास करने लगे लेकिन इस उन्नति के लिए ऊर्जा एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है जिसके बिना सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक विकास असंभव है।

इस असंभव कारक को प्राप्त करने के लिए विश्व के प्रत्येक राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा स्पर्धा के लिए संघर्ष करने लगें। जिसमें अमेरिका, चीन, जापान, और भारत इत्यादि देश सम्मलित हैं। वहीं ऊर्जा उत्पादक देश अपनी प्राकृतिक संपत्ति का उच्चतम मूल्य प्राप्त करना चाहते हैं क्योंकि इन देशो की आर्थिक स्थिति पूर्ण रूप से खनिज पदार्थों पर निर्भर है। विश्व में उर्जा संपन्न देशों में सऊदी अरब, इराक, ईरान सबसे प्रसिद्ध है।

भारत ईरान सम्बन्ध का विश्लेषण करें तो पायेंगे कि इनका इतिहास सकारात्मक रहा है। पश्चिमी एशियाई क्षेत्रों से विभिन्न सभ्यता एवं संस्कृति भारत में आयीं तथा ईरान की कला और संस्कृति का स्पष्ट उदाहरण बौद्ध धर्म से सम्बन्धित बुद्ध की मूर्तियां हैं।[1] वहीं भारतीय सभ्यता एंव संस्कृति की झलक ईरान में भी देखनें को मिलती हैं।

भारत ने भी अमेरिका द्वारा ईरान–इराक पर तेल संकट (1973) के समय लगाये गये अनुचित प्रतिबन्धों का विरोध किया था। शीत युद्ध के बाद सोवियत संघ के विघटन से अमेरिका की दबावपूर्ण नीति इस क्षेत्र में बढ़ गयी है। इसी का परिणाम 2003 में इराक के खिलाफ युद्ध के रूप में सामने आया (Tharoor, June 16, 2014)। इराक के विरुद्व आर्थिक एवं सैनिक प्रतिबन्ध 1990 से लागू किये गये थे तथा इराक के निःशस्त्रीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने निःशस्त्रीकरण आयोग की स्थापना की। इसी परिप्रेक्ष्य में अमेरिका अनेक खाड़ी देशों को निःशस्त्रीकरण के नाम पर युद्ध की धमकी भी दे चुका है। इसी का परिणाम था कि सद्दाम हुसैन को हटाकर वहाँ पर पश्चिमी समर्थक सरकार को सत्ता की गद्दी सौंप दी गयी। अतः इराक में पुर्ननिर्माण तथा युद्ध में हुए हर्जाने के तौर पर अमेरिका ने इराक से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से तेल के साथ–साथ बड़ी धनराशि का लाभ उठाया।

ईरान में भी परमाणु कार्यक्रम के नाम पर अमेरिका ने अपना दबाव बढ़ाया तथा परमाणु प्रसार को बन्द करने की बात कही। इसी को लेकर परमाणु अप्रसार के लिए वोट डाला गया, जिसमें भारत ने न चाहते हुए भी अमेरिका के दबाव में ईरान के खिलाफ वोट डाला। भारत ने ईरान का खुलकर समर्थन तो नहीं किया, परन्तु ऊर्जा जरूरतों की पूर्ति के लिए ईरान के परमाणु कार्यक्रम का पक्षधर रहा। रूस और चीन ने तो ईरान के परमाणु कार्यक्रम का खुलकर समर्थन किया। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ का मतलब अमेरिका ही लगता है, क्योंकि जो भी इनकी नीतियों के आड़े आता है, वह सीधे अमेरिका का शत्रु बन जाता है और अमेरिका थोड़ी बात–चीत के बाद सीधे उक्त राष्ट्र को देख लेने (युद्ध) की धमकी देता है।

[1] India Iran Historical Links. Embassy of India Retrieved on 27 November, 2018 from https://www.indianembassy-tehran.ir/pages.php?id=17.

विश्व राजनीति में पश्चिम एशिया 20वीं सदी के प्रारम्भ से ही महत्वपूर्ण बना रहा है क्योंकि विश्व का 60 से 90 प्रतिशत ऊर्जा पश्चिम एशिया से निर्यात की जाती रही है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर आधारित अनुसंधान बिना ऊर्जा के नहीं चल सकता है। यही कारण है कि पश्चिम एशिया 21वीं सदी में उतना ही महत्वपूर्ण है, जितना कि 20वीं सदी में था।

देखा जाये तो शीत युद्धोंपरान्त भूमण्डलीकरण के दौर में सुरक्षा की अवधारणा में अनेक बातें सम्मिलित हुई हैं जिसका सम्बन्ध ऊर्जा से है। जहाँ पर पश्चिम एशिया प्राकृतिक तेल एवं गैस से सम्पन्न है, वहीं पर दक्षिण एशिया में जनसंख्या की एक बहुत बड़ी फौज खड़ी है। जब हम इन बातों को संज्ञान में लेते हैं तो भारत और ईरान के सम्बन्धों की चर्चा स्वाभाविक रूप से उठती हैं। भारत और ईरान का सम्बन्ध कोई नई घटना नहीं है वरन् इसकी जड़े इतिहास से जुडी हुई हैं। यही कारण है, कि ईरान और भारत में किसी की भी सरकार रही हो, दोनों देशों के बीच एक आपसी समझ बनी रही है। स्वाभाविक समझदारी से बंधा यह संबंध अनिवार्य होने साथ ही एक दूसरें का पूरक भी हैं।

भारत–ईरान से खाद्य, उर्वरक तथा तेल एवं गैस का आयातक रहा है। बदले में भारत उसे दैनिक खाद्य्य जरूरतों की सामग्री निर्यात करता हैं। ईरान की आन्तरिक राजनीति में भारत हस्तक्षेप का पक्षधर नहीं है। मानवाधिकार के मुद्दे पर तथा बालश्रम नियम–कानून पर भारत ईरान के साथ है। वैश्विक संगठन तथा विश्व व्यपार संगठन (डब्लू0टी0टो0) की स्थाई सदस्यता, पर्यावरणीय संगठन संयुक्त राष्ट्र संगठन (यू0एन0ओ0) आदि पर हमने साथ–साथ आवाज उठाई है। पर्यावरणीय मुद्दों पर ईरान तथा भारत का नजरिया एक है। भारत तथा ईरान दोनों ही पर्यावरण तथा मानवाधिकार के नाम पर पश्चिमी देशों के अनुचित प्रतिबन्ध के विरोधी रहे हैं।

खाद्य सुरक्षा तथा ऊर्जा संकट, प्रबन्धन वर्तमान समय की सबसे बड़ी चुनौती है। ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए ईरान भारत का खुलकर समर्थन करता है। भारत–ईरान से गैस पाइपलाइन द्वारा गैस की पूर्ति सुनिश्चित करना चाहता है। ईरान ने इस ओर दिलचस्पी दिखाते हुए बढ़–चढ़ कर इसका समर्थन किया तथा

गैस देने का वादा भी किया। परन्तु भारत द्वारा ईरान के परमाणु प्रसार के खिलाफ वोट देने के कारण यह परियोजना अभी तक शुरू नहीं हो पायी है। इसके पहले 123 डील के बाद से भी सम्बन्धों में थोड़ा बिखराव नजर आने लगा है। भारत खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में लगभग आत्मनिर्भर है तथा ईरान को खाद्य सुरक्षा की हर सम्भव मदद करता है। सामरिक दृष्टि से ईरान मुस्मिल बाहुल्य मध्य एशिया में स्थित ऐसा देश है जहां से अन्य देशों तक आसानी से पहुंच बनाई जा सकती है और आर्थिक एंव सामाजिक लाभ उठाया जा सकता है।

उपरोक्त वैचारिक पृष्ठभूमि से शीत युद्धोपरान्त भारत और ईरान के सम्बन्धों में सुरक्षा धारणा का अध्ययन अति महत्वपूर्ण बन जाता है। इसमें रोजगार, खाद्य–सामग्री, ऊर्जा, विकासपूर्ण कार्य से लेकर कला एवं संस्कृति आदि की भी चर्चा करते हैं जिससे ये दोनों देश आपसी सम्बन्धों को सुदृढ़ बनाकर इस समस्या का समाधान पा सकते हैं। इससे असुरक्षा का भाव कम हो सकता है, और इस सम्बन्ध से किसी तीसरे राष्ट्र को नुकसान नहीं पहुंच रहा है। प्रगाढ सम्बन्धों द्वारा भारत–ईरान से रूपये में ही व्यापार कर सकता है, उसे बदले में डॉलर नहीं देना पड़ेगा। इससे दोनो देशों की आर्थिक सुरक्षा भी बनी रहेगी।

1. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान तथा अन्य खाड़ी देशों से भारत की हड़प्पा संस्कृति मेलुहा (हड़प्पा सभ्यता क्षेत्र) का व्यापारिक सम्बन्ध था जिसमें मेलुहा से लकड़ी, ताँबा एवं कई प्रकार के बीज और सोने का व्यापार होता था। भारत और ईरान का सम्बन्ध सदियों पुराना है। दिल्ली सल्तनत एवं मुगलकालीन शासकों का सामाजिक सांस्कृतिक सम्बन्ध मुख्यतः फारसी सभ्यता से प्रभावित रहा है। इन शासकों ने भारत में इनका प्रचलन प्रारम्भ किया जैसे नवरोज का त्यौहार मनाना, सिजदा (दण्डवत प्रणाम) की प्रथा का प्रचलन आदि यहाँ भी लेकर आये।

भारत की शिल्प कला एवं संस्कृत में ईरान का बहुत प्रभाव रहा है। भारतीय ऋग्वेद और ईरानी ग्रंथ (अवेस्ता) में भी काफी समानता देखने को मिलती है। 1947 तक दोनों देश आपस में एक ही सीमा सांझा कर रहे थे। कई आम सुविधाओं,

भाषा, संस्कृति एवं परम्पराओं का आदान–प्रदान कर रहे थे। ईरान के शाह 15 अगस्त 1950 में भारत यात्रा पर आये ओर दोनों देशों के बीच कूटनीतिक सम्बन्धों की शुरूआत शुरूवात हुई।

1959 में पं0 जवाहर लाल नेहरू ने ईरान की यात्रा की। श्रीमती इंदिरा गाँधी ने 1974 में ईरान की यात्रा की थी। 29 अप्रैल 2008 में ईरान के राष्ट्रपति डा0 मोहम्मद अहमदीनेजाद भारत आये। भारत एवं ईरान दोनों देशों के मध्य द्वि–पक्षीय सम्बन्धों को लेकर कई वार्ता एवं बैठकें होती रही है। भारत और ईरान का सम्बन्ध सदियों पुराना है, परन्तु इसकी कूटनीतिक शुरूआत 1950 से मानी जाती है, क्योंकि भारत ने अपनी बढ़ती हुई ऊर्जा की मांग को पूरा करने के लिए तेल और गैस आयात हेतु समझौता किया। इसका मुख्य कारण था, कि ईरान के पास दुनिया का 15 प्रतिशत प्राकृतिक गैस संरक्षित है तथा विश्व में दूसरा स्थान है।

ईरान का विश्व के अन्य देशों के साथ सम्बन्ध उतने अच्छे नहीं हैं, जितने कि भारत के साथ है। वर्तमान में भारत ईरान से लगभग 70 प्रतिशत कच्चे तेल एवं लगभग 12 प्रतिशत प्राकृतिक गैस का आयात करता है। गैस का आयात करने के लिए 1999 में भारत ने ईरान के साथ समझौता किया, जबकि पाकिस्तान यह समझौता 1995 में ही कर चुका था। तीनों देशों ने 1999 में आई0पी0आई0 जिसकी दूरी 2700 किमी है, पर समझौता किया है, परन्तु भारत द्वारा ईरान के परमाणु प्रसार पर रोक के लिए वोट देने के कारण वर्तमान में भी यह परियोजना शुरू नहीं हो पायी है। यही कारण है, कि ईरान भारत में तेल का दूसरा सबसे बढ़ा निर्यातक था, लेकिन अब यह छठे स्थान पर पहुॅच गया है।

ईरान एक मुस्लिम देश है तथा यहाँ प्राकृतिक संसाधनो का विशाल भण्डार है। यही विशेषता ईरान को अन्य देशों से अलग पहचान देती है। ईरान में तेल की प्रमुख कम्पनी 1920 में अस्तित्व में आयी तथा 1970 के मध्य तक यह विश्व की चौथी पेट्रोलियम उत्पादक कम्पनी थी 1989 तक यह चौथे नम्बर पर बनी रही।[2] 1979 के ईरान की इस्लामिक क्रान्ति के बाद भी प्राकृतिक संसाधनों में कमी नहीं

[2]Oil. Global Security.org. Retrieved on 2 Feb 2019 from https//www.Globalsecurity.org/ military/world/iran/oil.htm.

आयी, जो वर्तमान तक जारी है। ईरान भारत को लगभग 4,25,000 बैरल कच्चा तेल प्रतिदिन निर्यात करता है। आज प्राकृतिक संसाधनों की वजह से ईरान का आर्थिक विकास बहुत ऊपर उठ है। जिसमें तेल और गैस का मुख्य निर्यात ही ईरान की विकसित अर्थव्यवस्था एवं उसकी आमदनी का माध्यम बन गया है।

ईरान भारत से चावल, मशीनरी, मेटल सामग्री, स्टील, लोहा, कृतिम प्लास्टिक, खनिज पदार्थ, कृषि सामग्री आयात करता है। ईरान ने तेल और गैस के निर्यात के लिए भारत को तीन रास्ते बताये हैं। पहला, आई0पी0आई0 परियोजना, दूसरा समुद्र के रास्ते पाइप लाइन के माध्यम से एवं तीसरा समुद्री जहाज के द्वारा। यह भारत पर निर्भर करता है कि भारत कौन सा रास्ता चुनता है।

1.1. भारत–ईरान सम्बन्ध

भारत और ईरान का सम्बन्ध हजारों साल पुराना है, क्योंकि 1200 के लगभग में इण्डो–आर्यन प्रवर्जन ईरान से भारत देखा गया। यहॉ तक की भाषा में भी अदला–बदला होती रही है। संस्कृत और परसियन भाषा के समाचार आज भी पढ़े जाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में लेखक और छात्र–शोधछात्र दोनों देशों में अध्ययन कर रहें हैं। अगस्त 1947 में जब भारत और पाकिस्तान स्वतंत्र हुए तो इस महाद्वीप में नई स्थिति उत्पन्न हो गयी, जिसका प्रभाव ईरान और कुछ एशियाई देशों पर भी पड़ा, क्योंकि दोनों स्वतंत्र राज्य अत्याधिक विवादस्पद मुद्दों पर उलझ रहे यह समस्या कश्मीर है जो आज भी एक विवाद का विषय बना हुई है। अपने जन्म के बाद पाकिस्तान अपनी विचार धारा और वैधता की खोज में लग गया है, साथ ही इसने भारत की छवि को खराब करने की दोहरी नीति शुरू किया।

ईरान में पत्रकारिता विभाग (प्रेस) और जनता के बीच पाकिस्तान के लिये सहानुभूति थी। हालाकि सरकार का रवैया भौगोलिक, राजनीतिक, सामरिक और सुरक्षा कारणों से निर्धारित किया गया था। अतः स्पष्ट है कि ईरान–पाकिस्तान के मध्य ज्यादा सहानुभूत दिखाई दिया। यह वस्तुतः स्पष्ट है कि ईरान पहला ऐसा देश है जिसने पाकिस्तान की स्थिति को मान्यता दी और 1948 तक कुटनीतिक सम्बन्धों की स्थापना की। पाकिस्तान प्रधानमंत्री लियाकत अली जिन्न ने ईरान का

दौरना 1949 में किया तत्पश्चात ईरान के शाह भी 1950 में पाकिस्तान के दौरे पर आये[3] तो दोनों देशों ने आर्थिक, सामरिक क्षेत्रों पर हस्ताक्षर कियें।

इन तथ्यों से यह पता चलता है कि भारत और पाकिस्तान में पाकिस्तान को ज्यादा महत्व दिया गया। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पं0 जवाहर लाल नेहरू देश के शीर्ष भारतीय राष्ट्रीय काग्रेंस और राष्ट्रवादी नेता में से हैं जिन्होंने 1946 में रूसी सेना के वापसी के लिये ईरानी मांग का समर्थन किया लेकिन सोवियत संघ को जवाहर लाल नेहरू ने प्रत्यक्ष रूप से आलोचना नहीं की। यह भी माना जाता रहा है कि सोवियत संघ संकट से जूझ रहा था और ऐसा करने के लिये नेहरू की प्रतियिा भारत की आजादी से पहले निहिर्ताथ थी। ईरान ने कहा कि इन्हें नेहरू के समर्थन का गुमान रहा है उस समय पाकिस्तान का जन्म नहीं हुआ था। इससे यह स्पष्ट होता है कि ईरान की विदेश निति में सोवियत संघ की छाया थी। हालांकि ईरान के लिये सहायक कम्यूनिष्ठ राज्य के लिये एक कोना मात्र रहा है। इस तरह से इस क्षेत्र में त्रिपक्षीय समीकरण देखा गया और भारत के प्रति ईरान का रवैया एक प्रमुख कारक के रूप में अच्छा प्रभाव पाया गया था।

भारत के लिये यह एक मिश्रित टिप्पणी है जिसमें अपनी स्वतंत्रता आन्दोलन में इस पराकाष्ठा का अनुभव किया। ईरान में शीत युद्ध के समय इसका गहरा प्रभाव पाया गया और एक नये राज्य पाकिस्तान का जन्म हुआ इसके साथ ही भारत ने ईरान की पुरानी क्षेत्रीय समीपता (सीमा रेखा) को खो दिया। भारत अपने 390 मील सीमारेखा पाकिस्तान को विरासत में दे दिया जिसकी सीमा रेखा ईरान से लगती थी।[4] तब से सटीकता के साथ कहा जा सकता है कि पाकिस्तान केवल भगौलिक दृष्टि से भारत और ईरान के बीच ही नहीं उभरा बल्कि दोनों देशों के बीच एक कारक के रूप में सामने आया।

फिर भी ईरान की स्थित के बारे में भी आलोचना किये बिना भारत के प्रति अच्छी तरह से रिस्ता निभाया और नेहरू ने इस तथ्य को स्वीकार किया इसका यह

[3] Bhattacharjee, D., (2017). Pakistan and Iran – Changing Dynamics and Challenges. *Indian council of world Affairs.* Retrieved on 21 March 2018 from https://icwa.in/pdfs/vp/2014/pakistanandiranchangingvp07072017.pdf

[4] What is the length of the Pakistan-Iran border?. Retrieved on 11 Sep 2017 from https://www.quora.com/What-is-the-length-of-the-Pakistan-Iran-border.

रूप दोस्ताना समबन्ध का एक चिन्ह के रूप में भी देखा जा सकता है। ईरानी प्रशासन पहली गैर सरकारी संगठन एशियाई सम्बन्ध सम्मेलन मार्च 1947 में दिल्ली में भाग लिया[5] और इस मंच पर ईरानी प्रतिनिधी ने अपने सम्बन्धों को दोहराया साथ ही भारत की आजादी के लिये शुभ कामना भी दिया। उपर्युक्त स्थित से विदित होता है कि जिस प्रकार दो व्यक्तियों की आवश्यकताएँ समय के साथ–साथ परिवर्तित होती रहती है। इसी आवश्यकता की वजह से दोनों देशों के बीच रिश्तों में उतार–चढ़ाव आता रहता है, इसलिये दोनों देशों के बीच समबन्धों को मजबूती प्रदान करने के लिये एक दूसरे की अवश्यकताओं को समझना होगा। 1947 तक यह देखा गया है कि दोनों देशों ने द्वितीय विश्व युद्ध के जटिल नतीजों को भी साथ में अनुभग किया है।

भारत ने ईरान के खिलाफ वोट दिया जिससे दोनों देशों के सम्बन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। हालांकि यह माना जाता है कि जब भारत ने ईरान के खिलाफ मतदान किया था, यह एक तरह से अमेरिकीय दबाव य झुकाव था, लेकिन 2013 में भारत ने अमेरिकीय दबाव को नजर अन्दाज करते हुए ईरान के साथ ऊर्जा व्यापार जारी रखा जिसे दोनों देशों के बीच सम्बन्धों में स्थिरता शुरू हुई। भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मई 2016 में ईरान की यात्रा किया जिसको भारत ने एक उच्च कोटि की यात्रा करार दिया। इस यात्रा से भारत ने ईरान के साथ चाबाहार बन्दरगाह का विकास, अफगानिस्तान और मध्य एशिया के साथ क्षेत्रीय सड़क और रेल सम्पर्क मार्ग बनाने के लिये 500 मिलियन डॉलर का निवेश करने पर अपनी सहमती व्यक्त की है। इसके अतिरिक्त भारत चाबाहार बंन्दरगाह में लगभग 80 करोड़ अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की योजना बनाई है जिसके तहत दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार होगा। दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार लगभग 13 अरब अमेरिकी डॉलर है जिसमें भारत ईरान से लगभग 12 अरब डॉलर का तेल आयात करता है भारत ने चालू वित्त वर्ष में ईरान से लगभग 25 मिलियन टन कच्चा तेल आयात करने की योजना बनाई थी, जो 2017–18 में आयातित 22.6

[5] Swamy, S., (2002). An Iranian sister. Frontline. 19 (07). Retrieved on 10 March 2016 from https://frontline.thehindu.com/static/html/fl1907/19070560.htm.

मिलियन टन था।[6] भारत में ईरान की सांस्कृतिक भूमिका भारत के अन्दर शिया मौल्बी पादरी के चारों ओर धूमती रहती है। भारत में सत्ता की प्रतिष्ठा इस बात से अवगत है और चुपचाप उसे समर्थन देती है। यहॉ तक कि भारत में ईरान के राजदूत एच0 रजा अन्सारी ने एक बार दिल्ली के विश्वविद्यालय में एक भाषण में स्विकार किया कि इतिहास में कई बार भारत के साथ ईरान के सम्बन्ध अन्य दूसरे मुस्लिम पड़ोसी देशों की अपेक्षा बेहतर रहा है। भारत के सुन्नी मुस्लिम कट्टरवाद पाकिस्तान से उत्पन्न आतंकवाद को अपने राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे को प्रमुख मानता है।

द्विपक्षीय सन्धि दोनों देशों के आर्थिक अैर भूराजनैतिक हितों पर आधारित है। जाहिर है कि अपने बेहतर द्विपक्षीय सम्बन्धों के माध्यम से ईरान को करीब लाने के लिये भारत कई तरह से भारतीय शिया समुदाय को संतुष्ट करने का प्रयास करेगा। भारत–ईरान सम्बन्धों के विविध आयाम निम्नलिखित है जो किसी देश के साथ अपने सम्बन्धों की एक नई रूपरेखा तैयार करते हैं जैसेः–जनसांख्यिकी, क्षेत्रीय संयोजता, द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दो पर सहयोग प्रदान करना इत्यादि।

1. क्षेत्रीय संयोजकता
2. आर्थिक सहयोग तथा द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देना।
3. क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दो पर दोनों देशों का सहयोग।
4. आतंकवाद।
5. सांस्कृतिक, कूटनीति।

1.2. अध्ययन की प्रासंगिकता

विकास की प्रमुख आवश्यकता ऊर्जा सुरक्षा है, जिसके बिना विकास संभव नहीं है। 21वीं सदी में भारत की बढ़ती जनसंख्या के साथ भारत की आतंरिक

[6] India to Continue Iranian oil Imports Post US Sanctions. (Oct 5, 2018). The Times of India. Retrieved on 23 March 2019 from https://economictimes.indiatimes.com/industry/energy/oil-gas/india-to-continue-iranian-oil-imports-post-us-sanctions/articleshow/66088584.cms?from=mdr

आवश्यकता में काफी परिवर्तन आया है। आज देश को तीव्र विकास की आवश्यकता है, परन्तु भारत की ऊर्जा आवश्यकता की निर्भरता बाह्य देशों से प्राप्त ऊर्जा पर निर्भर हुई है। अतः भारत की प्रमुख आवश्यकता है, कि ऊर्जा निर्भरता वाले देशों के साथ अपने संबंध प्रगाढ़ बनाये। भारत का ईरान के साथ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से घनिष्ठ संबंध रहा है। ईरान के पास ऊर्जा का अपार भंडार है, जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकता है। ईरान की आवश्यकताओं को हम और हमारी आवश्यकताओ को ईरान पूरा करने में सक्षम है। इस संदर्भ में भारत ईरान के संबंधों का विश्लेषणात्मक अध्ययन वर्तमान एवं भविष्य के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा यह शोध कार्य बहुत ही प्रासंगिक होगा।

प्रस्तुत अध्ययन के माध्यम से यह जानने का प्रयत्न किया जायेगा, कि भारत की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकता के रूप में ईरान के पास मौजूद विशाल ऊर्जा भण्डार के अवसर के रूप में वर्तमान स्थिति एवं भविष्य की सम्भावनाओं का विश्लेषण करने का प्रयास किया जायेगा।

1.3.साहित्य की समीक्षा

राजेन्द्र एम. अभंयकर द्वारा रचित 'वेस्ट एशिया एण्ड द रीजन डिफाइनिंग इण्डियास् रोल' में भारत में गैस और तेल की खपत एवं उत्पादन की व्याख्या की गयी है, साथ ही भारत का ईरान, अमेरिका एवं खाड़ी आदि देशों से व्यापारिक सम्बन्धों में ऊर्जा के महत्व को बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है।

अनवर आलम ने अपनी पुस्तक 'इण्डिया एण्ड ईरानः एन एसेसमेंट ऑफ कॉनटेम्पोररी रिलेशन' में विशेष रूप से 9/11 के हमले के बाद अमेरिका और भारत के सम्बन्ध एवं भारत–ईरान सम्बन्धों में मुख्य रूप से ऊर्जा सम्बन्ध तथा आई. पी.आई. परियोजना के बारे उल्लेख किया है।

नेमातुल्लाह फजेली की पुस्तक 'पॉलिटिक्स ऑफ कल्चर इन ईरान एन्थ्रोपोलॉजी, पॉलीटिक्स एण्ड सोसाइटी इन द 20th सेन्चुरी' में ईरान के लगभग 100 वर्षों के इतिहास में सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीति परिवर्तन की पत्र, सन् एवं घटना सहित व्याख्या की है। और 1979 की ईरानी इस्लामिक क्रांन्ति तथा

ईरान का इस्लामीकरण और उसके बाद भूमण्डलीकरण तथा आधुनिकीकरण के बारे में भी बताया है।

क्रिस्टन ब्लैक ने अपनी पुस्तक 'द यू0 एस0–सोवियत कॉनफ्रेन्टेशन इन ईरान, 1945–1962: ए केस इन द एनालस् ऑफ द कोल्डवार में ईरान द्वारा परमाणु कार्यक्रम की शुरूआत और अमेरिका द्वारा प्रतिबन्ध, रूस द्वारा समर्थन, 1979 में ईरानी इस्लामी क्रान्ति तथा शीत युद्ध के बीच में यू.एस.ए. एवं सोवियत संघ रूस की प्रतिद्वन्दिता और संयुक्त राज्य से ईरान के सम्बन्धों का प्रमुख रूप से उल्लेख किया गया है।

माइकल वेसले द्वारा रचित पुस्तक 'एनर्जी सिक्योरिटी इन एशिया' में एशिया के देशों में ऊर्जा सुरक्षा के बारे में विस्तृत रूप से लिखा गया है। सन् 2025 तक दो विकसित रूप से तैयार देश चीन और भारत, ऊर्जा दोहन के मामले में, चीन का 2025 तक ऊर्जा दोहन 156 प्रतिशत हो जायेगा और भारत का 152 प्रतिशत। इसमें ऊर्जा संकट का मुद्दा भी उठाया गया है।

जॉन ई. पीटरस् द्वारा दी गयी रिसर्च रिपोर्ट जिसका शीर्षक 'वार एण्ड इसकॉलेशन इन साउथ एशिया' में बताया गया है कि दक्षिण एशिया में विश्व युद्ध के बाद जो छोटे–छोटे देश आजाद हुए थे, वे अपनी क्षेत्रीय क्षमता को उभारने में लगे थे। जिससे दक्षिण एशिया में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गयी थी अमेरिका मध्य–पूर्व एशिया को छोड़कर दक्षिण एशिया में अपना लक्ष्य तलाशने लगा। यह युद्ध के बाद संयुक्त राज्य और ईरान के सम्बन्ध को भी दर्शाया गया है। साथ ही भारत–पाकिस्तान के आपसी मतभेदों, युद्धों, तनाव और कटुतापूर्ण सम्बन्धों के साथ–साथ भारत–चीन सम्बन्धों का भी उल्लेख किया गया है।

हामिद दबोशी ने अपनी पुस्तक 'थियोलॉजी ऑफ डिस्कॉन्टेन्टः द आइडियोलॉजिकल फॉउन्डेशनस् ऑफ द इस्लामिक रिवॉल्यूशन इन ईरान' में ईरानी इस्लामीक क्रान्ति (1979) का ईरान के राजनीतिक विचारों एवं सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा आदि के बारे मे 1979 से लेकर 1997 तक का विवरण दिया गया है।

फरहांग रॉजी ने अपनी पुस्तक 'इस्लामिज्म एण्ड मॉडरनिज्मः द चेंजिंग डिस्कोर्स इन ईरान' के अनुसार ईरान में इस्लामिक आन्दोलन एवं इसके विचार द्वारा वैकल्पिक रूप से 20वीं एवं 21वीं सदी में आधुनिकरण की शुरूआत हो गयी थी। इसमें विश्व के ध्रुवीकरण और शीत युद्ध की समाप्ति के बाद ईरान के आधुनिकीकरण का विवरण है।

अली मोहम्मदी द्वारा अपनी पुस्तक 'ईरान एन्कांउटरिंग ग्लोबेलाइजिंगः प्रॉबलम् एण्ड प्रास्पेक्टस्' में ईरान में इस्लामिकरण के बाद जो आधुनिकीकरण शुरू हुआ, उससे जिस तरह का राजनीतिक, औद्योगिक, सांस्कृतिक परिवर्तन हुआ है। ईरान में प्रेस का आधुनिकीकरण और इस्लामिकरण के बीच ईरानी महिलाओं का स्थान, आर्थिक भूमण्डलीकरण और विश्व मार्केट में ईरान का स्थान आदि का विशेष उल्लेख है।

मीना सिंह रॉय द्वारा अपनी पुस्तक 'इण्टरनेशनल एण्ड रिजनल सिक्योरिटी डॉयनॉमिक्सः इण्डिया एण्ड ईरानीयन प्रस्पेक्टीव' में भारत–ईरान सम्बन्धों का वर्तमान और भविष्य का विश्लेषण राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं ऊर्जा के सम्बन्ध में किया गया है तथा भारत के पड़ोसी देशों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से विश्लेषण किया गया है।

अनुप शाह द्वारा अपने लेख 'ईरान में रजा शाह पहलवी' के समय का औद्योगिक कम्पनियों का विकास, आधुनिकीकरण और राष्ट्रीय साक्षरता आदि का वर्णन करते हुए बताया है, कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ईरान, अमेरिका तथा भारत इत्यादि देशों के साथ सम्बन्धों, भारत द्वारा ईरान परमाणु प्रसार के खिलाफ वोट तथा अमेरिका द्वारा विरोध आदि को प्रमुखता दिया गया है।

बहमन मलेकी ने अपने लेख 'भारत ईरान सम्बन्धों पर परिप्रेक्ष्य' में, शोधकर्ता ने ईरान में 1979 में हुई इस्लामिक क्रान्ति के बाद ईरान को विश्व के अन्य देशों के साथ सम्बन्धों का पुर्नगठन हुआ तथा ईरान पर लगाये गये पश्चिमी देशों के द्वारा प्रतिबन्धों के बीच भारत ईरान सम्बन्धों में अधिक जटिलता आने की सम्भावना को व्यक्त किया गया है। ईरान के प्रति 1947 के बाद भारत का दृष्टिकोण तथा भारत

के प्रति ईरान का दृष्टिकोण एवं भारत अमेरिकी सम्बन्धों के बीच ईरान के महत्व को दिखाया गया है।

अनुप सिंह द्वारा लिखे गये लेख 'द इकोनॉमिक्स ऑफ ईरान–पाकिस्तान –इण्डिया नेचुरल गैस पाइप लाइन' में उन्होने भारत में प्राकृतिक गैस के उत्पादन, मांग और पूर्ति का विवरण चार्ट द्वारा किया है। और ईरान–पाकिस्तान–भारत गैस पाइप लाइन के सम्बन्ध में गैस मूल्य तथा गैस लाने में लगे समय का विश्लेषण हुआ है।

एनी सोफी कॉरव्यू ने अपने लेख 'नेचुरल गैस इन इण्डिया' में प्रमुख रूप से भारत में औद्योगिकीकरण का इतिहास और भारत में गैस उत्पादन, उपभोग तथा मांग, गैस मूल्य, गैस परिवहन कम्पनी, गैस आयात और अनुबन्ध आदि पर विस्तृत जानकारी दी है। इसमें प्रमुख रूप से अन्तर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेन्सी की रिपोर्ट 2010 के आंकड़े है।

डॉ० इदरीस अहमद ने अपनी पुस्तक "ग्लिमपसेस ऑफ सोशल एंड कल्चरल हिस्ट्री ऑफ ईरान" के अंतर्गत भारत और ईरान के बीच अंतर संबंधों के इतिहास को दर्शाया है। लेखक ने भारत और ईरान के सांस्कृतिक एवं राजनीतिक संबंधों को पूर्ण इस्लामिक बताते हुए भारत और ईरान के अतः सम्बन्धों को एक नए दृष्टिकोण से देखा हैं उन्होंने कहा है कि भारत ईरान के संबंध पूर्व इस्लामिक रहे हैं। इन संबंधों में सिर्फ ब्रिटिश शासन काल से ही दूरियां रही हैं उन्होंने दावा किया है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भारत के अन्य देशों के साथ अच्छे संबंध है और इनमें ईरान के साथ बहुत नजदीकी संबंध है। लेखक ने बताया है कि भारत की आजादी से पहले और वर्तमान समय में भी ईरान एक ऐसा देश है। जिसके भारत के साथ प्रदेश स्तर जैसे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक संबंध रहे हैं। लेखक ने अपनी पुस्तक में कहा है कि ईरान सांस्कृतिक रूप से अपने आप में एक विकसित देश है और एशिया एंव पश्चिम एशिया के बीच एक पुल के रूप में कार्य कर रहा है।

जमाल एस. अल–सुवैदी ने अपनी पुस्तक "ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम रियेलिटीज एंड रिप्रकसन 2006" के अंतर्गत ईरान के महान शक्ति क्षेत्रों को दर्शाया है लेखक ने दावा किया है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम यूनाइटेड स्टेट एंड इयू–3 (यूनाइटेड किंग्डम, फ्रांस एंड जर्मनी) के कूटनीतिक दवाब का परिणाम है। इस्लामिक रिपब्लिक आफ ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से जुड़े हुए हैं लेखक ने बताया है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान वर्तमान समय में एक न्यूक्लियर पावर स्टेट बनता जा रहा है, यह क्षेत्रीय एवं वैश्विक स्तर उसके स्थायित्व का परिणाम है। ईरान खाड़ी देशों में पहले से सैनिक शक्ति के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका में बिद्यमान है। लेखक ने ईरान न्यूक्लियर पावर विकास को अलग–अलग स्तर पर परिभाषित किया है। इस पुस्तक के अंतर्गत ईरान के साथ–साथ अन्य देशों जैसे–रूस, चीन, यूनाइटेड किंग्डम एवं फ्रांस के स्पष्ट संबंधों को भी दर्शाया गया है। यह पुस्तक ईरान की वर्तमान न्यूक्लियर पावर क्षमता एवं विकास के साथ–साथ भविष्य में ईरान के बदलते अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर प्रकाश डालती है।

तुलसीराम ने अपनी पुस्तक "पर्शिया टू ईरानः वन स्टेप फॉरर्वड टू स्टेप बैक" के अंतर्गत भारत–ईरान अर्न्तसंबंधों को दर्शाया है। उन्होंने बताया है कि भारत और ईरान अपने अंतरराष्ट्रीय संबंधों की नींव पर एक भावी भविष्य की आशा रखते हैं तथा वर्तमान में भी दोनों देश शांति एवं सुरक्षा स्थापित करने के लिए अग्रसर है। लेखक बताते हैं कि 21 वर्षों से भारत एक शांतिपूर्ण क्रांति करता आ रहा है तथा ईरान में एक हिंसक उपद्रव चलता रहा है। दोनों देश गरीब हैं परंतु प्राकृतिक संसाधनों से धनी है, दोनों देश विदेशी हस्तक्षेप के प्रति एक पारस्पारिक सहयोगी संबंधों से जुड़े हुए हैं। लेखक ने पुस्तक के अंतर्गत पर्शिया से लेकर ईरान के राजनीतिक व्यवस्था का उदय युद्ध एवं लोकतंत्र, ईरान का खाड़ी देशों के साथ अंतर्विरोध तथा भारत का खाड़ी देशों के प्रति प्रभाव को मुख्य रूप से दर्शाया है। लेखक ने तर्क दिया कि ईरान में तानाशाही हमेशा युद्ध को जन्म देती रही है। ईरान में प्राचीन समय से ही प्रोग्रेसिव उग्रवादी आंदोलन चलता रहा है और इसका आंदोलनकारी इतिहास इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान को जन्म देता है।

बाला भास्कर ने अपनी पुस्तक 'एनर्जी सिक्योरिटी एंड इकोनामिक डेवलपमेंट इन इंडिया ए हिस्टोरिकल अप्रोच' के अंतर्गत वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के मुद्दे को प्रदर्शित किया है उन्होंने तर्क दिया है कि आज ऊर्जा सुरक्षा प्रत्येक देश के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि ऊर्जा सुरक्षा किसी भी देश के समावेशी विकास का एक महत्वपूर्ण आधार है।

विनोद कुमार मिश्र ने अपनी पुस्तक "अक्षय ऊर्जा स्रोत, 2017" में अक्षय ऊर्जा के प्रकार जैसे–पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस, सागर ऊर्जा, आदि के प्रयोग और उत्पादन के बारे में विस्तार पूर्वक बताया है। लेखक ने भविष्य के प्राकृतिक ऊर्जा स्त्रोत का संरक्षण, भंडारण को विकासशील देशों के लिए महत्वपूर्ण है जिसकी वजह से विकास की गति तीव्र होती जाएगी। साथ ही यह भी कहा है कि अक्षय ऊर्जा स्त्रोत ज्यादातर स्थानीय होते हैं इसलिए इसमें जनता की भागीदारी होनी चाहिए। इससे उन्हें अपने प्राकृतिक ऊर्जा स्त्रोतों के बारे में पर्याप्त जानकारी भी मिल जाएगी और ऊर्जा के संकट का सामना भी कर सकेंगे।

बाला भास्कर ने अपनी पुस्तक एनर्जी सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया" में भारत के विकास के लिए (आर्थिक विकास भारत की ऊर्जा से सुरक्षा) ऊर्जा मांग को कैसे पूरा किया जाए जिससे विकास की दर प्रभावित न हो इसके संबंध में बताया है तथा यह भी कहा है कि आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण है। भारत की ऊर्जा स्त्रोतों के बारे में आंकड़ों सहित उल्लेख किया है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि कैसे पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना ऊर्जा के आर्थिक विकास में किस प्रकार सहायक हो सकता है। इसमें उन्होंने नवीकरणीय ऊर्जा, प्राकृतिक संसाधन, ऊर्जा, जीवाश्म आदि का विस्तार से उल्लेख किया है।

पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी कृति "हिंदुस्तान की कहानी" (द डिस्कवरी ऑफ इंडिया का हिंदी अनुवाद 2013 संस्करण) में आजादी के पहले के भारत का वर्णन किया है। भारत और ईरान के ऐतिहासिक संबंधों के वर्णन के साथ ही अन्य देशों के साथ भारत के संबंधों पर विचार किया हैं। कला–संस्कृति और सामाजिक समरसता, भाषाई समानता, आदि का सुन्दर चित्रण किया है। उन्होंने यह

भी तर्क दिया कि ईरानी (पारसी) लोग भारत में आकर कैसे घुल–मिल गये और यहीं के होकर रह गये।

पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी कृति "विश्व इतिहास की झलक 2015 (भाग–1)" में अपने अर्न्तराष्ट्रीय राज नीति के ज्ञान को बखूबी दिखाया है। इसमें विश्व के अनेक देशों के इतिहास साम्राज्यों के उत्थान एवं पतन का बखूबी वर्णन किया है। इसमें ईरान और यूनान की लड़ाई तथा दारा (डेरियस) के साम्राज्य का उल्लेख है। नेहरू ने आश्चर्य व्यक्त किया है कि ईरान के बड़े साम्राज्य को एक छोटा सा यूनानी नगर राज्य ने कैसे हरा दिया।

पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी कृति "विश्व इतिहास की झलक 2015 (भाग–2)" में ईरान की सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक परिवर्तन को दर्शाया है। एवं रूस, ईरान के ऊपर कैसे घात लगाए बैठे थे इसका भी जिक्र किया है। तेल कंपनी से मुनाफा बाहरी देशों को ज्यादा और ईरान को कम मिलने पर और उसके बाद ठेका रद्द करने से ब्रिटिश सरकार की झल्लाहट के मुद्दे का भी वर्णन है। इसमें ब्रिटेन और रूस द्वारा किसी भी तरह से ईरान पर अधिपत्य करने के उनके नाकाम मंसूबों को बयां किया गया है क्योंकि अंग्रेजों की पूरी नीति का आधार यही था कि उनका भारतीय साम्राज्य और उनसे जाने वाले रास्ते में कोई रुकावट ना हो।

राम प्रसाद त्रिपाठी ने अपनी पुस्तक (विश्व का इतिहास, 1988) में विश्व के कई देशों जैसे यूनानी तथा चीनी, सिंधु घाटी, आर्य–ईरानी, रोमन आदि के मानव–जातियों का विकास क्रम का वर्णन किया है। लेखक ने ईरान के भगौलिक, राजनीतिक, सामाजिक आदि क्षेत्रों का उल्लेख किया है तथा इसे चार भागों में विभाजित करके ईरान के संबंध में विस्तार पूर्वक बताया है। ईरान के शासक, उनके शासनकाल तथा बड़े समाज के बारे में जानकारी दी गई है।

ए.के. बक्शी ने अपनी पुस्तक "ऊर्जा" (अनुवादक– ध्रुव देव शर्मा 2013) ने ऊर्जा को परिभाषित करते हुए प्रमुख स्रोतों जैसे पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक स्रोत तथा इसका पर्यावरण पर होने वाले प्रभाव का विस्तृत एवं सचित्र तर्क प्रस्तुत किया है। साथ ही उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि ऊर्जा के इन स्रोतों का कैसे और

किस प्रकार उपयोग किया जाए कि वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ–साथ भविष्य में इनके जरूरतों को पूर्ण किया जा सके। अतः बक्शी ने ऊर्जा के संवहनीय विकास की अवधारणा को गति प्रदान की है।

फ्रेड होलिडे द्वारा लिखित एवं अली मोहम्मदी द्वारा अनुवादित पुस्तक "ईरान इन काउंटरिंग ग्लोबलाइजेशन, 2003" में ईरान के वैश्वीकरण के संबंध में दो पहलू बताया गया है– एक पहलू विश्व अर्थव्यवस्था में परिवर्तन और विश्व राजनीति तथा संस्कृति में परिवर्तन की प्रक्रिया जिसे वैश्वीकरण कहा जाता है। तेल एंव गैस संसाधन तथा एक प्रभावशाली संस्कृत का मालिक ईरान अर्न्तराष्ट्रीय संदर्भ में कई सारे झेल रहा था। ईरान की दूसरी चुनौती राजनीति को बताया गया है साथ ही लोकतंत्र और मानव अधिकारों के पालन के लिए प्रतिबद्धता को बताया है तथा ईरान को एक क्रांतिकारी राज्य भी बताया है जो क्रांति के बाद इस्लामिक देश के रूप में उभरा। ईरान की राजनीतिक स्थिरता पर भी चिंता व्यक्त की है।

ए. के. रामाकृष्णन ने अपनी पुस्तक "यूएस परसेप्शन्स ऑफ ईरान, अपरोचेस एंड पॉलिसी 2008," में संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच चल रही प्रतिद्धंद्धिता समकालीन अंतरराष्ट्रीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण पहलू बताया है तथा परमाणु मुद्दा मौजूदा परिस्थितियों में निरंतर राजनीतिक वैचारिक और रणनीतिक लड़ाई पर हावी हो रही है तथा इस लड़ाई को ईरानी क्रांति से प्रेरित बताया है क्योंकि ईरानी क्रांति के बाद अमेरिका का प्रभाव ईरान में कम हो गया था। लेखक ने पुस्तक में यह भी तर्क दिया है कि ईरान कभी किसी पश्चिमी शक्ति का औपचारिक उपनिवेश नहीं था, लेकिन उसके इतिहास को बाहरी शक्ति द्वारा उसके आयामों को बदला गया।

अरुणोदय बाजपेई ने अपने लेख 'भारत–अमेरिका संबंध और भारत की सामरिक संप्रभुता का भविष्य में शीत युद्ध के बाद के युग में भारत की विदेश नीति एक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में उभरा भारत अगर अमेरिका, रूस, चीन आदि देशों के साथ रणनीतिक समझौते करता है तो पर्यवेक्षकों का दावा होता है कि रणनीतिक स्वायत्तता के सिद्धांत का उल्लंघन किया जाता है, इस पर विचार विमर्श

किया गया है। शीत युद्ध के बाद भारत–अमेरिका के बीच घनिष्ठ रणनीतिक तक साझेदारी को भारतीय विदेश नीति की विशेषता बताया गया है।

अब्दोलमाजीद याजदानपनाह सीसख्त एंड आर्मीन महमोउदी का लेख– "द रोल ऑफ एनर्जी इन ईरान एंड इंडिया रिलेशन" (2012), में बताया गया है कि आज ऊर्जा किसी भी देश की सरकार के लिए आर्थिक विकास की चिंता का विषय बन गया है। भारत को ऊर्जा प्रदान करने में ईरान की भूमिका मध्य पूर्व एशिया में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है भारत को ऊर्जा प्रदान करने में ईरान को सबसे सस्ता विश्वसनीय विकल्प बताया है ईरान की अर्थव्यवस्था तेल की आय पर निर्भर बताया और यही तेल आयात भारत–ईरान संबंधों में अहम भूमिका निभा रहा है।

हर्ष वी. पंत तथा जूली एम. सुपर ने अपने लेख "बैलेंसिंग रिवाल्सः इंडिया टाइट्रोप बिटवीन ईरान एंड द यूनाइटेड स्टेट, नवंबर 15, जनवरी 2013," में सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत ने अमेरिका के साथ संबंधों को आगे बढ़ाते हुए आर्थिक और विदेशी नीतियों को बदलते हुए भारत में खुद को वैश्विक शक्ति के रूप में देखना शुरु किया है। भारत में तीव्र विकास के लिए ऊर्जा संसाधनों की सुरक्षा की आवश्यकता को अत्यधिक बढ़ा दिया। ऊर्जा सुरक्षा को लेखक ने किसी भी राज्य के लिए वैश्विक शक्ति के रूप में भरने की उम्मीद में एक आवश्यक घटक बताया है। भारत की सुरक्षा को एक प्रमुख चिंता बताया है जिसने अमेरिका, ईरान, इजरायल सऊदी अरब के बीच के रिश्तो के नाजुक संतुलन को बनाए रखने पर सुझाव दिया है।

मनीष चन्द ने अपने लेख "भारत–अमेरिका कूटनीतिक संवाद महत्वपूर्ण क्यों है? कूटनीतिक संवादः भारत–अमेरिका संबंधों की चौसर, (29 जुलाई 2014)" ने कूटनीतिक संवाद को भारत अमेरिका संबंधों की जटिल संरचना माना है। कूटनीति संवाद में 5 स्तंभों पर कार्य होता है इसके बारे में बताया है। लेख में भारत अमेरिका का आर्थिक, रक्षा, परमाणु ऊर्जा आदि समझौते भारत के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है तथा कुटनीतिक सम्पर्क को भारत के लिए अहम बताया है।

रितु माथुर (मई 2014) ने अपने लेख "भारतीय ऊर्जा सुरक्षा–चुनौतियां एवं संभावनाएं" में स्वच्छ ऊर्जा सुरक्षा के लिए विश्वसनीय उपलब्धता पर पर्याप्त ध्यान देने की आवश्यकता बताया है। साथ ही जापान का उदाहरण देकर बताया है कि कैसे घरेलू स्तर पर ऊर्जा का कोई स्रोत नहीं होते हुए भी उसने उच्च विकास दर हासिल की है। कोयला और तेल के खनन के प्रयासों को बढ़ाने पर जोर दिया है वही परमाणु ऊर्जा को प्रत्येक भारतीय के लिए जरूरी बताया है, साथ ही यह बात आम जनता को समझाने पर जोर दिया है।

डॉ० राजेश कुमार ने अपने लेख "21वीं सदी में भारत–अमेरिका रक्षा और अंतरिक्ष सुरक्षा सहयोग" में भारत द्वारा अमेरिका से रक्षा सौदों का आंकड़ा तथा अमेरिका के लिए भारत व्यापार करने लिए करने के लिए महत्वपूर्ण आयातक देश बताया है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा निर्यात का दौरा दौरा एवं मेक इन इंडिया को अमेरिकी रक्षा उद्योगों के साथ रक्षा साझेदारी के बेहतर मौका मिलने का आशा व्यक्त की है।

रीमा दुग्गल ने अपने लेख "दक्षिण एशिया में ऊर्जा सुरक्षा की राजनीतिः ऊर्जा के जरिए दूरी मिटाने में भारत की भूमिका" में ऊर्जा सुरक्षा को लेकर विश्व में की जा रही राजनीति पर दुख व्यक्त किया है तथा राष्ट्रीय ऊर्जा राजनीति को एक अहम मुद्दा माना है। ऊर्जा का विश्व में सामरिक महत्व बहुत बढ़ गया है इसलिए अक्षय ऊर्जा सुरक्षित नीति हो गई है। दक्षिण एशिया में बढ़ते ऊर्जा खपत चीन और भारत के ऊर्जा की बढ़ती मांग और श्रीलंका, मालदीव जैसे सार्क देशों के पास जीवास्म ईंधन के स्त्रोतों का अभाव का भी आंकड़ों सहित उल्लेख किया गया है साथ ही भारत को सार्क देशों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने पर जोर दिया है।

बालाजी चंद्रमोहन ने लेख "इण्डो–ईरानियन रिलेशन इन दी 21st सेंचुरी में भारत–ईरान का संबंध 21वीं शताब्दी में कैसा है, तथा मध्य एशिया में दोनों देशों के संबंधों से क्या प्रभाव पड़ रहा है इसका वर्णन किया है। भारत–ईरान के सामाजिक एवं सांस्कृतिक संबंध को बहुत मजबूत तथा विश्वसनीय बताया है साथ ही चाबहार बंदरगाह का भारत और ईरान के लिए महत्व पर प्रकाश डाला है।

डॉ रंजना मिश्रा ने अपने लेख "जोड़ने वाला चाबहार भारत ईरान और अफगानिस्तान और मध्य एशिया" में ईरान के इतिहासिक संबंधों के साथ–साथ मुगल साम्राज्य का ईरानी संबंध और ईरान तथा मध्य एशियाई देशों के साथ व्यापारिक संबंधों का वर्णन किया है। भारत तथा ईरान व्यापार के संबंध में ही चाबहार बंदरगाह का महत्व बताइए ईरान दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बताया है इससे भारत का पश्चिम एशिया एवं यूरोप में नया रास्ता खुल जाएगा, क्योंकि यह बंदरगाह आर्थिक और सामरिक दृष्टि से भारत के लिए बहुत महत्व रखता है।

सोबंती रॉय डडवाल ने अपने लेख इंटरनेशनल एंड रीजनल सिक्योरिटी डॉयनामिक्स इंडिया एंड ईरानियन पर्सपेक्टीव (आई0डी0एस0ए0) (2009) में कहा है, कि ऊर्जा सुरक्षा के मुद्दे को मुख्य रूप से पश्चिमी हितों के लिए ही माना जाता है लेकिन 1990 के बाद कुछ विकासशील देशों विशेषकर एशिया में अर्थव्यवस्था में वृद्धि के लिए ऊर्जा की मांग बढ़ने लगी और ऊर्जा बाजार में धीरे–धीरे बदलाव आया। ऊर्जा सुरक्षा के लिए विकसित देशों ने अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार पर अपना वर्चस्व स्थापित करना शुरूकर/ ऊर्जा की मांग विशेष रुप से तेल बाजार दिया। भारत और चीन के बीच स्थानांतरित हो रहा है, साथ ही लेख भारत–ईरान के बीच के ऊर्जा संबंधों का जिक्र किया है।

प्रोफेसर आर. जी गिदा धुबली ने अपने लेख "वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य में रूस में रूस" में रूस की ऊर्जा परिदृश्य में बड़ी भूमिका को दिखाया है क्योंकि रूस की कंपनी गाज प्रोम का उसके उत्पादन, आर्थिक, राजनीति मामले और ऊर्जा निर्यात पर विशेष रूप रोशनी डाला है। रूस, चीन के साथ मिलकर गैस पाइपलाइन संधि किया है जिससे अमेरिका और कनाडा आदि देश निर्यात अवसरों को खो सकते हैं ऐसा अनुमान लगाया गया है। रूस विश्व का सबसे बड़ा तेल एवं प्राकृतिक गैस का निर्यातक देश है इसलिए भारत को रूस के साथ को हिंद महासागर से कैस्पियन सागर जोड़कर अपनी ऊर्जा की जरूरतों को पूरा कर सकता है।

इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी में प्रकाशित वर्किंग पेपर "नेचुरल गैस इन इंडिया, 2010" में एन्ने–सोफीकोरबेय ने अपने वर्किंग पेपर में भारत का गैस औद्योगिक ढांचा, उद्योगों का इतिहास, मूल्य, उत्पादन, आयात, मांग आदि को आंकड़ों सहित

उनका विश्लेषण किया है। भारत की कंपनियां का उत्पादन एवं उनका वितरण भी बताया है। साथ ही सचित्र वर्णन द्वारा समझाया है, भारत के गैस बाजार को तेजी से उभरता हुआ बाजार बताया है।

तपन बिस्वाल की पुस्तक "अंतरराष्ट्रीय संबंध (2016)" में लेखक अंतरराष्ट्रीय संबंधों का महत्व शीतयुद्धोत्तर काल में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ (भूतपूर्व) अपने अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में रणनीति एवं सैनिक प्रतिस्पर्धा करने में लगे होने के उल्लेख किया है। शीत युद्ध के बाद शस्त्रों की अंधाधुंध दौड़ शुरू हो गई थी। इसके रोकथाम के लिए कई संधियां बनी जिसके बारे में उल्लेख किया गया है। साथ ही भारत की विदेश नीति अंतरराष्ट्रीय आतंक तथा भू–राजनीतिक भारत का खाड़ी देशों तथा पश्चिमी एशिया से संबंधों के बारे में गहनता से बताया है।

पुष्पेश पंत की पुस्तक "भारत की विदेश नीति 2010" में भारत की विदेश नीति तथा भारत के पड़ोसी देशों के साथ कैसा संबंध है एवं बाद में क्या क्या बदलाव आया है इसका बखूबी वर्णन है इस पुस्तक में भारत के विश्व के अन्य देशों अमेरिका, रूस, यूरोप, अफ्रीका, पश्चिमी एशिया तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ संबंध भारत ईरान संबंध के बारे में भी वर्णन किया है। भारत को दक्षिण एशिया के साथ–साथ पश्चिम एशिया के भारत साथ भी संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने पर जोर दिया है।

1.4. शोध प्रश्न

1. भारत की बढ़ती ऊर्जा की मांग को ईरान में मौजूद ऊर्जा भण्डार को किस अवसर के रूप में देखा जा सकता है?
2. भारत–अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते से भारत–ईरान के सम्बन्धों पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
3. भारत–ईरान सम्बन्ध पर चीन–पाकिस्तान धुरी की क्या भूमिका है?
4. पश्चिम एशिया में गृहयुद्ध और आंतकवाद का भारत–ईरान सम्बन्धों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है?
5. भारत–ईरान सम्बन्धों के मध्य कटुता बढ़ने के कौन–कौन से कारण है?

6. अमेरिका द्वारा ईरान पर प्रतिबन्ध लगाने और भारत द्वारा ईरान के खिलाफ वोट देने के बाद भारत–ईरान के सम्बन्धों पर क्या प्रभाव पड़ा है?
7. ईरान के सन्दर्भ में भारत की विदेश नीति का आर्थिक नीति पर क्या प्रभाव पड़ा है?
8. भारत की ऊर्जा जरूरतों के सन्दर्भ में ईरान का क्या दृष्टिकोण है?
9. क्या आई0पी0आई0 परियोजना को पाकिस्तान सुरक्षा देगा?

1.5. शोध के उद्देश्य

1. भारत–ईरान के द्विपक्षीय सम्बन्धों एवं पारस्परिक हित के मुद्दों का विश्लेषण करना।
2. भारत की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकता के रूप में ईरान के पास मौजूद विशाल ऊर्जा भण्डार के अवसर के रूप में वर्तमान स्थिति एवं भविष्य की सम्भावनाओं का विश्लेषण करना।
3. भारत की ईरान पर ऊर्जा निर्भरता तथा अमेरिका सहित पश्चिमी देशों को ईरान के साथ कटु संम्बन्धों में भारत की संतुलन परक भूमिका का समीक्षा करना।
4. दोनों देशों के बीच आर्थिक व्यापारिक सम्बन्धों को गहन बनाने में अमेरिका का ईरान पर प्रतिबंध से आयी बाधाओं का मूल्यांकन करना।
5. सीरिया, फिलिस्तीन, ईजराइल आतंकवाद आदि के सम्बन्ध में भारत–ईरान के दृष्टिकोणों की समीक्षा करना।
6. संयुक्त राष्ट्र में सुधार, अंतराष्ट्रीय वृत्तीय संस्थाओं, जलवायु परिवर्तन, सतत् विकास के साथ अन्य वैश्विक मुद्दों पर भारत व ईरान के दृष्टिकोणों की समीक्षा करना।
7. भारत–ईरान सम्बन्धों में चीन–पाक धुरी की भूमिका का मूल्यांकन करना।

1.6. शोध परिकल्पना

1. भारत–अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते का भारत–ईरान के बीच ऊर्जा सुरक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

2. भारत, पाकिस्तान और ईरान के नेताओं में ऊर्जा सुरक्षा को लेकर दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव है।
3. अमेरिका स्वयं अपने सम्बन्धों को ईरान के साथ बेहतर करने में लगा है और वह नहीं चाहता है कि भारत का ईरान के साथ सीधे सम्बन्ध स्थापित हो।

1.7. शोध की विधि

प्रस्तुत शोध में ऐतिहासिक, विशलेषणात्मक, तुलनात्मक एवं आनुभाविक पद्धति व सौउद्देश्यात्मक पद्धति का प्रयोग किया गया हैं। इसके साथ प्राथमिक (Primary) एवं द्वितीयक (Secondry) स्रोतों से जानकारी एकत्रित करने का प्रयत्न किया गया हैं। इसके लिए प्रमुख राजनयिकों एवं विषय–विशेषज्ञों के साथ साक्षात्कार किया गया हैं। साथ ही साथ सरकारी दस्तावेजों व विभिन्न समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं का विश्लेषण किया गया हैं। इस प्रकार हम उपरोक्त पद्धतियों का सहारा लेते हुए शीत युद्धोत्तर भारत–ईरान सम्बन्धः ऊर्जा सुरक्षा के विशेष संदर्भ में निष्पक्ष एवं वैज्ञानिक विश्लेषण अपने शोध के माध्यम से करने का प्रयास किया गया हैं।

1.8. अध्यायीकरण (Chapterization)

1. प्रस्तावना
2. ऐतिहासिक संदर्भ में भारत–ईरान सम्बन्ध।
3. भारत–ईरान सम्बन्ध में उर्जा सुरक्षा।
4. भारत–ईरान सम्बन्धों के विविध आयाम।
5. भारत–ईरान संबंधों में अमेरिका की भूमिका का परीक्षण।
6. भारत–ईरान सम्बन्ध का पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया पर प्रभाव।
7. वैश्विक राजनीति में भारत–ईरान सम्बन्ध।
8. निष्कर्ष।

1.9. अध्यायों का संक्षिप्त परिचय

प्रथम अध्याय

इस अध्याय के अंतर्गत सम्पूर्ण शोध कार्यो का विश्लेशण किया गया है तथा विभिन्न आयामों को भी परिभाषित किया गया है जैसे–अध्ययन की प्रासंगिकता, साहित्य की समीक्षा, शोध प्रश्न, शोध के उद्देश्य, शोध परिकल्पना तथा शोध की विधि का वर्णन किया गया है।

द्वितीय अध्याय

इस अध्याय के अंतर्गत भारत–ईरान सम्बन्धों का उल्लेख किया गया है साथ ही दोनों देशों के परम्परागत रूप से प्राचीन काल से ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इसी दौर से लेकर आज तक दोनों देशो के बीच न केवल संस्कृतक जुडाव रहा है बल्कि आर्थिक राजनीतिक सम्बन्ध भी रहे हैं। हालांकि यह व्यापार केवल सिंधु घाटी तक ही सीमित था क्योंकि अन्य स्थानों से या राज्यों से प्राचीन ईरान के साथ व्यापार का कोई प्रमाण नहीं मिला है जो भी प्रमाण मिले हैं, वह केवल मेलुहा से मिलते हैं, जहां से प्राचीन पारस (ईरान) के बीच व्यापार होता था। मुगल काल एवं मौर्य काल में भारत–ईरान के संबंधों को स्वर्णकाल भी कह सकते हैं क्योंकि मुगल काल के शासकों का संबंध ईरान से था, वे ईरान की भाषा, संस्कृति, स्थापत्य कला, चित्रकारी, आदि से बहुत ही प्रभावित थे तथा ईरान के स्थापत्य कला के प्रमाण भारत में मिलते हैं।

तृतीय अध्याय

इस अध्याय में भारत और ईरान के ऊर्जा संबंधों को परिभाषित किया गया है साथ ही भारत में ऊर्जा की खपत व उपलब्धता को विश्लेषित किया गया है, भारत–ईरान के राजनीतिक संबंधों व आने वाले दिनों में क्या रणनीतियां रहेंगी के अलावा यह भी परिभाषित करने का प्रयास किया गया है कि क्या भविष्य में ईरान–भारत की ऊर्जा आवश्यकता को पूरी कर पाएगा। भारत की क्या नीति रहेगी,

विशेषकर ऊर्जा संबंध में, भारत–ईरान के संबंधों में क्या–क्या समस्याएं व बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं इसका भी इस अध्याय में उल्लेख किया गया है।

चतुर्थ अध्याय

इस अध्याय में दोनों देशों के बीच राजनीतिक, सामरिक, और आर्थिक इत्यादि विभिन्न पहलुओं को उल्लेखित किया गया है साथ ही दोनों देशों में हो रहे राजनितिक बदलावों को भी सम्मिलित किया गया है। भारत ईरान संबंधों के विविध आयाम में निरंतर परिवर्तन के स्वरूप भी रहे है जिससे दोनों देशों के बीच रिश्तों में उतार–चढवा भी आते रहते है जिसकी वजह से भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में भारी नुकसन भी सहना पड़ता है लेकिन दोनों देश विश्व जगत में एक साथ काम कर रहे है।

पंचम अध्याय

इस अध्याय में भारत अमेरिका सम्बन्धो का विश्लेशण किया गया तथा शीत युद्ध के बदलते समीकरण व विश्व के विभिन्न देश आपसी प्रतिस्पर्धा के दौर से गुजर रहे हैं। इस बदलते परिवेश में ईरान और अमेरिका का आपस में कैसा संबंध है। भारत का अमेरिका और ईरान के संबंधों में क्या बदलाव या परिवर्तन हुआ है साथ ही भारत की अमेरिका से दोस्ती पर ईरान की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस अध्याय में यह भी परिभाषित किया गया है कि ईरान पर अमरीकी प्रतिबंध से भारत की ऊर्जा सुरक्षा एवं अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भारत ईरान के संबंधों से अमेरिका को अपने व्यापारिक हित पर खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए वह दक्षिण एशिया में अपने आपको मजबूत करने के लिए खाड़ी देशों को सुरक्षित अर्थव्यवस्था की दौड़ से बाहर करने में लगा हुआ है।

षष्ठम् अध्याय

इस अध्याय के अन्तर्गत भारत और ईरान दोनों देश आपसी सामंजस्य को बढ़ाते हुए विश्व के अन्य बिभिन्न क्षेत्रों में अपना विस्तार कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त दोनों देश दक्षिण और पश्चिम एशियाई क्षेत्रों में अपना आर्थिक, राजनीतिक व सामाजिक समरसता के द्वारा प्रभाव स्थापित करने की कोशिश भी

कर रहे हैं। भारत दक्षिण एशिया में अपने प्रभाव को स्थापित करने के लिए पड़ोसी देशों को आर्थिक सहायता करने व उनकी विभिन्न समस्याओं को सुलझाने की कोशिश कर रहा है।

सप्तम् अध्याय

इस अध्याय में भारत–ईरान संबंधों के बदलते स्वरूप व वैश्विक मुद्दों पर सहयोग की संभावनाएं देखी जा रही हैं। ईरान एशिया में भू–स्थानिक संबंधों को बदलने में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। भारत–ईरान के बीच अक्सर अनदेखे द्विपक्षीय संबंध न केवल आकर्षित करते हैं, बल्कि एक ऐसा प्लेटफार्म प्रदान करते हैं, जिसके द्वारा पूरे एशिया में स्थानांतरित किये गये भू–स्थानिक संबंधों को देखा और समझा जा सकता है। दोनों देश विश्व में हो रहे परिवर्तनों में भी साथ है जैसे जलवायु परिवर्तन, संस्थागत परिवर्तन इत्यादि। एशिया में हो रहे परिवर्तनों के चलते भारत और चीन एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं इस प्रतिस्पर्धा में ईरान भारत को पूर्ण सहयोग करता हुआ नजर आ रहा है।

अष्टम् अध्याय

इस प्रकार उपरोक्त विश्लेषणों से स्पष्ट होता है कि भारत ऊर्जा सुरक्षा को ध्यान में रखे हुए अपने तेल भू–राजनीति के क्षेत्र को विस्तृत कर रहा हैं। जिसकी वजह से ईरान भारत की ऊर्जा जारुरत को पूरा करने सक्षम हैं लेकिन बाह्य दबाव के चलतें ऊर्जा प्राप्त करने में असक्षम हो जाता हैं।

शीतयुद्व के बाद की राजनीति समूचे विश्व में एक नितान्त नई प्रक्रिया को जन्म देता है जिसे वैश्वीकरण का नाम दिया जाता है। इस वैश्वीकरण ने न सिर्फ पूँजीवादी और समाजवादी विमर्शों को प्रभावित किया है बल्कि तीसरी दुनिया में चल रहे समाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं धार्मिक ठहराव को भी गतिशील कर दिया है। इस समूचे वैश्वीकरण की प्रक्रिया में कुछ केन्द्र में ज्ञान, विज्ञान, तकनीकि ही बनी रही। इस प्रक्रिया में उर्जा की जरूरत अचानक ही बढ़ गयी। भारत ईरान सम्बन्ध में अन्य सम्बन्धों के अलावा उर्जा एक अत्यन्त महत्वपूर्ण घटक के रूप में प्रासंगिक बना रहा। 1979 में ईरान में हुई इस्लामिक क्रांति के बाद

अलग थलग पड़े ईरान की स्थिति एक बहिस्कृत देश की तरह हो गयी थी जिसे मित्र की नहीं बल्कि मित्रों की जरूरत थी। भारत और ईरान सम्बन्ध उक्त विमर्श का स्वाभाविक परिणाम रहा है।

अध्याय–द्वितीय
ऐतिहासिक संदर्भ में भारत–ईरान सम्बन्ध

भारत ईरान संबंध को आज किसी नयी पहचान की जरूरत नहीं है, एक समय था जब दोनों देश सीमा साझा करते हुए आपसी हितों का पालन करते थे। प्राचीन काल में ईरान की आर्य जाति भारत में हड़प्पा सभ्यता तक फैली हुए थी तथा भारतीय आर्य द्रवीड से इनका बहुत घनिष्ठ संबंध था। वैदिक युग में पारस से लेकर गंगा, सरयू किनारे तक की भूमि अनेक प्रदेशों में विभक्त थी। प्राचीन काल में पारसी अपने नाम के साथ बड़े गौरव से 'आर्य' शब्द लगाते थे।[1] ईरान से आए पारसियों ने भारतीय संस्कृति को अपनाया और यहीं के होकर रह गए। 16वीं सदी में भारत में आये मुगल शासकों का ईरान से बहुत घनिष्ठ संबंध था, मुगलों ने ईरान के रीति रिवाजो एवं परंपराओं को अपनाने के साथ ही महत्वपूर्ण ईरानी ग्रंथों का भी फारसी भाषा में भी अनुवाद कराया। मुगल शासकों की शासन व्यवस्था एवं स्थापत्य कला इत्यादि में ईरानी संस्कृति की झलक स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होती थी।

भारत ईरान दोनों देशों में लोगों का ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सभ्यता आदि का संबंध साझा करने का लंबा इतिहास रहा है। भारतीयों ने ईरानी भाषा के अनेक आम बोलचाल के शब्दों को अपनी भाषा में प्रयोग किया। दोनों सभ्यताओ की खोज में एक महत्वपूर्ण खोज आर्य लोग हैं जिनके संबंध दोनों देशों से लगभग 3000 साल पहले का माना जाता है। दोनों देशों के बीच बहुत सी समानताएं पाई जाती है जो रीति रिवाज, भाषा इत्यादि में देखने को मिलती है।[2]

भारत–ईरान का संबंध ऊर्जा पर आधारित है। दक्षिण एशिया के देशों के पास ऊर्जा के स्त्रोत बहुत कम है जिसकी पूर्ति के लिए भारत सहित सभी दक्षिण एशियाई देश पश्चिमी देशों (खाड़ी देश) पर निर्भर भारत–ईरान के मध्य प्राचीन संबंधों एवं

[1] इस्लाम से पहले के ईरान का इतिहास से लिया गया- http://hindi.webdunia.com/history-and-culture-of-world/history-of-iran-117122100059_1.html.

[2] शुल्क (नवम्बर 3, 2015)राम चंद्र प्राचीन पारस का इतिहास से लिया गया है– https://bhithaad.wordpress.com/2013/11/03/

भाईचारे को देखते हुए भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्र नाथ टैगोर ने लिखा है कि ''फारस की मेरी यात्रा ने पूर्वी लोगों की शक्ति में मुझे विश्वास दिया उन्हें मजबूती और तेजी से संघर्ष और हर मुश्किल के बावजूद अपनी अमर विरासत की एक संयुक्त अभिव्यक्ति के लिए अपने रास्ते खोजने और आर्थिक परिस्थिति में अपने दावे को पुख्ता रखने के लिए तत्पर रहते हैं''(मिश्रा, 2017)।

इस अध्याय में भारत–ईरान के ऐतिहासिक संबंध को देखते हुए इसके विभिन्न पहलुओं जैसे–राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, कला एंव सांस्कृतिक और धार्मिक आदि का विस्तृत विश्लेषण किया गया है।

2.1. भारत–ईरान संबंध का ऐतिहासिक परिपेक्ष्य

भारत और ईरान का संबंध प्रागऐतिहासिक काल से रहा है। इसमें सिंधु घाटी के मोहरों को मेसोपोटामिया, बेबीलोन आदि स्थानों पर पाया गया है। ऐतिहासिक स्थल मार्ग से ईरान के शासक वर्ग एवं जन सामान्य लोग व्यक्तिगत प्रयासों से भारत के पश्चिमी भागों में आए। इसमें सबसे आश्चर्य की बात भारत–ईरान यात्रियों का अंतर्संबंध है। भारत व ईरानी आर्यों के धर्म, समाज, सांस्कृतिक क्रियाकलाप आदि बहुत मिलते–जुलते है। दोनों देशों में आपसी भेदभाव बहुत कम देखने को मिलते थे। 'भारत ईरान के लिए पहला आर्यन प्रवास 2000 ईसा पूर्व के आसपास हुआ (Violatti, 2008)। इन लोगों ने अपने साथ अपनी पितृवंशीय प्रणाली, आकाश देवताओं, उनके घोड़ो और रथों को लाकर उनकी पूजा शुरू की। वेदशास्त्र और जिन्द अवेस्ता दोनों उनकी पलायन के स्त्रोत हैं। वैदिक स्त्रोत के अनुसार बाढ़ एक प्रमुख आधार थी जिसके कारण उन्हें पलायन करना पड़ा। और अवेस्ता के अनुसार इनके पलायन का प्रमुख कारण अत्यधिक बर्फ एवं ठंड थी। अचाईमींड साम्राज्य के शासक दारा महान ने 586 से 522 ईसा पूर्व में भारत के लिए बन्दार अब्बास का मार्ग प्रशस्त किया। भारतीयों और फारसियों ने काबुल और सिस्तान की सीमाओं पर मिलकर सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संस्थाओं की स्थापना की थी। फारसी बेहिस्टन शिलालेख (518 ईसा पूर्व) में गंधार

विदेशों की सूची में शामिल था। पर्सपोलिस शिलालेख में पंजाब को फारसी साम्राज्य का हिस्सा बताया गया। नक्श–ए–रुस्तम के शिलालेख भारत को अपने साम्राज्य के 24वां राज्य के रूप में पेश करते हैं। अल्बरूनी ने इस पौराणिक इतिहास के साथ ही अपनी किताब 'तहकीक ए हिन्द' में भारत के बारे में भी विस्तार से बताया है। उसने कहा है कि उत्तर पश्चिम में बसने वाले लोगों में ज्यादातर लोग उसके इलाके यानि मध्य ऐशिया के थे (मिश्रा, 2017)। इस प्रकार देखा जाए तो प्राचीन काल से ही भारत ईरान का संबंध विभिन्न क्षेत्र में बहुत गहरा रहा हैं।

2.1.1. व्यापार

पुरातात्विक स्त्रोत के अनुसार फारस की खाड़ी और अरब सागर के माध्यम से दक्षिणी ईरान और भारत के तट के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक रिश्ते सबसे अधिक थे। हडप्पा के लोग फारस और अफगानिस्तान से चांदी, तांबा, फिरोजा, शीशा आदि का आयात करते थे तथा भारत के मेलूहा से मेसोपोटामिया में आबनूस एवं इमारती लकड़ी, हाथी दांत, रत्नों के मनके आदि निर्यात किये जाते थे। मेसोपोटामिया के लोग उर अन्य नगरों के व्यापारी दिलमुल, मगन, एवं मेलुहा इत्यादि से लोहा का व्यापार करते थे (Kumar, 2010) संस्कृत ग्रन्थों और अवेस्ता दोनों में सामान्य भाषाएं, उनकी शब्दावली और कविता लिखने की लय एवं शैली बहुत समान है।

भारत–ईरान संबंधों से अभिभूत और उनकी कला के मुरीद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय–ईरानी कला की सबसे श्रेष्ठ कृति ताजमहल को बताया है। भारत और ईरान का सर्वाधिक प्रभाव मिश्रित रूप में दृष्टिगत है। 'फ्रेंच विद्वान' ग्राउजे ने कहा है कि "ईरान की आत्मा ने भारत के शरीर में अवतार लिया है।"[3] भारत ईरान का संबंध भी आत्मीय था और यह लगाव कला, भाषा, संस्कृति, स्थापत्य कला में साफ नजर आता है। भारत ईरान संबंधों के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि

[3] नेहरू, जवाहरलाल (2015). विश्व इतिहास की घलाक (भाग–2) सस्ता साहित्य मंडल नई दिल्ली पेज न० 609

"बहुत सी नस्ले भारत के संपर्क में आयी थी और भारत के जीवन और संस्कृति को ज्यादा प्रभावित किया, उसमें ईरान का नाम सबसे ऊपर है।"[4]

पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कई जगह भारत ईरान संबंधों के बारे में जिक्र किया है कि ईरानी संस्कृति मिशन के नेता ने इलाहाबाद में कहा था कि 'ईरानी और हिंदुस्तानी दोनों भाई की तरह हैं जो फारसी किस्से के अनुसार "एक दूसरे से छूट गए थे, एक पूरब चला गया और दूसरा पश्चिम। उनके खानदान वाले भी एक दूसरे को भुला बैठे थे, दोनों के बीच जो बात समान रह गई थी। वह कुछ पुराने गीतों की धुनें थी, जिन्हें दोनों अब भी अपनी बांसुरियों पर निकाला करते थे। इन धुनों के माध्यम से ही दोनों खानदान वालों ने सदियों बाद एक दूसरे को पहचाना और फिर मिल गए। इसी तरह हम भी हिंदुस्तान आए हैं अपनी युगों पुरानी तानों को अपनी बांसुरीयों पर गाने के लिए जिसमें कि उन्हें सुनकर हमारे हिंदुस्तानी भाई हमें पहचान सके और अपना ही समझें और फिर वे अपने ईरानी भाईयों से मिल जाए।"[5] अतः स्पष्ट है कि भारत और ईरान ऐतिहासिक स्तर पर एक दूसरे से अनेक क्षेत्रों में प्रभावित थे। उन्होंने एक दूसरे के प्रभाव में बहुत कुछ था जिसे गृहण किया।

2.1.2. कला एवं शैली

भारत–ईरान के परिपेक्ष्य में कला एवं शैलीगत संबंधों की यदि बात की जाए तो यह दृष्टिगत है कि राजवंशानुगत आधार पर कला का वर्गीकरण करने के प्रति विद्वानों में आसक्ति रही है। कला के वर्गीकरण में मौर्य, शुंग, सातवाहन, पल्लव, चोल, पांडय, चालुक्य, राष्ट्रकूट आदि कला धाराओं की परिकल्पना दर्शनीय है। वास्तव में वंशानुगत विभाजन शैली एवं स्थानीयता दोनों ही आधारों पर अप्रमाणित प्रतीत होता है। भारतीय ईरानी संबंधों से विकसित कला को मौर्य कला का नाम दिया गया जिसमें ग्रीक परंपराओं का भी परस्पर सामंजस्य था।[6]

---

[4] नेहरू जवाहरलाल (2013) हिंदुस्तानी की कहानी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया का अनुवाद सस्ता साहित्य मंडल नई दिल्ली पेज नंबर 170
[5] वही–पेज न–172
[6] मिश्रा राम नाथ (2008). भारतीय मूर्ति कला का इतिहास, प्रकाशक ग्रन्थ शिल्पी (इण्डिया), दिल्ली. पेज न 27

प्रिमिटिव कला शैली–यह सर्वविदित है कि मौर्यकाल के विकास में सम्राट अशोक का योगदान अविस्मरणीय है। मौर्य युगीन कला के उद्भव के पीछे एक अन्य स्रोत भी हैं जिसे विदेशी कला की प्रेरणा के रूप में अभिहित किया जा सकता है। मौर्यकालीन कला के संदर्भ में कलामर्मज्ञों द्वारा दी गई दो विचार धाराएं स्पष्ट रूप से सामने आती हैं–एक के अनुसार मौर्य युगीन कला का उद्गम पूर्ण रूप से भारतीय है तथा दूसरी विचारधारा मौर्यकालीन कला के सृजन में विशेष रूप से स्तंभों के निर्माण में ईरानी अथवा यूनानी कला प्रवृत्तियों के प्रभाव को उल्लेखनीय मानती है।

स्मिथ एवं मार्शल ने ईरान एवं वहां के महत्वपूर्ण नगर पर्सोपोलिस की विशिष्ट कला परंपराओं को मौर्य स्तंभों के निर्माण का पूर्ण श्रेय दिया। मार्शल का कथन है कि भारत में ईरानी प्रभाव बैक्ट्रिया में स्थापित सेल्यूकस वंशीय राजाओं के माध्यम से आया। मौर्य वंश के शासकों के इन राजाओं से घनिष्ठ संबंध थे। भारत में मौर्य युगीन कलाओं में इन प्रभावो का स्पष्टीकरण विभिन्न आधारों पर दृष्टिगत होता है।[7]

2.2. भारत पर ईरानी तथा यूनानी हमले

भारत के उत्तर पूर्वी भाग में जिस समय नंद वंश के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सम्राज्य की स्थापना तैयारियॉ अपने चरम बिंदु पर थी। ठीक उसी समय उत्तर पश्चिम भारत की राजनीतिक अवस्था बहुत अव्यवस्थित थी वहॉ कई छोटे राज्यों में आपसी सामंजस्य न होने के कारण वे एक दूसरे का विरोध कर रहे थे। इस आपसी रंजिश और राजनीतिक उथल–पुथल का लाभ उठाकर ईरान के शासकों ने भारत के पश्चिमी प्रदेश पर आधिपत्य कर लिया। आगामी दो शताब्दियों तक यह अधिकार स्थापित रहा। इस संदर्भ में कुछ प्रमुख आक्रमण उल्लेखनीय है यथा–

2.2.1. ईरानी आक्रमण : साइरस (558–536 ई0पू0)–ईरानी इतिहासकारों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि साइरस पहला ईरानी सम्राट था. साइरस को कुरूप के नाम

[7] 15– मिश्रा राम नाथ (2008). प्रिमिटिव से क्लासिकल. प्रकाशक ग्रन्थ शिल्पी (इण्डिया), दिल्ली.

से भी संबोधित किया जाता था। साइरस का उदभव ईरान में छठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ साइरस ने छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। तथ्यों के अनुसार भारत में मुगलों के आखिरी दिनों में ईरानी सरदार नादिरशाह ने आक्रमण कर कत्लेआम कर दिया और शाहजहां के तख्त–ए–ताउस एवं बेश कीमती खजाने को लूटकर साथ ले गया।

2.2.2. दारा प्रथम (डेरियस)–(521–485 ई0पू0)–ईरानियो ने भारत पर दूसरी बार दारा प्रथम के नेतृत्व में आक्रमण किया था। ईरान में हखमनी वंश का अंतिम सम्राट दारा तृतीय था। जिसे भारत में यूनानी शासक सिकंदर महान ने युद्ध में पराजित कर दिया था। इसी के फलस्वरुप भारत–ईरान के आपसी संबंध लगभग समाप्त हो गये थे। मैगस्थनीज द्वारा दिए गए विवरण में तथाकथित रूप से कहा गया है कि भारतीय शासकों ने कुछ इरानी प्रभावों को प्राथमिकता देते हुए स्वीकार किया था।

2.3. ईरानी प्रभुत्व का प्रभाव

ईरानियो के आगमन एवं आक्रमण दोनों का ही प्रभाव भारत में सामाजिक सांस्कृतिक तथा आर्थिक क्षेत्रों में देखने को मिलता है जो इस प्रकार है–

2.3.1. लिपि एवं भाषा

भारत में ईरानी प्रभाव को उन क्षेत्रों में अधिक देखा गया जहां पर ईरान का अधिकार था। यह प्रभाव लिपि एवं भाषा पर विशेष रूप से परिलक्षित हुआ। भारतीय सम्राट अशोक के अभिलेखों से प्राप्त होने वाले शब्द 'दिपि' (लिपि) और दाई से बाई ओर लिखी जाने वाली खरोष्ठी लिपि दोनों ही मुख्य रूप से ईरानियों के प्रभाव का परिणाम थी। पश्चिमोत्तर भारतीय प्रदेशों में इसका प्रयोग विशेष रूप से चौथी शताब्दी तक होता रहा। भारत के पश्चिमोत्तर भाग में स्थित अशोक स्तंभ वस्तुतः खरोष्ठी लिपि के ही परिचायक हैं। इतिहासकारों के मतानुसार अशोक के शिलालेखों की घोषणाओं की प्रस्तावना पर भी ईरानी भाषा एवं लिपि की छाप दृष्टिगत है।

2.3.2. सांस्कृतिक प्रभाव

ईरानी प्रभावोनुरूप भारतीय मौर्य कालीन दरबार में प्रस्तुत कुछ विशिष्ट ईरानी रीति–रिवाज वर्षों तक प्रचलन में रहे। यह स्मरणीय है कि भारत में चंद्रगुप्त मौर्य अपनी मंत्री परिषद की बैठक का आयोजन ईरानी मंत्री परिषद की भॉति करते थे। मंत्री परिषद में अग्नी जलाये जाने की प्रथा भी ईरानी मंत्री परिषद के प्रभाव की ही देन थी। इसके अतिरिक्त मौर्य सम्राज्य को सभी शासकों ने ईरानी उपाधि 'क्षत्रप' को मूल रूप से धारण किया था। इनके अधिकारियों के नामों में भी ईरानी प्रभाव झलकता था। ईरानी सम्राज्य के पतन के बाद भी बड़ी संख्या में ईरानी भारत में ही बस गए। अधिकांश ईरानियो ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ही नौकरी भी प्राप्त कर ली परिणामस्वरुप गुजरात के वायसराय के पद पर ताषस्य नामक ईरानी को नियुक्ति प्राप्त हुई। अतः भारत–ईरान के मध्य बने संबंध सिंधु सभ्यता से लेकर वर्तमान में अनवरत रूप से चल रहे है।[8]

ऐतिहासिक संदर्भ में भारत–ईरान का संबंध उपरोक्त व्याख्या के बाद हम ईरान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अवलोकन करेंगे। इस अध्याय में हम देखेंगे कि ईरान का इतिहास क्या रहा है और वहां की संस्कृति भाषा भौगोलिक स्थिति आदि के बारे में भी उल्लेख किया गया है।

भारत के लिए ईरान बहुत ही महत्ववपूर्ण और सामरिक देश है तथा ईरान–भारत का निकटतम पड़ोसी है। फारस की खाड़ी के साथ लम्बी तटरेखा होने के कारण इसकी अत्यंत सामरिक स्थिति है। जिसमें होर्मुज जलडमरूमध्य से एक संकीर्ण प्रवेश द्वार भी शामिल है। यह क्षेत्र भारत की सुरक्षा परिधि के भीतर आता है तथा ईरान ऊर्जा एवं हाइड्रोकार्बन आपूर्ति करने का एक बड़ा स्त्रोत है। तेजी से एक हो रहे

[8] लेखक :– डा0 एस0 एल0 नागोरी, श्रीमती कान्ता नागोरी (2007), पब्लिकशर :पोइन्टर पाबलिशर्स जयपुर (राज.) (नंद युगीन भारत) द्वितीय खण्ड (प्रा0 भारत का वृहद इतिहास') P.No.-17.

विश्व में भारतीय अर्थव्यवस्था में व्यवसाय एवं निवेश के लिए अपार संभावनाएं हैं। दोनों ही देशों के सामाजिक, आर्थिक, संस्कृतिक आदि सम्बन्ध बहुत ही महत्वपूर्ण है।[9]

पश्चिम एशिया के उत्तर पूर्वी छोर पर तीसरी महान ऐतिहासिक सभ्यता का स्त्रोत ईरान में स्थित है ईरान कट्टरपंथी इस्लाम का अनुयायी है। इस्लाम के अनुयायी सिया और सुन्नी समुदायों में बँटे हैं। ऊर्जा की सुरक्षा एंव मांग ने इस पूरे क्षेत्र को (खाड़ी देश) असाधारण रूप से सामरिक महत्व प्रदान कर दिया है। ऊर्जा की बढ़ती मांग के द्वारा ऊर्जा उपभोक्ता देशों को आकर्षित कर रही है।

2.4. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में ईरान

प्राकृतिक स्रोतों से धनी देश ईरान का खाड़ी देशों एवं ऊर्जा आयातित देशों के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। पश्चिम एशिया तथा यूरोप में अपने खनिज पदार्थों की वजह से तथा शिया मुस्लिम आबादी के कारण ज्यादातर खाड़ी मुस्लिम देशों से ईरान के संबंध ज्यादा अच्छे रहे हैं। परन्तु ईरान दक्षिण एशिया खासकर भारत, चीन, पाकिस्तान से संम्बद्व हैं।[10]

2.4.1. ईरान की भौगोलिक स्थिति

ईरान भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम एशिया के उत्तर–पूर्वी छोर पर स्थित है यह एक महान ऐतिहासिक सभ्यता का प्रतीक एवं प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न देश है। इसकी प्राकृतिक संपदा ही विश्व के अनेक देशों को अपनी ओर आकर्षित करती है। पश्चिम एशिया को अंग्रेज मध्य पूर्व एशिया भी कहते थे। ईरान क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनियां का सबसे बड़ा देश है तथा इसका क्षेत्रफल लगभग 1.648 मिलियन किलोमीटर है इसका अधिकांश भाग मरुस्थलीय है। इसकी दक्षिण दिशा में फारस तथा ओमान की खाड़ी और अरब सागर है। इसके पश्चिमी क्षेत्र में ईराक है जो कि प्राकृतिक तेल

[9] श्री एन एस भारत और ईरान एक स्थाई संबंधी विषय पर आई डी एस ए आई टी आई एस सामरिक संवाद में निवेश विदेश सचिव का संबोधन 5 जुलाई 2010

[10] पुष्पेश पंत भारत की विदेश नीति 2010 पेज नंबर 7

भंडार से युक्त है। इन देशों के बीच सालों तक युद्ध चला और वर्तमान में भी इनके आपसी संबंध तनाव पूर्ण हैं। उत्तर दिशा में तुर्की, रूस तथा कैस्पियन सागर स्थित है। इसके पूर्व में पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान है, इनके साथ ईरान के आर्थिक एवं व्यापारिक संबंध अच्छे हैं। यह उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में 1400 मील लम्बा तथा उत्तर से दक्षिण दिशा में लगभग 875 मील चौड़ा है[11] जो हिंद महासागर क्षेत्र में पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान में मार्ग प्रशस्त करता है। ईरान ऊर्जा संसाधनों से भरपूर क्षेत्र है ऊर्जा संसाधनों की यही उपलब्धता इसे विश्व में एक अलग पहचान देती है। ईरान के पास खनिज तेल और प्राकृतिक संसाधनों का पर्याप्त भंडार है जिसके कारण ईरान विश्व के कई शक्तिशाली देशों के लिए आंख की किरकिरी बना हुआ है। हालांकि ईरान का खाड़ी के देशों के साथ बेहतर संबंध है लेकिन सऊदी अरब और इजरायल के साथ इसके संबंधों में खटास जगजाहिर है।

ईरान के मरुस्थल में कई प्रकार की भूमि पाई जाती है। वहां के देशवासियों ने इसे अपने तरीके से विशेष नाम दिए हैं जैसे–बजरी या बालू के कठोर पृष्ठ को 'दश्त' कहते हैं तथा जहां पानी और वनस्पति नहीं होता है उन क्षेत्रों को 'लुट' कहते हैं । ईरान के जल स्रोत का आधे से अधिक भाग 3,50,000 वर्ग मील का जल संचरण आंतरिक है। ईरान के पहाड़ी क्षेत्रों की तलहटी में भूगर्भ जल की पर्याप्त उपस्थिति है। करीब 3000 साल पहले ही ईरानियों ने भूगर्भ जल को गहराई से ढलान के जरिए ईरान के दूरदराज क्षेत्रों तक पहुंचाने का तरीका सीख लिया था जिसे फारसी भाषा में 'कारिज' कहते हैं। पानी निकालने की ईरान की इस तकनीक को 2016 में 'वर्ल्ड हेरिटेज साइट' में शामिल किया गया है।

ईरान की जलवायु कैस्पियन तटीय भाग को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में अति विषम है। यहां का तापमान कम रहता हैं और अत्यधिक तेज गति के साथ वायु चलती है तथा कैस्पियन सागर के तटीय क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा होती है। ईरान के सिस्तान

[11] ईरान. India Water Portal. Retrieved on 12 March 2019 From -https://hindi.indiawaterportal.org/node/32568

मरुस्थल क्षेत्र में बालू तथा धूल युक्त वायु लगभग 70 मील प्रतिघंटे के वेग से चलती है इसीलिए इसे आंधियों का देश कहा जाता है। ईरान के दक्षिणी भाग में खजूर की पर्याप्त पैदावार होती है जिसे विश्व के अन्य देशों में निर्यात किया जाता है। साथ ही ईरान फल के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। नतांज की नाशपाती तथा करमनशाह की अंजीर विशेष रूप से प्रसिद्ध है। ईरान में इसकी खेती लगभग 40,000 साल पहले ही शुरू हो गई थी। कैस्पियन सागरीय तटीय क्षेत्रों के अतिरिक्त शेष भागों में नदियों एवं कनातों द्वारा सिंचाई करके कृषि कार्य किया जाता है। ईरान के मुख्य खाद्य फसलों में गेहूँ, जौ एवं बाजरा प्रमुख हैं।[12]

2.4.2. धर्म

ईरान एक इस्लामिक देश है, जिसमें शिया समुदाय की बहुलता है। वैसे तो ईरान में इस्लाम सातवीं सदी में आ गया था परंतु 1979 में ईरान में धार्मिक क्रांति हुई जिसके परिणाम स्वरूप ईरान में खोमैनी के नेतृत्व में इस्लामिक गणराज्य की स्थापना हुई। इस्लामी क्रांति के बाद ईरान में पहलवी वंश के शासन को उखाड़ फेंका गया और पश्चिमी संस्कृति को छोड़कर इस्लामीकरण पर जोर दिया गया। ईरान के इस्लामीकरण से पहले वहां 'जरदोश्त धर्म' को मानने वाले अनुयायी रहते थे, लेकिन बाद में जिन लोगों ने इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया उन्हें यातनाएं दी गयी जिसके कारण कुछ लोग वहां से भाग कर भारत आ गए, जिन्हें भारत में पारसी कहा जाता है। ईरान को शिया संस्कृति का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता था आर्यों के आगमन के पूर्व ईरान के लोग वरुण, भू–लोक और आकाश के देवता की पूजा करते थे, उसके बाद आहुर मजदा तथा मित्र आदि देवता की पूजा करते थे। ईरानी लोगों द्वारा मूर्ति पूजा के लिए अनाहिता देवी के मंदिर, एगबाटन, सूसा आदि नगरों में स्थापित किये गये।[13]

[12] जुबिन एक रात 26 जून 2018 ईरान का वह पूरा सीन कारनामा जिसकी दुनिया का जोरदार है बीबीसी हिंदी वहीं
[13] राम प्रसाद त्रिपाठी विश्व का इतिहास पेज नंबर 311

2.4.3. जाति

ईरान वैसे तो इस्लामिक गणराज्य घोषित कर दिया गया, परन्तु ईरान शिया मुस्लिम जाति का प्रमुख गढ़ माना जाता है। यहां शिया समुदाय कुल आबादी का लगभग 60 से 70 प्रतिशत है जबकि शेष आबादी के लगभग 30 से 40 प्रतिशत में फारसी, बाकी, कुर्द, अरबी, बलोची, गरकी अजरी इत्यादि जातियां निवास करती है।

2.4.4. नाम

ईरान का प्राचीन नाम फारस या पारस था, किन्तु इस्लामी क्रांति के बाद पारस का नाम ईरान रख दिया गय। ईरान नाम की उत्पत्ति अफगानिस्तान से लगा हुआ पूर्वी प्रदेश 'अरियान' या 'एयान' (यूनानी एरियाना) कहलाता था जिससे 'ईरान' शब्द बना है। ईरान शब्द आर्यवास के अर्थ में पूरे देश के लिए प्रयोग किया जाता था।

2.4.5. कला एवं संस्कृति

ईरान की कला एवं संस्कृति प्राचीन काल में बहुत संपन्न थी। ईरान में गृह–निर्माण कला का बहुत विकास हुआ था। गृह निर्माण में उनकी कला की अपनी अलग विशेषता थी। भारत में प्राचीनकाल, मौर्यकाल एवं मुगल काल आदि के समय की स्थापत्य कला पर ईरानी स्थापत्य कला की झलक या छाप स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। प्राचीन ईरानी स्थापत्य कला के अवशेषों में बड़े–बड़े आंगन, चबूतरे, पतले सुंदर खम्भे आदि बने रहते थे, वे बागों को सजाने में भी निपुण थे। भारत में ताजमहल के सामने लगा हुआ फब्बारा एवं मुगल गार्डन इसका साक्ष्य हैं। चमकीले पॉलिशदार रंगीन पत्थरों पर मेसोंपोटामियां के सौन्दर्य चित्र आदि बने होते थे। ईरानी सम्राटों को नगर निर्माण कराने का बहुत शौक था तथा खम्भों, चबूतरों आदि पर बने पशुओं, मनुष्यों के चित्र से स्पष्ट है कि इन्हें कला का बहुत ज्ञान था।[14]

[14] त्रिपाठी, राम प्रसाद (2008) विश्व का इतिहास पेज नंबर 31

2.5. राजनीतिक व्यवस्था

2.5.1. हखामनी वंश

ईरान के हखामनी वंश का पहला प्रतापी राजा साइरस हुआ जिसने 'मीद्रिया' के सम्राट के खिलाफ विद्रोह का आगाज किया। इस विद्रोह में मीद्रिया सम्राट की सेना ने साइरस का भरपूर सहयोग दिया और 550 ईसा पूर्व में साइरस का अपना सम्राट स्वीकार किया। साइरस मीद्रिया का सम्राट होने के साथ–साथ अपने आप को फारस का सम्राट भी घोषित कर लिया, क्योंकि मीड़ों के प्रति साइरस का व्यवाहार बहुत ही कुशल था जिससे यहां के लोग उनका पूरा सहयोग करने लगे तथा सम्राट ने भी उन्हें अपनी सेना में भर्ती कर लिया। इसी बीच साइरस की पहली लड़ाई लीबिया के राजा क्रीसस से हुई क्योंकि साइरस क्रीसस की बढ़ती हुई शक्ति को शीघ्र ही रोकना चाहता था जिसके लिए उसने क्रीसस पर आक्रमण की योजना बनाई थी। इस योजना में क्रीसस को पूर्ण विश्वास था कि उसे बेबीलोन, यूनान, तथा मिस्र से सहायता मिलेगी, लेकिन क्रीसस की यह चाल समझ कर साइरस ने क्रीसस पर आक्रमण करने को सोचा लेकिन आक्रमण से पूर्व साइरस ने क्रीसस पर अपना अधिपत्य स्वीकार कराने के लिए अपने दरबार में आमंत्रित किया लेकिन क्रीसस ने इस आमंत्रण को ठुकरा दिया, इस युद्ध में साइरस की विजय हुई तथा क्रीसस को पकड़ कर नजर बंद कर दिया गया। इस विजय की वजह से मीद्रिया की राजधानी में साइरस की पताका फहरने लगी। हखामनी वंश का अगला प्रतापी योग्य राजा दारा हुआ जिसने लगभग 20 वर्षोंतक शासन किया तथा उसका विशाल साम्राज्य पूर्व में भारत के सिंधु नदी तक फैला था।[15]

2.5.2. सासानी वंश

सासानी ईरान के इतिहास में सबसे प्रभावशाली शासको में से एक रहा है। यह ईरान में सबसे सशक्त शासको में माना जाता रहा है, अनेक लेखक इस वंश को

[15] त्रिपाठी, राम प्रसाद (1988). "विश्व का इतिहास" उत्तर प्रदेश हिंदी सस्थान, लखनऊ, पेज न 311.

हखामनी शासकों के मूल स्थान से मानते है। इस शासन के बाद से फारस में किसी एक शासक का अधिपत्य नहीं रहा। हालाँकि रोम ने दजला नदी के पूरब में कभी भी अपना अधिपत्य स्थापित करने के बारे में नहीं सोचा क्योंकि फारसी शासक रोम के शासको से हमेशा से डरते रहे, लेकिन कुछ समय पश्चात् सासानी शक्ति के विस्तार होने की वजह से इस वंश का संस्थापक अर्दाशिर प्रथम ने 224 ई० में पार्थियन शासक अर्दवन को हरा दिया और रोम शासक को चुनौती दी, साथ ही कई वर्षों तक आक्रमण भी करते रहें तथा 241 ई० में शापुर ने रोम को मिसिको के युद्ध में पराजित किया। 244 ई० अर्मेनिया फारस के नियंत्रण में रहा इसके बाद भी पार्थियनों ने रोम को विभिन्न स्थानों पर परेशान करते रहें तथा 273 ई० में शापुर की मृत्यु हो गयी। इसके बावजूद भी रोम और फारस के बीच आक्रमण का सिलसिला चलता रहा और इसका परिणाम हुआ कि अमेर्निया के दो टुकड़े हो गए–पहला रोम तथा दूसरा फारस। जिसके चलते शापुर के शासन को काफी नुकसान सहना पड़ा क्योंकि फारस के कुछ क्षेत्र रोम के नियंत्रण के हिस्से में चले गये। शापुर द्वितीय सन् 310 में गद्दी पर बैठा और 379 ई० तक शांत पूर्ण तरीके से शासन किया और क्षेत्र में धार्मिक सहिष्णुता के मार्ग पर चलने का प्रण लिया था। इसके उपरांत यही नीति इनके उत्तराधिकारियों ने भी विदेश नीति में अपनाई। लेकिन फारस के सभी शासक संदिग्ध अवस्था में मारे गए थे।

2.6. अर्थव्यवस्था

ईरान मध्य–पूर्व एशिया में प्राकृतिक खनिज संसाधनों से युक्त एक महत्वपूर्ण देश है। ईरान की अर्थव्यवस्था को देखा जाए तो यह मुख्य रूप से खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस के निर्यात पर अत्यधिक निर्भर है। ईरान के कच्चे तेल के आयातकों में चीन और भारत क्रमशः प्रथम और द्वितीय रहे है, ईरान में ज्ञात तेल भंडार विश्व के सभी तेल भंडार का 10 प्रतिशत के लगभग है तथा प्राकृतिक गैस के भंडार का ज्ञात वैश्विक भंडार का लगभग 15 प्रतिशत है इसके अतिरिक्त ईरान की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण कारक इसके पास हाइड्रोकार्बन का विशाल भंडार भी है, जो इसके

निर्यात में 80 प्रतिशत तक का योगदान देता है साथ ही ओपेक देशों में ईरान कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है (बंसल, 2017)।

2.7. ईरान की इस्लामिक क्रांति

रजा शाह पहलवी ने 1980 ई० के दशक में ईरान का आधुनिकीकरण करना आरंभ किया परंतु वो इस कार्य में सफल नहीं हो पाए। पहलवी शासक को अमेरिका का पथ प्रर्दशक भी कहा जाता था। यही वजह थी कि वो आधुनिकरण में ईरानी जनता का विश्वास नहीं जीत पाये तथा पहलवी वंश के राजा के खिलाफ जनता उग्र हो गई और ईरानी नेता अयातोल्लाह अली खोमैनी के नेतृत्व में इस्लामिक क्रांति 1989 में हुई। ईरान को एक मुस्लिम गणराज्य घोषित कर दिया। इस क्रांति में मंदिरों, मकबरो तथा मूर्तियों को तोड़ दिया गया। इस क्रांति को फ्रांस की राज्यक्रांति और बोल्शेविक क्रांति के बाद विश्व की सबसे महान क्रांति कहा जाता है। इस क्रांति की वजह से पहले वंश का अंत हो गया तथा अयातोल्लाह अली खोमैनी ईरान के राष्ट्रपति बने ईरान में इस्लामिक क्रांति होने के बहुत से कारण थे– गरीबी और सूखा से लोग परेशान थे तथा शाह अकूत पैसा खर्च कर रहे थे जिससे जनता में उनके खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया और नतीजा ईरान की इस्लामी क्रांति के रूप में आया। पहलवी वंश के शासक रजाशाह पहलवी के शासन के अंत के सन्दर्भ में फारसी में एक कहावत है कि-" tareekh ast ayeena-e gozashta ema amma darsi st baraya ayandeh e ma" जिसका अर्थ है–इतिहास अतीत का दर्पण है और भविष्य के लिए अगर हम ईरानी राजशाही इतिहास को देखे तो किसी भी शासक ने इतिहास से कोई सबक नही सीखा यही वजह है कि ईरानी जनता ने पहलवी साम्रज्य को 1979 में उखाड़ फेंका"[16]

भारत ईरान का संबंध किसी भी अन्य देश से ज्यादा प्राचीन है। दोनों देशों में प्राचीन काल से विभिन्न प्रकार के व्यापारिक संबंध थे। हालांकि यह व्यापार केवल सिंधु

[16]तुलशीराम (1985). पर्सिय टू ईरान वन स्टेप फोरवर्ड टू स्टेप बैक, महजान पब्लिसिग हॉउस

घाटी तक ही सीमित था क्योंकि अन्य स्थानों से या राज्यों से प्राचीन ईरान के साथ व्यापार का कोई प्रमाण नहीं मिला है। जो भी प्रमाण मिले हैं, वह केवल मेलुहा से मिलते हैं, जहां से प्राचीन पारस (ईरान) के बीच व्यापार होता था। मुगल काल एवं मौर्य काल में भारत ईरान के संबंधों को स्वर्णकाल भी कह सकते हैं क्योंकि मुगल काल के शासकों का संबंध ईरान से था। वे ईरान की भाषा, संस्कृति, स्थापत्य कला, चित्रकारी, आदि से बहुत ही प्रभावित थे तथा ईरान के स्थापत्य कला के प्रमाण भारत में मिलते हैं। मुगल काल के शासक फारसी भाषा के बहुत प्रेमी थे। मौर्यकाल में भी भारत ईरान सम्बन्धो का बहुत विकास हुआ था मौर्य कालीन इमारतों में भी इरानी शैली की छाया दिखती है तथा ईरान से व्यापार के प्रमाण मिले हैं। भारत ईरान का संबंध उस समय लगभग समाप्त हो गया था या संपर्क टूट सा गया था जब भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य का अधिपत्य हो गया था और ईरान पर रूस का ज्यादा प्रभाव था। ब्रिटिश सरकार ने सबसे पहले भारत का संपर्क पश्चिम एवं मध्य एशिया से खत्म कर दिया क्योंकि वह चाहते थे कि भारत में उनके अलावा कोई और व्यापार न करें। यही वजह था कि ब्रिटिश भारत के समय तक भारत ईरान का ज्यादा संपर्क या संबंधों के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है। आजादी के बाद भारत ईरान के संबंध राजनीतिक रूप से शुरू हो गये क्योंकि भारत की बढ़ती ऊर्जा की मांग को ईरान पूरा करने में सक्षम देश था इसीलिए भारत के लिए एक देश से बढ़कर ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने वाला देश अधिक महत्वपूर्ण था। वर्तमान संबंधों में उतार–चढ़ाव चलता आ रहा है परंतु दोनों देश अपने आपसी हितों के लिए एक दूसरे से बंधे हुए हैं। विभिन्न क्षेत्रों में और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपना पक्ष रखते हैं। वर्तमान संबंधों की बात की जाए तो हम पाते हैं कि भारत ईरान अपने राष्ट्रीय हितों के लिए बहुत से मुद्दों पर असहमति व्यक्त कर चुके हैं। भारत की अमेरिका से बढ़ती दोस्ती और ईरान का परमाणु परीक्षण की जीत दोनों देशों के संबंधों को धीरे धीरे रसातल की तरफ ले जा रही हैं।

अध्याय–तृतीय

भारत–ईरान सम्बन्ध में ऊर्जा सुरक्षा

ऊर्जा एक ऐसा श्रोत है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने जीवन की दैहिक, दैविक एवं भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यह व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र के निर्माण का महत्वपूर्ण साधन है। ऊर्जा का प्रकृति में अनेक परम्परागत एवं गैर परम्परागत स्रोत मौजूद है जो आधुनिक वैश्विक परिदृश्य में एक राष्ट्र के अस्मिता एवं उन्नति का द्योतक है जिस पर उस राष्ट्र का ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य राष्ट्रों की भी उन्नति निर्भर करती है। इतिहास प्रतिबिंबित करता है कि मानव समाज अपने लाभ के लिए ऊर्जा स्रोतों यथा–जल, वायु, कोयला, तेल, इत्यादि पर नियंत्रण करने का प्रयास करता रहा है। एक देश के लिए ऊर्जा सुरक्षा आधुनिक युग में एक महत्वपूर्ण संकेतक बन गया है। पारंपरिक ऊर्जा संसाधन अर्थात तेल और प्राकृतिक गैस बड़े पैमाने पर कुछ देशों व क्षेत्रों में केंद्रित हैं जो कि विकसित तथा विकासशील देशों द्वारा बड़े पैमाने पर आयात की आवश्यकता को पुरा करते हुए, वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में तेल और प्राकृतिक गैस की लागत और भू–राजनीतिक सुरक्षा का मुद्दा महत्वपूर्ण चिंता का विषय बन गया है। विश्व में तेल और प्राकृतिक गैस का उद्‌भव लगभग 30 से 40 वर्षों और कोयले का डेढ़ सौ से 200 वर्षों दशक पहले शुरू हुआ था। लेकिन प्रश्न यह है कि प्राकृतिक संसाधनों के मूल्यों का निर्धारण कौन करता है, इसके लिए विश्व के अनेक संगठन मौजूद है। क्या इनके द्वारा तेल और प्राकृतिक गैसों के मूल्यों का निर्धारण किया जाता है, जैसे पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन OPEC जिसका अप्रत्याशित वित्तीय मामला और भौतिक नुकसान के साथ–साथ गरीब देशों तक पहुंचता है। 1925 और 1972 के बीच औद्योगिक देशों के ऊर्जा बजट में शानदार बदलाव देखा गया। 1925 तक विश्व के अनेक देश 80 प्रतिशत कोयले पर निर्भर थे लेकिन 1972 के बाद 70 प्रतिशत तेल और गैस पर निर्भर हो गए (Kalicki & Goldwyn, 2013)। इसलिए विश्व के सभी देश अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर बहुत ही चिंतित हैं। साथ ही वह

विश्व के अनेक जगहों से ऊर्जा का आयात करने का प्रयत्न कर रहे हैं जैसे चीन, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका इत्यादि (Dutt, 2003)।

भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए अनेक देशों के साथ अपने राजनीतिक व आर्थिक संबंध स्थापित कर रहा है। इसके तहत यह विश्व के अनेक भागों से अपनी जरूरतों को पूरा कर सकता है तथा भारत अपनी अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूत कर सकता है क्योंकि यह सर्वविदित है की जैसे–जैसे आर्थिक स्थिति बढ़ती है वैसे–वैसे ऊर्जा की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। आधुनिक युग में भारत ऊर्जा की समस्याओं से ग्रसित है। जिसकी पूर्ति के लिए भारत आज भी विश्व के ऊर्जा सम्पन्न देशों पर निर्भर है। साथ ही भारत ऊर्जा परिदृश्य व आगामी ऊर्जा चुनौतियों को लेकर के पहले से ही चिंतित है। वर्तमान समय में भारत लगभग 80 प्रतिशत तेल का आयात विश्व के अनेक भागों से करता है इसमें से पश्चिम एशिया से सबसे अधिक है। सऊदी अरब, इराक, ईरान उनमें से एक है जो कि भारत की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं और आने वाले दिनों में यह एक अच्छा ऊर्जा निर्यातक साबित होगें।[1]

इस अध्याय में भारत और ईरान के ऊर्जा संबंधों को परिभाषित किया गया है साथ ही भारत में ऊर्जा की खपत व उपलब्धता को विश्लेषित किया गया है भारत ईरान के राजनीतिक संबंधों व आने वाले दिनों में क्या रणनीतियां रहेंगी के अलावा यह भी जानने का प्रयास किया गया है कि क्या भविष्य में ईरान भारत की ऊर्जा आवश्यकता को पूरी कर पाएगा। भारत की क्या नीति रहेगी विशेषकर ऊर्जा संबंध में, भारत–ईरान के संबंधों में क्या–क्या समस्याएं व बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं इसका भी इस अध्याय में उल्लेख किया गया है।

[1] Iraq continues to be India's top oil supplier, imports from US rises 4-folds (1 may 2019). The Economic Time. Retrived on 4 May 2019 form https://economictimes.indiatimes.com/industry/energy/oil-gas/iraq-continues-to-be-indias-top-oil-supplier-imports-from-us-rises-4-folds/articleshow/69129071.cms

ऊर्जा को दो वर्गों में विभाजित किया गया है एक नवीकरणीय ऊर्जा जैसे–पानी, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा इत्यादि। दूसरा गैर नवीकरणीय ऊर्जा जैसे कोयला, गैस व तेल इत्यादि को परिभाषित करते हुए ऊर्जा के गैर नवीकरणीय साधन पर विशेष रूप से बल दिया गया है।

3.1. ऊर्जा सुरक्षा

ऊर्जा सुरक्षा वह है जो किसी निश्चित अवधि में ऊर्जा खपत के लिए प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता को संदर्भित करता है साथ ही सस्ते दामों पर कितनी मात्रा में ऊर्जा आयात किया जाता है का लेखा–जोखा भी होता है। ऊर्जा सुरक्षा जटिल और बहुआयामी है। यह आत्मनिर्भरता या स्वतंत्रता की अधिक सरलीकृत धारणाओं से परे है। यह इस बारे में है कि हमारी ऊर्जा कहां से आती है? और इसकी लागत विश्वसनीयता स्थिरता और हमारे ऊर्जा उपयोग का पैमाना क्या है? इसके साथ ही तकनीकी, आर्थिक, भू–राजनीतिक और अन्य कारक भी अपनी भूमिका निभाते है, इसके बावजूद यह भी देखा जाता है कि एक देश दूसरे देश को किस तरह सहयोग प्रदान करते हैं। ऊर्जा सुरक्षा केवल ऊर्जा का मामला नहीं है बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा को भी प्रभावित करती है (Hillebrand, Evan, 2016)। सभी देश अपनी भविष्य की ऊर्जा खपत को ध्यान में रखकर आगे की कार्य प्रणाली को निश्चित करते हैं क्योंकि ऊर्जा भविष्य की आर्थिक विकास के लिए मुख्य पूर्वापेक्षा है। हमारी अर्थव्यवस्था परंपरागत रूप से तेल, कोयला और प्राकृतिक गैस पर निर्भर है।

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संगठन ऊर्जा सुरक्षा को कुछ ऐसे परिभाषित करती है कि "एक सस्ती कीमत पर ऊर्जा स्रोतों की निर्बाध उपलब्धता है।"[2] ऊर्जा सुरक्षा के कई पहलू हैं: दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा मुख्य रूप से आर्थिक विकास के लिए समय पर की

[2] What is Energy Security. Interntional Energy Agency. Retrieved on 23 March 2018 from https://www.iea.org/topics/energysecurity/whatisenergysecurity/

गई ऊर्जा आपूर्ति पर निर्भर करती है।[3] साथ ही पर्यावरणीय आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। दूसरी ओर, अल्पकालिक ऊर्जा सुरक्षा, अर्थात अचानक ऊर्जा आपूर्ति–मांग में संतुलन बनाए रखने के लिए तुरंत किए गए प्रतिक्रिया पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

विश्व में ऊर्जा सुरक्षा एक सार्वभौमिक चिंता का विषय बना हुआ है यह विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों नीति निर्धारण, राष्ट्रीय ऊर्जा नीति, राजनीति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों के रूप में इस विषय पर गहन अध्ययन किया जा रहा है (Dyer, & Trombetta, 2013)। ऊर्जा सुरक्षा एक नीति या रणनीति के बजाय एक अवधारणा है। ऊर्जा सुरक्षा को लेकर समाज व ऊर्जा रणनीतिकारों का यह एक प्रमुख लक्ष्य रहा है क्योंकि बुनियादी मानव समाज के जरूरतों को पूरा करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हालाँकि ऊर्जा सुरक्षा के उच्च स्तर को लक्षित करने के परिणाम स्वरूप ऊर्जा सुरक्षा में अतिरंजना हो सकती है। परिणामस्वरूप संसाधनों का गैर–इष्टतम उपयोग होता है जो कहीं और अधिक मूल्यवान रूप से निवेश किया जा सकता है। नतीजतन, सवाल उठता है कि ऊर्जा सुरक्षा का आवश्यक स्तर क्या है?

विश्व में उर्जा संकट 1973 व 1974 में देखा गया[4] जब अरब पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ने तेल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था लेकिन वर्ष 1990 में खाड़ी संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा की समस्या विश्व के सामने आयी परन्तु आधुनिक युग में एक बार पुनः राष्ट्रीय सुरक्षा में ऊर्जा की अवधारणा एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में देखी जा रही है। ऊर्जा जरूरतें दिन प्रतिदिन बढती जा रही हैं जैसे परिवहन, औद्योगिक विकास, संचार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में उर्जा की महत्ता को समझते हुए भारत को ऊर्जा की उपयोगिता और पर्याप्त सुनिश्चित करने के लिए अपना ध्यान देने की आवश्यकता है। वर्ष 2031–32 तक देश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 8 प्रतिशत से 10 प्रतिशत बनाए रखने के लिए और सभी नागरिकों को

[3] Energy Security. (n.a). International Energy Agency. Retrived on 21 December 2018 from https://www.iea.org/topics/energysecurity/

[4] Retrived on 23 November 2018 from https://networks.h-net.org/system/files/contributed-files/henergy-f-venn-1973-oil-crisis.pdf

ऊर्जा आवश्यकताओं की पूरा करने के लिए एक अनुमान के अनुसार, भारत को वर्ष 2031–32 तक लगभग 1350 एम्टीओई व्यवसायिक उर्जा की जरूरत होगी जबकि वर्ष 2003–2004 में यह जरूरत केवल 327 एम0टी0ओई0 थी (माथुर, रितु, 2014)। गरीबी समाप्त करने और मानव विकास लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वर्ष 2031–32 तक भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 8–10 प्रतिशत तक होनी चाहिए (योजना आयोग 2006) इसलिए उर्जा को अर्थव्यवस्था का सतत विकास सुनिश्चित करने और राष्ट्रीय विकास हितो को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण कमोडिटी के रूप में देखा जा रहा है।

3.2. भारत में ऊर्जा सुरक्षा की रूपरेखा

आधुनिक युग में ऊर्जा सुरक्षा के कई मतलब हो सकते हैं जोकि विभिन्न आयामों पर निर्भर करते हैं एक ऐसे देश में करोड़ों लोग जहॉ रोशनी के लिए परम्परागत स्त्रोत का उपयोग करते हों अर्थात बिना बिजली कनेक्शन के रहते हो और अपनी रसोई जीवन की जरूरतें परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से पूरी करते हो, वहां ऊर्जा सुरक्षा का मतलब परिवार स्तर पर सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा के आस–पास से हो सकता है रितु माथुर ने अंपने लेख में परिभाषित किया है कि सभी प्रकार के ईधनों और बिजली पर ग्रामीण उपभोक्ता अपनी कुल पारवारिक बजट का छह प्रतिशत उर्जा जरूरतों पर व्यय करते हैं जबकि शहरी उपभोक्ता इसी मद पर चार प्रतिशत खर्च करते हैं। ग्रामीण परिवारों के अपर्याप्त परंपरागत ईधन ज्यादा इस्तेमाल करने के कारण शहरी परिवारों के मुकाबले अधिक व्यय करते है।

इससे साफ पता चलता है कि ग्रामीण उपभोक्ताओं के पास विकल्प की कमी होती है अक्सर ग्रामीण उपभोक्ताओं की पहुंच उपकरणों तक नहीं होती है जिनके पास बिजली के कनेक्शन हैं भी तो बिजली उपलब्धता सुनिश्चित नहीं है। लोगों के एक बड़े वर्ग के लिए ऊर्जा सुरक्षा का तात्पर्य बिजली कनेक्शन का है इसका मतलब बिजली की विश्वसनीय आपूर्ति होना भी है समाज के एक बड़े वर्ग के पास बिजली का कनेक्शन है और इसका भुगतान भी कर सकते हैं। बिजली की विश्वसनीयता और निरंतर आपूर्ति से वंचित है इसका असर उनके जीवन स्तर और परिवारिक कल्याण पर

पड़ता है तथा उनको अधिक कीमत वाले ईधन खरीदने पर मजबूर होना पड़ता है वर्ष 2011–12 में भारत की ऊर्जा आपूर्ति और अधिकतम कमी क्रमशः लगभग 8.5 प्रतिशत और 10.6 प्रतिशत थी (माथुर, रितु, 2014)। लगातार बिजली की कमी का असर आवासीय वाणिज्य और औद्योगिकी उपभोक्ता पर इस रूप में पड़ता है। उर्जा सुरक्षा के रूप में नही देखा जाना चाहिए।

3.3 ईरान में ऊर्जा की रूपरेखा

ईरान दुनिया के शीर्ष 10 तेल उत्पादकों और शीर्ष 5 प्राकृतिक गैस उत्पादक देशों में भी शुमार है। वर्ष 2017 के आकड़ों के अनुसार ईरान प्रतिदिन लगभग 4.7 million barrels per day (b/d) तेल का उत्पादन करता है। इसके साथ ही अन्य तरल प्राकृतिक गैस का उत्पादन 7.2 Trillion cubic feet रहा है।[5] वर्तमान समय में ईरान विश्व में चौथा सबसे बड़े प्राकृतिक तेल भण्डार वाला देश है साथ ही प्राकृतिक गैस के भण्डार की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान रखता है।

3.3.1. तेल भंडार

ईरान के पास विश्व का 10 प्रतिशत कच्चा तेल है और ओपेक देशों के भंडार में ईरान 13 प्रतिशत का भागीदारी करता है। ईरान का लगभग 70 प्रतिशत कच्चा तेल समुद्री तट पर स्थित हैं और शेष फारस की खाड़ी में स्थित हैं। ऑयल एंड गैस जर्नल के अनुसार जनवरी 2018 तक ईरान के पास अनुमानित कच्चे तेल भंडार का 157 बिलियन बैरल है, जो दुनिया के कच्चे तेल के भंडार का लगभग 10 प्रतिशत हैं, यह ओपेक संगठन बनाये जाने के बाद लगभग 13 प्रतिशत कच्चा तेल के भंडार में प्रतिनिधित्व करता है (Oil & Gas Journal, 2018)।

[5] Iran Executive Summary. Eia Beta. (January 7, 2019). Retrived on 25 March 2019 from https://www.eia.gov/beta/international/country.php?iso=IRN

चित्र–3.1. विश्व के बड़े कच्चे तेल उत्पादक देश

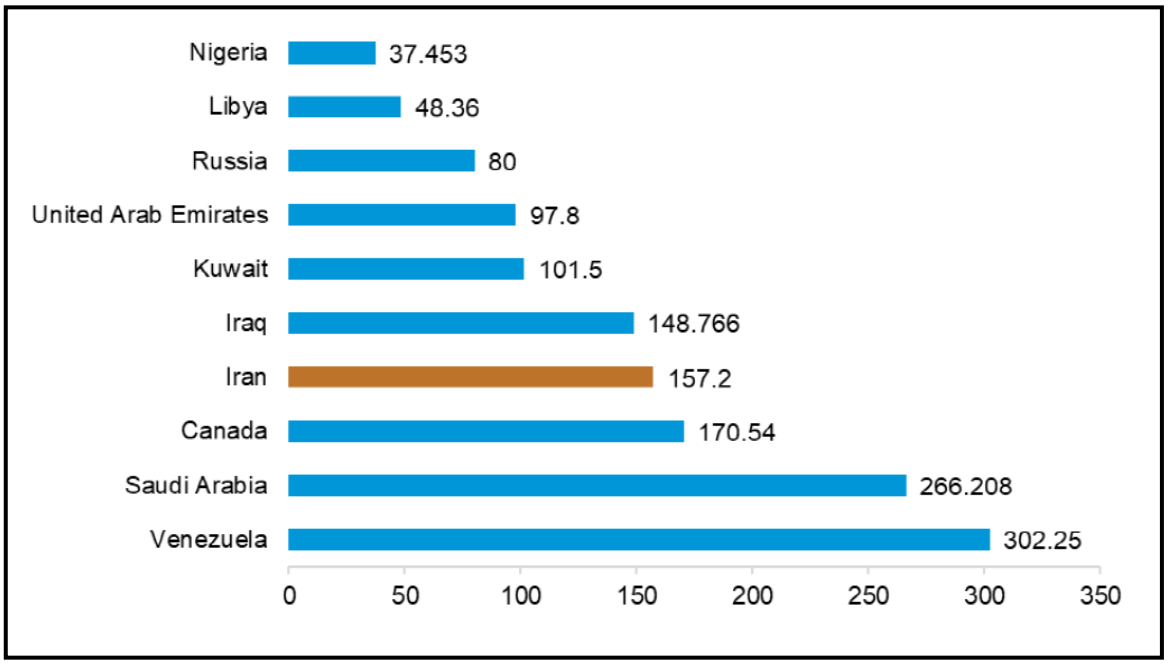

Source: Oil & Gas Journal, December, 2017

चित्र 3.2. ईरान के सबसे बड़े तेल क्षेत्र

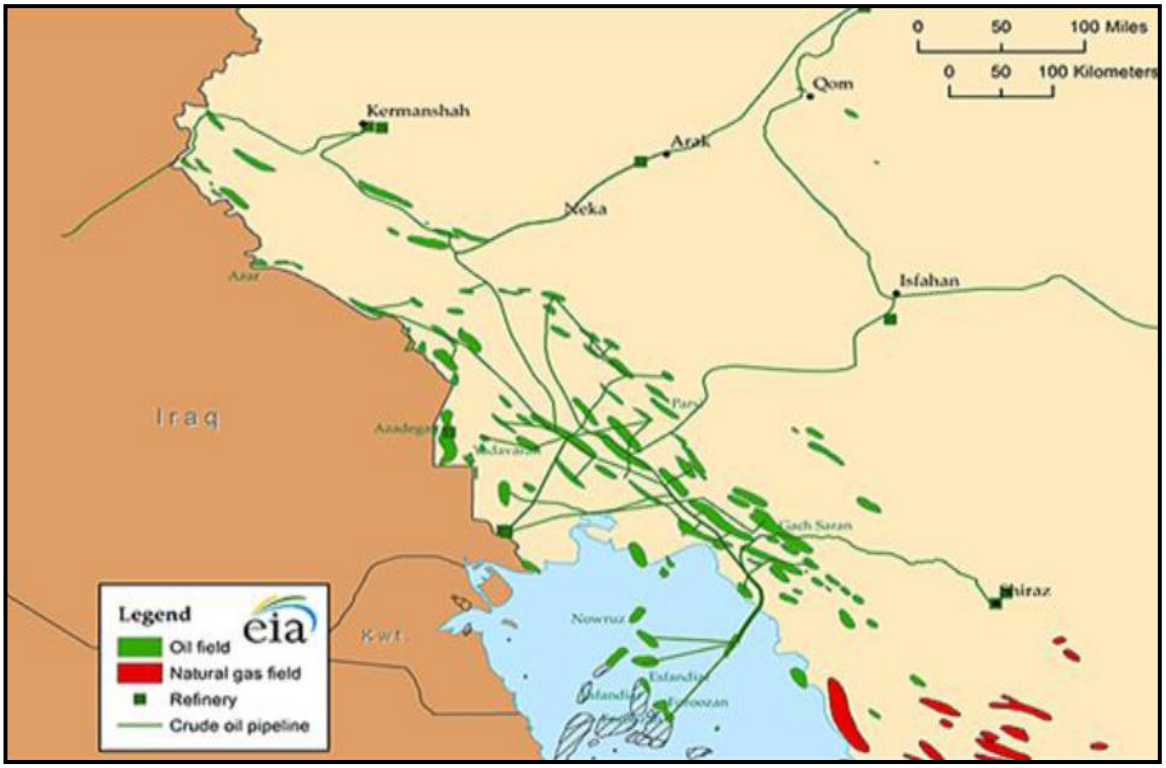

Source: U.S. Energy Information Administration, HIS EDIN

3.3.2. ईरान के सबसे बड़े तेल क्षेत्र

ईरान के सबसे बड़े तेल क्षेत्र यथा–अहवाज़, मारून, अघाजरी, गाचसरन, करंज इत्यादि, मारुन फील्ड एक तेल क्षेत्र है, जो ईरान के खुजेस्तान प्रांत में स्थित है ईरान में दूसरा सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है। यह क्षेत्र 1963 में खोजा गया था, और राष्ट्रीय स्वामित्व वाली ईरानी तेल कंपनी के स्वामित्व में राष्ट्रीय ईरानी दक्षिण तेल कंपनी द्वारा संचालित किया गया था। अघाजरी तेल क्षेत्र खुजेस्तान प्रांत में स्थित एक ईरानी तेल क्षेत्र है। यह 1938 में एंग्लो–फारसी ऑयल कंपनी द्वारा खोजा गया था और राष्ट्रीय ईरानी तेल कंपनी द्वारा विकसित किया गया था। तथा इसने 1940 में तेल का उत्पादन शुरू किया। गाचसरन तेल क्षेत्र कोहगिलुइह और बोयर–अहमद प्रांत में स्थित एक ईरानी तेल क्षेत्र है तथा यह गाचसरन शहर या डॉग अबादान के आसपास है। यह 1928 में खोजा गया था और एंग्लो–फारसी ऑयल कंपनी द्वारा विकसित किया गया तथा इसने 1930 में कच्चे तेल का उत्पादन शुरू किया।

तालिका 3.1–ईरान के पांच सबसे बड़े तेल क्षेत्र

Rank	Field Name	Formation	Initial Oil in Place (Billion Barrels)	Initial Recoverable Reserves (Billion Barrels)	Production Thousand barrels per day
1	Ahvaz Field	Asmari & Bangestan	65.5	25.5	945
2	Marun Field	Asmari	46.7	21.9	520
3	Aghajari Field	Asmari & Bangestan	30.2	17.4	200
4	Gachsaran Field	Asmari & Bangestan	52.9	16.2	560
5	Karanj Oil Field	Asmari & Bangestan	11.2	5.7	200

3.3.3. प्राकृतिक गैस का भंडार

ऑयल एंड गैस जनरल दिसंबर 2017 के अनुसार ईरान का अनुमानित प्राकृतिक गैस भंडार 1,191 ट्रिलियन क्यूबिक फीट (Tcf) था जो रूस के बाद ईरान का दूसरा स्थान पर है जो निम्न चित्र 3.3 में दर्शाया गया है (Oil & Gas Journal, December 2017)। ईरान के पास दुनिया के 17 प्रतिशत प्राकृतिक गैस भंडार हैं।

इसके पास ओपेक देशो की तुलना में एक तिहाई से अधिक भंडार हैं। इसके साथ ईरान दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सूखा प्राकृतिक गैस उत्पादक देश है जबकि पहला स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका तथा दूसरा रूस का है।[6]

चित्र 3.3. प्राकृतिक गैस के सबसे बड़े आरक्षित धारक वर्ष 2017

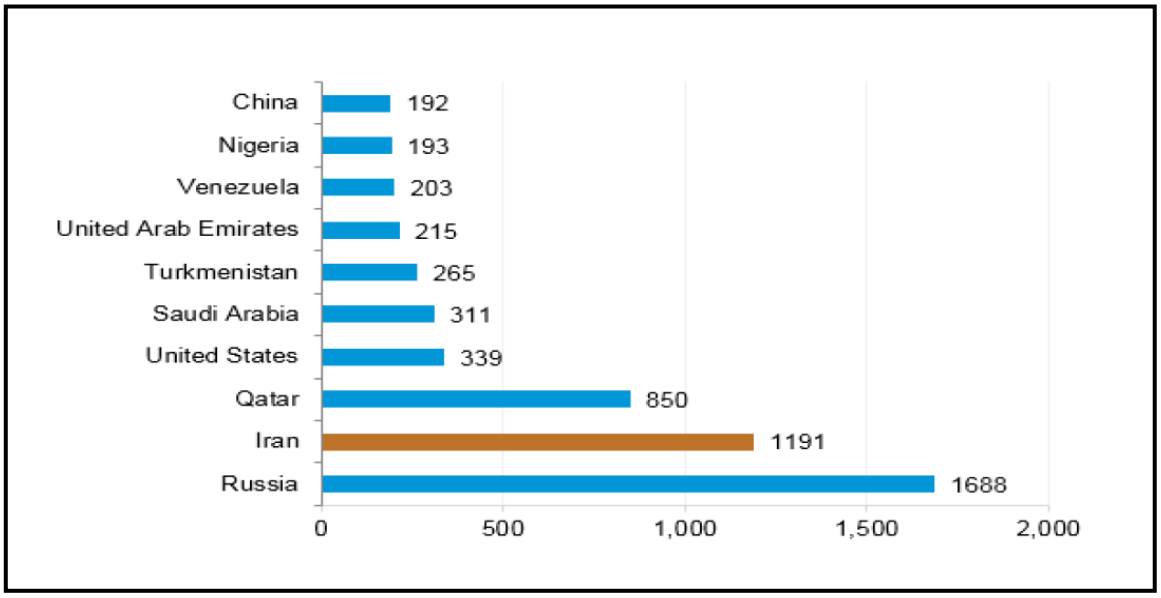

Source: Oil & Gas Journal, December, 2017

ईरान का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस क्षेत्र, दक्षिण फारस, ईरान के प्राकृतिक गैस भंडार का लगभग 40 प्रतिशत अनुमानित है। ईरान में प्राकृतिक गैस की खोज की उच्च सफलता दर है, जो एफईजीई के अनुसार विश्व की औसत सफलता दर 30 प्रतिशत से 35 प्रतिशत की तुलना में 79 प्रतिशत है (Oil & Gas Journal, December 2017)। ईरान में नए प्राकृतिक गैस भंडार का पता लगाना उच्च प्राथमिकता नहीं है क्योंकि देश में बड़ी मात्रा में अविकसित ज्ञात भंडार हैं।

ईरान का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस क्षेत्र दक्षिण पारस है जो फारस की खाड़ी में एक गैर–संबद्ध गैस क्षेत्र है। दक्षिण पारस एक बड़ी गैस संरचना का हिस्सा है एवं ईरान और कतर के क्षेत्रीय जल को कतर में उत्तर क्षेत्र कहा जाता है। दक्षिण पारस

[6] Independent Statistics Analysis U.S Energy Information Administration. (April9, 2018) Country Analysis Brief: Iran. Retrived 12 Janury 2019 from http://www.ieee.es/en/Galerias/fichero/OtrasPublicaciones/Internacional/2018/EIA_Iran_9abr2018.pdf.

के पास ईरान के कुल प्राकृतिक गैस भंडार का लगभग 40 प्रतिशत है। (Facts Global Energy, 2017)। ईरान के अन्य प्रमुख प्राकृतिक गैस क्षेत्रों में किशए उत्तरी पारसए सरदार–ए–जांगल, फरजाद–बी, अगहर, गोलशान और कंगन शामिल हैं। ये अन्य क्षेत्र भी बड़ी मात्रा में घनीभूत भंडार रखते हैं। ईरान के प्राकृतिक गैस भंडार का लगभग 80 प्रतिशत के अनुसार जुड़ा नहीं है।

3.4. भारत में ऊर्जा मांग

भारत की लगभग 70 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। जहां पर अभी तक हमारे देश के 21 प्रतिशत गाँवों तथा लगभग 50 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों तक बिजली नहीं पहुँच पाई है। वर्तमान विकास की गति को बरकरार रखने के लिए ग्रामीण ऊर्जा की उपलब्धता को सुनिश्चित करना हमारी सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है।[7]

ऊर्जा की बढ़ती मांग के हिसाब से उत्पादन भी बढ़ता ही जा रहा है। जहां सन् 2000–01 में भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 374 किलोवाट प्रतिवर्ष थी, वहीं वर्तमान में 602 किलोवाट हो गयी है। हमारे योजनाकार वर्ष 2012 तक प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 1000 किलोवाट का अनुमान लगा रहे हैं तथा इस हिसाब से ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने वाली परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। विकसित देशों में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष लगभग 10000 किलोवाट ऊर्जा खपत है। विकास का जो मॉडल हम अपनाते जा रहे हैं उस दृष्टि से अगली प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में हमें ऊर्जा उत्पादन को लगभग 2 गुना करना होगा।[8]

भारत दुनिया का ग्यारहवां सबसे बड़ा ऊर्जा उत्पादक और छठा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। जीवाश्म ईंधन अर्थात् तेल, कोयला और प्राकृतिक गैस भारत के लिए प्राथमिक ऊर्जा खपत का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। भारत में 54 प्रतिशत कोयला, 34 प्रतिशत तेल और 12 प्रतिशत प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा तथा अन्य नवीनीकरण

[7] ऊर्जा, भारत में ऊर्जा के इस्तेमाज की वर्तमान स्थिति, ऊर्जा के स्रोत , भारत सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं, ऊर्जा और महिलाओं का सशक्तीकरण (September 28, 201). IAS Hindi. Retrived from https://iashindi.com/article/ecology-and-environment/energy/

[8] ऊर्जा की बढ़ती मांग, Retrived on 13 October 2018, From. https://prashanttechguru.wordpress.com

स्रोतों का उपयोग किया जाता है और काफी हद तक, भारत जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भर करता है (SEE India briefing by USEIA, 2007)।

भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा की खपत कोयले पर निर्भर है। यह 2008–09 में 53 प्रतिशत योगदान देता है। उसी वर्ष, तेल और गैस का योगदान क्रमशः 33 प्रतिशत और 8 प्रतिशत था। 2008–09 में भारत में 492.8 मीट्रिक टन कोयला और 32.4 मीट्रिक टन लिग्नाइट का उत्पादन किया गया था। 2007–08 में 156 मीट्रिक टन तेल की खपत हुई थी।

हालांकि, यह समझा जाता है कि विविधीकरण की यह नीति भारत को चीन के साथ सीधी प्रतिस्पर्धा में लाती है जिससे गैर–मध्य पूर्वी तेल संसाधनों की तेजी से गिरावट हो रही है। एक परिणाम के रूप में, वर्ष 2020 से मध्य पूर्वी तेल संसाधनों पर भारत को और भी अधिक निर्भर करेगा। यह अब भारत को तेल के मूल्य स्तर को प्रभावित करने में मदद नहीं करेगा और प्राकृतिक गैस भारत को अधिक विश्वसनीता से प्राप्त करेगा।

आधुनिक युग में मानव के विकास के लिए ऊर्जा सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है, और इस तरह, सभी देशों के आर्थिक विकास को निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में कार्य करता है। भारत में प्राथमिक ऊर्जा की खपत चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर है वर्ष 2017 में 4.6 प्रतिशत से अधिक है और यदि हम विश्व से तुलना करते है तो वही वर्ष 2017 में 5.6 प्रतिशत से अधिक है (BP Statistical Review, 2018)।

भारत में ऊर्जा स्रोतों की खपत निम्न प्रकार है कच्चा तेल 221.1 Mtoe, प्राकृतिक गैस 46.6 Mtoe, कोयला 424 Mtoe, परमाणु ऊर्जा 8.7 Mtoe, पन बिजली 30.7 Mtoe से कुल प्राथमिक ऊर्जा खपत करता है। 2017 में, भारत का कच्चे तेल और अन्य तेल उत्पादन का आयात लगभग 198.8 मिलियन टन है। भारत की लगभग 75 प्रतिशत बिजली का उत्पादन जीवाश्म ईंधन से होता है। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा

स्थापित एक ट्रस्ट, इंडिया ब्रैंड इक्विटी फाउंडेशन (IBEF) ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें दुनियाभर में सबसे अधिक उत्पादन होने वाली बिजली का जिक्र किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2016 में 1,423 बिलियन यूनिट उत्पादन के साथ भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा उपभोक्ता बन गया है इस मामले में चीन पहले और अमेरिका अभी दूसरे स्थान पर है (Kumar, March 2018)।

भारत, साल 2017 से 2022 के बीच लगभग 200 गीगावॉट तक बिजली क्षमता बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, इसके लिए सरकार हाइड्रो गैस और नवीनीकृत ऊर्जा स्रोतों से बिजली बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसके अलावा भारत साल 2022 तक लगभग 60 गीगावॉट विंड एनर्जी और लगभग 100 गीगावॉट सौर ऊर्जा बनाने की योजना पर काम रहा है (Kumar, March 2018)।

भारत में बढ़ती ऊर्जा मांगों को पूरा करने के लिए यह बड़े पैमाने पर तेल गैस आदि तत्त्वो का आयात करने का प्रयास के रहा है। वर्ष 2009–10 में, देश ने 159.26 मिलियन टन कच्चे तेल का आयात किया यह घरेलू कच्चे तेल की खपत का 80 प्रतिशत था और देश के कुल खर्च का 31 प्रतिशत तेल आयात था।

भारत की बढ़ती ऊर्जा माँगों और सीमित घरेलू तेल और गैस भंडार को देखते हुए, देश के पास अपने नवीकरणीय और सबसे अधिक काम करने वाले परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के विस्तार के लिए सरकार प्रयत्नशील है। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा पवन ऊर्जा बाजार है और 2020 तक लगभग 100,000 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता को जोड़ने की योजना है। भारत 25 वर्षों के भीतर कुल बिजली उत्पादन क्षमता में परमाणु ऊर्जा के योगदान को 4.2 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत करने की भी परिकल्पना करता है। देश में निर्माणाधीन पांच परमाणु रिएक्टर (दुनिया में तीसरा सबसे ऊंचा) है और 2025 तक 18 अतिरिक्त परमाणु रिएक्टर (दुनिया में दूसरा उच्चतम) बनाने की योजना है।

भारत में उपयोग होने वाले विभिन्न ऊर्जा स्रोतों को सारणी 2 में प्रदर्शित किया गया है जैसे– कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस इत्यादि। साथ ही यह भी देखा गया है कि किन–किन वर्षो में कितना ऊर्जा खपत हुआ है, और किन वर्षो में कम रहा है, और क्या कारण रहे है। जैसा की तालिका 3.5 उल्लेख वर्ष 2007 में कोयला की खपत 502 मिलियन टन था जो कि 2016–17 में बढ़कर 841 मिलियन टन हो गया यह निरंतर बढ़ता जा रहा है। वही लिग्नाइट वर्ष 2007–08 में 34.65 मिलियन टन था। वर्ष 2008–09 में कम हो कर 31.85 मिलियन टन हो गया लेकिन वर्ष 2009–10 में बढ़कर 34.41 हो गया इसके पश्चात निरंतर बढ़ता ही रहा, लेकिन वर्ष 2013–14 में कम हो गया उसके बाद 2016–17 में 43.16 रहा है। यदि कच्चे तेल की मांग को तालिका में देखें तो वर्ष 2007–08 में 156.10 MMT था जो 2016–17 में बढ़कर 245.36 हो गई और वही प्राकृतिक गैस की मांग को देखें तो वह भी दिन प्रति दिन बढ़ ही रहा है जैसा की वर्ष 2007–08 में 39.80 Billion Cubic Metres था। वहीं 2016–17 में बढ़कर 50.78 Billion Cubic Metres हो गई।

तालिका 3.2. भारत में ऊर्जा स्रोतों का उपभोग

Years	Coal (Million Tonnes)	Lignite (Million Tonnnes)	Crude Oil MMT	Natural Gas (Billion Cubic Metres)
2007-08	502.82	34.65	156.10	39.80
2008-09	549.57	31.85	160.77	39.81
2009-10	585.30	34.41	186.55	48.34
2010-11	589.87	37.69	196.99	52.02
2011-12	642.64	41.89	204.12	60.68
2012-13	688.75	46.1	219.21	53.91
2013-14	724.18	43.90	222.50	48.99
2014-15	821.85	46.94	223.24	46.95
2015-16	836.73	42.21	232.86	47.85
2016-17	841.56	43.16	245.36	50.78

Source: Energy Statistics 2018

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि भारत की ऊर्जा खपत दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं साथ ही यह भी दर्शाता है कि आने वाले दिनों में भारत को और अधिक ऊर्जा की

जरुरत होगी इसके द्वारा भारत अपनी अर्थव्यवस्था को तेजी के साथ आगे बढ़ा सकता है साथ ही विश्व पटल पर अपने आप को सुरक्षित रख सकेगा। अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन (ईआईए) ने कहा कि भारत 2025 तक अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता बन जाएगा। वर्तमान में भारत अमेरिका, चीन और जापान के बाद दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता बना रहेगा, लेकिन इसकी मांग में कोई वृद्धि नहीं हुई है। अमेरिका ने 2012 में 18.21 Million BPD तेल की खपत की 2020 में 19.23 Million BPD तक बढ़ने का अनुमान लगाया। चीन के तेल की खपत 2012 में 10.36 Million BPD से बढ़कर 2025 में 15.70 Million BPD और 2040 में 20.48 Million BPD होने का अनुमान है 2.5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर के साथ। 2012 से 2040 तक भारत की तेल खपत वृद्धि दर 3 प्रतिशत चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर के साथ दुनिया में सबसे अधिक होगी।[9] ईआईए के अनुसार इसकी तेल की खपत 2030 में 6.11 मिलियन बीपीडी और 2040 में 8.33 मिलियन बीपीडी तक पहुँच जाएगी।

भारत में आयात के माध्यम से 80 प्रतिशत तेल की जरूरत पूरी होती है। चीन का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) भारत की तुलना में लगभग 4.5 गुना अधिक है और अमेरिकी सकल घरेलू उत्पाद भारत के लगभग नौ गुना अधिक है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का अनुमान है कि भारत 2020 तक दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयातक देश बन जाएगा।

3.5 भारत में उपलब्ध ऊर्जा भण्डार

अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा का बढ़ता उपयोग और जनसंख्या का बढ़ता दबाव भारत के लिए चिंता का विषय है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 8 प्रतिशत की लक्षित जीडीपी विकास दर के साथ, ऊर्जा की माँग 5.2 प्रतिशत बढ़ने की

[9] India to overtake Japan to become third-largest oil consumer: US (13 May 2014). US Energy Information Administration predicts India to overtake Japan by 2025. Retrived from https://www.livemint.com/Industry/9dYI7IYqh3AmR67Rj1kPKJ/India-to-overtake-Japan-to-become-thirdlargest-oil-consumer.html.

उम्मीद थी (योजना आयोग 1999)। बढ़ती जनसंख्या विस्तारित अर्थव्यवस्था, और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रेरित कुल प्राथमिक ऊर्जा की खपत क्रमशः प्रतिशत दसवीं और ग्यारहवीं योजनाओं के टर्मिनल वर्षों में लगभग 412 MTOE (मिलियन टन तेल के बराबर) और 554 MTOE होने की उम्मीद है।

भारत के पास ऊर्जा के सभी संभावित स्रोत हैं। इनमें गैर–नवीकरणीय और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के सभी प्रकार शामिल हैं। हालांकि ऊर्जा स्रोतों को समान रूप से वितरित नहीं किया जाता है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा तैयार किया गया विवरण के अनुसार देश में कुल अनुमानित कोयला संसाधन 315.149 बिलियन टन (वर्ष1.04.2017) है।[10]

भारत में प्रचुर मात्रा में विभिन्न स्रोत उपलब्ध है जैसे–कोयला, लिग्नाइट, कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस इत्यादि साथ में यह भी देखा गया है कि किन–किन वर्षो में कितनी ऊर्जा उपलब्ध रही है और किन वर्षो में ऊर्जा की मात्रा कम हुई है और क्यों तथा क्या कारण रहे है, जैसा कि वर्ष 2007–08 में कोयला की उपलब्धता 507 मिलियन टन था जो 2016–17 में बढ़कर 863.90 मिलियन टन हो गई और यह निरंतर बढ़ता जा रहा है। वर्ष 2012–13 में यह घट कर 68.14 हो गयी थी तथा बाद में फिर से अपने स्थान को प्राप्त कर लिया किया। वही लिग्नाइट वर्ष 2007–08 में 33.31 मिलियन टन था। वर्ष 2016–17 में यह 47.30 है। यदि कच्चे तेल की उपलब्धता को तालिका में देखें तो वर्ष 2007–08 में 155.79 मिलियन टन था 2016–17 में बढ़कर 249.94 हो गई वही प्राकृतिक गैस की उपलब्धता को देखें तो वह भी दिन प्रति दिन बढ़ ही रहा है, जैसा की वर्ष 2007–08 में 39.80 बिलियन क्यूबिक मीटर था 2016–17 में बढ़कर 50.53 बिलियन क्यूबिक मीटर है।

[10] Press Information Bureau Government of India Ministry of Coal. (07-March-2018). Retrived from http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=177058

तलिका 3.3. भारत में ऊर्जा उपलब्धता

Years	Coal (Million Tonnes)	Lignite (Million Tonnes)	Crude Petroleum (Million Tonnes)	Natural Gas (Billion Cubic Metres)
2007–08	507.68	33.31	155.79	39.80
2008–09	550.64	33.00	166.28	40.90
2009–10	620.39	33.73	192.95	56.65
2010–11	604.53	37.78	201.28	62.15
2011–12	642.64	42.77	209.82	60.77
2012–13	68.14	46.89	222.66	53.81
2013–14	724.19	44.64	227.03	48.40
2014–15	824.26	49.57	226.90	47.75
2015–16	847.58	45.47	239.79	48.39
2016–17	863.90	47.30	249.94	50.53

Source: Energy StatisticS 2018

3.6 ईरान से ऊर्जा आयात एक तुलनात्मक अध्ययन

1990 के बाद भारत और ईरान दोनों देशों के बीच आर्थिक सम्बन्धों में और अधिक मजबूती आयी है। इसके पश्चात भारत के आर्थिक हित हमेशा से ही ऊर्जा पर केंद्रित रहा है इसके साथ ही ईरान एक ऐसा देश है जो भारत को मध्य एशियाई क्षेत्र से जोड़ता है। ईरान भारत की ऊर्जा जरूरत को समझता है साथ ही इस जरूरत को दूर करने में भी सक्षम है साथ ही यह भारतीय विकास को भी आगे बढ़ा सकता है। इसलिए भारत–ईरान में आर्थिक निवेश कर रहा है क्योंकि यहाँ पर भारत को तेल और गैस के अवसर दिख रहे हैं।

भारत–ईरान से तेल का आयात करता है यह आयात 2008 में 13.8 बिलियन डॉलर था और वही 2012 में बढ़ कर 13.3 बिलियन डॉलर तथा 2015 में घटकर $ 6.2 बिलियन रह गया । इन निर्यातों में पेट्रोलियम उत्पाद, जैविक और अकार्बनिक रसायन, उर्वरक, प्लास्टिक, खाद्य फल और मेवे, कांच, मोती, और कीमती और अर्ध–मूल्यवान पत्थर शामिल हैं। अर्थात रूस, चीन, अमेरिका, इत्यादि में से भारत को सबसे ज्यादा

ऊर्जा की आवश्यकता है। ईरान भारत को तेल निर्यात करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है जो 2017 में 11.2 प्रतिशत तथा इराक विश्व का प्रथम देश है जो भारत को सबसे ज्यादा कच्चे तेल का आयात करता (18.6 प्रतिशत) है तथा दूसरा स्थान सऊदी अरब (17.5 प्रतिशत) है।[11] भारत और ईरान के संबंध ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती प्रदान करते हैं साथ ही एक दूसरे के हितों में सहारा प्रदान करते है।

प्रतिबंधों से पहले ईरान–भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता था। 2006 में, भारत ने ईरान से कच्चे तेल का आयात $ 4.35 बिलियन किया था, यह कुल कच्चे तेल आयात का 10 प्रतिशत था। वहीं 2008 में, ईरानी कच्चे तेल का आयात बढ़कर 11.2 बिलियन डॉलर हो गया। हालांकि प्रतिबंध लगाए जाने के बाद 2015 में 3.7 बिलियन डॉलर तक गिर गया था।

संयुक्त व्यापक योजना (JCPA) के समापन के बाद जनवरी 2016 में U.N और EU ने प्रतिबंध हटा दिए थे। इसके पश्चात दोनों देशों में तेल के बचे हुए भुगतानों को संसोधित करने के लिए एक व्यवस्था बनाई गई जिसमें $ 6.4 बिलियन के स्थापित कोष को खोला गया।[12] इसकी वजह से 2016 में ईरान से कच्चे तेल का भारत का आयात बढ़कर 6.68 बिलियन डॉलर हो गया। अक्टूबर 2016 के महीने के दौरान ईरान भारत में शीर्ष आपूर्तिकर्ता था[13] इसके अतिरिक्त भारत–ईरान का दूसरा सबसे बड़ा तेल बाजार बना हुआ है। 2016–17 में तेल आपूर्तिकर्ता के रूप में ईरान के प्रतिशत की हिस्सेदारी के नीचे तुलना आंकड़े बताते हैं।

---

[11] Daniel Workman, "Crude Oil Imports by Country," World's Top Exports. (May 11, 2018) http://www.worldstopexports.com/crude-oil-imports-by-country/.

[12] Douglas Busvine and Nidhi Verma, "India, IranAgree to Clear $6.4 Billion in Oil Payments via European Banks: Minister," Retrieved on May 6, 2018, from https://www.reuters.com/article/us-india-iran-payment-idUSKCN0XX0P5.

[13] Nidhi Verma, "Iran Overtakes Saudi Arabia as Top Oil Supplier to India," Retrieved on November 17, 2016, http://in.reuters.com/article/india-iran-oil-imports-idINKBN13C0Z3.

चित्र 3.4. भारत के तेल आयात के स्त्रोत वर्ष 2013–2017

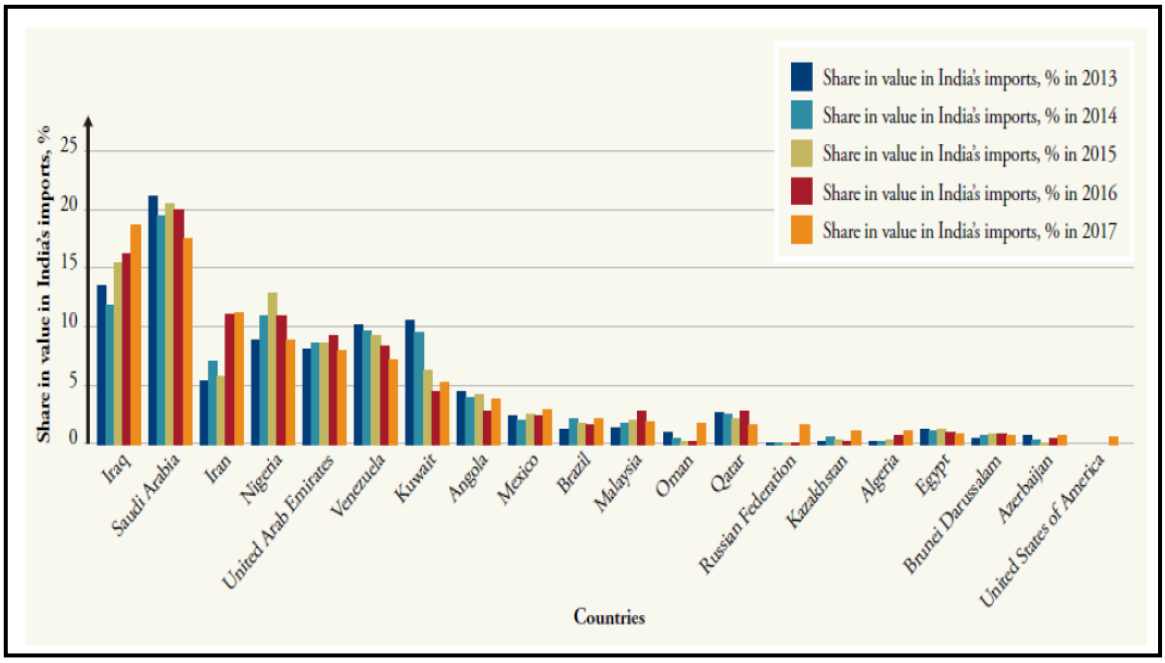

Source: Oil & Gas Journal, December, 2017

भारत और ईरान के बीच ऊर्जा संबंधों में धीमी प्रगति और असहमति का इतिहास है। परन्तु भारत ने कभी भी ईरान के साथ अपने सम्बन्धों में खटास नहीं की है साथ ही यह ईरान के विभिन्न क्षेत्रों में भारत नेचुरल गैस की खोज में या उत्पादन में हमेश ही साथ दिया है उदाहरण के लिए भारतीय कंपनी, तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ONGC) फरजाद–बी गैस क्षेत्र को विकसित अर्थात खोज करने में भारत शामिल था, लेकिन 2012 में पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण यह कार्य रुक गया। लेकिन फिर 2016 के अंत में, ईरान ने भारतीय निवेश के लिए विशेष रूप से गैस क्षेत्र शामिल करने पर सहमति व्यक्त की।[14] बाद में यह मौका रूस को दे दिया जिसकी वजह से भारत और ईरान के बीच एक दरार पैदा कर दिया। ईरान ने पहली बार एक तिहाई की कटौती करके जवाबी हमला किया। हालांकि बार–बार असहमति और संबंधों के टूट जाने के बाद जुड़ना काफी समस्या हो जाती है जिसके वजह से अनुबंध नहीं हुआ। मई 2017 में, ईरान ने रूस को फर्जाद–बी गैस क्षेत्र विकसित करने की अनुमति

[14] Taneja, Taneja. (July 11, 2016).“The Reality of India-Iran Ties.” The Diplomat. Retrived on 13 February 2017 from https://thediplomat.com/2016/07/the-reality-of-india-iran-ties/

दे दी। और ईरानी अधिकारियों ने भारत को कहा कि इस क्षेत्र में एक साथ कई विकल्प है जो आप को बाद में उपलब्ध कराई जाएगी और इसके पश्चात दोनों देशों में बातचीत जारी रही।

इसके पश्चात् रूस की तानाशाही को कम करने के लिए ईरानी तेल मंत्री बिजन नामदार जंगानेह ने वियना में आर्गस से बात करते हुए गजप्रॉम के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया।[15] इसी बीच भारतीय फर्मों ने कहा कि वे भी तेल और गैस की संपत्ति खरीदने के लिए कहीं और देख रहे हैं। कुछ समय पश्चात कच्चे तेल की कीमत में बदलाव के कारण दोनों को फिर से संगठित होना पड़ा। यह सौदा प्रस्तावित है कि ईरान भारत को प्रति वर्ष 7.5 मिलियन टन द्रवीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) की आपूर्ति करता है।[16] इसके अलावा, भारत को अपने आप को ईरान–पाकिस्तान–भारत (IPI) गैस पाइपलाइन परियोजना से हटना पड़ा क्योंकि भारत–यू०एस० परमाणु सौदा किया गया था। अर्थात ये चुनौतीपूर्ण प्रकरण आर्थिक संबंधों की जटिल बहुमुँखी प्रकृति को दर्शाते हैं। ये चुनौती कुछ संरचनात्मक बाधाओं को प्रकट करते हैं जैसे कि भारत और ईरान के बीच सौदा करने की प्रवृत्ति साथ ही साथ प्रगति में भारतीय नौकरशाही की सुस्ती और सावधानी ये बाधाएं संबंधों और विश्वास को भी कम करती हैं।

ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने के भारत के प्रयासों के बावजूद भारत–ईरान और अन्य प्रमुख ऊर्जा आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर है। तेल खरीदने के अलावाए दिल्ली अपनी ऊर्जा सुरक्षा को बचाना चाहती है, और इसके लिये यह आपूर्तिकर्ताओं के साथ दीर्घकालिक निवेश कर रही है और राजनयिक सम्बन्ध भी बना रही है।

ईरान के प्रति भारत की नीति हमेशा से ही एक सहयोगात्मक रही है क्योंकि भारत अपनी अर्थवस्था को आगे बढ़ाने के लिए ऊर्जा की जरुरत पूरा करता रहा है।

[15] Iran ropes in Russia's Gazprom for Farzad B gas field, puts pressure on India https://www.financialexpress.com/industry/iran-ropes-in-russias-gazprom-for-farzad-b-gas-field-puts-pressure-on-india/705954/

[16] Nidhi Verma, "ONGC Seeking Oil Assets in Other Regions amid Iran Gas Row," November 2, 2017.

दोनों देशों को अपनी अर्थवस्था को आगे बढ़ाने के किये एक दूसरे को सहयोग प्रदान करना एक जरुरत भी है। भारत वैश्विक शक्ति बनने के लिए अपने पड़ोस से परे अपने रणनीतिक प्रभाव का विस्तार करने के उद्देश्य से अपने आप को विस्तृत किया है। यह संबंध भू–राजनीतिक और आर्थिक हितों से संचालित होता है, जिसका अर्थ है भारत की ऊर्जा, व्यापार और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी तक पहुंच। ईरान भारत के प्रमुख बाहरी ऊर्जा स्रोतों में से एक है। दिल्ली ने प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए, अफगानिस्तान और मध्य एशिया के साथ अपने संबंधों को बढ़ाने और रिश्तों को मजबूत करने के लिए तेहरान के साथ अपने संबंधों का उपयोग करने की मांग की है। इसमें ईरान के चाबहार बंदरगाह में भारत ने निवेश किया है। भारत ने चीनी और पाकिस्तानी क्षेत्रीय प्रभाव को कम करने के लिए तेहरान के साथ अपने संबंधों को बढ़ाने का प्रयास कर रही है (Pethiyagoda, Kadira, 2018)।

अध्याय–चतुर्थ

भारत–ईरान सम्बन्धों के विविध आयाम

भारत–ईरान संबंधों की पिछले कई वर्षों में एक विशेषता रही है। वर्तमान में दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक, राजनीतिक, व्यापारिक एवं सामरिक निकटता बढ़ी हैं, जो दोनों देशो के मध्य पारस्परिक सम्बन्धों का आधार है। वर्तमान परिदृश्य में दोनों ही देश सभी मुद्दों पर आपसी सहमती से विचार–विमर्श करके किसी निष्कर्ष पर पहुॅचते हैं और एक दुसरे के हितों को ध्यान में रखकर आपसी विवादों को सुलझाते है। दोनों देशों के मध्य रिश्तों की शुरुआत मोहम्मद रेजा शाह के शासनकाल (1919–1980) के समय से रही है। समय के साथ–साथ इस रिश्ते को और मजबूत एवं सुदृढ़ बनाने के लिए काफी उतार–चढ़ाव का सामना करना पड़ा। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद शीत युद्ध के दौरान दोनों देशो के मध्य विभिन्न सामरिक मुद्दों पर वैचारिक मतभेद रहे है। जिसकी वजह से कुछ वक़्त दोनों देशों ने एक–दुसरे से दूरी बनाये रखी परन्तु वैश्विक परिदृश्य बदलने से भारत और ईरान एक दूसरे के करीबीनजर आये। भारत और ईरान के बीच वैचारिक मतभेदों की बात करे तो भारत ने जहां गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की वहीं दूसरी ओर ईरान ने अमेरिका का साथ देते हुए पूंजीवाद के सिद्धान्त की वकालत करके अपने देश में औधोगिक क्रांति की शुरुआत की। शीत युद्ध के दौरान वैश्विक स्तर पर दो विचार धाराओं के मध्य टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई। जिसमें पहली विचारधारा पूंजीवाद के समर्थन में थी जिसका समर्थन अमेरिका, ईरान, जापान, इजराइल, दक्षिण कोरिया, पाकिस्तान, मलेशिया और दक्षिण अफ्रीका जैसें देशों ने किया। वही दूसरी तरफ साम्यवादी विचारधारा थी। जिसका समर्थन चीन, क्यूबा, लाओस, वियतनाम इत्यादि देशों ने किया। इस पूरे परिदृश्य में भारत ने गुट–निरपेक्षता की नीति को अपनाते हुए विभिन्न देशों के साथ अपने सम्बन्धों को बनाये रखा। इसी क्रम में भारत–ईरान सम्बन्धों के बीच वैचारिक मतभेद भी यदा–कदा रहे हैं। वैश्विक स्तर पर दोनों ही देश एक दुसरे की आवश्यकता को समझते हुए पुनः आपस में

मिल–जुलकर आर्थिक विकास की ओर अग्रसर हो रहे हैं। उपर्युक्त सन्दर्भ में यह बात विचार करने योग्य है कि ऐसी कौन सी परिस्थिति है जिसकी वजह से दोनों देश एक दूसरे के करीब आये हैं। दोनों ही देश एक दूसरे के विचारों और समस्याओं को समझने और समझाने में एक दूसरे की मदद करने लगे हैं।

भारत ने वर्ष 1991 में उदारीकरण की नीति को देश में लागू किया जिसकी वजह से भारत में तमाम विदेशी कंपनियों ने निवेश किया और भारत में आर्थिक बदलाव हुए इस कारण भारत–ईरान सम्बन्धों में भी निकटता आयी। इसी दौरान वैश्विक स्तर पर विभिन्न बदलाव होने के कारण विश्व एकध्रुवीयता से बहुध्रुवीयता की ओर परिवर्तित हो गया। इससे विश्व के छोटे–छोटे देशों का भी महत्व उभरने लगा था। भारत–ईरान विश्व पटल पर एक नए रस्ते पर चल पड़े और दोनों देश एक दूसरे के महत्व को समझने लगे। भारतीय अर्थव्यवस्था की बढ़ती विकास दर ने भारत–ईरान संबंधों में एक नया अध्याय जोड़ दिया है।

विकास के इसी क्रम में अग्रसर भारत को आर्थिक विकास के लिए अत्यधिक उर्जा की जरुरत है। भारत को उर्जा पूर्ति के लिए ईरान के सहयोग की और ईरान को एक नए बाज़ार की आवश्यकता है। ईरान तेल भंडारण के लिए विश्व में सबसे बड़े तेल निर्यातक देशों में से एक है इसलिए इन परिस्थियों में दोनों देशों को आपस में व्यापार बढ़ाने का अवसर मिला और यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि वैश्वीकरण के कारण इनके मध्य रिश्ते मधुर हुए हैं। मई 2016 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेहरान की यात्रा की, जिसके तहत दोनों देशों के बीच व्यापारिक मुद्दों पर बात हुई और साथ ही भारत–ईरान में चाबहर बंदरगाह विकास और अफगानिस्तान व मध्य एशिया के साथ क्षेत्रीय सड़क निर्माण और रेल संपर्क मार्ग बनाने के लिए 500 मिलियन डॉलर का निवेश करने पर भारत ने अपनी सहमति दी। इसके अतिरिक्त 16 अरब डालर का निवेश करने की एक योजना बनाई जिसमें भारत–ईरान देशों के बीच

मुक्त व्यापार होगा और द्विपक्षीय व्यापार लगभग 13 अरब अमेरिकी डॉलर है इसमें भारत ईरान से लगभग 12 अरब डालर की लागत का तेल आयात करता है।[1]

इस अध्याय में दोनों देशों के बीच राजनीतिक, सामरिक, और आर्थिक इत्यादि विभिन्न पहलुओं को उल्लिखित किया गया है साथ ही दोनों देशों में हो रहे राजनीतिक बदलावों को भी सम्मिलित किया गया है। भारत ईरान संबंधों के विविध आयाम निम्नलिखित हैं किसी देश के साथ अपने संबंधों की एक नई रूपरेखा तैयार करते हैं।

4.1. सांस्कृतिक सम्बन्ध

भारत ने दक्षिण एशिया के बाहर किसी अन्य देश की तुलना में ईरान के साथ यकीनन ऐतिहासिक संबंध बनाए हैं, फिर भी वर्तमान संबंधों पर सांस्कृतिक संबंधों का प्रत्यक्ष प्रभाव मापना मुश्किल है। यद्यपि कुछ कारक ऐसे होते हैं जो भारत–ईरान संबंधों को आकार देने वाले कारकों में प्रमुख माने जाते हैं जैसे–आर्थिक और सामरिक कारक तथापि इसे समझने के लिए एक पृष्ठभूमि और संदर्भ प्रदान करना पड़ता है। भारतीय संस्कृति ने कुछ सिद्धांतों के साथ देश की विदेश नीति को पुनर्जीवित किया है। इनमें बहुलवाद मूल्य शामिल हैं, जो विभिन्न शासन की स्वीकृति, संप्रभुता के लिए सम्मान और अन्य राज्यों के आंतरिक मामलों में गैर–हस्तक्षेप की अनुमति प्रदान करतें है। इससे यह समझने में मदद मिलती है कि भारतीय राजनेता ईरान की राजनीति को कैसे देखते हैं जो सीमित नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के साथ आती है। भारतीय संस्कृति ने इसे धरातलीय स्तर से सहारा दिया साथ ही विदेश नीति की ओर झुकाव और रणनीतिक स्वायत्तता के सिद्धांत में भी मदद की है।[2]

भारत के पहले प्रधानमंत्री, जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा था, *"Among the many people and races who have come in contact with*

[1]India and Iran sign 'historic' Chabahar port deal. (23 May 2016). BBC News. Retrieved on 23 Novermber 2017 from https://www.bbc.com/news/world-asia-india-36356163

[2]Pethiyagoda, Kadira. (2018). *India's Pursuit of Strategic and Economic Interests in Iran*. The Brookings Institution, N.W. Washington, D.C. U.S.A.

Indians and influenced India's life and culture] the oldest and most persistent have been the Iranians."[3] ईरान और भारत के विशाल पठार में आर्यों के बसने से पहले ही इतिहास में ईरानी और भारतीयों के बीच परस्पर यातायात सम्बन्ध था। मीलों दूर और पड़ोसियों से अलग–अलग रहने वाले दोनों देशों ने नियमित जीवन के कई पहलुओं में जातीय संबंधों और लगातार समानता को दर्शाया है। भारत और ईरान के बीच समानताएं समय के साथ परिपक्व हुई हैं क्योंकि भारत के संस्कृत विद्वानों ने भारतीय वेदों और ईरानी जिन्द अवेस्ता के बीच भाषाई समानता को परिभाषित किया है। आज भी ये समानताएं मौजूद हैं जो व्यंजनों से लेकर, कला और मनोरंजन के साथ ही धार्मिक प्रथा को दोनों देशों के बीच साझा करती हैं। भारत का सम्बन्ध पर्सिया (ईरान) से लगभग 2000 ईसा पूर्व का है। 532 ईसा पूर्व में ईरान के सबसे बड़े राजा, साइरस ने उत्तर–पश्चिम भारत पर अधिकार कर लिया और उनके उत्तराधिकारी डेरियस ने पूर्व में अपने क्षेत्र का विस्तार किया। इसके साथ ही आक्रमणकारी अपने साथ अपनी संस्कृति और विभिन्न सामग्री जैसे पालक, पिस्ता, बादाम, अनार, केसर और शीशम आदि लाए। विदित है कि इसी दौरान भारत ने उन्हें चावल से परिचित कराया जबकि भारत के लिए यह स्वदेशी था। अभी भी भारत का चावल ईरान में बहुत प्रसिद्ध है। दोनों देशों में कला और संस्कृति के क्षेत्र में भी समानता है। लद्दाख में अलची मठ की दीवारों पर पेंटिंग आदि सासियान शासन को पुनः परिलक्षित करती हैं। इसके साथ ही दीवारों में पौराणिक जानवरों के साथ गोल पदक दर्शाए गए हैं, जिन्हें ईरानी धर्मग्रंथों में स्पष्ट रूप में परिभाषित किया गया है। फिरोजा रंग जो अब ईरान की अधिकांश मस्जिदों पर देखा जाता है, वह बौद्ध भिक्षुओं द्वारा भारतीय विमानों पर ध्यान के रंग के रूप में उपयोग किया गया था। प्राचीनकाल में ईरानियों द्वारा बनाए गए सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र भारतीय संगीत पर प्रेरक प्रभाव डाल रहे हैं। सूफीवाद पर्सिया और भारत के बीच आध्यात्मिक बातचीत का एक माध्यम था। इस्लाम का सूफीवाद हिंदू धर्म और वेदांत के दर्शन के प्रभाव में आया। हिंदू धर्म ने कुछ इस्लामी तत्वों जैसे–समानता और

[3]Similarities between India and Iran (November 8, 2014). *New Delhi Times*. Retrieved on 21 sep 2016 from https://www.newdelhitimes.com/similarities-between-india-and-iran123/

एकेश्वरवाद को भी स्वीकार किया। कई हिंदू संतों ने इस्लाम और हिंदू धर्म के सिद्धांतों को संयोजित किया। सम्राट अकबर ने भी एक नए धर्म का प्रचार किया जो 'दीन–ए–इलाही' के नाम से जाना जाता है और आधुनिक युग में यह भारत में प्रचलित धर्मों का एक संयोजन है। दोनों देशों के बीच व्यापार का मुख्य रूप से विस्तार हुआ, क्योंकि प्रागैतिहासिक ईरानियों द्वारा प्रस्तुत सिक्के से व्यापर में विनिमय की सुविधा मुहैया करायी गयी। बादाम और अखरोट के साथ पर्सिया से लाए गए अंगूर की खेती पश्चिमी हिमालय में की जाती थी। सिक्के को पहले भारतीय भाषा में करसा कहा जाता था जो कि पर्सिया मूल का शब्द है।

उपरोक्त विभिन्न सम्बन्धों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि भारत–ईरान ने अपनी–अपनी सांस्कृतिक पहचान के साथ एक दुसरे को अपनाया है। यह सम्बन्ध बिना किसी सीमारेखा के साथ शुरू हुआ और निरन्तर चल रहा है। समय–समय पर दोनों देशों में मन मुटाव भी देखा गया परन्तु आपसी हित और भारत की ऊर्जा जरूरतों ने दोनों देशों को अभी तक एक सूत्र में बॉध रखा है। शिया सांस्कृतिक सम्बन्ध देखा जाय तो भारत के लखनऊ शहर में दक्षिण एशिया का एक बहुत बड़ा केन्द्र है। भारत के मुगल शासकों का पारसी प्रेम जग जाहिर है। स्थापत्य कला में ईरानी कला की झलक भारत के प्राचीन ऐतिहासिक भवनों में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। भारत की ऊर्जा जरूरत और ईरान को एक विश्वसनीय मित्र की उनके सम्बन्धों को विश्व में एक अलग पहचान देती है। समय के बदलते पहिये के साथ दोनों के आपसी हितों में बदलाव स्पष्टतः देखे जा सकते हैं जो सम्भवतः प्रकृति के नियम की तरह हैं। दोनों देशों के अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर सहमति–असहमति होतीी रहती है परन्तु इनके सम्बन्धों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है। भारत और ईरान दोनों का विश्व मंच पर मतभेद भले हो परन्तु मनभेद नहीं होना चाहिये। आपसी सम्बन्धों को सुचारू रूप से जारी रखना होगा नहीं तो तीसरा देश इसका गलत फायदा उठा सकता है।

4.2. राजनीतिक संबंध

ब्रिटेन और रूस के बीच सदियों पुरानी प्रतिद्वंदिता के साथ ईरानी रंगमंच में सबसे अधिक ध्यान देने योग्य नई भू–राजनीतिक स्थिति थी। जिसने शुरूआत में भारत और ईरान के बीच संबंधों को प्रभावित किया। ब्रिटिश काल के दौरान कई शताब्दियों के करीबी रिश्तों के बीच सद्भावना और अन्तरग संबंधों को लगभग खो दिया था। ईरान में ब्रिटिश नीतियों के कारण व रूस के साथ व्यापारिक मार्गों और प्राकृतिक संसाधनों में इसकी प्रतिद्वंदिता थी। दोनों देशों के बीच संबंधों को काफी हद तक कमजोर कर दिया गया था। भौगोलिक आत्मीयता का यह नुकसान राजनीतिक क्षेत्र में भी दिखाई दिया, जब ईरान–पाकिस्तान को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया। ईरान ने पाकिस्तान के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए, साथ ही ईरान ने मई 1950 में पाकिस्तान के साथ दोस्ती की संधि पर भी हस्ताक्षर किया। जबकि भारत को समान राजनयिक शिष्टाचार का विस्तार करने में दो साल लग गए। भारत की अपनी कुछ समस्याएं थी जैसे घरेलू और कश्मीर पर संघर्ष इत्यादि। इसी बीच पाकिस्तान को ईरान सहित मध्य पूर्वी क्षेत्र के कई देशों से सहानुभूति हासिल करने में सहायता मिल गयी।

15 मार्च 1950 को भारत और ईरान ने औपचारिक रूप से 'मैत्री संधि' पर हस्ताक्षर के साथ ही राजनयिक संबंध स्थापित किए।[4] यह उल्लेखनीय है कि ईरान के शाह ने पाकिस्तान की यात्रा के दौरान इसी तरह की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। यह भारत और ईरान के बीच भविष्य में द्विपक्षीय संबंधों में पाकिस्तान द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका का एक संकेत था।

1950 के दौरान, साम्यवाद के खतरे का मुकाबला करने और एक मजबूत रक्षा बल का निर्माण करने की अपनी खोज में, ईरान ने खुद को संयुक्त राज्य के नेतृत्व वाले पश्चिमी उपद्रव में दृढ़ता से उलझा पाया। ईरान के शाह मोहम्मद रजा शाह

[4] Ministry of External Affairs, Government of India, Annual Report 1950–51, Retrived on 23 Jan 2016 form http:// mealib.nic.in/reports/1950-51.pdf.

पहलवी ने पश्चिम के देशों के साथ बहुत करीबी सम्बन्ध बनाए, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। नेहरू का स्वाभाविक रूप से समाजवादी विचार धारा की तरफ झुकाव था जिसके कारण दोनों देशों के बीच मतभेद हुए थे। ईरान में भी एक मजबूत धारणा थी कि भारत–सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक (यू0एस0एस0आर0) को समर्थन कर रहा है जिसकी वजह से ईरान–भारत को अपना साथी नहीं मानता था। जबकि भारत ने एक स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई और पाकिस्तान के साथ ईरान भी 1955 में अमेरिका के नेतृत्व वाली बगदाद संधि में सम्मिलित हो गया (Hussain, 2012)। बाद में इसका नाम बदल कर केंद्रीय संधि संगठन या CENTO रख दिया गया। इसके विरोध में नेहरू ने कहा था की भारत को अपना शत्रु मानते है इसलिए वे बगदाद संधि सेंटो में शामिल हो गए हैं।[5]

भारत के दोनों देशों के बीच बेहतर सम्बन्ध बनाने के लिए, उठाए गए कुछ कदम ईरान के साथ सही नहीं साबित हुए। प्रधानमंत्री नेहरू के गामल अब्देल नासर के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध थे और बाद में अरब के नेता के रूप में उनका समर्थन एक ऐसा कारक था जिसने ईरान को संदिग्ध देश बना दिया था। वास्तव में, 1952 की क्रांति के बाद, भारत 1953 में नए मिस्र शासन के लिए राजनयिक मान्यता का विस्तार करने वाला पहला एशियाई देश था।[6] भारत ने किसी भी खेमे में न जा कर अपने आप को गुट से अलग रखा और इसके बाद गुट–निरपेक्ष आंदोलन (एन0ए0एम0) की स्थापना में अग्रणी भूमिका निभाई जिससे दोनों देशों के बीच तनाव पैदा हो गया। भारत के प्रधानमंत्री ने मोहम्मद मोसादेग एंग्लो–अमेरिकन ऑयल कंपनी के राष्ट्रीयकरण का समर्थन किया था लेकिन 1953 में अमेरिका ने इस कम्पनी की राष्ट्रीयकरण की मान्यता रद्द दी। इन मतभेदों के बावजूद, दोनों पक्षों में एक दूसरे के लिए प्रेम–भाव का स्थान बना रहा।

[5] Shah Alam (2004). Iran Pakistan Relations: Political and Strategic Dimensions', Strategic Analysis, 28(4).
[6] El- Din Mursi Saad (2006). Plain Talk. Al Ahram Retrieved on 23 Nov 2016 from http://weekly.ahram.org.eg/2006/780/cu3.htm.

बगदाद समझौते पर हस्ताक्षर करने के मात्र चार महीने बाद फरवरी–मार्च 1956 में शाह ने भारत का दौरा किया।[7] जिसमें भारतीय नेताओं के साथ बातचीत की गयी। अपने सार्वजनिक बयानों में शाह ने दोनों देशों के बीच अंतर का उल्लेख किया लेकिन पारंपरिक संबंधों पर भी जोर दिया। उन्होंने भारत को यह भी आश्वासन दिया कि पाकिस्तान के साथ ईरान के घनिष्ठ संबंधों को न तो इसके खिलाफ निर्देशित किया गया था और न ही वे भारत के साथ ईरान की दोस्ती को प्रभावित करेंगे। हालांकि, यात्रा के अंत में कोई संयुक्त बयान या सूचना जारी नहीं की गई थी क्योंकि दोनों देशों के नेताओं के बीच आम सहमति नहीं बन पायी थी। प्रधानमंत्री नेहरू ने सितंबर 1959 में ईरान की यात्रा की जिसमें दोनों देशों के बीच पारस्परिक सहयोग पर सहमति बनी। हालांकि, इस यात्रा ने दोनों देशों के बीच गहरी खाई को पाटने का काम किया (Ganai & Pandey, 2016)। 1950 के दशक तक दोनों देशों के बीच राजनीतिक और विदेश नीति की आकांक्षाओं और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अवसर बहुत ही कम थे। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि दोनों देशों के बीच ज्यादातर आर्थिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों तक ही सम्बन्ध सीमित रहे जो राजनीतिक दशा को सुधारने के लिए पर्याप्त नहीं थे।

द्विपक्षीय संबंधों में सुधार की गति को बनाये रखने के लिए ईरान की राजनीति को बड़े संदर्भ में समझना होगा। 20वीं शताब्दी के आधे से अधिक समय तक ईरान पहले ब्रिटेन फिर अमेरिका जैसी महान शक्तियों की छाया में फल फूल रहा था। इस देश की भी कई अपनी समस्याएं रही है जिसकी वजह से शाह का अपने देश पर कमान पूरी तरह से नहीं थी। प्रमुख शक्तियों ने ईरान के भाविष्य को अपने तरीके से निर्धारित किया था। यह प्रथा 1960 के दशक के मध्य तक सीमित थी उसके पश्चात शाह ने अपने देश से संबंधित मामलों को एक संप्रभु प्राधिकरण के रूप में व्यहवृत करना शुरू कर दिया था।[8] 1960 के दशक के मध्य में वैश्विक महाशक्तियों ने

[7]The Baghdad Pact (1955) and the Central Treaty Organization (CENTO) January 20, 2009. US Department of State. Retrieved on 23 Feb 2016 from https://2001-2009.state.gov/r/pa/ho/time/lw/98683.htm.
[8] Alidad Mafinezam and Aria Mehrabi (2008). Iran and Its Place among Nations, Praeger, London.

भारत–ईरानी संबंधों के क्रम को प्रभावित किया। कुछ समय पश्चात् ईरान के प्रति अमेरिका के रवैये में एक सूक्ष्म परिवर्तन हुआ जिसकी वजह से ईरान की विदेश नीति में बदलाव आया। अमेरिका ने ईरान को सुरक्षा की पूर्ण गारंटी दी और संकेत दिया कि सोवियत संघ के अलावा किसी अन्य तरह का कोई खतरा होता है तो बिना किसी दबाव में सहायता के लिए खड़ा होना पड़ेगा। इसका परिणाम यह हुआ की अमेरिका ईरान से अपनी सेना हटाने लगा इसके अलावा ईरान ने कथित तौर पर यह महसूस किया की ईरान की कीमत पर तुर्की और पाकिस्तान दोनों को अमेरिका ने छोड़ दिया।[9]

इन वास्तविक परिवर्तनों को ध्यान रखते हुए यह कहा जा सकता है कि ईरान की विदेश नीति का यह एक पुनर्संयोजन था, जिसे शाह ने सियासत–ए–मुस्ताकिल–ए–मिल्ली (स्वतंत्र विदेश नीति) कहा था।[10] इसके बाद ईरान ने अमेरिका के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखते हुए, समर्थन और गठबंधन के लिए फारस की खाड़ी और पाकिस्तान से हट कर देखना शुरू कर दिया। शाह ने भी सोवियत संघ के साथ अपने भू–राजनीतिक संबंधों में सुधार करने के लिए प्रयास तेज कर दिये।

इसके पश्चात सोवियत संघ–ईरान को पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान करने लगा। परिणान स्वरूप 15 सितंबर 1962 में, ईरान को सोवियत संघ की तरफ से यह आश्वासन मिला कि वह किसी भी विदेशी राष्ट्र को ईरान की धरती पर किसी भी तरह के रॉकेट बेस नहीं बनाने देगा।[11] इस घोषणा के बाद, सोवियत–ईरानी संबंधों में पर्याप्त सुधार हुआ। इसने ईरान के साथ–साथ भारत के संबंधों को भी प्रभावित किया। हालांकि 1962 के चीन–भारतीय युद्ध के दौरान ईरान द्वारा भारत को दिया गया समर्थन अयोग्य था। इसने द्विपक्षीय संबंधों में गर्मजोशी लाने में योगदान तो दिया, परन्तु बुद्धिजीवियों के कुछ वर्गों में इस समर्थन को भारत समर्थक झुकाव से अधिक

[9] Farah Naaz, Indo Iranian Relations, 1947–2000. (2008). Institute of Defence Studies and Analyses, New Delhi.
[10] A.H.H. Abidi. (2000). Relations between India and Iran: 1947–1979, in A.K. Pasha (ed.), India, Iran and the GCC States, Manas Publications, New Delhi.
[11] Relation between India and Iran (1947-1989). Retrieved on 23 March 2017 from http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/10680/15/15_chapter%204.pdf

चीन विरोधी रुख के रूप में देखा गया। बहरहाल, मई 1963 में राष्ट्रपति एस. राधाकृष्णन तेहरान की यात्रा पर गए तो ईरान ने भारत को अपनी स्वीकृति प्रदान कि और इसी वर्ष नेहरू ने दूसरी बार ईरान का दौरा किया।[12] द्विपक्षीय संबंधों में यह बढ़ती गर्माहट दोनों देशों के बीचएक नया आयाम था। भारत ने पाकिस्तान की तुलना में ईरान को बड़े आर्थिक अवसर पेश किये।

हालांकि, यह संक्षिप्त अभिव्यक्ति समय से पहले और अल्पकालिक साबित हुई। 1965 में भारत–पाकिस्तान युद्ध के दौरान, ईरान ने पाकिस्तान को मजबूत राजनीतिक और भौतिक समर्थन दिया। भारतीय समकक्ष में लिखे अपने पत्र में, ईरान के प्रधानमंत्री ने भारतीय सेना द्वारा सीमा उल्लघन पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सीमाओं और पाकिस्तान की क्षेत्रीय अखंडता के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की।[13] दोनों देशो के बीच ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को देखें तो भारत–ईरान संबंधों को एक बार पुनः बाहरी घटनाक्रम द्वारा बंधक बना लिया गया। जबकि ईरान के बहु प्रचारित पाकिस्तान रुख को भारतीय प्रतिष्ठा के साथ ठीक नहीं किया गया, फिर भी इस तथ्य की सराहना की गई कि कई अवसरों पर ईरान ने भारत को अपने तेल की आपूर्ति को बाधित नहीं किया था और भारत के साथ बाद के विवादों में पाकिस्तान पर प्रतिबंधात्मक प्रभाव के रूप में काम किया था।[14] बाहरी कारकों ने आने वाले वर्षों में द्विपक्षीय भावनाओं को प्रभावित करना जारी रखा। पाकिस्तान और चीन के बीच बढ़ती नजदीकियों पर ईरान को डर लगने लगा था। नासिर के निधन के बाद भारत से रिश्तों की पुनरावृत्ति दूसरी तरफ पाकिस्तान के कई अरब राज्यों के साथ बढ़ते संबंधों ने भारत और ईरान दोनों देशों को अपनी क्षेत्रीय विदेश नीति को फिर से तैयार करने और पुनर्गठित करने के लिए मजबूर किया।

---

[12] Kashif Mumtaz. Changing Patterns of Iran-India Relations. Institute of Strategic Studies, Islamabad, retrieved on Sep 23, 2017 From http://www.issi.org.pk/old-site/ss_Detail.php?dataId=388.

[13] Ministry of External Affairs, Government of India, Annual Report 1965–66. Retrieved on 30 Oct 2015 from http://mealib.nic.in/reports/1965-66.pdf.

[14] ibid

जनवरी 1969 में शाह की दूसरी भारत यात्रा के साथ ही दोनों देशो में एक नये संबंधों की शुरुआत हुई। इसने भारत की विदेश नीति में एक नए जोश के रूप में आर्थिक सहयोग पर जोर देने की पृष्ठभूमि तैयार की। 1961 में विदेश मंत्रालय में एक आर्थिक विभाजन किया गया था जिसे मित्र देशों के साथ आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने का काम सौंपा गया था। इस नीति का नए भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा सख्ती से समर्थन दिया गया था। उसी समय ईरान अपने औद्योगिक बुनियादी ढांचे का निर्माण और अपनी अर्थव्यवस्था तथा व्यापारिक आधार में विविधता लाने की कोशिश कर रहा था। शाह की यात्रा के अंत में जारी संयुक्त सूचना में भारत के साथ गहरे और व्यापक आर्थिक सहयोग के विचार के साथ उनकी सहमति को दर्शाया गया। जनवरी 1969 में स्थापित आर्थिक, व्यापारि और तकनीकी सहयोग के लिए एक भारत–ईरानी संयुक्त आयोग इस यात्रा का एक परिणाम था।[15]

1970 कि शुरुआत में फिर से द्विपक्षीय संबंधों में गिरावट देखी गई। 1971 में भारत–पाकिस्तान युद्ध की समाप्ति के बाद ईरान ने इस क्षेत्र के माध्यम से अमेरिकी सैन्य आपूर्ति को मदद करते हुए, पाकिस्तान को राजनयिक और सामरिक समर्थन की पेशकश किया था।

ईरान द्वारा अपनाई गई नीति में द्विपक्षीय संबंधों के लिए हानिकारक धारणाएं हैं, लेकिन यह भी बड़े क्षेत्रीय विचारों से प्रभावित थी। मास्को के साथ नई दिल्ली का घनिष्ठ संबंध था और ईरान ने बगदाद के फैसले को प्रभावित किया, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ उसके अपने करीबी संबंध थे। ईरान के बचाव में कहा जा सकता है कि उसने पाकिस्तान का समर्थन किया क्योंकि इस क्षेत्र में शक्ति संतुलन बनाए रखने और क्षेत्रीय अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक होगा। लेकिन तब भी इसने भारत के प्रति बहुत कठोर रवैया नहीं अपनाया और CENTO को सक्रिय करने के लिए पाकिस्तानी दबाव का विरोध किया साथ ही भारत के खिलाफ किसी भी सीधे उकसावे में लिप्त नहीं रहा। बहरहाल युद्ध के बाद कुछ समय के लिए

[15] Retrieved on 23 March 2017 from http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/10680/15/15_chapter%204.pdf

संबंध ठंडे बस्ते में रहें हैं। यह भारत और ईरान दोनों के विदेश मामलों के मंत्रियों द्वारा आदान–प्रदान की गई यात्राओं की एक पहल थी, जिसने द्विपक्षीय संबंधों के लिए सामान्य स्थिति की एक झलक पेश की।

भारतीय विदेश मंत्री स्वर्ण सिंह ने जुलाई 1973 में और फिर फरवरी 1974 में ईरान का दौरा किया जबकि उनके ईरानी समकक्ष अब्बास अली खालतबरी ने दिसंबर 1973 में भारत का दौरा किया।[16] दोनों मंत्रियों ने लगातार भारत–ईरानी संयुक्त आयोग की बैठकों की अध्यक्षता की और द्विपक्षीय संबंधों से संबंधित सभी मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और स्वर्ण सिंह ने अप्रैल–मई 1974 में ईरान की आधिकारिक यात्रा की। इस यात्रा के दौरान अंतर्राष्ट्रीय महत्व, आपसी हित और द्विपक्षीय सहयोग के मामलों पर चर्चा हुई। भारत–ईरान राष्ट्रीय आयोग की पांचवीं बैठक में भाग लेने के लिए नवंबर 1975 में विदेश मंत्री ईरान गए। इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण परिणाम कुद्रेमुख लौह अयस्क परियोजना के अन्वेषणों के लिए $ 630 मिलियन के समझौते को अंतिम रूप देना था। यह दोनों देश आर्थिक और राजनीतिक संबंधों में एक मील का पत्थर साबित हुए था।[17] अन्य महत्वपूर्ण यात्राओं में जून 1977 में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई और फरवरी 1978 में शाह द्वारा की गयी यात्रा थीं। ये उच्च–स्तरीय दौरे सामान्य हित और बहुमुखी आर्थिक सहयोग के मामलों पर केंद्रित थे। इसके साथ ही विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी बात हुई जैसे–मध्य पूर्व में निःशस्त्रीकरण और हिंद महासागर में शांति बनाये रखना इत्यादि। सांस्कृतिक संबंधों के लंबे इतिहास को ध्यान में रखते हुए भारत–ईरानी संबंधों के इतिहास में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए दो पीठ स्थापित करने का निर्णय लिया गया, एक तेहरान में और दूसरी दिल्ली में (Wagay, 2018)

भारतीय और ईरानी नेताओं द्वारा किए गए प्रयासों के अलावा, कुछ अन्य बाहरी कारक थे जिन्होंने द्विपक्षीय संबंधों के विकास को निर्धारित किया। ईरान के लिए,

[16] India and Iran. Retrieved on 23 Sep 2017 from https://mea.gov.in/Portal/ForeignRelation/India-Iran_bilateral_August_2017.pdf

[17] India-Iran Joint Statement during Visit of the President of Iran to India (February 17, 2018) retrieved on 23 Nov 2018 from https://www.mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/29495/india iran+joint+statement+during+visit+of+the+president+of+iran+to+india+february+17+2018

फारस की खाड़ी क्षेत्र में पूर्व–प्रतिष्ठित शक्ति बनने की अपनी महत्वाकांक्षा के साथ, आस–पास के दक्षिण एशियाई क्षेत्र में प्रमुख राज्य के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध आवश्यक थे।

शीत युद्ध की समाप्ति के बाद, सुरक्षा की धारणाओं को मद्दे नजर रखे हुए भारत और ईरान के बीच निकटता आयी। अमेरिका के संबंध अरब देशों के साथ अच्छे होने के कारण ईरान बहुत चिंतित था क्योंकि इसके उत्तर में अस्थिर राज्य हैं परिणामस्वरूप ईरान क्षेत्रीय संबंधों को बढ़ावा देना चाहता था। भारत की मुख्य सुरक्षा दुविधाएं अंतर्राष्ट्रीय दबावों और क्षेत्रीय प्रतिद्वंदियों से पैदा होती हैं। यह सब उनके हितों के अभिबिन्दुता का कारण बना। इसके ऊर्जा व्यापार मार्ग अफगानिस्तान, मध्य एशिया आदि है। भारत और ईरान उच्च स्तर के संपर्कों को बनाए रखते हुए प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव 1993 में ईरान की यात्रा पर गए, यह एक ऐतिहासिक यात्रा के रूप में मानी जाती है। इस यात्रा को ईरान के राष्ट्रपति अकबर हशमी रफसंजानी द्वारा द्विपक्षीय संबंधों में एक नया मोड़ दिया। इसके बाद दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय द्विपक्षीय आदान–प्रदान में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे निरंतर राजनीतिक संपर्कों, प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में आर्थिक वृद्धि में समेकित में सुधार हुआ है। इसके बाद ही भारतीय राष्ट्रपति के० आर० नारायण अक्टूबर 1996 में ईरान की यात्रा पर गए थे लेकिन प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेई 2001 में ईरान की यात्रा पर गए तो इस प्रवृत्ति को स्वर्ण शताब्दी के रूप में सम्मिलित किया गया था।

जनवरी 2003 में राष्ट्रपति खातमी की भारत यात्रा केवल द्विपक्षीय संबंधों के लिए ही नहीं, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता और शांति के लिए एक ढांचे के पुनर्गठन के लिए भी थी। यह एक ऐसा दौर था जब अमेरिकी विदेश नीति की एक तरफा वैश्विक सुरक्षा की सीमाओं को नए सिरे से परिभाषित कर रही थीं, और एशिया में दो प्रमुख महत्वपूर्ण खिलाड़ियों के बीच वार्तालाप हो रहा था। 2003 के गणतंत्र दिवस समारोह में खातमी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करके, भारत ने न केवल ऐतिहासिक रूप से मैत्रीपूर्ण संबंधों को रेखांकित किया, बल्कि एक मजबूत संकेत भी दिया कि ईरान क्षेत्रीय

राजनीतिक और सुरक्षा व्यवस्था में एक साथ खड़ा हुआ है। दोनों पक्षों ने "नई दिल्ली घोषणा" पर हस्ताक्षर किए, जिसने भारत और ईरान के बीच रणनीतिक साझेदारी के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाया।[18] इसके पश्चात ईरानी राष्ट्रपति महमूद अहमद ने 29 अप्रैल 2008 को भारत का दौरा किया, इसी दौरान दोनों पक्षों ने गैस पाइपलाइन और प्राकृतिक गैस परियोजना की प्रगति की समीक्षा की।

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अगस्त, 2012 को तेहरान में आयोजित 16वें गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ईरान गए। इसी दौरान प्रधानमंत्री ने सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खोमैनी और राष्ट्रपति अहमदीनेजाद से मुलाकात की साथ ही दोनों देशो के व्यापरिक और सुरक्षा मुद्दों पर बात हुई। इसके बाद विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने मई 2013 में 17वीं भारत–ईरान संयुक्त आयोग की बैठक (J.C.M) के लिए तेहरान का दौरा किया, साथ ही कुछ समय पश्चात् भारत के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने अगस्त 2013 में नवनिर्वाचित ईरानी राष्ट्रपति हसन रूहानी के शपथ ग्रहण समारोह की अध्यक्षता की।[19]

4.3. आर्थिक सम्बन्ध

भारत और ईरान एक लंबी अवधि से एक आर्थिक संपूरकता को साझा करते रहे हैं जिसके कारण दोनों देशों में द्विपक्षीय संबंध मजबूत हुए हैं। भारत की बढ़ती ऊर्जा मांग और ईरान के ऊर्जा संसाधनों का भंडारण दोनों देशों को प्राकृतिक आर्थिक भागीदार बनाता है। ईरान तेल के सबसे बड़े भंडार के साथ ही दुनिया का चौथा सबसे और प्राकृतिक गैस का दूसरा सबसे बड़ा भंडार होने के कारण भारत के लिए आकर्षण का केंद्र बना। राष्ट्रपति खातमी ने भारत की यात्रा के दौरान कहा था कि भारत–ईरान के सबसे अच्छे ग्राहकों में से एक है, और यहां तक कि इराक के खिलाफ एक अमेरिकी सैन्य हमले के बावजूद भी भारत को अधिक कच्चे तेल की आपूर्ति करने की पेशकश की (Pant, 2004)।

[18] India-Iran Relations Retrieved on 23 March 2017 from https://mea.gov.in/Portal/ForeignRelation/India-Iran_bilateral_August_2017.pdf
[19] Annual Report of the Ministry of the External Affairs, 2013-14 Government of India. New Delhi.

भारत–ईरान दोनों देश कई क्षेत्रों को रेखांकित करते हुए आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों को आगे बढ़ा रहे हैं, हालांकि यह परम्परागत रूप से ईरानी कच्चे तेल के आयात पर हावी रहा है। यहां तक की अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के समय में भी भारत–ईरान के साथ जुड़ता रहा। भारत–ईरान को प्रमुख रूप से चावल, चाय, लोहा इस्पात, कार्बनिक रसायन, धातु, विद्युत मशीनरी, दवाईयां, अन्य खाद्य सामग्री आदि चीजों का निर्यात करता हैं। साथ ही ईरान भारत को निम्न चीजों का आयात करता है जैसे– पेट्रोलियम और उसके उत्पाद, अकार्बनिक / कार्बनिक रसायन, उर्वरक, प्लास्टिक लेख, खाद्य फल, मेवे, कांच और कांच की बनी सामग्री, प्राकृतिक या परिष्कृत मोती, कीमती या अर्ध–स्वच्छित पत्थर आदि शामिल हैं। भारतीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ओ0एन0जी0सी0, आई0ओ0सी0एल0, गेल और एम0आर0पी0एल0 के प्रतिनिधियों के साथ अप्रैल, 2016 में ईरान गए। इस यात्रा के दौरान दोनों देशो के बीच अहम मुद्दों पर चर्चा हुई जिसमे ईरान के तेल मंत्री बिजन नामदार झंगानेह के साथ फरजाद बी से संबंधित मामलों में सम्मलित हुए।[20]

निम्न सारणी में यह देखा जा सकता है की वर्ष 2000–2001 में भारत का आयात 211.23 यू०एस० मिलियन था जोकि वर्ष 2005–06 में 702.46 यू०एस० मिलियन डॉलर और वर्ष 2017–18 में बढ़ कर 11,111.52 यू०एस० मिलियन डॉलर हो गया। वहीं भारत का निर्यात वर्ष 2000–2001 में 226.97 यू०एस० मिलियन डॉलर था जो वर्ष 2005–06 में 1,188.35 यू०एस० मिलियन डॉलर और वर्ष 2017–18 में बढ़ कर 2,652. 37 यू०एस० मिलियन डॉलर हो गया। निम्न सारणी से पता चलता है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सम्बन्धों में निरंतर वृदि हो रही है।

[20]India-Iran Relations. Retieved from https://mea.gov.in/Portal/ForeignRelation/India-Iran_bilateral_August_2017.pdf

तालिका 4.1. भारत–ईरान के आर्थिक संबंध (मूल्य यू० एस० मिलियन डॉलर में)

वर्षों	आयात	निर्यात
2017-18	11,111.52	2,652.37
2016-17	10,506.51	2,379.61
2015-16	6,278.75	2,781.51
2014-15	8,955.02	4,175.06
2013-14	10,307.16	4,971.35
2012-13	11,594.46	3,351.07
2011-12	13,790.16	2,411.33
2010-11	10,928.21	2,492.90
2009-10	11,540.85	1,853.17
2008-09	12,376.77	2,534.01
2007-08	10,943.61	1,943.92
2006-07	7,618.55	1,446.48
2005-06	702.46	1,188.35
2004-05	410.21	1,231.39
2003-04	266.82	918.11
2002-03	258.30	654.73
2001-02	283.82	253.03
2000-01	211.23	226.97

Source: Government of India] Ministry of Commerce &Industry Department of Commerce

इसके साथ ही दोनों देशों के बीच विभिन्न आर्थिक पक्ष को मजबूत करने के लिए कई प्रयास किये गए। पश्चिम एशिया और खाड़ी देशों के साथ गहन उच्च–स्तरीय सम्बद्धता की एक श्रृंखला को शामिल करते हुए, ईरानी राष्ट्रपति हसन रूहानी 15–17 फरवरी 2018 में भारत की यात्रा पर आये और इस क्षेत्र में अपनी रणनीतिक स्थिति को मजबूत करने के, साथ ही अपनी सुरक्षा और क्षेत्रीय प्रासंगिकता को बढ़ाने के लिए दोनों देशो के बीच सहयोग प्रदान करने पर सहमति व्यक्त किया। इस यात्रा में भारत और ईरान ने नौ समझौतों पर हस्ताक्षर करके अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया। उनमें से यह मुख्य रूप से आर्थिक साझेदारी व चाबहार बंदरगाह को भारत से जोड़ने, तथा दोहरे कराधान से बचाव, इत्यदि दोनों पक्षों ने 2008 में

हस्ताक्षर किए थे। इसके साथ ही स्वास्थ्य, चिकित्सा, कृषि की पारंपरिक प्रणालियों और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग तथा व्यापार उपायों पर एक विशेषज्ञ समूह की स्थापना भी शामिल हैं (Chaudhury, 2018)।

4.4. क्षेत्रीय सहभागिता

भारत व ईरान दोनों देश क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि दोनों देशों के बीच क्षेत्रीय संपर्क न होने के कारण आपस में व्यापार करने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके लिए दोनों देशों ने अफगानिस्तान को भी शामिल करने का फैसला लिया जिसे एक पक्षीय समझौता माना जाता है। इसके साथ ही भारत ईरान में स्थित चाबहार बंदरगाह पर भी अपना ध्यान आकर्षित कर रहा है। चाबहार बंदरगाह भारत के लिए स्त्रातेजिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बंदरगाह के द्वारा पश्चिम एशिया एवं यूरोपीय देशों के साथ–साथ मध्य एशियाई देशों से भी अपना संपर्क जोड़ सकता है। साथ ही भारत अपने व्यापारिक सम्बन्धों को आसानी से विश्व के विभिन्न देशों के साथ जोड़ सकता है। इस संपर्क मार्ग को जोड़ने के लिए भारत सरकार ने सड़क परिवहन और राजमार्ग, नौवहन, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्री नितिन गडकरी ने 6 अप्रैल 2015 को दक्षिण–पूर्वी ईरान, ओमान की खाड़ी पर स्थित चाबहार बंदरगाह के विकास के लिए एक समझौत पर हस्ताक्षर किये। ईरान के खिलाफ पश्चिमी प्रतिबंध अभी तक नहीं उठाए गए इसके साथ ही गडकरी ने बताया कि नई दिल्ली ईरान के बंदरगाहों, रेलवे परियोजनाओं में योगदान देने के लिए इच्छुक है और आशा व्यक्त किया की चाबहार बंदरगाह दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को बढ़ाने में मदद कर सकता है। निम्न मानचित्र–1 में यह दिखाया गया है कि भारत ईरान के बंदरगाह द्वारा विश्व के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़कर अपना क्षेत्रीय संपर्क मार्ग दिन–प्रतिदिन बढ़ा रहा है।

चित्रः 4.1 क्षेत्रीय संपर्क मार्ग

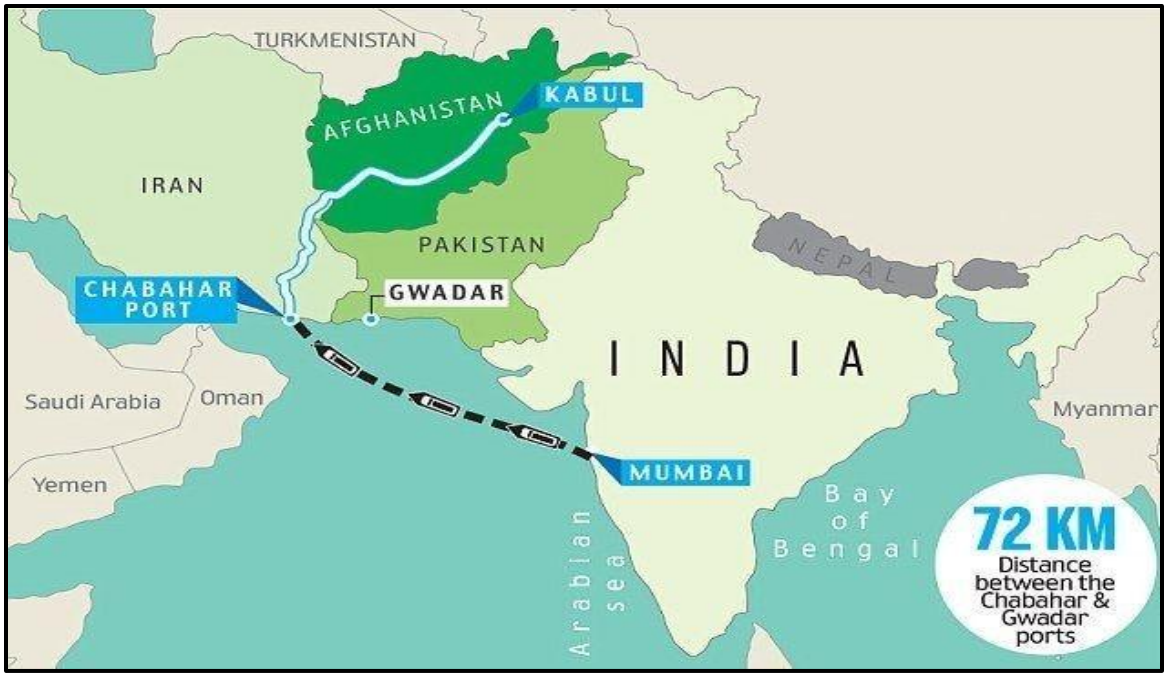

Source: India Toda, Chabahar port begins commercial operations: Why Iran's port is important for India

भारत के बाहर बंदरगाहों को विकसित करने की इस परियोजना की पेशकश ईरान के राष्ट्रपति द्वारा 2003 में की गई थी। यह रास्ता फारस की खाड़ी से हो कर गुजरता है तथा जलडमरू के मुहाने पर स्थित है। अफगानिस्तान के लिए यह एक महत्वपूर्ण पक्ष प्रदान करता है, इससे अफगानिस्तान को पाकिस्तान के रास्ते नहीं जाना पड़ेगा।

यह बंदरगाह विकास परियोजना बाद में ईरान के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच में नहीं आयी क्योंकि पी 5+1 परमाणु मुद्दे पर एक निर्णय निर्णायक वार्ता इस साल के अंत में ईरान पर पश्चिमी प्रतिबंधों को हटाने में होगी और पहले से ही व्यापारी धारणाएं तेहरान अदालत में शुरू हुई है।[21] ईरान सरकार ने चाबहार में एक परिवहन और औद्योगिक केंद्र विकसित करने के लिए निवेश किया है। साथ ही पोर्ट सिटी के आस–पास आने वाली बुनियादी सुविधाओं में निवेश करने के लिए बहुत उत्सुकता व्यक्त की।

[21]An Effective P5+1 Nuclear Deal with Iran and the Role of Congress. *Arms Control Association*. Retieved on 23 Feb 2018 from https://www.armscontrol.org

ईरान ने संपर्क मार्ग को बढ़ाने के लिए भारत और खाड़ी क्षेत्र के बीच एक पुल बनाने की पेशकश की है। ईरानी विदेश मंत्री एम० डी० जवाद जरीफ ने रायसीना डायलॉग में भाषण देते हुए कहा कि ''उनका देश, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर–दक्षिण परिवहन गलियारे की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जो की भारत और खाड़ी देशों के बीच संपर्क गलियारा भी हो सकता है''(Chaudhury, Jan 10, 2019)।

ईरान का बंदरगाह कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय गलियारों में से एक है जो पूर्व पश्चिम, उत्तरएवं दक्षिणी गलियारों और ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में से एक माना जाता है। यह स्वतंत्र राज्यों के बीच स्थित अफगानिस्तान को गोल्डन गेट के रूप में संदर्भित करता है। चाबहार बंदरगाह एक अत्यधिक क्षमता वाला केंद्र रहा है एवं दक्षिण एशिया, मध्य पूर्व, मध्य एशिया और अफगानिस्तान को जोड़ने की क्षमता रखता है। इसके साथ ही उसके साथी एशिया और यूरोप को जोड़ने वाले मुख्य लाइन शिपिंग मार्गों के करीब है।

भारत, अफगानिस्तान तथा ईरान के अधिकारियों के बीच एक त्रिपक्षीय बैठक हुई जिसके तहत ऊर्जा संपन्न ईरान के दक्षिणी तट के सिस्तान–बलूचिस्तान प्रांत में रणनीतिक चाबहार बंदरगाह के संचालन का काम भारत ने संभाला है। यह एक पहल है जिसमें भारत अपने क्षेत्र के बाहर एक बंदरगाह का संचालन करेगा। नौवहन मंत्रालय ने कहा की भारत सरकार ने 24 दिसंबर, 2018 को चाबहार त्रिपक्षीय समझौते की बैठक के दौरान ईरान में शहीद बेहेश्टी बन्दगाह के एक हिस्से का संचालन किया जो चाबहार में आता है।[22] चाबहार बंदरगाह के पहले चरण का उद्घाटन दिसंबर 2017 में ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने किया। जिसमें भारत, अफगानिस्तान और ईरान, को जोड़ने वाले एक नए सामरिक मार्ग का शिलान्यास किया गया।

[22]Chabahar Port Begins Commercial Opertion: why Iran's Port is Important for India. *India Today*. Retieved on 23 Nov 2016 from https://www.indiatoday.in/education-today/gk-current-affairs/story/india-takes-over-operations-chabahar-port-iran-importance-1426057-2019-01-08

4.5. भू–राजनीति व सामरिक आयाम

राज्य के व्यवहार में भू–राजनीति हमेशा अपने पड़ोसी देशों के साथ एक अभिन्न विचार रखते हैं, और भारत–ईरान संबंध कोई अपवाद नहीं है। भू–राजनीति एक देश को दूसरे देश से जोड़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जिसके द्वारा दोनों देशों के सम्बन्धों और व्यापार में सहज भूमिका निभाता है। भारत और ईरान के भू–राजनीति में पाकिस्तान एक बाधा रहा है जिससे ईरान और भारत की बहुत कोशिशें के बाद भी आपसी सम्बन्ध नहीं सुधर सके जबकि ईरान ने पाकिस्तान को समय समय पर मदद भी की लेकिन पाकिस्तान और ईरान के बीच अब उस तरह का विश्वास गायब हो गया है।

हालाँकि पाकिस्तान को ईरान के विरोधी के रूप में नहीं देखा जाता है, क्योंकि ईरान, पाकिस्तान के सुन्नी कट्टरपंथियों से चिंतित है। यह भी एक तरह का इस्लामिक कट्टरवाद हैं आतंकवादियों का समर्थन करता है और भारत में जिहादी को भेजता है।[23]

भारत और ईरान ने इस धारणा को एक दूसरे के साथ साझा किया कि पाकिस्तान कट्टरपंथी तालिबान के माध्यम से पूरे अफगानिस्तान क्षेत्र में स्थिरता के लिए खतरा पैदा कर रहा है। जो किसी राज्य की राजनीति में नहीं है जबकि पाकिस्तान ने तालिबान शासन को मान्यता दे दी है।[24] वहीं भारत और ईरान ने तालिबान के साथ कभी राजनयिक संपर्क स्थापित नहीं किया।[25] भारत और ईरान दोनों ने मिलकर रूस के साथ तालिबान में उत्तरी गठबंधन का विरोध किया लेकिन नवंबर 2001 में अफगानिस्तान में अमेरिकी मदद से कट्टर इस्लामिक ने शासन को प्राप्त कर लिया। भारत और ईरान ने आतंकवाद और सुरक्षा पर एक संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया, जिसका मुख्य उद्देश्य अफगानिस्तान में

[23]"Geopolitics Binds India, Iran"January 27, 2003. Times of India New Delhi.
[24]For Pakistan's reasons in supporting the Taliban, and the movement's impact on Pakistan's foreign policy, see Kenneth Weisbrode, "Central Eurasia: Prize or Quicksand?" Adelphi Paper 338(London: International Institute for Strategic Studies, 2001).
[25]For background on Iran's relations with the Taliban, see Amin Saikal, "Iran's Turbulent Neighbor: The Challenge of the Taliban," Global Dialogue.

अल–कायदा की गतिविधियों पर खुफिया जानकारी साझा करना है।[26] दोनों देश अफगानिस्तान में एक स्थिर शासन चाहते हैं, जो न केवल देश की जातीय और सांस्कृतिक विविधता का पूर्ण प्रतिनिधित्व करे, बल्कि यह आर्थिक विकास और सामाजिक स्थिरता के मार्ग का नेतृत्व करने में भी सक्षम हो, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा भी बनी रहे। ऐसा भी मना जाता है की दोनों देशों के बीच समझौते हुए हैं ये भारत और पाकिस्तान के साथ तनाव की स्थिति में और अन्य किसी भी प्रकार की स्थिति में ईरानी सैन्य ठिकानों का उपयोग करने की अनुमति देगें।

यह रणनीतिक समझौता, जनवरी 2003 की खातमी की भारत यात्रा से एक सप्ताह पहले हस्ताक्षर किया गया था, यह समझौता दोनों देशों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस समझौते से भारत–पाकिस्तान के राजनीतिक घेराव का सफल प्रयास हो रहा है। वहीं ईरान के लिए, यह समझौता क्षेत्र में सैन्य और राजनयिक कद को बढ़ने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।

पश्चिम एशिया और खाड़ी के साथ गहन उच्च–स्तरीय जुड़ाव की एक श्रृंखला को शामिल करते हुए, ईरानी राष्ट्रपति हसन रूहानी ने भारत की यात्रा 15–17 फरवरी 2018 में की जो इस क्षेत्र में अपनी रणनीतिक स्थिति को मजबूत करना और क्षेत्रीय प्रासंगिकता को बढ़ाने के लिए एक अहम कोशिश रही है।[27] इस यात्रा के दौरान भारत और ईरान ने नौ समझौतों पर हस्ताक्षर करके अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया, साथ ही मुख्य रूप से आर्थिक साझेदारी को जोड़ने के लिए सामरिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए चाबहार बंदरगाह के माध्यम से भारत विश्व के अनेक देशो के साथ अपने सम्बन्ध और अधिक सुधार सकता है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया के चार–दिवसीय यात्रा के दौरान चार देशों के दौरा किया और इस देश की राजनीतिक स्थिति का बारीकी से निरिक्षण किया, जिसमें फिलिस्तीन, यू0ए0ई0, ओमान और जॉर्डन सम्मिलित है। इसी दौरान रूहानी के साथ संयुक्त सम्मेलन, प्रधानमंत्री

[26]India, Iran Join Hands against Al-Qaeda. (Feb 12, 2003). Hindustan Times, New Delhi.
[27]Chaudhury, N. R. (2018). India and Iran: Historical ties attain strategic dimensions. *IDR Indian Defence Review*. Retrived on 11 Feb 2019 from http://www.indiandefencereview.com/india-and-iran-historical-ties-attain-strategic-dimensions/.

मोदी ने अपने भाषण में दोनों देशों के बीच सूफी संबंधों और आतंक से निपटने के लिए संयुक्त दृढ़ संकल्प की बात की। रूहानी ने आतंकवाद को इस क्षेत्र में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक समस्या बताया और कहा कि हमें आतंकवाद की जड़ों से लड़ना चाहिए। जिसके चरमपंथी, हिंसक विचारों को बढ़ावा देने से मुख्य रूप से बौद्धिक और सांस्कृतिक नुकशान होता है। ईरान भारत सहित मित्र देशों के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारे पड़ोसी देश आतंकवाद से मुक्त होने चाहिये। साथ ही भारत और ईरान दोनों अपने करीबी पड़ोसी अफगानिस्तान को शांतिपूर्ण, सुरक्षित, स्थिर, समृद्ध और बहुलतावादी देश के रूप में देखना चाहते हैं।[28]

4.6. विभिन्न क्षेत्रों में भारत–ईरान गठबंधन

भारत और ईरान दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में समय–समय पर गठबंधन हुए हैं, इसके द्वारा दोनों देश आपसी सामंजस्य व वैश्विक मुद्दों को ध्यान में रखते हुए एक दूसरे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तेहरान और नई दिल्ली के बीच राजनीतिक और कूटनीतिक गठबंधन बहुत अच्छी तरह से पाकिस्तान को बंद रख सकता है। भारत स्पष्ट रूप से मुस्लिम दुनिया में पाकिस्तान के प्रभाव को बेअसर करने का इच्छुक है। भारत और ईरान के मिलने से भारत के लिए अपनी सामरिक प्रविष्टि से पाकिस्तान की आपत्ति जनक हरकतों को पराजित करना आसान हो सकता है। साथ ही इस्लामिक मंचों में पाकिस्तान द्वारा समर्थित समर्थन को शीघ्रता से खत्म कर सकता है। इस गठबंधन के आधार पर ईरान का संबंध भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण लगता है और मुस्लिम उम्माह के लिए एक मशाल के रूप में पाकिस्तान की पारंपरिक भूमिका को कम करने की संभावना व्यक्त की जा सकती है।

इसके बदले में भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा ईरान पर हो रहे कुपित स्थिति से बचने में ईरान की मदद करेगा। भारत को यह लाभ पाने से रोकने के लिए

[28]India, Iran Sign Nine Agreements, Agree to Stop Terror Forces (17 February 2018). The Pioneer. Retrieved on 4 may 2019. https://www.dailypioneer.com/2018/top-stories/india-iran-sign-nine-agreements-agree-to-stop-terror-forces.html

पाकिस्तान ने भरपूर कोशिश की। उसके संयुक्त राज्य अमेरिका से अपनी निकटता को बनाए रखने की कोशिश हो रही है। जिससे भारत और ईरान की बढ़ती निकटता को प्रभावित किया जा सके, और अपनी सहानुभूति हासिल की जा सके।

भारत–ईरान संबंध अफगानिस्तान और मध्य एशिया को सीधे प्रभावित करना चाहता है, ताकि तेहरान और नई दिल्ली के किसी भी फैसले पर विशेष रूप से पाकिस्तानी प्रभाव को सीमित किया जा सकें। दोनों देश अफगानिस्तान में सहायता प्रदान कर रहे है और काबुल में करजई सरकार से जुड़े हुए हैं। नई दिल्ली के साथ अपने समझौते के तहत, ईरान ने भारत को अफगानिस्तान के लिए एक भूमि मार्ग की अनुमति दी है जिसे पाकिस्तान ने भारत के परिप्रेक्ष्य में लम्बे समय से बाधित किया हुआ था। भारत–ईरान की इस पहल का प्रभाव स्पष्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका, अफगानिस्तान में हर दूसरे तरीके से हावी है लेकिन जब अमेरिका अपनी वापसी कर लेता है तो प्रत्येक देश अपने हितों को आक्रामक रूप से पूरा करने की कोशिश करेंगे। भारत और ईरान के बीच एक गठबंधन अवसर का लाभ उठाने के लिए एक समन्वित रणनीतिक के ढाँचे की जरूरत है। इस घटना का सामना करते हुए, पाकिस्तान ने उदारवादी तालिबान को शामिल करने की अपनी मांग को करजई के मंत्रिमंडल में उठाया, क्योंकि यू.एस. शायद अपने हितों के लिए सहमत होगा।

अध्याय पंचम

भारत–ईरान संबंधों में अमेरिका की भूमिका का परीक्षण

भारत–ईरान सम्बन्धों के लिए किसी पहचान की जरूरत नहीं है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि भारत–ईरान ऐतिहासिक रूप से घनिष्ठ मित्र हैं परन्तु कुछ वर्षो में इस घनिष्ठता में सेंध लग गई है। इस मित्रता में सेंध लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि पूँजीवादी देश अमेरिका है, जिसकी आँख की किरकिरी ईरान है जो भारत–ईरान सम्बन्धों को खत्म कराना चाहता है। शीतयुद्ध के पहले और शीतयुद्ध के बाद भी ईरान से बहुत अच्छे सम्बन्ध रहे हैं, वहीं अमेरिका से भारत के सम्बन्ध उतने अच्छे नहीं थे क्योंकि भारत ने जब पहली बार परमाणु परीक्षण (1974) किया[1] तो विश्व की सारी शक्तियाँ भारत के खिलाफ हो गईं जिसमें अमेरिका भी शामिल था। अमेरिका ने भारत पर कड़े आर्थिक प्रतिबन्ध लगा दिया। जिसकी वजह से भारत–अमेरिका के सम्बन्धों में निष्ठुरता पैदा होती गई। वर्तमान में भारतीय विदेश नीति–निर्माताओं की कोशिश है कि ईरान के साथ अपने सम्बन्धों को सन्तुलित करने के साथ ही साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपनी निकटता बढ़ती रहे। इस अध्याय में भारत– ईरान संबधों पर अमेरिका की बढ़ती भूमिका का विस्तृत विश्लेषण किया गया है साथ ही इस बात का भी जिक्र किया गया है कि अमेरिकी हस्तक्षेप से इन देशों के आपसी संबंधों पर क्या प्रभाव हुआ है? भारतीय संदर्भ में विश्लेषण करने से पहले, भारत–अमेरिका संबधों का विकासक्रम का विश्लेषण करना जरुरी है।

भारत–अमेरिका के मध्य द्विपक्षिय सम्बन्धों की शुरूआत आज से लगभग 70 साल पहले हुई थी। अमेरिका की यात्रा करने वाले भारत के प्रथम प्रधानमन्त्री पं० जवाहर लाल नेहरू थे। 1949 में नेहरू अमेरिका गये और हैरी टूमैन से मुलाकात

[1] Chakma, B. (2005). Toward Pokhran II: Explaining India's Nuclearisation Process. *Modern Asian Studies*, *39*(1), 189-236.

की।[2] इसके बाद 1956, 1960, 1961 में यात्राएँ की। 1959 में अमेरिका के राष्ट्रपति ड्रवाइट डी आइजहावर भारत का दौरा करने वाले अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। उन्होंने भारत के राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद, प्रधानमंत्री पं० जवाहर लाल नेहरू से आइजनहावर ने मुलाकात की तथा भारतीय संसद को सम्बोधित भी किया। 1960 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में पुनः नेहरू और आइजनहावर से मुलाकात हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व दो गुटों में बंट गया–प्रथम गुट जिसका नेतृत्व पूँजीवादी विचारधारा का पोषक अमेरिका कर रहा था एवं दूसरा गुट साम्यवादी विचारधारा का पोषक सोवियत संघ रूस कर रहा था। आजादी के उपरान्त भारत के सम्मुख प्रमुख समस्या थी कि वह किस गुट के साथ जाये पूँजीवादी या साम्यवादी। साम्राज्यवादी एवं ब्रिटिश उपनिवेशवादी व्यवस्था के प्रभाव का भारत के पास एक लम्बा अनुभव था अतः भारत के लिए पूँजीवादी गुटों से जुड़ना मुनासिफ नहीं था। वहीं दूसरी तरफ नवीन आजादी मिलने के कारण भारत के पास इतने संसाधन नहीं थे कि वह साम्यवादी व्यवस्था को अपना सके, साथ ही भारत के पास एक सुनहरा अवसर था कि वह साम्राज्यवादी एवं ब्रिटिश उपनिवेशवादी व्यवस्था से स्वतंत्र विषेशकर एशिया में एक नयी विदेश नीति का श्रीगणेश करें। इन नव उदित देशों के हित में हो अतः भारत ने गुटनिरपेक्ष नीति का पालन करने हुए अपने प्रति विश्व के नवसृजित देशों के आर्कषित करते हुए संसार में अपनी द्विपक्षिय संबंधों का मजबूत किया। किन्तु 1990 के दशक में सोवियत संघ के विघटन के कारण एक ध्रुवीय व्यवस्था के उदय का इसकी प्रासंगिकता पर भी प्रश्न उठाया जाता रहा है। भारत तथा अमेरिका का संबंध आरम्भ से ही उतार–चढ़ाव या दुविधापूर्ण रहा है, कभी भारत–चीन युद्ध के संबंध में तो कभी भारत–पाक युद्ध, तो कभी भारत–बांग्लादेश एवं भारत परमाणु परिक्षण को लेकर।[3] 1962 में भारत–चीन के बीच युद्ध छिड़ गया उस समय भारत के पास रक्षा सामग्री चीन के अपेक्षा बहुत कम थी। युद्ध की स्थिति को देखते हुए प्रधानमन्त्री नेहरू ने अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को खत लिखकर मैकमोहन रेखा को ''सीमा रेखा' मानने का अनुरोध किया था। सर्वपल्ली राधा कृष्णन अमेरिकी यात्रा (जून 1963) करने वाले

[2] India-USA: A friendship that began way back then. (September 26, 2014). Retrieded on 23 November 2018 from https://www.rediff.com/news/special/modi-in-us-india-usa-a-friendship-that-began-way-back-then/20140926.htm
[3] Hkkjr&vesfjdk lEcU/k % bfrgkl ds vkbus esa&BBC News fgUnh] i`0la0 2

भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। 1963 में ही अमेरिका के कृषि विशेषज्ञ नॉरमन बोरलॉग भारत की यात्रा पर आये और भारतीय वैज्ञानिक एम0एस0 स्वामीनाथन से मुलाकात किए इसके बाद ही भारत में 'हरित क्रान्ति' का बीज पड़ा जिससे एक दशक के अन्दर ही भारत खाद्यान्न संकट से उबरते हुए आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ने लगा।[4] इसके बाद 1966, 1971 में श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने अमेरिका की यात्रा की। 1971 में भारत–पाकिस्तान का तीसरा युद्ध हुआ, जिसमें अमेरिका कहीं न कहीं पाकिस्तान की तरफ झुका हुआ था जिसका नतीजा था कि अमेरिका चीन के साथ निकटता दिखाते हुए मध्यस्थ की भूमिका निभाते हुए पाकिस्तान का ही सहयोग किया।

शीतयुद्ध काल में गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन करते हुए भारत ने सोवियत संघ के साथ 20 वर्षें के लिए 'दोस्ती और सहयोग' सन्धि पर हस्ताक्षर किये यह सन्धि गुटनिरपेक्षता की नीति से एकदम उलट कदम था।[5] सर्वविदित है कि अमेरिका और सोवियत संघ एक दूसरे के कट्टर शत्रु थे जब तक कि सोवियत संघ का विघटन (1991) में नहीं हो गया। वर्तमान में भारत–अमेरिका न केवल राजनीतिक बल्कि रक्षा क्षेत्र के साथ–साथ सामरिक आयुध का बाजार आदि प्रमुख संबंध आगे बढ़ रहा है

5.1 शीतयुद्ध के दौरान भारत–ईरान संबंध और अमेरिका

स्वतंत्रता के बाद भारत में गुटनिरपेक्ष रहने की घोषणा की, इससे भारत के साथ अमेरिका के संबंधों में तनाव आने लगा। शीत युद्ध के दौरान विश्व दो गुटों में बँट गया था और अमेरिका का यह कहना था कि जो उनके साथ नहीं है वह देश हमारे विरुद्ध है। पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मिलकर सैन्य सामग्री हासिल किया जबकि अमेरिका यह बखूबी जानता था कि पाकिस्तान सैन्य सामग्री का इस्तेमाल किसी साम्यवादी देश के विरुद्ध नहीं वरन् भारत के खिलाफ ही कर सकता है। इस तरह अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद करके दक्षिण एशिया में शक्ति

[4] Norman Borlaug : 'Father of the Green Revolution. Retrieved on 17 March 2017 from http://pib.nic.in/newsite/erelcontent.aspx?relid=52671.

[5] वही, पृ0 सं0 4

संतुलन को प्रभावित कर दिया था। जिससे भारत–अमेरिका संबंधों में कटुता और बढ़ गई।

अमेरिका को यह लगता था कि भारत तकनीकी और आर्थिक सहायता पाने के लिए गुटनिरपेक्ष नीति को छोड़ अमेरिकी खेमे में शामिल हो जाएगा परंतु ऐसा नहीं हुआ।

1950 के दशक में अमेरिका के राष्ट्रपति कैंनेडी ने सत्ता संभाला तब लोगों को लगा कि भारत अमेरिका के संबंधों में सुधार आएगा क्योंकि कैनेडी, नेहरू से प्रभावित थे।[6] उन्होंने शीत युद्ध का तनाव घटाने का लगभग प्रयास किया तथा 'पीस कोर' नामक अमेरिकी शांति सेना की स्थापना की। इसके स्वयंसेवकों, ने भारत में आकर अमेरिका के पक्ष में भारतीय जनता के हृदय में स्थान पाने में बहुत योगदान किया।

1979–80 के वर्षों में भारत के पड़ोस में बहुत बदलाव हो चुका था, ईरान में पहलवी वंश समाप्त हो गया था और शिया नेता अयातुल्ला खुमैनी विश्व पटल पर उभर कर सामने आये। ईरान समर्थित कट्टरपंथी आंदोलनकारियों ने अमेरिकी दूतावास को घेर लिया था, अमेरिकी राष्ट्रपति कार्टर सैनिक हस्तक्षेप के बाद भी राजनयिकों को छुड़वाने में असफल हो गए थे, इससे बौखलाये अमेरिका ने बैंकों में जमा ईरानी सरकार के मुद्रा कोष को अपने कब्जे में ले लिया।[7] इस संबंध में अमेरिका चाहता था कि भारत–ईरान को शत्रु मान ले परंतु भारत ने अमेरिका के इस उम्मीद पर पानी फेर दिया। इसी तरह अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान पर सैनिक हस्तक्षेप से भारत और अमेरिका संबंध और तनावग्रस्त होता चला गया वह सर्वविदित है कि ईरान–इराक का लगभग एक दशक खाड़ी युद्ध चला जिसमें अमेरिका ने ईरान का साथ दिया था और यह अमेरिका नीतियों का ही परिणाम था कि सद्दाम को फांसी पर चढ़ा दिया।

[6] U.S-India Relations. Retrieved from https://www.cfr.org/timeline/us-india-relations.
[7] Curtis, G. E., & Hooglund, E. (Eds.). (2008). *Iran: a country study*. Government Printing Office.

5.2. 1971 का भारत–पाकिस्तान युद्ध और अमेरिका

एक तरफ जहाँ भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गाँधी 1971 में बांग्लादेश के शरणार्थी की समस्याओं एवं पाकिस्तानी सैनिकों की क्रूरता को दुनिया एवं अमेरिका को बता रही थीं। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन जो एक औरत के शासन के बजाए अपने चहेते फौजी जनरल याह्या खान का पक्ष लेते रहे वही दूसरी तरफ सोवियत संघ ने भारत को मदद का भरोसा दिया। वैसे यह स्पष्ट था कि अमेरिकी प्रशासन भारत एवं पाकिस्तान दोनों के बारे में कोई अच्छी राय नहीं रखता था, इन्दिरा गाँधी को लेकर नापसंदगी और भी ज्यादा थी, और यह बात तब जगजाहिर हो गई, जब नवम्बर 1971 में पूर्व पाकिस्तान की समस्या को लेकर इन्दिरा गाँधी अमेरिका गई पूर्वी पाकिस्तान की समस्या को लेकर तो राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने हेनरी किसिंजर से इन्दिरा गाँधी के लिए अपमान जनक शब्दों का इस्तेमाल किया। मुलाकात में ही निक्सन ने चेतावनी दी, कि ''अगर भारत ने पूर्वी पाकिस्तान में सैन्य कार्यवाही की हिम्मत की तो नतीजे अच्छे नहीं होंगे।''[8]

किसी और देश के लिए अमेरिका की ऐसी चेतावनी डरा देती परन्तु इन्दिरा गाँधी इस धमकी से जरा भी नहीं घबराई और आखिरकार पाकिस्तान ने पहले हमला कर दिया जिसका भारत नें मुँहतोड़ जवाब दिया। इसी बीच निक्सन ने पाकिस्तान की मदद करने या भारत के खिलाफ कार्यवाही के लिए चीन से सम्पर्क किया क्योंकि निक्सन किसी भी सूरत में ये नहीं चाहते थे कि भारत–पाकिस्तान पर कार्यवाही करें, परन्तु चीन ने निक्सन के मन्सूबों पर पानी फेर दिया। क्योंकि चीन यह मानता था कि पूर्वी पाकिस्तान की स्वतन्त्रता ही एक मात्र विकल्प है। तब इन्दिरा गाँधी पर संघर्ष–विराम के लिए दबाव डाला गया परन्तु इन्दिरा गाँधी ने मना कर दिया इससे निक्सन बौखला गए और अपने सातवें बेड़े को हिन्द महासागर में भेजा परन्तु उनके सामने सोवियत संघ आकर खड़ा हो गया। भारत ने संघर्ष–विराम किया परन्तु भारतीय फौज के ढ़ाका में 17 दिसम्बर 1971 के फ्लैग मार्च के बाद सर्वविदित है कि अमेरिका के सातवें बेड़े के पहुँचने से पहले ही

[8] News 18 Hindi November 19, 2018, 12 :35 PM IST

पाकिस्तान ने 90 हजार सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया और निक्सन देखते ही रह गये। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन इसलिए भी भारत से खफा थे क्योंकि उस समय अमेरिका 'या तो आप हमारे साथ हैं या फिर खिलाफ है' की नीति पर चल रहा था यही वजह थी कि निक्सन और किसिंजर इन्दिरा गाँधी और भारतीयों के बारे में अपशब्द बोल रहे थे जिसे भारतीय जनमानस में उनके खिलाफ रोष व्याप्त हो गया था और 1971 के युद्ध में भारत और अमेरिका के सम्बन्ध बहुत निम्न स्तर पर आ गये थे। राष्ट्रपति निक्सन तो इन्दिरा गाँधी को बिल्कुल भी पसन्द नहीं करते थे। 1971 के बाद जहाँ इन्दिरा गाँधी पूरे विश्व में एक सशक्त महिला बनकर उभरी वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति को अपने कार्यकाल के बीच में ही इस्तीफा देना पड़ा।

5.3. 18 मई 1974 परमाणु परीक्षण और अमेरिकी प्रतिबंध

1971 से ही भारत–अमेरिकी सम्बन्ध रसातल में थे। 18 मई 1974 को भारत द्वारा परमाणु परीक्षण करने के पश्चात सम्बन्ध और निम्न स्तर पर चले गये। इस परीक्षण के विरोध में संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान ने प्रतिबन्ध लगा दिये। अमेरिका–पाकिस्तान की वजह से भारत पर दबाव बनाने की कोशिश में लगा रहता था। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन करने वाला देश था और अमेरिका चाहता था कि भारत उसकी हर बात का समर्थन करें परन्तु भारत ऐसा नहीं कर रहा था। भारत को शक्ति सन्तुलन के लिए परमाणु परीक्षण में बहुत कठिनाई भी आई लेकिन अन्ततः परमाणु परीक्षण करने में भारत सफल हुआ। अमेरिका ने भारत पर अनेक प्रतिबन्ध लगाए परन्तु भारत की आर्थिक स्थिति पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा और अमेरिका ने पांच वर्षों के अन्दर में प्रतिबन्ध हटा लिए[9]

5.4. 1998 में भारत का परमाणु परीक्षण और अमेरिकी प्रतिबंध

11 व 13 मई 1998 को ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा (बुद्ध मुस्कुराए) नाम से सफल परमाणु परीक्षण किया गया था यह परीक्षण इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अमेरिका समेत पूरी दुनिया को इसकी भनक तक नहीं लगी थी। इसे

[9] वही, पृ0 सं0 5

बड़ी ही गोपनीयता के साथ पूरा करना भारतीय वैज्ञानिकों के लिए एक कठिन चुनौती थी उस समय अमेरिका खुफिया एजेंसी सी0आई0ए0 भारत पर कड़ी नजर रख रहा था परंतु भारत ने अमेरिकन सेटेलाइट्स को चकमा देकर परमाणु विस्फोट किया इससे अमेरिका नाराज हो गया क्योंकि भारत परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया था। हालांकि भारत ने हमेशा कहा है कि वह परमाणु बम का परीक्षण शांति के लिए करेगा है परंतु बौखलाए अमेरिका ने भारत पर कई प्रतिबंध लगा दिए लेकिन बाद में यह प्रतिबंध हटा लिया गया था भारत का यह परमाणु परीक्षण दुनिया के लिए उभरती हुई एक परमाणु संपन्न राष्ट्र का उदय था।[10]

5.5 भारत–अमेरिकी संबंध–एक घटनाक्रम

1947 के बाद से शीतयुद्ध की समाप्ति तक भारत–अमेरिका के संबंध उसी धरातल पर थे, जिस धरातल पर भारत–पाकिस्तान, चीन–USSR के संबंध थे। भारत–सोवियत संघ के संबंधों को अमेरिका ने ऐतिहासिक रूप से शीत युद्ध की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में ही देखा था। 1991 से सोवियत संघ के पतन के पश्चात अमेरिका का भारत के प्रति दृष्टिकोण परिवर्तित अवश्य हुआ, परंतु शीत युद्धात्तर काल में भारत के द्वारा अपने परमाणु कार्यक्रम को बंद न करने के कारण भारत–अमेरिका संबंधों में विवाद का एक प्रमुख कारण बना रहा। 1998 में अत्यधिक तनावपूर्ण स्थिति तब उत्पन्न हुई जब अमेरिका ने भारत के परमाणु परीक्षण के पश्चात कडें आर्थिक प्रतिबंध लागू कर दिए थे।[11]

5.5.1 वर्तमान में भारत–अमेरिका संबंध

21वीं शदी में भारत अमेरिका के बीच नई राजनीतिक साझेदारी में बढ़ोतरी होने लगी है दक्षिण एशिया में अमेरिकी हितों के विस्तार के फलस्वरुप भारत उसके लिए अति महत्वपूर्ण बन गया है। 9/11 के बाद दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ युद्ध, वैश्विक आर्थिक मंदी और एशिया में उभरते नए शक्ति केंद्रों के

[10] नवभारत टाइम्स. इंडिया। www.navbharattimes.com visited on 11 May 2018
[11] U.S Department of State. Rerieved on 21 Sep 2018 From https://2001-2009.state.gov/p/sca/c17361.htm

परिदृश्य में अपने संबंधों में आमूलचूल सुधार किये। 2006 में भारत–अमेरिका के मध्य असैन्य परमाणु (123) समझौते के पश्चात अमेरिका ने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश के रूप में मान्यता प्रदान की।[12]

भारत के लिए यह एक बहुत बड़ी कूटनीतिक विजय थी। एशिया में चीन को संतुलित करने के लिए भी अमेरिका, भारत को एक महत्वपूर्ण धुरी मानता है। हाल के वर्षों में भारत–अमेरिकी संबंधों में प्रगाढ़ता आई है, दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और पारस्परिक हितों पर नियमित संवाद स्थापित कर रहे हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत–अमेरिका के लिए जुड़वा देश की संज्ञा दी थी और आपसी संदेहो को दूर करने की बात कही, वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दोनों देश के मध्य द्विपक्षीय संबंध 21वीं सदी की निर्णायक साझेदारी है।[13]

भारत–अमेरिका संबंध वर्तमान में यात्रा करते सहयात्री की तरह हो गए हैं जो अपने–अपने हितों को पूरा करने के लिए एक ही वाहन में यात्रा कर रहे हैं और यह रिश्तों का वाहन पथरीले रास्ते से होकर गुजर रहे हैं, जिसमें आंतरिक विरोध और नकारात्मक तत्व बांधा उत्पन्न कर रहे हैं। यहीं नकारात्मकता आपसी संबंधों में क्षति पहुंचा रही है परंतु यह नकारात्मकता कम करने में भारत–अमेरिका द्विपक्षीय सहयोग ने दोनों देशों के आपसी संबंधों को आगे बढ़ाने का काम भी कर रहे हैं। "भारत–अमेरिका रक्षा साझेदारी का महत्व यह है कि वो एक ऐसे जहाज में सवार हैं जो कायापलट की यात्रा पर है।"[14]

भारत और अमेरिका द्विपक्षीय सहयोग से आर्थिक और रक्षा में कुछ वर्षों से बढ़ोतरी साफ देखी जा सकती है अमेरिकी गृह मंत्री जॉन केरी और वाणिज्य मंत्री पेन्नी प्रिट्जर नए संबंधों को मजबूती प्रदान करने के लिए 22 सितंबर 2015 को भारत अमेरिका कूटनीतिक, रक्षा और राजनयिक संबंधों पर मुहर लगाई।[15]

---

[12] भारत–अमेरिका असैनिक परमाणु ऊर्जा सहयोग संबंधी तथ्य पत्र : 123 समझौता संपन्न करना, (2007), विदेश मत्रालय भारत सरकार।
[13] Ibid
[14] Ibid.
[15] भारत में अमेरिकी दूतावास और वाणिज्य दूतावास (भारत में अमेरिकी राजदूत केनेथ आई जस्टर का भाषण) http://inusembassy.gov./ visited in 11 january 2018.

'भारत–अमेरिका संबंध के बारे में भारत अमेरिकी राजदूत के केनेथ आई. ने अपने भाषण में कहा कि "भारतीय–अमेरिकी विविधता, गतिशीलता, बहुलतापूर्ण लोकतंत्र के साथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता, उद्यम, मुक्त बाजार, मानवाधिकार के मूलभूत मूल्यों को साझा करते हैं। व्यापार, वाणिज्य की स्वतंत्रता तथा अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार विवादों का हल शांतिपूर्ण ढंग से करने में हमारे हित समान हैं यही हमारी मित्रता का आधार है।'[16]

5.5.2 भारत और अमेरिका के बीच 123 असैन्य परमाणु सहयोग समझौता और ईरान

भारत–अमेरिका के बीच 123 असैन्य परमाणु सहयोग समझौता पर जुलाई 2005 में हस्ताक्षर हुए इस समझौते से भारत–अमेरिकी संबंधों की एक नई सामरिक सबंधों की शुरुआत हो गई। सर्वविदित है कि हेनरी हाइड एक्ट 1950 अमेरिका को उन्हीं देशों के साथ परमाणु क्षेत्र में सहयोग (व्यापार) की इजाजत देता है। जिसने व्यापक परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किया हो परंतु भारत ने (सी0टी0बी0टी0) पर हस्ताक्षर किए बिना ही यह समझौता किया। इस समझौते ने कहीं ना कहीं भारत–ईरान संबंधों में कटुता घोलने का कार्य किया है क्योंकि भारत–अमेरिका के साथ रक्षा सहयोग हासिल कर रहा था और दूसरी तरफ ईरान को हासिल न हो इसका अमेरिका के साथ मिलकर विरोध भी कर रहा था।

123 समझौता कहीं न कहीं यह दर्शाता है कि अमेरिका यह नहीं चाहता है कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए ईरान के साथ व्यापारिक संबंध बनाए रखे। 2012 तक भारत–ईरान के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंधों को सही ठहराता रहा, यह अमेरिकी प्रभाव का स्पष्ट प्रभाव दिखाई दे रहा था। परंतु कुछ समय पश्चात भारत ने इस दबाव से उबरते हुए चाबहार बंदरगाह का निर्माण कर दिया यह परियोजना 2012 में शुरू हुई थी जो आज लगभग मूर्त रूप ले चुकी है। इस प्रकार देखे तो भारत–अमेरिका संबंधों में समय–समय पर उतार–चढ़ाव देखने को मिलते रहते हैं।

[16] Ibid.

5.6. शीत युद्ध के बाद भारत–ईरान संबंध और अमेरिका की भूमिका

ईरान–भारत का संबंध, भारत–अमेरिकी संबंधों में एक अड़चन बनकर रह गया है। कई भारतीय विद्वानों ने आरोप लगाया है कि अमेरिका, भारत की ईरान नीति को प्रभावित कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आई०ए०ई०ए०) में ईरान के खिलाफ भारत का वोट और दिसंबर 2010 के भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश, जिसने एशियाई समाशोधन संघ के माध्यम से ईरान को तेल भुगतान करने से रोक दिया। इन मामलों में से प्रत्येक में भारत पर जबरदस्त अमेरिकी दबाव था और भारत की निति पर प्रभाव पड़ सकता था।

भारत इस समय अपनी विदेश नीति के विकल्पों को किस तरह पुनर्गठित करता है। आज यह दीर्घकालिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की गतिशीलता को एक निर्णायक मोड़ पर ले जायेगा, विशेष रूप से पश्चिम एशिया के लिए सामरिक एवं भू–राजनीतिक पारी के संदर्भ में महत्वपूर्ण होगा। भारत धीरे–धीरे विश्व मामलों में अपने बढ़ते प्रभाव के साथ उभर रहा है और यह प्रभाव शक्ति संतुलन में बदलाव के नए अवसरों के साथ–साथ भारत के लिए चुनौतियां भी खोली हैं (पो़रूषोत्तम, 2012)।

भारतीय विदेश नीति आज अपने सर्वश्रेष्ठ समय में है जिसमें शीत युद्ध के बाद से एक बदलाव स्पष्ट देखा गया है। शीत युद्ध के दौरान इसकी विदेश नीति जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा से चलती थी, यह नीति गुटनिरपेक्षता पर आधारित थी, बाद में अपनी विदेश नीति में रणनीतिक स्वायत्तता और स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए सोवियत संघ के साथ खड़ी दिखाई दी थी। इसकी गुटनिरपेक्ष नीति, विदेश नीति के निर्णय लेने की क्षमता पर अधिक प्रभावी दी थी। दो महाशक्तियों द्वारा लगाए गए अवरोधों के बाहर, तटस्थता की तुलना में शीत युद्ध का अंत सुरक्षा से वंचित भारत यूएसएसआर प्रदान किए गए सहायता और आर्थिक संकट ने भारतीय नीति निर्माताओं को आर्थिक और विदेशी नीतियों में अधिक व्यावहारिक बनने के लिए मजबूर किया (पो़रूषोत्तम, 2012)।

शीत युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका के साथ भारत के सम्बन्धों में कई नई अभिव्यक्ति हैं। अमेरिका के साथ भारत की सामरिक निकटता ने ईरान के प्रति भारत की नीति पर पश्चिम का ध्यान केंद्रित किया है। भारत चाहता है कि ईरान के साथ अपने संबंधों को आदर्श रूप से द्विपक्षीय संबंधों के दायरे में बने रहने के लिए किसी तीसरे देश के साथ उसके संबंधों पर कोई असर न पड़े। परंतु ऐसा अमेरिका के साथ अपने रणनीतिक संबंधों के कारण ऐसा नहीं हो पाया। भारत–ईरान संबंध, 2005 में भारत–अमेरिका संबंधों के लिए एक कारक बन गया, जब भारत–अमेरिका परमाणु समझौते पर बातचीत की जा रही थी।

5.7 शीत युद्ध के बाद भारत–ईरान संबंध

भारत–ईरान संबंध अपने सभ्यतागत संबंधों से बहुत आगे निकल गए हैं, तथा दोनों देशों के बीच घनिष्ठ सामाजिक, आर्थिक और सामरिक संबंध हैं। "2003 में, नई दिल्ली और तेहरान ने दिल्ली घोषणा पर हस्ताक्षर कियें और एक रणनीतिक साझेदारी शुरू किया। ईरान कई कारणों से भारत के लिए महत्वपूर्ण हैं। ऊर्जा आपूर्तिकर्ता एवं एक अग्रणी इस्लामिक देश के रूप में जो इस्लामिक दुनिया में पाकिस्तान के प्रभाव का मुकाबला कर सकता है एक ऐसे देश के रूप में जो मध्य एशिया और अफगानिस्तान तक पहुंच प्रदान कर सकता है, जहां भारत दीर्घावधि के लिए बिजली परियोजना शुरू करना चाहता है (पो़रूषोत्तम, 2012)।" शीत युद्ध के दौरान भारत–ईरान ज्यादा नजदीक नहीं थे, ईरान ने अन्य देशों के साथ संबंध बनाकर अपने अंतर्राष्ट्रीय अलगाव को समाप्त करने के प्रयास किए थे और भारत गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन करते हुए भी यू.एस.एस.आर. से प्रभावित था।

शीत युद्ध के बाद में भारत–ईरान ने घनिष्ठ आर्थिक सैन्य संबंध स्थापित किए। दोनों देश ने उत्तरी गठबंधन का समर्थन करके, तालिबान शासन को हटाने के लिए अफगानिस्तान में सहयोग किया। ईरान के लिए भारत परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों का एक प्रमुख बाजार है। ईरान और भारत का एक स्थिर मध्य एशिया का गठन करने में रुचि है। भारत चाबहार के ईरानी बंदरगाह के निर्माण में तथा जारगंज–डेलाराम मार्ग का निर्माण, जारगंज से अफगान–ईरान सीमा पर डेलाराम तक कर रहा है। जिससे ईरान के माध्यम से अफगानिस्तान, यूरोप और मध्य

एशिया में भारतीय वस्तुओं का परिवहन आसान हो जायेगा। भारत ने ईरान के साथ मिलकर चाबहार से रेलवे लिंक भी बनाने की योजना बनाई है। यह परियोजना अफगानिस्तान में भारत की उपस्थिति को मजबूत करने और अफगानिस्तान को समुद्र तक आसान पहुंच प्रदान करने में मदद करेगी, जिससे अफगानिस्तान की पाकिस्तान पर निर्भरता कम हो जाएगी।[17]

ईरान अपने सैन्य आधुनिकीकरण कार्यक्रम में भारत को हथियारों के स्रोत के रूप में देखता है और भारत–ईरान को हथियारों के संभावित खरीदार के रूप में देखता है। ईरान–भारत को पश्चिम के लिए एक संभावित पुल के रूप में भी देख रहा है। हालाँकि, भारत और ईरान के बीच कई मुद्दों पर मतभेद भी हैं। मिसाल के तौर पर, ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी का समर्थन अभी तक नहीं किया है। 9 दिसंबर 2001 में भारत की संसद पर आतंकवादी हमले की ईरान ने, भारत के अनुरोधों के बावजूद निंदा नही किया। ईरान ने भारत–अमेरिका परमाणु समझौते का भी विरोध किया था। शायद यही वजह है जिससे भारत–ईरान संबंध ऐतिहासिक होते हुए भी पूरी तरह स्थिर संबंध नही बन पाया है (Chaudhury, 2018)।

5.8 भारत–अमेरिका संबंध में ईरान एक मुद्दे के रुप में

5.8.1 भारत–अमेरिका संबंध

भारत तथा अमेरिका दोनों देश अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद के शिकार हैं इसलिए आतंकवाद से मुकाबला करने में सहयोग करते हैं। सामान्य हित का एक अन्य क्षेत्र हिंद महासागर है, जहां व्यापारिक मार्गों को सुरक्षित करने में अमेरिका और भारत दोनों की समान दिलचस्पी है। भारत–अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देने वाला अप्रभावी कारक दक्षिण एशिया में चीन का उदय है। भारत और अमेरिका दोनों को इस बात की चिंता है कि चीन कैसे व्यवहार करेगा, क्योंकि यह एक वैश्विक शक्ति में बदलता जा रहा है। हालाँकि दोनों देशों ने चीन से सन्धि की है, और इसके साथ महत्वपूर्ण व्यापारिक संबंध हैं।

[17] https://www.deshbandhu-co-incdn.ampproject.org

भारत के पड़ोस में, दोनों अफगानिस्तान में स्थिरता लाने में रुचि रखते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि यह फिर से आतंकवादियों के लिए पनाहगाह बने। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत का समर्थन किया। जबकि ईरान ने भारत का समर्थन नहीं किया है।[18]

अमेरिका में बढ़ते भारतीय अमेरिकी समुदाय के साथ–साथ व्यापार और आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देते हुए सामाजिक संबंधों ने साझेदारी को और आगे बढ़ाया है। यह भारत–अमेरिकी परमाणु समझौता ही था जिसने वास्तव में भारत–अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को मजबूत किया[19] साथ ही यह समझौता भारत–ईरान के पारस्परिक संबंधों को रसातल में ले जाने का काम भी किया था।

भारत–अमेरिका संबंध भी उनके मतभेदों के बिना नहीं हैं। उदाहरण के लिए, भारत–ईरान संबंध पिछले कुछ समय से एक अथाह गहराई में चलता जा रहा है। अमेरिकी अधिकारियों ने ईरान के साथ भारत के करीबी संबंधों को अमेरिका–भारत संबंधों के भविष्य की सबसे बड़ी बाधा के रूप में बताया जो हमारी रणनीतिक साझेदारी को प्रभावित कर सकता है। भारत–ईरान संबंधों ने अमेरिका के भीतर चिंताएँ बढ़ाई हैं।[20] भारत–ईरानी संबंध कुछ अमेरिकी नीति–निर्माताओं के लिए अमेरिका–भारत रणनीतिक साझेदारी का मूल्यांकन करने के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। इस तरह देखा जाए तो भारत इस समय ईरान और अमेरिका से अपने संबंधों को संतुलन बनाने में लगा हुआ है।[21]

5.8.2. अमेरिका–ईरान संबंध

ईरान आज अमेरिका के सामने सबसे अधिक चुनौती देने वाले देशों में से एक है। अमेरिका, ईरान को अपने राष्ट्रीय हितों के लिए एक बड़े खतरे के रूप में देखता है। सर्वविदित है कि, शीत युद्ध के दौरान दोनों देश सहयोगी थे और ईरान केंद्रीय संधि संगठन (CENTO) में शामिल हो गया था, जिसका उद्देश्य यूएसएसआर को शामिल करना था। परतुं 1979 की इस्लामिक क्रांति और अमेरिकी समर्थक शाह

[18] प्रो0 मो0 बदरुल आलम (फरवरी), भारत–अमेरिका संबंध की ऐतिहासिक समीक्षा और मादीमय अमेरिका, वर्ल्ड फोकस।
[19] Ibid.
[20] नवभारत टाइम्स. इंडिया। Retrieved on 13 November 2018 from www.navbharattimes.com
[21] https://doi.org/10.180/09700161.2012.728867

के पतन के बाद से दोनों देश एक–दूसरे के विरोधी हो गये हैं। इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान–अमेरिका संबंध पर संकट छा गया, जब कई ईरानी छात्रों ने तेहरान में अमेरिकी दूतावास को कब्जे में कर लिया। यही राजनयिक संबंधों के टूटने का कारण बनी और दोनों देशों के बीच संबंध रसातल में चले गये। ईरान– ईराक का युद्ध (1980–1990) जब हुआ था तो अमेरिका ने इराक के साथ खड़ा था जिससे ईरान को अमेरिका से निराशा हाथ लगी।

शीत युद्ध के बाद भी, अमेरिका ने ईरान को 'दोहरी नियंत्रण' की अपनी नीति के माध्यम से शामिल करने का प्रयास किया। अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने अरब–इजरायल की शांति प्रक्रिया में बाधा डालने, आतंकवाद का समर्थन करने और शक्तिशाली हथियार विकसित करने का आरोप लगाते हुए ईरान को अलग–थलग करने की नीति फिर शुरू की। 1995 में, राष्ट्रपति क्लिंटन ने ईरान के साथ काम करने वाली अमेरिकी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे व्यापारिक संबंध टूटने शुरू हो गये। 1996 में, राष्ट्रपति क्लिंटन ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम और आतंकवादी समूहों के समर्थन के बारे में बढ़ती चिंताओं के बीच ईरान पर ईरान–लीबिया प्रतिबंध अधिनियम (ILSA) के तहत प्रतिबंध लगा दिये। इन प्रतिबंधों का नवीनीकरण और विस्तार किया गया है और अब इन्हें ईरान प्रतिबंध अधिनियम के रूप में जाना जाता है। मोहम्मद खातमी के नेतृत्व में क्लिंटन प्रशासन और ईरान ने साथ जुड़ने की कोशिश की, लेकिन ये प्रयास भी विफल हो गया।

अमेरिका–ईरान संबंधों में सबसे बड़ी चुनौती ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। अमेरिका का मानना है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम के बाद से परमाणु हथियारों को विकसित करने के लिए यह एक चाल है। अमेरिका ईरान को परमाणु हथियार क्षमता हासिल करने की अनुमति नहीं देने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। अमेरिका सहयोगी देशों के साथ, ईरान पर अपने परमाणु कार्यक्रम की घोषणा करने के लिए दबाव डाला और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा कठोर कार्यवाही की पैरवी किया है। अमेरिका का मानना है कि एक परमाणु ईरान वाशिंगटन के हितों के खिलाफ मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन को पूरी तरह से बदल देगा और इस क्षेत्र को संभावित रूप से अस्थिर कर देगा। वाशिंगटन ने अक्सर ईरान पर रासायनिक और जैविक हथियार

हासिल करने का आरोप लगाया है परतुं ईरान ने इन आरोपों का हमेशा से खण्डन किया है।[22]

ईरान ने अमेरिका पर लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ताओं और आंदोलनों का समर्थन करके फारस की खाड़ी के स्वायत्ततावादियों का समर्थन करके देश में परेशानी पैदा करने की कोशिश का आरोप लगाया और संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों को लागू करने के अलावा ईरान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अलग–थलग करने का आरोप भी लगाया। इस प्रकार, ईरान–अमेरिकी संबंधों की तुलना की जाये तो अमेरिका का मुख्य उद्देश्य ईरान को विश्व राजनीति में अलग–थलग करने का भी है। अमेरिका के पास दूसरे देशों के द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित करने की कोशिश का पुराना इतिहास रहा है। शीत युद्ध के दौरान यह सोवियत संघ और क्यूबा थे, आज ईरान है। हम भारत–ईरान संबंधों में अमेरिकी प्रभाव को इंगित करने वाले तीन मामलों की विश्लेषण करेंगे।

5.8.3. ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध नवंबर 2018

अमेरिका ने 2015 में ईरान पर प्रतिबंध हटा लिया था, परंतु परमाणु प्रसार के संदेह में नवंबर 2018 में अमेरिका सन्धि से अपने आपको अलग कर लिया और ईरान पर पुनः कड़े प्रतिबंध लगा दिया। जब से अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगाया है तब से ईरान को बीच–बीच में धमकी भी दे रहा है। अमेरिकी सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने सिंगापुर में एक सम्मेलन समारोह में कहा कि ईरान को आखरी बूंद तक निचौड़ा जाएगा।[23] उन्होंने यह भी कहा कि ईरान सरकार इस समय बहुत दबाव में है, और हमारा उद्देश्य ईरान को पूरी निचोड़ देना है, जैसा कि अंग्रेज कहते हैं तब तक निचौड़ो जब तक की गुठली चीखने ना लगे। आगे बोल्टन ने यह भी कहा कि हम प्रतिबंधों को बढ़ाने जा रहे हैं।[24]

इस प्रतिबंध को लेकर ईरान के साथ परमाणु समझौते P5 + 1 में शामिल अन्य देश अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि बाकी के

[22] Ibid
[23] m.novbharattimes.indiatime.com13no.2018
[24] ibid

सदस्य (P5 + 1) समझौते को जारी रखना चाहते हैं। इन देशों का मानना है कि ईरान समझौते के खिलाफ कोई काम नहीं कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र के निरीक्षकों का भी यही मानना है कि ईरान और परमाणु समझौते की शर्तों का पालन कर रहा है। अमेरिकी प्रतिबधों को सिर्फ सऊदी अरब ही समर्थन कर रहा है। ईरान पर कड़े प्रतिबधों से कुछ अन्य देशों को भी छूट दिया है इनमें भारत भी शामिल है। इन देशों में भारत के अलावा जापान, ग्रीस, चीन, इटली, ताइवान, तुर्की और दक्षिण कोरिया है। महत्वपूर्ण बात यह है, कि यह आठ देश ईरान के तेल निर्यात का कुल 75 प्रतिशत तेल का खपत करते हैं इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन देशों पर अमेरिका द्वारा ईरान पर प्रतिबंध लगाने से क्या प्रभाव पड़ेगा?[25] इस समझौते से अमेरिका अलग हो गया है, उसके प्रारूप या समझौते के प्रमुख बिंदु का उल्लेख निम्नलिखित है–

5.8.3.1. ईरान परमाणु समझौता P5 + 1

2015 में ईरान तथा 6 देशों अमेरिका, रूस, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन तथा जर्मनी यूरोपीय संघ के बीच ईरान ने परमाणु समझौता किया, 2018 में अमेरिका इस समझौते से यह कहते हुए बाहर हो गया कि ईरान फिर से परमाणु समझौते का उल्लंघन कर रहा है इससे 2018 में अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगा दिया है।[26]

P5+ 1 का अर्थ है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांच स्थाई सदस्य अमेरिका, चीन, यूनाइटेड किंग्डम, फ्रांस और रूस। जब यह परमाणु समझौता हुआ, तो इससे P5 + 1 एवं के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि इसमें जर्मनी भी था जो संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थाई सदस्य नहीं है।[27]

ज्ञातव्य है कि अमेरिका ने ईरान परमाणु हथियार बनाने का आरोप लगाते हुए समझौते से अपने आप को बाहर कर लिया है।

[25] Sansarloachan.in/Iran-nucleardeal- P5hindi
[26] ibid
[27] https://www.pritfriendly.com/p/g/86ttf4 28 sep 2018

5.8.3.2. ईरान परमाणु समझौता–मुख्य बिंदु

1. समझौते के तहत ईरान द्वारा माध्यम संवर्धित यूरेनियम के अपने भंडार को पूर्ण रूप से समाप्त करने निम्न संवर्धित यूरेनियम (एल0डी0यू0) के भंडारण को 98 प्रतिशत तक कम करने और 13 वर्षों में गैस सेंट्रीफ्यूज की संख्या 2/3 तक कम करने पर सहमति व्यक्त की गई है।

2. इस समझौते के माध्यम से ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर लगाए गए प्रतिबंधों की निगरानी के लिए कठोर तन्त्रों की स्थापना की गई थी।

3. इसके तहत यह प्रावधान किया गया था कि वर्ष 2031 तक के ईरान के अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आई0ए0ई0ए0) के प्रत्येक जांच अनुरोध को स्वीकार करना होगा। ऐसा ना किए जाने की स्थिति में, आयोग बहुमत के आधार पर निर्णय लेते हुए प्रतिबधों को पुनः को आरोपित करने सहित उचित दंडात्मक कार्यवाही कर सकता है।

4. संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा समझौते से बाहर होने का प्रमुख कारण यह है कि यह समझौता ईरान के बैलेस्टिक मिसाइल कार्यक्रम 2025 के बाद इसकी परमाणु गतिविधियों तथा यमन एवं सीरिया में जारी संघर्ष में इसकी भूमिका लक्षित नहीं करता है।

5. वर्तमान स्थिति के अनुसार, परमाणु समझौते को कब तक समाप्त नहीं किया जा सकता है जब तक कि ईरान एवं अन्य हस्ताक्षरकर्ता इसकी प्रतिबद्धताओं से संबंध रहें।[28]

5.8.4 भारत ईरान संबंधों, में भारत–अमेरिका 2+2 वार्ता का प्रभाव

भारत और अमेरिका के बीच पहली बार सितंबर 2018 में 2+2 वार्ता हुई। प्रमुखतः इस वार्ता में दोनों देशों में द्विपक्षीय रक्षा एवं सुरक्षा साझेदारी को मजबूत करने के साथ वैश्विक राजनीति में विशेष सहयोग देने पर बल दिया गया। 2+2 वार्ता में भारत की तरफ से विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और रक्षा मंत्री निर्मला

[28] http://printfriendly.com/ Retrieved on 28 September 2018

सीतारमण और अमेरिका के विदेश सचिव माइक पॉम्पियो, रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस से बातचीत हुई। अमेरिका ने इस वार्ता में भी ईरान से कच्चा तेल के आयात को मुख्य मुद्दा बनाने का प्रयास किया। ज्ञातव्य है कि ईरान से कच्चा तेल आयात करने में भारत शीर्ष देशों में शामिल है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत ने पिछले वर्ष ईरान से लगभग सात अरब डॉलर का तेल आयात किया था। इसी को देखते हुए अमेरिका–भारत पर बहुत दबाव डाल रहा है कि ईरान से कच्चे तेल का आयात बंद करे।[29]

अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि दूसरे देशों से भी वह ईरान से तेल आयात को 5 नवंबर 2018 से अमेरिकी एक पक्षीय प्रतिबंध लग जाएगा, प्रतिबंध के बारे में घोषणा कर दिया है इसलिए ईरान से कच्चे तेल का आयात सभी देश को बंद करना होगा।[30]

इस प्रतिबंध के बाद तेल आयात करने वाले देश क्या करेंगे? इस बात पर चर्चा नहीं की गयी। भारतीय विशेषज्ञों ने इसको हास्यपद बताया, क्योंकि अमेरिका यह चाहता है कि भारत, ईरान से कच्चा तेल आयात नहीं करें वहीं तेल आयात न करने पर जो संकट पैदा होगा उससे निपटने के बारे में न बताकर विचार करने के लिए कहा। प्रतिबंध के बारे में भारत ने कहा है कि इस मामले में बिना दबाव और देशहित में ही फैसला किया जाएगा। ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध से अमेरिका और ईरान का संबंध फिर से कटुता की तरफ बढ़ गया है। हालांकि ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने कहा है कि इस प्रतिबंध से ईरान पर आर्थिक दबाव नहीं पड़ेगा।

2+2 वार्ता के बीच भारत–ईरान चाबहार बन्दरगाह में पेमेंट कैसे हो? इस काम पर लग गए हैं, क्योंकि अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते भारत–ईरान को पूरा भुगतान नहीं कर सकता है। प्रतिबन्धित समय में आधा भुगतान होगा, आधा प्रतिबंध हटने के बाद रुपए में भुगतान के लिए ईरान मान गया है, और वित्तीय लेन–देन को पूरा करने के लिए दिल्ली में ईरान से पासरगाड बैंक और यूको बैंक से बातचीत चल रही है, इससे ईरान पर प्रतिबंध से निपटने में मदद मिलेगी।

[29] Novbharat times (13 Nov 2018) from https://novbharattimes.indiatimes.com
[30] Ibid

भारत में तेल के बदले अनाज फार्मूले पर ईरान से बातचीत चल रही है इससे भारत पर पैसे का भुगतान करने में ज्यादा कठिनाई नहीं होगा, और ईरान को जरूरी सामान भी मिल जाएगा जो भारत से निर्यात होता है। अमेरिकी प्रतिबंधों से छूट मिलने के बाद भारत प्रतिबंध की अवधि में कच्चे तेल का 40–45 प्रतिशत हिस्से का भुगतान भारतीय रुपए में होगा, शेष भुगतान यूरो में होगा। भारतीय रुपए में जो भुगतान होगा उसका उपयोग ईरान चावल, दवाइयां, कपड़ा अन्य खाद्य सामग्री भारत से आयात में कर सकेगा।[31]

अमेरिका नहीं चाहता कि भारत ईरान के साथ संबंध रखे, और वह रूस से 4.5 अरब डालर की लागत से खरीदे जा रहे विमान भेदी प्रक्षेपास्त्र रक्षा–व्यवस्था–टायम्फ–5 के खिलाफ भारत पर प्रतिबंध लगाने का संकेत दे चुका है। ये प्रतिबंध अमेरिका द्वारा पारित 'अमेरिकी के विरोधी–प्रतिस्पर्धियों के प्रतिरोध हुते प्रतिबंध कानून' (सी0ए0ए0टी0एस0ए0–काट्सा) के अंतर्गत लगाए जाएंगे।[32]

निकी हेली ने दिल्ली में कहा कि उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से स्पष्ट कहा है कि भारत ईरान से अपने संबंधों पर पुनर्विचार करें। इसका कारण राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की ईरान के प्रति आक्रामक नीति है, जिस कारण उन्होंने 2015 में राष्ट्रपति ओबामा द्वारा पांच अन्य देशों–चीन, रूस, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के साथ मिलकर ईरान से परमाणु समझौता किया था।[33] ट्रम्प ने अपने चुनाव में जनता से वादा किया था कि वे इस समझौते को रद्द करेंगे, और पांच देशों की असहमति के बावजूद उन्होंने समझौता रद्द कर दिया।

निकी हैले ने दिल्ली में कहा कि ईरान अगला उत्तरी कोरिया होगा, यह अमेरिकी दृष्टि है। परंतु भारत का मानना है कि अगला उत्तर कोरिया पाकिस्तान है, जो प्रतिदिन भारत पर आतंकवादी हमले करता रहता है, आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर चलाता है, खुले तौर पर आतंकी सरगना हाफिज सईद को राजनीति में आने दे रहा है। भारतीय दृष्टि से देखा जाए, तो अमेरिका को पाकिस्तान पर पहले आर्थिक

[31] प्रभा साक्षी तरण विजय 6 जुलाई 2018। www.prabhasakshio.com/ visited on December 2018
[32] ibid.
[33] ibid.

प्रतिबंध लगाने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जो वैश्विक आतंक का सबसे बड़ा अड्डा बनता जा रहा है। लेकिन निकी हेली पाकिस्तान पर महज शाब्दिक बयानबाजी को पर्याप्त समझती है। जिसका यथार्थ में कोई महत्व नहीं होता है।[34]

यह हमारा अधिकार है कि हम अपने मित्र और सहयोगी स्वयं तय करें। भारत की विदेश नीति का सफल पक्ष यह है कि इजरायल, सऊदी अरब और ईरान जैसे देशों के साथ जिनका कोई परस्पर मैत्री संबंध नहीं हैं, भारत के उनसे अच्छे संबंध हैं। अमेरिका, अपने हितों के लिए काम करें, लेकिन अमेरिकी हितों के लिए भारत कभी अपनी विदेश नीति में बदलाव नहीं कर सकता है।

5.9. भारत–ईरान संबंधों में अमेरिका की भूमिका का परीक्षण

अमेरिका ने ईरान पर सख्त आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया है अमेरिका इस मुद्दे पर भारत से 2+2 वार्ता में बात भी कर चुका है। अमेरिका चाहता है कि भारत अपने पुराने मित्र ईरान से कच्चा तेल आयात करना बंद कर दें क्योंकि प्रतिबंध 5 नवंबर 2018 से लागू हो गया है, परंतु भारत ने ईरान से कच्चा तेल लेना फिलहाल बंद नहीं किया है। इस संबंध में अमेरिका ने 6 माह का समय दिया है। 6 माह के अन्दर ही भारत के साथ–साथ अन्य देशों को भी ईरान से कच्चा तेल का आयात बंद करना होगा।[35]

ईरानी अखबार तेहरान टाइम्स में लिखा है कि "साल 2012 से 2016 के बीच ईरान के खिलाफ अमेरिका और यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों के बावजूद ईरान भारत को कच्चा तेल बेचने वाला सबसे बड़ा देश था"[36] परंतु भारत के नजदीकी अमेरिका से बढ़ने पर ईरान–भारत से दूर होने लगा और तेल आयात करने में ईरान छठे नंबर पर आ गया है। यह दूरी कोई आपसी मतभेद नहीं है बल्कि भारत–ईरान की मित्रता के बीच तीसरा देश (अमेरिका) की दखल अंदाजी है। अमेरिकी प्रतिबंध से निःसंदेह ईरान की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ेगा, लेकिन भारत की ऊर्जा जरूरतों पर इसका प्रभाव कितना पड़ेगा, यह विचार करने योग्य

[34] ibid
[35] नवभारत टाइम्स. इंडिया। www.navbharattimes.com visited on 13 November 2018
[36] https://www.bbc-com.cdn.amproject.org

सवाल है, क्योंकि भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए ऊर्जा की महती जरूरत है, और यह जरूरत अभी तक ईरान पूरी करता आ रहा है। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का ईरान परमाणु समझौते से अलग होना निश्चित रूप से भारत के हित में नहीं है। इसमें केवल अमेरिका का ही हित नजर आ रहा है क्योंकि अमेरिका चाहता है कि भारत–ईरान से तेल आयात बंद करके उससे तेल आयात करे। यह आयात रुपया में नहीं डॉलर में होगा जबकि भारत–ईरान को रुपया, रुबल या यूरो में भुगतान करता है।[37]

भारत ने अमेरिकी प्रतिबंध को अभी ज्यादा महत्व नही दिया है, परंतु भारत को दोनों देशों के बीच संतुलन बनाकर चलना होगा, नहीं तो भारत अमेरिकी संबंधों के बीच, भारत एक परममित्र को खो देगा।

भारत का अमेरिका के साथ संबंध शीत युद्ध के बाद से थोड़ा चलना शुरू हुआ या यूं कहें कि वर्ष 2006 में भारत–अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते से दोनों देशों में राजनीतिक रिस्तों का पहिया आगे बढ़ा। भारत में जब अमेरिका से समझौता किया तो ईरान ने ज्यादा विरोध नहीं किया, परंतु अमेरिका–ईरान का समझौता P5+1 के तहत ईरान परमाणु प्रसार करना चाहा तो अमेरिका ने विरोध शुरु कर दिया और ईरान के खिलाफ आई0ए0ई0ए0 में भारत ने वोट डाल दिया। ईरान जैसे परम मित्र के लिए असहनीय दर्द था, परंतु भारत ने यह स्पष्ट कर दिया कि यह वोट ईरान के खिलाफ नहीं है, बल्कि विनाशक परमाणु प्रसार के खिलाफ था। भारत को ईरान की शर्त पर अमेरिका से घनिष्ठता के बारे में पड़ताल करना चाहिए क्योंकि भारत का ऊर्जा सुरक्षा की गारंटी है और हमारी महत्वपूर्ण आवश्यकता भी है। ऐसे में अगर हम ईरान की अनदेखी करते हैं तो इसमें नुकसान हमारा ही होगा दक्षिण एशिया में चीन की अर्थव्यवस्था से अमेरिका ज्यादा भयभीत है, इसलिए वह चीन को घेरने के लिए भारत को अपने हितों की पूर्ति करने वाला एक हथियार के रूप में देख रहा है, और तेल के खेल की राजनीति शुरू कर दिया है। चीन ईरान से कच्चा तेल आयात करने वाला सबसे बड़ा देश है इसलिए इस प्रतिबंध से कहीं ना कहीं चीन का भी हित अमेरिका से टकरा रहा है। यही वजह है

[37] (6 Nov 2018) Retrived on 10 January 2019 from https://m-punjabkesari-com.cdn.ampproject

कि चीन ने अमेरिकी प्रतिबंध को मानने से इंकार कर दिया है जबकि भारत में अमेरिकी प्रतिबंध के लिए ज्यादा विरोध नहीं किया। भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने एक कॉन्फ्रेंस में कहा था, "कि भारत किसी की पाबंदियों को स्वीकार नहीं करता है सिर्फ संयुक्त राष्ट्र की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों को मानेगा।"[38] ईरान ने भारत के इस कदम की प्रशंसा भी की थी, परंतु अमेरिका की प्रतिक्रिया अच्छी नहीं थी निक्की हेली ने भारत को चेताया था कि भारत को ईरान से आर्थिक संबंधों के बारे में समीक्षा करने की जरूरत है कि वह ईरान का साथ देगा अमेरिका का भारत की दुविधा यह है कि अमेरिका से सैन्य उपकरण, तकनीकी संसाधन और दक्षिण एशिया में चीन का घेराव (जो अमेरिका कर सकता है) के लिए दोनों देश महत्वपूर्ण है, ऐसे में किसी एक देश को चुनना भारत के लिए टेढ़ी खीर हो गया है।

5.10. भारत–ईरान संबंध से अमेरिका का टकराता हित

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति ओबामा द्वारा ईरान के परमाणु समझौते को न केवल खारिज कर दिया, बल्कि ईरान के विरुद्ध कड़े आर्थिक प्रतिबंध भी लागू कर दिया है। चिंताजनक बात यह है, कि ट्रंप ने अपने सभी संधि मित्रों और अन्य देशों को यह चेतावनी दी है कि यदि ईरान के साथ अपने आर्थिक संबंधों को यथावत रखा, तथा तेल आयात में कटौती नहीं की, तो उन्हें भी इन आर्थिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। भारत के लिए यह बड़ी चुनौती है, क्योंकि ईरान के साथ हम बड़ी मात्रा में तेल का आयात करते हैं। इराक और सऊदी अरब के बाद ईरान दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश है। यह सोचना तर्कसंगत नहीं हैं कि हम अमेरिका की धमकी के आगे आसानी से घुटने टेकने को मजबूर है। इस मामले में हमारे राष्ट्रहित का कोई भी संयोग अमेरिका के स्वार्थों के साथ नहीं है। अमेरिका और ईरान के संबंधों में वैमनस्य का इतिहास बहुत पुराना है। शीतयुद्ध के आरंभ में ही ईरान के जनतांत्रिक प्रधानमंत्री मोसादेग का खात्मा कर ईरानीयन–अमेरिकन पैट्रोलियन कंपनी को हथियाने में

[38] http://www.bbc.comcdn.ampproject.org/ visited on 25 December 2018

अमेरिकी तेल कंम्पनियां कामयाब रही थी और उसके बाद से ईरान के तानाशाह रजाशाह पहलवी अमेरिका के सहयोगी बने रहे और मध्य एशिया में अमेरिकी सामरिक हितों की रखवाली में प्रमुख भूमिका निभाते रहे। इस स्थिति में बदलाव 1970 के दशक में आया, जब अपनी अकूत तेल संपदा से रजाशाह ने कई बड़ी अमेरिकी कंपनियों को खरीद लिया और अमेरिकियों को यह स्थिति नागवार गुजरी। इस दशक के अंत तक फ्रांस में देश निकाला झेल रहे आयतुल्ला खुमैनी की प्रेरणा से 1979 में इस्लामी क्रांति संपन्न हुई, जिसने ईरान में राजशाही को खत्म कर दिया तथा इस्लामी गणराज्य की स्थापना हुई। ईरान एक शिया बहुल देश है और उसकी ऐतिहासिक प्रतिद्वंद्विता सुन्नी–सऊदी के साथ है. इस बात को भी भुलाया नहीं जाना चाहिए कि अमेरिकी पक्षधर इस्राइल को लगता है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम का मकसद उनके यहूदी राष्ट्र को निशाने पर रखना है, यह बात भी याद रखने लायक है कि कड़े आर्थिक प्रतिबंधों और अप्रत्यक्ष–अघोषित युद्ध के बावजूद अमेरिका ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने में असमर्थ रहा है, इसलिए ओबामा ने धमकी से नहीं सुलह से इस गुत्थी को सुलझाने का प्रयास किया. भारत की मजबूरी यह है कि लगभग 25 वर्ष से भारत गुटनिरपेक्षता की नीति छोड़कर अमेरिका के विश्व दर्शन का साझा रहा है। अमेरिकी दबाव में ही भारत ने संयुक्त राष्ट्र में ईरान के विरुद्ध कभी अनुपस्थित रहकर, तो कभी तटस्थ रहकर उसके विरोध में ही हाथ उठाया है। ईरान–भारत के आर्थिक विकास में सहकार में कोई उत्साह नहीं दिखा रहा, क्योंकि उसे लगता है कि भारत ने अमेरिका का मुकाबला करने में उसके साथ प्रत्याशित सहयोग नहीं किया है। विडंबना यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने एक–साथ कई मोर्चे खोले हैं, वह चीन के खिलाफ वाणिज्य युद्ध की घोषणा कर चुके हैं और इसी तरह अमेरिका को प्राथमिकता देने की हठ के कारण यूरोप के देशों और कनाडा को खिन्न कर चुके हैं. मैक्सिको में वामपंथी राष्ट्रपति के चुनाव के बाद उनके लिए एक और मुसीबत उठ खड़ी हुई है। भारत इस सब का राजनयिक लाभ उठा सकता है. भारत को भी एहसास है कि मध्य पूर्व में ईरान, लेबनान और पुतिन की फौजी टुकड़ियों ने उस रणक्षेत्र में तैनात अमेरिकी सेना और उसके सहयोगियों के बल से कहीं अधिक मजबूत जड़ें जमायी हैं. ट्रंप के लिए

ईरान पर काबू पाना प्राथमिकता हो सकती है। भारत के लिए अमेरिकी राजनय में हाथ बटाना अदूरदर्शी आत्मघातक नादानी ही समझा जा सकता है।

ज्ञातव्य है कि खाड़ी के देशों में ईरान का संबंध बहुत अच्छा नहीं है और अमेरिका का सऊदी अरब से संबंध ईरान से बेहतर है। अमेरिकी प्रतिबंध का सऊदी अरब ने खुलकर समर्थन किया था। दक्षिण एशिया में ईरान का संबंध भारत से अच्छा है, परंतु चीन, पाकिस्तान से उतना जुड़ाव नहीं है जितना भारत से है। यूरोपीय देशों में ईरान का संबंध बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है, संभवतः अमेरिका भी इसी बात का फायदा उठाकर ईरान को अलग–थलग करना चाहता है, जिससे जल्दबाजी में ईरान कुछ गलत करें और अमेरिका को कार्रवाई करने का मौका मिल जाए अमेरिका ने ईरान पर जो भी आरोप लगाया है उसका संयुक्त राष्ट्र ने जांच भी किया और कोई आपत्ति नहीं किया परंतु अमेरिका नहीं माना। अमेरिकी प्रतिबंध से ईरान– अमेरिकी संबंधों में कटुता बहुत बढ़ गई है, जो भविष्य में सुधरने की आशा नहीं दिख रही है।[39]

भारत–ईरान संबंध में अमेरिका की भूमिका के परीक्षण से यह निष्कर्ष निकलता है कि आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से तो दोनों ही देश भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक के पास रक्षा तकनीकी संसाधन है तो दूसरे के पास अप्राकृतिक संसाधन इसलिए भारत–अमेरिका और ईरान दोनों के साथ अच्छे संबंध रखने की कोशिश में लगा हुआ है। एक तरफ देखा जाए तो अमेरिका एशिया में उभर रही नई चुनौतियां एवं खतरों से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण सहयोगी साबित हो सकता है, वहीं दूसरी तरफ ईरान, भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में ऊर्जा सुरक्षा से भारत का भविष्य सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। भारत–ईरान कभी सीमा साझा करते थे, परंतु पाकिस्तान के जन्म के बाद सरहद बँट गई लेकिन वहीं है। समय के साथ संबंधों में उतार–चढ़ाव होता रहा है। अमेरिका को इस द्विपक्षीय रिस्तों का सम्मान करना चाहिए और समझना चाहिए, कि किसी भी इस द्विपक्षीय संबंध की तरह ही ईरान के विभिन्न मुद्दों पर

[39] पुष्पेश पंत Retrieved on 23 Nov 2018 From https://www_prbhatkhabar.com.cdn.amproject.org/v/s/oil.imports_india_ran_relations

अमेरिका और भारत के बीच भी मतभेद हो सकते हैं, तथापि इन्हें दिल्ली और वाशिंगटन के संबंधों के रास्ते में नहीं आने देना चाहिए, आदर्श राजनीति भी यही कहती है। भारत को ईरान और अमेरिका दोनों में से कोई एक का चयन करने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए।

भारत अमेरिका का आधिकारिक सहयोगी नहीं है, इसलिए उसे ईरान पर अपने हित में फैसले लेने का पूरा हक होना चाहिए। परंतु अमेरिका ने जब से ईरान पर प्रतिबंध लगाया है तब से वह भारत पर दबाव डाल रहा है, कि भारत ईरान से कच्चा तेल का निर्यात बंद कर दे। भारत की ऊर्जा जरूरतें ईरान को अमेरिका के लिए बलि नहीं चढ़ा सकती हैं, क्योंकि चीन की ईरान ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ती हो उपस्थिति और ईरान के साथ पाकिस्तान का संबंधों को देखते हुए ईरान को रणनीतिक गणना से बाहर नहीं निकाला जा सकता है अमेरिका रणनीतिक रूप से कोशिश में लगा है कि भारत के संबंधों को अमेरिका से ज्यादा महत्व न मिले। यही वजह है कि अमेरिका के साथ भारत के बढ़तें करीबी संबंधों ने ईरान के साथ विकसित पारंपरिक संबंधों पर पाबंदी लगा दिया है। अमेरिका द्वारा ईरान पर आर्थिक प्रतिबंधों से ईरान का अमेरिका और भारत दोनों से संबंध रसातल में जा रहे हैं।

अध्याय–षष्ठम्

भारत–ईरान सम्बन्ध का पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया पर प्रभाव

भारत और ईरान दोनों देश आपसी सामंजस्य को बढ़ाते हुए विश्व के अन्य क्षेत्रों में अपना विस्तार कर रहे हैं और एक दूसरे को समय–समय पर अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त दोनों देश दक्षिण और पश्चिम एशियाई क्षेत्रों में अपना आर्थिक, राजनीतिक व सामाजिक समरसता के द्वारा प्रभाव स्थापित करने की कोशिश भी कर रहे हैं। भारत दक्षिण एशिया में अपने प्रभाव को स्थापित करने के लिए पड़ोसी देशों को आर्थिक सहायता करने व उनकी विभिन्न समस्याओं को सुलझाने की कोशिश कर रहा है। भारत दक्षिण एशिया में बड़े भाई का रोल अदा करता है। यह भूटान, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, मालदीव, इत्यादि देशों के साथ अपने आर्थिक, सामरिक व राजनीतिक संबंध स्थापित कर रहा हैं और साथ ही भारत अपने पड़ोसी देश चीन व विश्व के अनेक देशों जैसे अमेरिका, रूस, फ्रांस इत्यादि देशों के क्रिया कलाप को समझने की कोशिश कर रहा है क्योंकि चीन भी इस क्षेत्र में अपना प्रभाव स्थापित करने की कोशिश में लगा हुआ है इसलिए भारत अपनी शक्ति का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए विश्व के अनेक देशों के साथ अपने संबंध बना रहा है।

पश्चिम एशिया एक ऐसा भू–भाग है जिसके अनेक नामों से जाना जाता है जैसे मध्य पूर्व, एशिया दक्षिण, पश्चिम एशिया इत्यादि। यह क्षेत्र पश्चिमी यूरोप व हिंद महासागर को स्पर्श करता है तथा यह आधुनिक राजनीति में एक ऐसे क्षेत्र के तौर पर कुख्यात है जहां केवल आतंकवाद, अशांति व अराजकता का बोलबाला रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही पश्चिमी एशिया कई छोटे व बड़े युद्ध झेल चुका है दूसरी तरफ पश्चिम एशिया प्राकृतिक रूप से धनी क्षेत्र भी है जहां पर कच्चे तेल व प्राकृतिक गैस जैसें तत्व प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। यह क्षेत्र विश्व के सभी देशों के लिए महत्वपूर्ण तथा प्रतिस्पर्धी है और भारत उनमें से एक है जो पश्चिम एशियाई देशों के साथ अपने राजनीतिक व आर्थिक संबंधों को बढ़ा रहा है। बीसवीं सदी के पहले दशक में खनिज तेल की खोज ने इस पूरे क्षेत्र को

असाधारण रूप से सामरिक महत्व प्रदान किया। यहां तक कि ब्रिटेन के उपनिवेश प्रशासन सर ओलेफ कैरो ने पश्चिम एशिया के तेल के कुओं को शक्ति कूप अर्थात वैल्स आफ पावर का नाम दिया (पंत 2010)। तब से लेकर आज तक इस क्षेत्र को तेल की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से अलग देखा जा रहा है। पश्चिम एशिया में ईरान एक ऐसा देश है जिसकी भौगोलिक स्थिति भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसके द्वारा भारत विश्व के साथ व्यापार आसानी से कर सकता है साथ ही यह विश्व में होने वाले परिवर्तन को आसानी से समझ सकता है क्योंकि इस बदलते हुए परिपेक्ष में दोनों देशों को एक दूसरे की मदद की आवश्यकता है। भारत अपने आप को विश्व पटल पर सुरक्षित करना चाहता है साथ ही पश्चिम में हो रहे बाहरी हलचल को भी आसानी से समझ सकता है क्योंकि चीन भी इस क्षेत्र में बहुत तेजी से अपना प्रभुत्व स्थापित कर रहा है। चीन का यह बढ़ता हुआ प्रभाव भारत के लिए एक खतरा साबित हो सकता है जो की भारत कभी भी नहीं चाहता है कि ऐसी कोई समस्या सामने आये। इसीलिए भारत अपनी सुरक्षा की दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए चीन को करारा जबाब देना चाहता है और भारत चीन की शक्ति को रोकना चाहता है। दूसरी तरफ ईरान भी पश्चिम एशिया में अपने कूटनीतिक प्रभाव बनाने की कोशिश में लगा हुआ है क्योंकि ईरान का पश्चिमी देशों के साथ अपना एक अलग सम्बन्ध है।

6.1 दक्षिण एशिया में भारत

भारतीय विदेश नीति के निर्धारण तत्वों में विस्तृत भू–भाग तथा विशाल जनसंख्या वाले देश की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और इसका प्रभाव विदेश नीति व विश्व राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। भारत की विदेश नीति प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सितंबर 1946 में यह कहते हुए शुरू कि–"वैदेशिक संबंधों के क्षेत्र में भारत एक स्वतंत्र नीति का अनुसरण करेगा और गुटों की खींचतान से दूर रहते हुए संसार के समस्त पराधीन देशों को आत्म–निर्णय का अधिकार प्रदान कराने तथा जातीय भेदभाव की नीति का दृढ़तापूर्वक उन्मूलन कराने का प्रयत्न

करेगा।"[1] यह कथन आज भी भारत की विदेश नीति की आधार शिला के रूप में माना जाता है। भारत की विदेश नीति राष्ट्रों के मध्य शान्ति, स्वतंत्रता तथा आपसी सहयोग व विश्वास रखते हुए पंचशील सिद्धान्त, गुटनिरपेक्षता, निःशस्त्रीकरण एवं वसुधैव कुटुम्बकमं पर आधारित है। भारत भौगोलिक रूप से पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका के साथ अपनी सीमा रेखा साझा करते हैं साथ ही एक दूसरे के साथ सांस्कृतिक जुडाव भी है। इन देशों की सामाजिक व्यवस्था, संस्कृति, आर्थिक व राजनीतिक समस्याएं लगभग एक जैसी है, जिसका प्रभाव इनके सामाजिक संबंधों के साथ–साथ राजनीतिक एवं आर्थिक संबंधों में भी दृष्टिगत होता है इसीलिए दक्षिण एशिया के इन देशों को एक दूसरे के सहयोग एवं विकास की योजनाओं को तीव्र गति से विकसित करने की आवश्यकता है। जिससे देश विश्व के अन्य देशों के साथ विकास की मुख्य धारा में अपने स्थान को सुनिश्चित कर सके, विशेषकर भारत के सन्दर्भ में यह और भी प्रासंगिक है।

इसी अवधारणा को मूर्त रूप देने के लिए तथा दक्षिण एशिया के देशों के मध्य आपसी सहयोग बढ़ाने एवं आर्थिक तथा सामाजिक विकास के उद्देश्य को पूर्ण करने हेतु 8 दिसम्बर 1985 को दक्षिण एशिया के सात देशों भारत, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान तथा बांग्लादेश ने मिलकर 'दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन' (SAARC) की स्थापना की। जिसका मुख्य उद्देश्य दक्षिण एशिया के लोगों के जीवन स्तर में गुणवत्ता लाने के साथ ही इस क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास को गति प्रदान करना है। इसकी सफलता को देखते हुए सार्क के 14वें शिखर सम्मेलन (2007) में अफगानिस्तान को इसका 8वॉ सदस्य बनाया गया। लेकिन सार्क की प्रासंगिकता पर यह प्रश्न उठाया गया कि क्या भारत सार्क देशों को लेकर आगे बढ़ सकता है? किन्तु भारत के प्रधानमंत्री ने 2014 के शपथ ग्रहण समारोह में सार्क देशों के सभी प्रमुख को आमंत्रित कर विश्व पटल पर यह स्पष्ट कर दिया कि भारत ने दक्षिण एशिया के देशों के साथ अपने संबंधों को प्रगाढ़ ही नहीं बनाया बल्कि यह संदेश भी दिया कि विश्व के अन्य देशों

[1] Sen, S. भारत की विदेश नीति पर निबंध, *Hindi Library India.* Retrived on 11 nov 2018 from http://www.hindilibraryindia.com

की तुलना में दक्षिण एशिया उसके लिए सबसे अहम एवं महत्वपूर्ण है (Swami, May 23, 2016)। जो यह संकेत देता है कि दक्षिण एशिया में खासतौर पर द्विपक्षिय स्तर पर क्षेत्रीय सहयोग की यह एक नई शुरूआत है।

भारत दक्षिण एशिया के केंद्र में स्थित है जिसकी सीमाएं अफगानिस्तान को छोड़कर अन्य सभी राज्यों से जुड़ी हुई है जिसके चलते भारत दक्षिण एशिया के सभी देशों के साथ आसानी से अपनी पैठ बना सकता है और भारत को इस क्षेत्र में एक विशेषाधिकार प्राप्त कराता है। जो कि व्यावहारिक रूप में एक परिसंपत्ति और एक दायित्व दोनों का गठन प्रदत करती है लेकिन वास्तविकता यह है कि भारत में क्षेत्रीय नेता की भूमिका को निभाने की आकांक्षा को अक्सर खारिज कर दिया गया न केवल पाकिस्तान के द्वारा बल्कि अन्य छोटे पड़ोसियों के द्वारा भी। इसलिए भारतीय रणनीतिकार यह अभी भी सोच रहे है की इस क्षेत्र में प्राकृतिक नेतृत्व सही मायने में कैसे किया जाए। दशकों से भारत ने अपने पड़ोसी देशों से निपटने और अपनी भूमिका का पता लगाने के लिए विभिन्न रणनीतियों का भी अनुसरण किया जैसे सैन्य निर्माण, हस्तक्षेप नीति–1971 में पूर्व पाकिस्तान संकट और 1983 से 1990 तक श्रीलंका का जातीय संघर्ष और आर्थिक दबाव 1989 में नेपाल पर नाकाबंदी लगाई गयी थी। शीत युद्ध के बाद भारत दक्षिण एशिया में लगातार समस्याओं को हल किए बिना वैश्विक स्तर पर अपनी पैठ बनाने की कोशिश करने लगा। पिछले दो दशकों में भारत ने अपने आकर्षण और विशेष नेतृत्व को मजबूत किया है साथ ही अपने पड़ोसियों के प्रति अधिक नरम शक्ति नीतियों का उपयोग किया है।

सन् 1985 से भारत ने चार क्षेत्रीय पहल करने में संस्थापक सदस्य की भूमिका का निर्वाहन किया है, लेकिन इनमें से किसी भी पहल का कोई ठोस परिणाम नहीं निकला. यूरोपीय संघ और आसियान दोनों ही संगठनों ने यह प्रमाणित कर दिया है कि भिन्न–भिन्न देशों के बीच भी बहुपक्षीय सहयोग करके भारी आर्थिक सहयोग और बेहतरीन विकास का मार्ग प्रशस्त हो सकता है, लेकिन दक्षिण एशिया, बंगाल की खाड़ी, ओशन रिम और मैकोंग–गंगा क्षेत्र ऐसे चार क्षेत्रीय समूह हैं, जिनमें इस तरह की कोई प्रगति नहीं हुई। इन सभी चारों समूहों की मूल

परिकल्पना और उनके सहकारी मामलों की स्थिति लगभग एक जैसी ही खराब है और न्यूनतम बहुपक्षवाद पर भारत के आग्रह के प्रमाण भी मौजूद हैं (माइकल, 2015)।

6.1.1. दक्षिण एशियाई देशों के साथ भारत के आर्थिक संबंध

दक्षिण एशियाई क्षेत्र दुनिया में सबसे कम आर्थिक रूप से एकीकृत क्षेत्रों में से एक है। उच्च परिवहन लागत, संरक्षणवादी नीतियों और राजनीतिक तनाव के कारण इनका आपसी क्षेत्रीय व्यापार अपनी क्षमता से काफी नीचे रहता है। एक तरफ दक्षिण एशियाई देशो के द्वारा निर्मित संगठन–दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) समझौते, दक्षिण एशियाई अधिमान्य व्यापार व्यवस्था और दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार व्यवस्था, व्यापार बाधाओं को तोड़ने में विफल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इन देशो के आपसी सीमा विवाद, संघर्ष शील दुश्मनी इसके आर्थिक सम्बन्धों को प्रभावित किया जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच गहरी दुश्मनी, जो चार युद्धों से विचलित है, व्यापक व्यापार विस्तार के रास्ते में बाधा बनकर खड़ी हो गयी है, जिससे भारत–पाकिस्तान सीमा पर माल का प्रवाह धीमा हो गया है। अधिकांश सार्क देश निर्यात स्थलों के रूप में विकसित राष्ट्रों पर बहुत अधिक भरोसा करते हैं, और चीन से तेजी से आयात करते हैं।[2] भारत अपने आकार और स्थान के कारण दशकों से दक्षिण एशियाई देशों के लिए एक प्राकृतिक शीर्ष व्यापारिक भागीदार था जो निम्न सारणी में उद्घृत किया गया है।

भारत दक्षिण एशियाई क्षेत्रों में विभिन्न वस्तुओं का निर्यात करता है जैसे चाय, कहवा, चीनी, चावल, दवाएं इत्यादि। भारत ने वर्ष 2007–08 में अफगानिस्तान के साथ 249.21 यू०एस० मिलियन डॉलर (US $ Million) का उत्पादन किया था तथा वर्ष 2008–09 में 394.23 यू०एस० मिलियन डॉलर, वर्ष 2016–16 में 506.34 यू०एस० मिलियन डॉलर तथा वर्ष 2017–18 में 709.75 यू०एस० मिलियन डॉलर का उत्पादन किया।

[2] Economics of Influence: China and India in South Asia (August 3, 2015). Council on Foreign Relations. Retrieved on 17 Jan 2016 from https://www.cfr.org/expert-brief/economics-influence-china-and-india-south-asia

बांग्लादेश भारत को वर्ष 2007–08 में 2923.72 यू०एस० मिलियन डॉलर का निर्यात किया था जबकि 2008–09 में यह घट कर 2497.87 यू०एस० मिलियन डॉलर हो गया लेकिन वर्ष 2016–17 में पुनः इसने अपनी रफ़्तार को प्राप्त कर लिया और यह बढ़कर 6820.11 यू०एस० मिलियन डॉलर हो गया। वर्ष 2017–18 में 8614.34 यू०एस० मिलियन डॉलर तक पहुँच गया जिसमें यह हा जा सकता हैं कि विगत वर्ष की तुलना में 26.31 प्रतिशत की उन्नति हुई है।

भारत–भूटान को निर्यात करने में अन्य दक्षिण एशियाई देशों की तुलना में पीछे है। वर्ष 2008–08 में 86.74 यू०एस० मिलियन डॉलर और वर्ष 2008–09 में 111.15 यू०एस० मिलियन डॉलर का निर्यात हो गया जो की 28.15 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद वर्ष 2016–17 में 509.28 यू०एस० मिलियन डॉलर हो गया तथा 2017–18 में यह बढ़ कर 546.12 यू०एस० मिलियन डॉलर हो गया। इन दो वर्षो में केवल 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

भारत–मालदीव का निर्यात भूटान की तुलना में लगभग समान है लेकिन भूटान से ज्यादा है वर्ष 2007–08 में 89.72 यू०एस० मिलियन डॉलर तथा वर्ष 2008–09 में बढ़कर 127.91 यू०एस० मिलियन डॉलर हो गया वर्ष 2016–17 में 197.79 यू०एस० मिलियन डॉलर का निर्यात किया गया। लेकिन वर्ष 2017–18 में 217.00 यू०एस० मिलियन डॉलर जो की गत वर्ष की तुलना में 9.71 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

भारत नेपाल के साथ मुक्त व्यापार का संबंध बनाता है इसलिए भारत का निर्यात नेपाल में अधिक देखा गया है। वर्ष 2007–08 में भारत का निर्यात 1507.42 यू०एस० मिलियन डॉलर था और वर्ष 2008–09 में बढ़कर 1570.15 यू०एस० मिलियन डॉलर रहा वहीं वर्ष 2016–17 में 5453.59 यू०एस० मिलियन डॉलर तथा वर्ष 2017–18 में 6612.96 यू०एस० मिलियन डॉलर हो गया इन दो वर्षों में भारत का निर्यात दक्षिण एशिया की तुलना में सबसे ज्यादा रहा है जोकि विगत वर्ष की तुलना में 21.26 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

भारत वर्ष 2007–08 में पाकिस्तान को 1950.53 यू०एस० मिलियन डॉलर का निर्यात किया तथा वर्ष 2008–09 में यह घट कर 1439.88 यू०एस० मिलियन डॉलर हो गया जो की –26.18 प्रतिशत घट गया। लेकिन वर्ष 2016–17 में पुनः बढ़ कर 1821.87 यू०एस० मिलियन डॉलर हो गया। वहीं वर्ष 2017–18 में यह बढ़ कर 1924.28 यू०एस० मिलियन डॉलर हो गया पीछले वर्ष की तुलना में 5.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

तालिका 6.1. दक्षिण एशिया में भारत का निर्यात–2007–2009

(Values in US$ Million)

S. No.	Name of Country	2007-08	2008-09	% Growth
1.	Afghanistan TIS	249.21	394.23	58.20
2.	Bangladesh Pr	2,923.72	2,497.87	-14.57
3.	Bhutan	86.74	111.15	28.15
4.	Maldives	89.72	127.91	42.56
5.	Nepal	1,507.42	1,570.15	4.16
6.	Pakistan Ir	1,950.53	1,439.88	-26.18
7.	Sri Lanka Dsr	2,830.43	2,425.92	-14.29
	Total	**9,637.76**	**8,567.12**	**-11.11**

Source: Ministry of Commerce & Industry, Government of India

तालिका 6.2. दक्षिण एशिया में भारत का निर्यात–2016–2018

(Valuesin US$ Million)

S. No.	Name of country	2016-2017	2017-2018	% Growth
1.	Afghanistan TIS	506.34	709.75	40.17
2.	Bangladesh Pr	6,820.11	8,614.35	26.31
3.	Bhutan	509.28	546.12	7.23
4.	Maldives	197.79	217.00	9.71
5.	Nepal	5,453.59	6,612.96	21.26
6.	Pakistan Ir	1,821.87	1,924.28	5.62
7.	Sri Lanka Dsr	3,913.15	4,476.46	14.40
	Total	**19,222.14**	**23,100.90**	**20.18**
India's Total	**275,852.43**	**303,526.16**	**10.03**	

Source: Ministry of Commerce & Industry, Government of India

भारत दक्षिण एशियाई देशों से कुछ वस्तुओं का आयात करता है जैसे डेयरी उत्पादक, खाद्य पदार्थ में कंद, जड़े, कॉफी, चाय, मसाले, मिलिंग उद्योग के उत्पादक जैसे माल स्टार्ट इंसुलिन, गेहूं आदि। जोकि निम्न सारणी में दर्शाया गया है वर्ष 2007–08 में अफगानिस्तान से 109.97 यू०एस० मिलियन डॉलर का आयात किया तथा वर्ष 2008–09 में यह बढ़कर 126.24 यू०एस० मिलियन डॉलर हो गया जो कि इन दो वर्षों में 14.80 प्रतिशत की उन्नति हुई है। वर्ष 2016–17 में बढ़कर 292.90 यू०एस० मिलियन डॉलर हो गया है और वर्ष 2017–18 में 433.78 यू०एस० मिलियन डॉलर तक पहुंच गया है इन दो वर्षों में 48.10 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है।

भारत और बांग्लादेश का संबंध आर्थिक साझेदारी और द्विपक्षीय विकास का एक लंबा इतिहास रहा है दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास और सहयोग पर आधारित रहा है (Balaji,2016)। जिसके चलते भारत बांग्लादेश से वर्ष 2007–08 में 257.02 यू०एस० मिलियन डॉलर का आयात किया तथा यह आयात वर्ष 2008–09 में बढ़कर 312.11 यू०एस० मिलियन डॉलर हो गया लेकिन वर्ष 2016–17 में 701.68 यू०एस० मिलियन डॉलर हो गया और वर्ष 2017–18 में घटकर 685.68 यू०एस० मिलियन डॉलर हो गया वर्ष 2016–2018 इन दो वर्षों में–2.29 प्रतिशत का नुकसान हुआ।

भारत–भूटान व्यापार और पारगमन समझौता 1972 में दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार व्यवस्था की शुरुआत हुई तब से इस समझौते को पांच बार नवीनीकृत किया गया लेकिन वर्ष 2017 में पुनः इसे नवीनीकृत किया गया।[3] और इस समझौते के चलते 2017–18 में भारत के आयात में मुख्य प्रभाव पड़ा जो कि निम्न है वर्ष 2007–08 में 194.72 यू०एस० मिलियन डॉलर था तथा वर्ष 2008–09 में घटकर 151.79 यू०एस० मिलियन डॉलर हो गया इन दो वर्षों में –22.05 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा वर्ष 2016–17 में 307.82 यू०एस० मिलियन डॉलर का आयात किया गया तथा वर्ष 2017–18 में बढ़कर 377.99 यू०एस० मिलियन डॉलर हो गया जोकि 22. 80 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

[3]India-Bhutan Trade Relation, Embassy of India Bhutan . Retrieved on 12 sep 2017 from https://indembthimphu.gov.in/pages.php?id=42

भारत और मालदीव ने 1981 में आर्थिक समझौता किया[4] जिससें दोनों देशों के बीच व्यापार पर मुख्य प्रभाव पड़ा जिसके चलते दोनों देश आपसी व्यपार आसानी से कर रहे है भारत मालदीव से केवल रद्दी माल का आयात करता है वर्ष 207–08 में 4.15 यू०एस० मिलियन डॉलर का आयात किया तथा वर्ष 2008–09 में घटकर 3.97 यू एस मिलियन डालर हो गया जोकि –4.19 प्रतिशत वृद्धि हुई है और वहीं वर्ष 2016–17 में बढ़कर 9.17 यू०एस० मिलियन डॉलर हो गया लेकिन वर्ष 2017–18 में यह घट कर 5.68 यू०एस० मिलियन डॉलर पर पहुंच गया।

नेपाल–भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश है तथा इसकी रणनीतिक अवस्थिति, खुली सीमा आदि दोनों देशों के संबंधों को असाधारण और घनिष्ठ बनाते हैं। इसके चलते दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध अधिक मजबूत रहें हैं भारत–नेपाल का आयात दिन प्रतिदिन बढ़ता रहा है लेकिन कुछ वर्षों में यह भी देखा गया है कि भारत नेपाल के आयात में कमी भी आयी है। वर्ष 2007–08 में 628.56 यू०एस० मिलियन डॉलर का आयात किया है तथा वर्ष 2008–09 में यह घटकर 496.04 यू०एस० मिलियन डॉलर हो गया जो कि इन दो वर्षों में –21.08 की वृद्धि हुई है तथा वर्ष 2016–17 में 445.13 यू०एस० मिलियन डॉलर और वर्ष 2017–18 में 438.38 यू०एस० मिलियन डॉलर आयात किया गया इन दो वर्षों में –1.25 प्रतिशत की कमी हुई हैं।

भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच पिछले पांच दशकों से अधिक समय से भू–राजनीतिक तनाव होने के कारण आपसी व्यापार प्रभावित रहा है लेकिन यह व्यापार एक उतार–चढ़ाव के दौर से गुजरता रहा है वर्ष 2007–08 में 287.97 यू०एस० मिलियन डॉलर का आयात किया और वर्ष 2008–09 में बढ़कर 370.17 यू०एस० मिलियन डॉलर हो गया तथा वर्ष 2016–17 में यह 454.49 यू०एस० मिलियन डॉलर और 2017–18 में 488.56 यू०एस० मिलियन डॉलर की वृद्वि हुई।

[4]India Maldives. Embassy of India Maldives. Retrieved on 16 nov 2018 from https://eoi.gov.in/male/?1185?000

भारत विश्व स्तर पर श्रीलंका का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जबकि श्रीलंका सार्क में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।[5] आई0एस0एफ0टी0ए0 (ISFTA) के तहत श्रीलंका से प्रमुख निर्यात होता हैं जैसे– वस्त्र, फर्नीचर, बोर्ड, कांच की बोतलें, पोल्ट्री फीड, तार और केबल, बोतल कूलर, वायवीय टायर, टाइल और सिरेमिक उत्पाद, रबर के दस्ताने, बिजली के पैनल बोर्ड और बाड़े, मशीनरी पाट्र्स, भोजन की तैयारी और मसाले आदि। वर्ष 2007–08 में 634.96 यू०एस० मिलियन डॉलर और वर्ष 2008–09 में आयात घटकर 356.57 यू०एस० मिलियन डॉलर हो गया तथा वर्ष 2016–17 में 602.20 यू०एस० मिलियन डॉलर का आयात किया गया और वर्ष 2017–18 में 772.63 यू०एस० मिलियन डॉलर का आयत रहा।

तालिका 6.3. भारत का दक्षिण एशिया से आयात (2007–2009)

(Values in US$ Million)

S. No.	Name of Country	2007-2008	2008-2009	% Growth
1.	Afghanistan TIS	109.97	126.24	14.80
2.	Bangladesh Pr	257.02	313.11	21.82
3.	Bhutan	194.72	151.79	-22.05
4.	Maldives	4.15	3.97	-4.19
5.	Nepal	628.56	496.04	-21.08
6.	Pakistan Ir	287.97	370.17	28.54
7.	Sri Lanka Dsr	634.96	356.57	-43.84
	Total	**2,117.35**	**1,817.89**	**-14.14**
India's Total	**251,654.00**	**303,696.30**	**20.68**	

Source: Ministry of Commerce & Industry, Government of India

[5]Indo-Lanka Relations. Consulate General of Sri Lanka Mumbai-India Rertived on 11 Jan 2019 from http://www.mumbai.mission.gov.lk/index.php/trade/indo-lanka-trade-relations

तालिका 6.4. भारत का दक्षिण एशिया से आयात (2016–2018)

(Values in US$ Million)

S No	Name of Country	2016-2017	2017-2018	% Growth
1.	Afghanistan TIS	292.90	433.78	48.10
2.	Bangladesh Pr	701.68	685.65	-2.29
3.	Bhutan	307.82	377.99	22.80
4.	Maldives	9.17	5.68	-38.14
5.	Nepal	445.13	438.38	-1.52
6.	Pakistan Ir	454.49	488.56	7.50
7.	Sri Lanka Dsr	602.20	772.63	28.30
	Total	**2,813.40**	**3,202.66**	**13.84**
India's Total	**384,357.02**	**465,580.98**	**21.13**	

Source: Ministry of Commerce & Industry, Government of India

6.2. दक्षिण एशिया में ईरान

दक्षिण एशिया की तुलना पश्चिम में स्थित अरब देशों के साथ करते हैं तो इस्लामी गणतंत्र ईरान अपने पड़ोसी देशों के साथ बड़े पैमाने पर सौहार्दपूर्ण संबंधों को बनाए रखने में कामयाब रहा है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भाषाई, धार्मिक और सांस्कृतिक लक्षण मिलते जुलते हैं जिसके चलते इस क्षेत्र में ईरान अपना प्रभाव बनाए रखने में सक्षम है। अमेरिका के नेतृत्व वाले प्रतिबंधों के बावजूद यह एक महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार बनने में मदद करता है।

ईरान अपनी राजनीतिक स्थिति को फारस की खाड़ी से लेकर हिन्द महासागर तक बनाये रखते हुए यह भारत को अफगानिस्तान के माध्यम से मध्य एशिया तक पहुंच प्रदान करता है जिसमे पाकिस्तान की परम्परागत भूमि की भी आवश्यकता नहीं है। हालांकि, पाकिस्तान और उसके पड़ोसियों को दुर्लभ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है–जैसे कि दुर्लभ और खराब जल संसाधनों, जातीय विद्रोह, ऊर्जा असंतुलन, और मादक पदार्थों की तस्करी इत्यादि जिनके लिए क्षेत्रीय समाधान की आवश्यकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका इन समस्याओं से निपटने के लिए ईरान और दक्षिण एशियाई देशों की क्षमता बढ़ाने वाले समझौतों और कार्यक्रमों

का समर्थन करके क्षेत्र में स्थिरता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है साथ ही दक्षिण एशिया में विवादास्पद अफगानिस्तान–पाकिस्तान संबंधों को सुधारने, और भारत–पाकिस्तान प्रतिद्वंद्विता को कम करने की कोशिश भी की गयी थी।

पाकिस्तान और ईरान का संबंध समय के साथ विकसित होता रहा है। ईरानी क्रांति के बाद दोनों राज्यों के बीच संबंध बिगड़ गए लेकिन कुछ वर्षों के पश्चात दोनों देशों के बीच पुनः संबंधों में सुधार हुआ और दोनों देशों ने 1999 में मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। समकालीन दौर में दोनों देश मिलकर अफगानिस्तान में स्थिरता लाने और एशियाई देशों में आतंकवाद को दूर करने के उद्देश्य से एक साथ सामने आए हैं। इनके द्विपक्षीय संबंध दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ाने, सीमा सुरक्षा तंत्र को विकसित करने और पाकिस्तान में धार्मिक चरमपंथियों की भयावह समस्या के समाधान के लिए संभावनाएं खोज रहे हैं और यह भी देखा गया है कि पाकिस्तानी समाज में धार्मिक कट्टरता और शियाओं के खिलाफ कथित भेदभाव दोनों देशों के बीच विवाद का एक मुख्य विषय रहा है जिसके चलते इस प्रयास को सफल व ठोस बनाने के लिए दोनों को एक संयुक्त योजना की आवश्यकता है।

पाकिस्तान और ईरान आर्थिक सहयोग संगठन के प्रमुख संस्थापक हैं और वर्तमान में दोनों दोनों देश आपसी गठबंधन बना रहे है इसके साथ ही कई मुद्दों पर सहयोग कर रहे हैं इन हितों में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, अवैध क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट, ड्रग–व्यापार और बलूचिस्तान विद्रोह शामिल हैं। ईरान ने आर्थिक और व्यापारिक सहयोग के लिए चीन–पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) में भी बहुत रुचि दिखाई है। इस स्थिति में ईरान को एक महत्वपूर्ण सहयोगी के रूप में शामिल करने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि भारत चाबहार समुद्री बंदरगाह के विस्तार में आर्थिक मदद कर रहा है।

ईरान ने अपने सुन्नी मुस्लिम बहुसंख्यक पड़ोसी के साथ व्यवहार करते समय आम तौर पर विचारधारा से ऊपर सुरक्षा हितों को रखा। 1979 के बाद, ईरान ने बड़े पैमाने पर दमित शिया मुसलमानों का समर्थन किया और ईरान ने इस्लामी

क्रांति को पाकिस्तान की तरफ एक हवा दी।[6]. पाकिस्तान में अनुयायियों के ईरानी प्रयासों को इस तथ्य से भी बाधित किया गया कि पाकिस्तानी शिया ईरान के लोकतांत्रिक मॉडल के महान प्रशंसक नहीं हैं। 1979 में, पाकिस्तानी शियाओं में से अधिकांश अयातुल्ला मोहम्मद काज़म शरीयतमदरी के अनुयायी थे, जो ईरानी क्रांति के नेता, महान अयातुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी के बजाय अपने उदार विचारों के लिए जाने जाते थे।

1980–88के ईरान–इराक युद्ध के दौरान ईरान का समर्थन करने के लिए पाकिस्तान ने मदद करने वाले देशो में से एक था। हालांकि, अफगानिस्तान में 1979 के सोवियत आक्रमण के बाद पाकिस्तान में सुन्नी इस्लामी कट्टरपंथ के विकास के साथ तनाव बढ़ गया। उदहारण के लिए में 1990 में पाकिस्तानी शहर लाहौर में ईरान के महाधिवक्ता सादिक गंजी की हत्या शामिल हैं। 1990 के दशक में अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान समर्थित तालिबान का उदय और अगस्त 1998 में अफ़ग़ान शहर मजार–ए शरीफ़ में ईरानी वाणिज्य दूतावास पर तालिबान के हमले ने आठ ईरानी राजनायिकों और एक पत्रकार की जान ले ली। इस घटना ने ईरान को अफगानिस्तान के साथ युद्ध में जाने के लिए प्रेरित किया (Koepke, 2013)। हालांकि, इसी समय, पाकिस्तानी परमाणु वैज्ञानिक ए.क्यू. खान ईरान को परमाणु तकनीक प्रदान किया। 2004 में, खान ने ईरान सहित कई देशों को परमाणु तकनीक हस्तांतरित करने की बात स्वीकार की। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के सलाहकार के रूप में ईरान को आपूर्ति की है और पाकिस्तान की सेना के तत्कालीन कमांडर जनरल मिर्जा असलम बेग द्वारा आगे की भागीदारी का सुझाव दिया है। 2008 में, खान ने अपने बयान को वापस ले लिया, पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारियों पर प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए जिम्मेदारी का आरोप लगाते हुए, राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के प्रवक्ता द्वारा दावे को खारिज कर दिया।

[6]Fatemeh Aman. (November 13, 2009). Iran's Shia Policy Keeps Pakistan on Side," Jane's Islamic Affairs Analyst,.

6.3. पश्चिम एशिया में भारत

पश्चिम एशिया शुरू से ही भारत के साथ जुड़ा रहा है यहां की संस्कृति भारतीय संस्कृति से काफी मिलती–जुलती है साथ ही इसका भारत की कला संगीत व धार्मिक प्रथाओं के साथ जुड़ाव रहा है। इसीलिए इस क्षेत्र को ग्रेटर इंडिया के नाम से भी जाना जाता है । अमर्त्य सेन के अनुसार–Indina Culture as it has evolved, has always been pre powed to absorb ideas and material from elsewhere.जाहिर है कि सांस्कृतिक प्रभाव निश्चित रूप से दो तरफा प्रक्रिया है और भारत ने विदेशों से भी उधार लिया। साथ ही सांस्कृतिक और बौद्धिक अंतर संबंधों को देखें तो क्या पूर्व और क्या पश्चिम। इन सब में अंतर करना कठिन हो जाता है यह विचार करना कि यह पूरी तरीके से पश्चिमी है। इस तरह पश्चिमी देशों के साथ आपसी आर्थिक और व्यापारिक संबंध भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत इस क्षेत्र में से कच्चे तेल का एक मुख्य आयातक रहा है और इससे लाखों भारतीय नागरिकों को रोजगार तथा जीवन निर्वहन का मौका प्रदान किया है।

पश्चिम की भौगोलिक स्थिति पर प्रकाश डाले तो यह अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहां पर विशेष रूप से तीन धर्मों को मानने वाले लोग हैं यहूदी, ईसाई और इस्लाम साथ ही यहां धार्मिक तीर्थ जैसे मक्का मदीना, जेरूसलम स्थित है यहां से प्राचीन सभ्यताएं, भाषाएं, इस क्षेत्र को एक दूसरे से जोड़ कर रखती हैं जिसमें अरबी फारसी सामान्य तौर पर इसे मध्य पूर्व के रूप में जाना जाता है। इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति सामान्य नहीं है। यह पूरे अरब प्रायद्वीप से लेकर एशिया महाद्वीप के अन्य देशों सहित यूरोप महाद्वीप को छूती है मध्य पूर्व क्षेत्र इतनी जटिल है कि उनकी सीमाएं अपने आप में विशाल रूप धारण किये हैं और अफगानिस्तान पूर्व में इसके प्रमुख सदस्य अल्जीरिया, तुर्की मिस्र सीरिया, इराक सऊदी अरब और पूरा अरब प्रायद्वीप सम्मिलित है।

यह क्षेत्र राजनीतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है जो पिछले कई दशकों से अनियंत्रित एवं आस्थिर चल रहा है। यह एक लंबे समय से असुरक्षित क्षेत्र है जिसमें आतंकवाद व मैंकावे हिंसा के शिकार हुए ऐतिहासिक अभिलेख पर प्रकाश डाले तो साबित होता है कि यहां पर उग्रवाद और आतंकवाद का निकट संबंध रहा

है। ऐतिहासिक स्रोत इस बात का साक्षी हैं कि भारत पश्चिम एशिया के साथ एक लंबा और गहरा ऐतिहासिक संबंध साझा किया था क्योंकि इस पृष्ठभूमि से पश्चिम एशियाई देशों के सम्बन्ध पूरब से है। चूँकि सिंधु घाटी सभ्यताओं के बीच व्यापार संबंध स्थापित हुए थे इसलिए उन संबंधों की जड़े और भी गहरी हैं क्योंकि दोनों के बीच आर्थिक व वाणिज्य संबंध गहरे हैं।

मानव समुदाय का आवागमन सबसे पहले समुद्री मार्गो के द्वारा शुरू हुआ। प्राचीनतम मार्ग सुनहरी मार्ग के द्वारा बहरीन से सिंधु घाटी सभ्यता तक जिसे पश्चिम एशियाई देशों के द्वारा मेलूहा कहा जाता था यह बहुत ही महत्वपूर्ण मार्गों में से एक था। वास्तव में फारस की खाड़ी को ब्रिटिश साम्राज्यवादी हितों को ध्यान में रखते हुए भारत के माध्यम से संरक्षित किया गया था। यहां तक कि भारत में मुसलमानों और इस्लाम का आगमन क्षेत्र के माध्यम से आज भारत में सूफीवाद और मुस्लिम धर्मों के बीच मिश्रित शिष्टाचार विकसित हुआ हैं इस प्रकार भारतीय और पश्चिमी संस्कृतियों पर एक विशेष सम्बन्द्वता है साथ ही यहा बौद्धिक राजनीति और वाणिज्य का भी एक लंबा इतिहास है। यह आधुनिक काल के दौरान और अधिक प्रसिद्ध हो गया जब दोनों पक्षों ने वस्तु कला और साहित्य का आदान प्रदान किया, जिससे एक उच्च स्तर की सांस्कृतिक विरासत का विकास हुआ।

शीत युद्ध के अंत तक भारत पश्चिम एशिया के साथ अपने सम्बन्धो को मजबूत करने और मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस क्षेत्र में भू–राजनीतिक वास्तविकताओं को विकसित करने की नीति पर काम कर रहा था। यह इस क्षेत्र को नया आकर भी दे रहा था। जब भारत स्वतंत्र हुआ, तो पश्चिम ने पश्चिम एशिया देशों पर नियंत्रण का प्रयोग किया। सभी स्वतंत्र पश्चिम एशियाई देश कम्युनिस्ट–समर्थक, पश्चिम समर्थक शासन का जोरदार विरोध कर रहे थे और उभरे हुए शीत युद्ध में अमेरिकी नेतृत्व वाले ब्लॉक का हिस्सा बन गए थे। हालांकि, पश्चिम को बड़ी निराशा हुई क्योंकि भारत ने एक अनूठा तरीका अपनाया यह किसी भी दल में शामिल नहीं हुआ। 7 सितंबर, 1946 को, गवर्नर जनरल की कार्यकारी बैठक हुई जिसके बाद, नेहरू ने घोषणा की *"We propose, as far as possible, to keep away from the power politics of groups aligned against one another ... far too*

long have we of Asia been petitioners in Western courts and chancelleries .... We do not intend to be the playthings of others.[7]*" India consciously decided to use the expression "West Asia" to refer to the "Middle East," the latter being a term which originated in Western colonialist perspectives."* भारत– इराक का संबंध घनिष्ठ, बहुआयामी और फलदायी था। दरअसल, यह शीत युद्ध के दौरान पश्चिम एशिया में भारत का सबसे मूल्यवान और द्विपक्षीय संबंध था। भारत ने इराक में दर्जनों परियोजनाएं लागू कीं और विशेष रूप से इराकी वायु सेना के लिए सैन्य प्रशिक्षण प्रदान किया। इराक भारत का प्रमुख तेल आपूर्तिकर्ता था। और सद्दाम हुसैन ने पाकिस्तान के साथ भारत की समस्याओं के संदर्भ में स्पष्ट राजनीतिक समर्थन बढ़ाया (Gupta, 2017)। दोनों देश सोवियत संघ के करीब थे। हालाँकि, यह लगभग सभी पश्चिम एशियाई देशों द्वारा नकारात्मक रूप से देखा गया था।

1969 में भारत को बहुत अपमानित किया गया था। सऊदी अरब के शासक, जॉर्डन और मोरक्को ने रबात में मुस्लिम देशों के शिखर सम्मेलन में भारत को आमंत्रित किया, जिसके कारण इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) का गठन 1994 में हुआ। पाकिस्तान को बाहर करने की धमकी के कारण उद्घाटन सत्र के बाद भारत को भाग लेने की अनुमति नहीं थी। तत्पश्चात भारत के विरोधी पाकिस्तान ने विशेष मुद्दों पर प्रश्न उठा जैसे कश्मीर समस्या और भारत में हो रहे मुसलमानों पर अत्याचार इत्यादि।

इसने शीत युद्ध के दौरान यू.एस., यू.के., फ्रांस, तुर्की, पाकिस्तान और छह पश्चिम एशियाई राजशाही (जॉर्डन सहित ओमान को छोड़कर) के बीच एक वास्तविक राजनीतिक–सैन्य–सामरिक साझेदारी का नेतृत्व किया। इसके कारण पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक विशेष संबंध का उदय हुआ, जिसमें सऊदी अरब पाकिस्तानी सैनिकों की तैनाती और पाकिस्तानी हथियारों के अधिग्रहण और उसके उभरते हुए परमाणु हथियार कार्यक्रम का वित्तपोषण शामिल था। जैसे ही अफगानिस्तान में सोवियत संघ के खिलाफ युद्ध तेज हुआ, संयुक्त अरब अमीरात

[7]India's Relations with West Asia: A New Era Dawns. Middle East Institute. Retrived on 19 November 2018 from https://www.mei.edu/publications/indias-relations-west-asia-new-era-dawns.

(U.A.E) भी विशेष रूप से पाकिस्तान का समर्थक बन गया। यही दो अरब देश तालिबान शासन के कट्टर समर्थक बन गए।

भारत ने अपने आप को इस बदलते हुए परिवेश में एक नया खेल खेला। भारत का पहला शीत–युद्ध प्रधानमंत्री पी वी नरसिम्हा राव, जिन्होंने जून 1991 में पदभार संभाला, और नई वैश्विक भू–राजनीतिक वास्तविकताओं को समायोजित करने के लिए नाटकीय रूप से आर्थिक और विदेश नीति में बदलाव किए। विचारधारा एक संरक्षणवादी अर्थव्यवस्था, और तीसरी दुनिया की चिंताओं की वकालत कर रहे थे। राष्ट्रीय हितों में उन्मुख व्यावहारिकता अधिभावी मार्गदर्शक सिद्धांत बन गया।

6.4. पश्चिम एशिया में ईरान

एशिया विश्व का सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला महाद्वीप है, जो मुख्य रूप से पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है।[8] इस भूभाग में पश्चिमी एशिया भी सम्मलित है जोकि (मध्य पूर्व) एशिया के भीतर अपनी स्थिति के बजाय पश्चिमी यूरोप के साथ भौगोलिक स्थिति के सम्बन्ध का वर्णन करता है। पश्चिमी एशिया पूर्वी यूरोप के सीधे दक्षिण में स्थित है। यह क्षेत्र सात प्रमुख समुद्रों से घिरा हुआ है जो निम्न है–एजियन सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, फारस की खाड़ी, अरब सागर, लाल सागर और भूमध्य सागर। पश्चिम एशिया में निम्नलिखित देशों और क्षेत्रों में पश्चिम एशिया का क्षेत्र शामिल हैः अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, बहरीन, साइप्रस, गाजा पट्टी, जॉर्जिया, ईरान (इस्लामिक गणराज्य), इराक, इजरायल, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरब, सीरियाई अरब गणराज्य, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, वेस्ट बैंक और यमन है।

1932 में सऊदी अरब की स्थापना से लेकर आज तक, किंगडम और इस्लामिक गणराज्य ईरान के बीच संबंध मधुर रहे हैं। दोनों देशो के बीच एक विस्तृत श्रृंखला रही है साथ ही दोनों के साहित्य की समीक्षा करे तो सांस्कृतिक रिति रिवाज आपस में मिलते जुलते है ऐतिहासिक विश्लेषण का उपयोग ईरान और

[8] Asia Facts Retrieved on 18 Nov 2018 from https://www.kids-world-travel-guide.com/asia-facts.html

सऊदी अरब के बीच शुरुआती संबंधों और ईरानी क्रांति से पहले विभिन्न चरणों में होने वाले बदलाव को भी देखा जा सकता है। सऊदी अरब की आधिकारिक स्थापना से पहले, ईरान और सऊदी अरब का विश्व के विभिन्न क्षेत्रों से सीमित संपर्क था।

हालाँकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दोनों देशों को दो धुरी शक्तियों के साथ बाँट दिया एक तरफ ब्रिटिश और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन। ऐसी स्थिति 1941 के बाद रेजा शाह ने सऊदी–ईरानी संबंधों के स्वरूप को बदल दिया था। दोनों रूढ़िवादी राजशाही पश्चिमी–गठबंधन के शिकार बन गए जबकि दोनों इस्लामिक राज्य थे, ईरान ने इस्लाम के भीतर सऊदी अरब के महत्वपूर्ण स्थान का मुकाबला नहीं करने का फैसला किया। दोनों देशो के बीच एक ऐसा समय भी आया जब ब्रिटिशो ने फारस की खाड़ी को खाली करने का निर्णय (1960 के दशक में) लिया था। और इस क्षेत्र में ब्रिटिश प्रभाव निर्विवाद हो चुका था। जोन्स के अनुसार ब्रिटिशो ने एक बसेरा बनाया था जिसमें से उन्होंने कई दशकों तक सत्ता का अनुमान लगाया था।[9] 1820 के बाद, ग्रेट ब्रिटेन ने अपने जहाजी मार्गों और संचार लाइनों को अपने साम्राज्य तक पहुच बनाने के लिए खाड़ी में अपनी उपस्थिति स्थापित की थी। जिससे भारत और ब्रिटेन का आवागमन आसानी से हो सके। इसके पश्चात ब्रिटेन और अमेरिका के बीच इस क्षेत्र में संघर्ष चलता रहा है और दोनों देश इस क्षेत्र में अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे लेकिन अपने फायदे के लिए कुछ भी करने को तैयार थे।

ईरान–सऊदी अरब के बीच सहयोग का यह युग 1979 में ईरानी क्रांति के साथ एक दुर्घटनाग्रस्त पड़ाव में आया। जब ईरान के क्रांतिकारियों ने सऊदी अरब के खिलाफ अपने शासन को परिभाषित किया। क्योंकि ईरान कभी नहीं चाहता था की पश्चिमी से कोई समझौता हो मुख्य रूप से अमेरिका के साथ और इस विरोध से दोनों राज्यों के बीच संघर्ष तेज हो गया क्योंकि वे वर्षों से कई क्षेत्रों में लड़े। क्रांति के तुरंत बाद, ईरान–इराक के साथ एक संघर्ष में सम्मिलित हो गया। रियाद ने आठ–वर्षीय ईरान–इराक युद्ध में बगदाद ने आर्थिक और तार्किक रूप से

[9]Gregory F. Gause, III, "British and American Policies in the Persian Gulf, 1968-1973." Review of International Studies 11,04 (1985).

समर्थन किया क्योंकि रियाद बगदाद को किसी भी तरह की क्षती ईरान न पंहुचा सके।

युद्ध समाप्त हो गया और क्रांति के सूत्रधार, अयातुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी की मृत्यु हो गई, तो ईरान की नियत भी बदल गई। ईरान अपनी क्रांतिकारी राजनीति के कारण दुनिया से अलग–थलग रहने की कामना नहीं करता था, और अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में फिर से प्रवेश करना चाहता था। दृष्टिकोण में परिवर्तन और अपनी क्रांतिकारी विचारधारा को ख़त्म करते हुए ईरान ने धीरे–धीरे सऊदी अरब से संपर्क किया। जैसे ही देशों के बीच संबंध सामान्य हुए, और एक दशक से अधिक समय तक चलने वाले संघर्ष में पुनः प्रवेश किया। 2003 में इराक में अमेरिकी हस्तक्षेप होने तक यह स्थिति बनी रही। सऊदी अरब और ईरान ने हस्तक्षेप से पहले इराक के प्रति एक समान दृष्टिकोण साझा किया था। ईरान और इराक में दुश्मनी का एक लंबा इतिहास था और 1990–91 के खाड़ी युद्ध के बाद सऊदी अरब और इराक के बीच सौहार्द गायब हो गया, जब इराक ने सऊदी अरब पर हमला किया।[10] उपयुक्त विशलेषण से पता चलता है की ईरान और सऊदी अरब के साथ राजनीतिक उतार चढ़व रहे है।

सऊदी अरब के साम्राज्य और इस्लामी गणतंत्र ईरान आज पश्चिम एशियाई राजनीति के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रीय खिलाड़ियों में से दो हैं। दोनों में बड़ी आबादी और विस्तृत क्षेत्र हैं, और सामूहिक रूप से दुनिया में तेल के सबसे बड़े भंडार में से कुछ देशो से ऊपर अपना स्थान ग्रहण करते हैं।[11] सऊदी अरब संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और मिस्र, सीरिया और इराक जैसी पारंपरिक शक्तियों के साथ निकटता और साझेदारी करने की कोशिश और भरोसा कर सकता है। लेकिन सऊदी अरब, ईरान के अंतर्राष्ट्रीयकरण और अमेरिका के साथ उसके बढ़ते संबंधों को अपनी क्षेत्रीय स्थिति के लिए एक गंभीर खतरे के रूप में देखा है।

[10] Weddington Derika (2017). Revalry in the Middle East: The History of Saudi Iranian Relations and its Implications on American Foreign Policy. Retrived on 20 November 2018 from https://bearworks.missouristate.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4139&context=theses

[11] Sharma Anu (2016). Iran Saudi Arabiya and Israel Trilateral Relations: Post Iran Nuclear Deal. Defence and Diplomacy. 5(2).

ईरानी–इजरायल संबंधों को चार प्रमुख चरणों में विभाजित किया जा सकता है पहला 1947–53 की अवधि अर्थात मुहम्मद रेज़ा पहलवी राजवंश के युग के दौरान अनुकूल अवधि के नाम से भी जाना जाता है दूसरा 1979 की ईरानी क्रांति से 1990 तक की बिगड़ती अवधि, और अंत में सोवियत संघ के विघटन के बाद। 1947 में, फिलिस्तीन जनादेश के मुद्दे को हल करने के लिए ईरान फिलिस्तीन (UNSCOP) पर एक विशेष समिति बनाने के लिए चुने गए ग्यारह देशों में से एक था। बहुत विचार–विमर्श के बाद समिति ने फिलिस्तीन के लिए एक विभाजन योजना प्रस्तुत की, जिसमें समिति के ग्यारह सदस्यों में से आठ का समर्थन था। 1947 में, ईरान उन 11 देशों में शामिल था, जिन्होंने फिलिस्तीन के लिए संयुक्त राष्ट्र विभाजन योजना के खिलाफ मतदान किया था और दो साल बाद, ईरान ने भी संयुक्त राष्ट्र संघ में इजरायल के प्रवेश के खिलाफ मतदान किया। फिर भी, ईरान तुर्की के बाद इजरायल को एक संप्रभु राज्य के रूप में मान्यता देने वाला दूसरा मुस्लिम बहुल देश था। 1953 के तख्तापलट के बाद, जिसने पश्चिमी मोहम्मद रजा पहलवी को सत्ता में फिर से स्थापित किया, दोनों देशों के बीच संबंधों में काफी सुधार हुआ। 1979 की क्रांति के बाद, ईरान ने सभी राजनयिक और वाणिज्यिक संबंधों को इजरायल के साथ जोड़ दिया, और इसकी इस्लामिक सरकार इजरायल की वैधता को एक राज्य के रूप में मान्यता नहीं देती है। हालाँकि आपसी दुश्मनी ने ईरान की 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से इजरायल–ईरानी संबंधों को आगे बढ़ने की कोशिश की है। दोनों पक्षों कभी भी प्रत्यक्ष सैन्य संघर्ष में शामिल नहीं हुए हैं।[12] ईरानी क्रांति से पहले और बाद में, दोनों ने आम क्षेत्रीय खतरों का सामना करते हुए कई बार सहयोग किया है। और इस तरह दोनों देश आपसी सहयोग के द्धारा आगे बढ़ रहे है.

1946 में सीरिया को फ्रांस से स्वतंत्रता मिली, लेकिन 1970 के दशक के अंत हाफिज अल–असद के शासनकाल तक इस देश में सरकार तंत्र, नेतृत्व या राष्ट्रीय स्थिरता नहीं थी। 1946–1970 के बीच सीरिया ने कई हिंसक तख्तापलट किए। स्वर्गीय हाफ़िज़ अल–असद ने 1970 तक सीरिया पर शासन किया लेकिन

[12]Kaye, D. D., Nader, A., & Roshan, P. (2011). *Israel and Iran: A Dangerous Rivalry*. RAND NATIONAL DEFENSE RESEARCH INST SANTA MONICA CA.

2000 में मृत्यु हो जाने के कारण इस देश का नेतृत्व उनके बेटे बशर अल–असद को दिया गया था जो वर्तमान समय में सीरिया का नेतृत्व करते हैं। 1979 में इस्लामिक ईरान के गठन के बाद से दोनों देशों के बीच संबंध विकसित हुए। दोनों देशो की विचारधाराओं, साथ ही साथ उनकी राजनीतिक नींव और संरचनाओं में अंतर होने के बावजूद भी सम्बन्धो को जारी रखा गया है। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कैसे एक क्रांतिकारी इस्लामी ईरान सीरिया के साथ एक धर्मनिरपेक्ष, व समाजवादी राज्य के साथ खुद को बदल सकता है। कुल मिलाकर, हाल के वर्षों में सीरियाई विद्रोह और मार्च 2011 के बाद से सीरियाई शासन के लिए ईरान का पूर्ण समर्थन रहा है[13] दोनों देशों की अपनी विदेश नीतियों को समन्वित करने की प्राथमिकताओं ने एक दूसरे को जोड़ रखा है और इसे आगे बढ़ाने के लिए, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय अखंडता के रखरखाव और दो राज्यों की स्वतंत्रता की रक्षा पर एक मजबूत ध्यान केंद्रित है। अगर आतंक के खिलाफ विश्वव्यापी जग की बात करें तो वर्तमान हालात यही इशारा कर रहे हैं कि अगर भारत ईरान व अमेरिका यह जंग हार नहीं रहा तो जीत भी उससे कोसों दूर है। पूरा पश्चिम एशिया समस्याग्रस्त है और अमेरिका जैसे देशो के पास भी ऐसी कोई विदेश नीति नही जिससे इन समस्याओं से जूझने के लिए कोई ठोस रणनीति की जा सके।

चित्र 6.1. ईरान की भौगोलिक स्थित

Adopted from Kanchana Ramanujam (2019). West Asia: An Overview of Recent Important Developments

[13] Ibrahim M, Dr. Nader. Nasur, Bani (*October*, 2014). *International Journal of Humanities and Social Science. 4(12).*

अध्याय–सप्तम् अध्याय

वैश्विक राजनीति में भारत–ईरान सम्बन्ध

आधुनिक युग में भारत–ईरान संबंध को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। ईरान एशिया के भीतर भू–स्थानिक संबंधों को बदलने में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है पश्चिमी देश हमेशा भारत और ईरान को अलग–थलग करने की कोशिश करने में लगे रहते हैं। इसके बावजूद दोनों देशों के आपसी संबंधों को कम नहीं किया जा सकता है। भारत–ईरान के बीच अक्सर अनदेखे द्विपक्षीय संबंध न केवल आकर्षित करते हैं, बल्कि एक ऐसा प्लेटफार्म प्रदान करते हैं, जिसके द्वारा पूरे एशिया में स्थानांतरित किये गये भू–स्थानिक संबंधों को देखा और समझा जा सकता है। दोनों देश विश्व में हो रहे परिवर्तनों में भी साथ है जैसे जलवायु परिवर्तन, संस्थागत परिवर्तन इत्यादि। इसके साथ ही दोनों देशों की विदेश नीतियों के रणनीतिक उद्देश्य तथा भौगोलिक निर्देश अंतरराष्ट्रीय संवाद की रूपरेखा को मोटे तौर पर परिभाषित करते हैं। लेकिन समय के अनुसार विदेश नीतियों में परिवर्तन होता रहता है। यह परिवर्तन न केवल घरेलू बाध्यताओं के अनुसार होता है बल्कि वैश्विक संपर्क की संभावनाओं एवं क्षमताओं के अनुसार भी परिवर्तित किया जाता है ताकि राष्ट्रीय हितों को सरकार उचित तरीके से पूरा कर सके।

भारत इस वैश्विक जगत में अपने आप को एक उभरती हुई शक्ति के रूप में अपनी जगह बनाने का प्रयत्न कर रहा है और अपना उत्तरदायित्व विश्व में निभाने के लिए हमेशा से प्रयत्नशील रहा है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों या समस्यों पर सिर्फ अपनी प्रतिक्रिया ही नहीं दी, अपितु होने वाले घटनाओ को भी रोकने का प्रयास करता रहा है। इसके चलते विश्व ने भी क्षेत्रीय और वैश्विक दूरदर्शिता रखने वाले इस प्रतिष्ठित व निष्पक्ष नेतृत्व वाले देश की भूमिका को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया। इसके परिणामस्वरूप वैश्विक शासन सुधार, जलवायु परिवर्तन, बहुपक्षीय व्यापार सौदों, इंटरनेट अभिशासन तथा साइबर सुरक्षा एवं अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद जैसे विभिन्न मुद्दों पर वैश्विक बहस को आकार देने में भारत के दृष्टिकोण ने

महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।[1] भारत ने विभिन्न सहभागी देशों के साथ आतंकवाद का मुकाबला करने संबंधी संयुक्त कार्य समूहों के माध्यम से सुनियोजित परामर्श करना जारी रखा, तथा नवंबर, 2015 में ब्रिक्स तथा जी–20 शिखर–सम्मेलनों में आतंकवाद के खतरे के प्रति अपनी कड़ी चिंता व्यक्त की।

भारत और ईरान वैश्विक दौर में एक दूसरे को न केवल साथ दे रहे है बल्कि भारत–चीन की प्रतिस्पर्धा में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है और भारत की आर्थिक उन्नति में भी पूर्ण सहयोग कर रहा है जिसे भारत विश्व स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बना सकता है इस अध्याय में वैश्विक राजनीति क्या है तथा इसके क्या पहलू है तथा दोनों देशो किस तरह से अपना सहयोग प्रदान कर रहे है साथ ही दोनों देशो का आतंकवाद के खिलफ क्या विचारधारा है विशेष तौर पर सीरिया, फिलिस्तीन, इजरायल देशों के खिलाफ क्या ईरान भारत का सहयोग कर रहा है कि नही क्यों की ईरान एक इस्लामिक राज्य होने के करण इसकी विचारधारा भी आतकंवादी के समरूप न हो। इसके साथ ही दोनों देशों के वैश्विक सम्बन्धो का भी वर्णन इस अध्याय में किया गया है।

7.1. वैश्विक राजनीति

वैश्विक राजनीति को विश्व राजनीति के रूप में भीं जाना जाता है जिसके तहत दुनिया के राजनीतिक, आर्थिक इत्यादि अहम् आयामों का अध्ययन किया जाता है साथ ही इस क्षेत्र के केंद्र में सामाजिक शक्ति से सम्बंधित राजनीतिक वैश्वीकरण के विभिन्न प्रकियाएं है जिसके तहत विश्व के विभिन्न राज्य–राष्ट्र, गैर सरकारी संगठन और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का अध्ययन किया जाता है शॉन व्हाइट (2016) के द्वारा यह कहा गया कि–भू–राजनीति अलग–अलग देशों या उनके भौगोलिक स्थानों के राजनीतिक महत्व के बीच संबंधों का अध्ययन भी करता है क्योंकि वैश्विक राजनीति का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय संबंध इसे गहराई से प्रभावित करते हैं।[2]

[1] वार्षिक रिपोर्ट .(2015–16). नीति नियोजन एवं अनुसंधान प्रभाग, विदेष मंत्रालय. नई दिल्ली

[2]White Sean (2016). What is global politics? Retrived on sep 11 2018 from https://www.quora.com/What-is-global-politics

वैश्विक राजनीति, एक राष्ट्रीय या क्षेत्रीय स्तर की बजाय वैश्विक स्तर पर संचालित राजनीति को संदर्भित करती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि राजनीति के वैश्विक या विश्वव्यापी आयाम हाल के दशकों में, अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसके अलावा यह भी कहा जा सकता है कि दोनों किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुये हैं और वह कौन–कौन से कारक है जिसके द्वारा विश्व एक दूसरे में पिरोया हुआ है जो किसी देश को प्रभावित करते हैं और राज्य एक दूसरे के साथ बातचीत करते है जैसा कि एंड्रयू हेवुड ने अपनी पुस्तक ग्लोबल पॉलिटिक्स में वैश्विक राजनीति के विभिन्न आयाम को प्रदर्शित किया है जो निम्न चित्र में परिभाषित है जिसके चलते विश्व एक दूसरे के करीबी के साथ जुड़ा हुआ है।

लॉयड कॉक्स (2007) ने अपने लेख में तर्क दिया है कि वैश्विक राजनीति से तात्पर्य उन राजनीतिक संबंधों और गतिविधियों के तरीको से है जो राज्य की सीमाओं के परे हैं, अर्थात जिनके परिणाम संभावित और वास्तव रूप में दुनिया भर में हैं। इस प्रकार, वैश्विक राजनीति में अंतर्राज्यीय संबंध शामिल नहीं हैं, लेकिन यह अंतरराष्ट्रीय संबंधों के यथार्थवादी विद्वानों द्वारा परंपरागत रूप से तैनात किए जाने वाले दृष्टिकोणों के मामले में उल्लेखनीय है।[3]

चित्र 7.1. वैश्विक राजनीति के विभिन्न आयाम

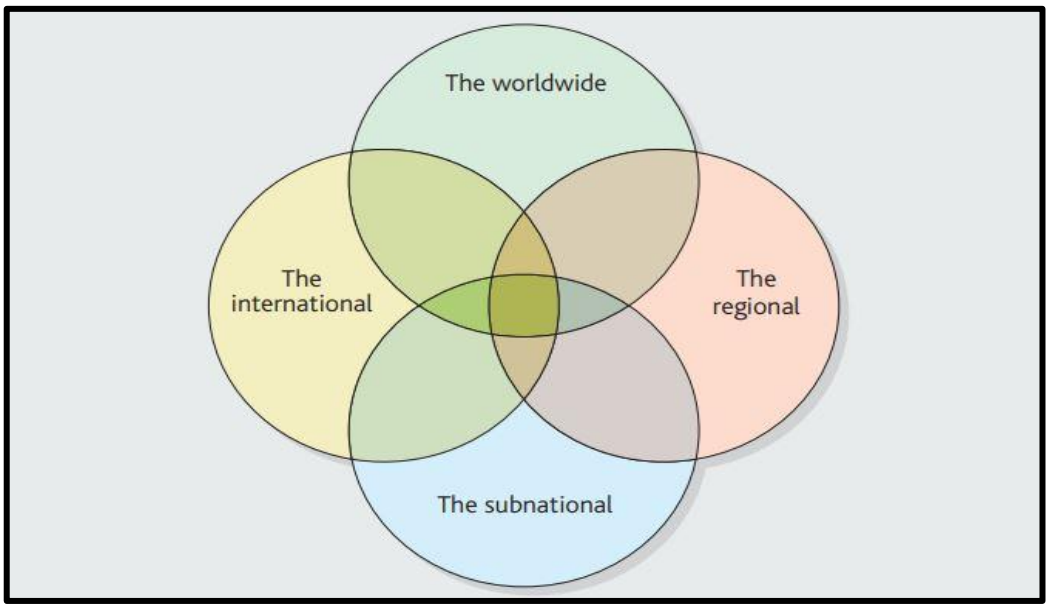

Adopted from Andrew Heywood Book Global Politics

[3]https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/9781405165518.wbeosg048#accessDenialLayout

वही कुछ लेखकों का मानना है की वैश्विक राजनीति में होने वाले प्रभावों व चुनौतियों का अध्ययन किया जाता है क्योंकि इस चुनौतियों को भुलाया नहीं जा सकता है। इवानोव, इगोर (2018) ने भी अपने लेख में लिखा है की मानव समुदाय यदि ऐतिहासिक चुनौती का सामना करती है तो इसका प्रभाव सीधे तौर पर भविष्य पर पड़ेगा और यह तस्वीर स्पष्ट रूप से उभरकर सामने आएगी हालाँकि, इस मामले की वास्तविकता यह है कि जैसे–जैसे विश्व 21वीं सदी के दूसरे दशक के अंत में जायेंगे तो हम सभी विभिन्न प्रकार के खतरों से निपटने के लिए मजबूर हो जायेंगे जैसे–अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से लेकर ग्लोबल वार्मिंग तक और एक असंतुलित विश्व वित्तीय प्रणाली, परमाणु हथियारों की दौड़ आदि अहम समस्या है जिसे भुलाया नही जा सकता है।[4]

7.2. भारत–ईरान संबंध आतंकवाद (सीरिया, फिलिस्तीन, इजरायल) की समीक्षा

भारत और ईरान वैश्विकरण के दौर में दोनों देश आतंकवाद जैसी समस्याओं से ग्रसित है क्योंकि ईरान में इस्लामिक स्टेट व भारत में अलकायदा जैसे आतंकवादी समूहों ने आतंक फैला रखा है इसलिए दोनों देश आतंकवाद को समाप्त करने के लिए प्रभावी प्रयास कर रहें हैं, इसलिए दोनों देश अपनी सुरक्षा को लेकर बहुत ही चिंतित है और पूरा विश्व आतंकवाद का विरोध कर रहा है। पिछले कई वर्षो के दौरान आतंकवाद आधुनिक विश्व में त्रासदी का मुख्य कारण रहा है। इसलिए इसके विरुद्ध भारत ही नहीं बल्कि विश्व के अनेक देश एक साथ खड़े है और भारत एक लम्बे समय से आव्हान कर रहा है। भारतीय प्रधानमंत्री ने बहुपक्षीय मंचों पर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के विरुद्ध अपनी बातो को रखा है जिसके वजह से विश्व में सभी देश इस चिंता को महत्वपूर्ण माना है। इसके साथ ही भारत सरकार ने आतंकी गतिविधियों पर रोक लगाने व आतंकी गुटों की पहचान करने के लिए अमरीका, रूस, फ्रांस, यू के और जापान के साथ मिलकर सहयोगी तंत्रों की स्थापना की। भारत तथा अरब देशों के साथ सामरिक सुरक्षा वार्ता तंत्र की स्थापना

[4]Igor, Ivanov, (2018). New Challenges in Global Politics: A Russian Perspective. Governance in an Emerging new World. Retrived on 11 Nov, 2018 from https://www.hoover.org/research/new-challenges-global-politics-russian-perspective

करने और आतंकवाद–विरोधी सहयोग में वृद्धि करने पर सहमत हुए। भारत अरब देशों के साथ अपने राजनीतिक, आर्थिक, व सामरिक सम्बन्ध बनाये हुये है जिसके कारण यह इस क्षेत्र में भी पूर्ण रूप से अपना अधिपत्य स्थापित कर रखा है।

भारत और ईरान दोनों फिलिस्तीन व इजराइल के आन्तरिक लड़ाई में सम्मलित रहे है। 1948 में फिलिस्तीन के विभाजन के बाद यहूदियों के राष्ट्र राज्य के रूप में इजराइल की स्थापना की गई थी इन दो राज्यों के बीच हमेशा से ही संघर्ष रहा है। सत्तर के दशक तक अधिकांश अरब राज्यों ने इजरायल के अस्तित्व को मानने से इनकार किया इजराइल के जन्म के बाद बड़ी संख्या में लोग अपना घर बार छोड़कर इजराइल में स्थापित हो गए लेकिन इस शत्रुता के वातावरण से नहीं निकल पाये। इन दो राज्यों के बीच चार युद्ध हुए जो क्रमशः 1948, 1956, 1967, तथा 1973 में हुए परन्तु इजरायल को पराजित नहीं किया जा सका इसके साथ ही यह अपने राज्य को विस्तृत करने में लगा रहा–पश्चिमी किनारा, गाजा पट्टी और गोलान की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया। इसके पश्चात फिलिस्तीन अपने अधिकारों की रक्षा व अपने घर को वापस पाने के लिए कई संगठन बनाये जिसमे से कुछ उग्रवादी संगठन भी थे जैसे–फिलिस्तीनी मुक्त संगठन। लेकिन यह संगठन लोगो में बहुत ही लोकप्रिय था। इसलिए भारत पूर्वी यूरोपीय सहित अनेक देशों ने फिलिस्तीनियों को निर्वासित सरकार के रूप में मान्यता प्रदान कर दिया। दूसरी तरफ इजरायल को पश्चिमी देश समर्थन कर रहे थे। तथा कुछ लेखक इस राज्य को पश्चिमी गुट की चौकी मानते थे। क्योंकि अमेरिकी और सोवियत संघ इस क्षेत्र में अपना अपना वर्चस्व स्थापित करना चाह रहे थे इसलिए यह कोई भी नही चाहता था कि इन दोनों देशों के बीच शांति कायम रहे। इसके बावजूद भी 1977 में अमेरिका ने इन दो गुटों के बीच शांति प्रयास आरम्भ किये। कैम्प डेविड ने 1976 में अमेरिकी राष्ट्रपति कार्टर की उपस्थिति में मिस्र–इजरायल समझौता हुआ लेकिन इस मौके पर इजरायल के प्रधानमंत्री व मिस्र के राष्ट्पति अनवर सादात ने शांति समझौता पर हस्ताक्षर किये और नयी दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास किया।

कई दशकों की शत्रुता के बाद इजरायल तथा फिलिस्तीन मुक्ति संगठन दोनों में शांति के लिए प्रयास करने प्रारंभ कर दिए और 1993 में इजरायल और

फिलिस्तीन मुक्ति संगठन में पूर्ण रूप से शांति के लिए समझौते पर हस्ताक्षर भी किये लेकिन इन दोनों राज्यों के मध्य कुछ ऐसी गलतफहमी है। जिससे आपसी संबंध सुधरने का नाम ही नहीं ले रही हैं हालांकि इजराइल के पास कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसके कारण किसी भी निर्णय पर पहुँचना असंभव दिखाई दे रहा है जैसे–पश्चिमी किनारे, गाजापट्टी उनमें से एक हैं। ब्रिटेन ने दोनों राज्यों के बीच शांत प्रक्रिया को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था लेकिन 1998 में अमेरिका की तरफ से होने वाला शिखर वार्ता में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेंतन्याहू ने भाग लेने से मना कर दिया।

भारत ने फिलिस्तीन से राजनीतिक व आर्थिक सहायता के रूप में अपना संबंध जारी रखा। भारत इस क्षेत्र में शांति प्रक्रिया स्थापित करने पर अपनी चिंता से फिलिस्तीन को अवगत कराया और इस क्षेत्र में दीर्घकालीन न्याय संगत और व्यापक शांति केवल संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के संकल्प 242 और 338 के आधार पर ही स्थापित हो सकती है। राष्ट्रपति यासिर अराफत अगस्त 2000 में दिल्ली का दौरा किया और भारत के गृहमंत्री ने फिलिस्तीन का दौरा किया।[5] जिसमे दोनों देशों के बीच विभिन्न मुदो पर बात हुई और वैश्विक राजनीति में एक साथ रहते हुए आर्थिक सामरिक क्षेत्र में एक दूसरे का सहयोग करते रहने का प्रण किया।

वर्ष 2000 में इजरायल के मंत्री के साथ आपसी सहयोग के साथ द्विपक्षीय संबंध मजबूत किये जाने की बात कही तथा इस वर्ष में गृहमंत्री ने आतंकवाद का मुकाबला करने से संबंधित कार्यकारिणी दल का नेतृत्व किया। इसके पश्चात भारतीय विदेश मंत्री ने इजरायल की यात्रा पर गए और द्विपक्षीय वार्ता में अहम मुद्दों पर बात हुई जिसमें से आर्थिक व क्षेत्रीय संबंध मजबूत करने की बात हुई। भारत आतंकवाद से संबंधित घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए भारत ने विभिन्न भागीदार देशो के साथ आतंकवाद का सामना करने पर सयुक्त कार्य समूह (जे०डब्लू०जी०सी०टी०) के माध्यम से सुनियोजित विचार विमर्श करना जारी रखा। वर्ष 2015–16 के दौरान भारत ने रूस, बिम्सटेक, यूरोपीय संघ, नीदरलैंड,

[5] वार्षिक प्रतिवेदन, (2000-2001). नीति नियोजन एवं अनुसंधान प्रभाग, विदेष मंत्रालय. नई दिल्ली

इजरायल, आस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, चीन, जापान, फ्रांस और मिस्र के साथ आतंकवाद का सामना करने हेतु सयुक्त कार्य समूह की बैठक का आयोजन किया।[6] भारत द्वारा आतंकवाद को रोकने के लिए 'ग्लोबल काउंटर टेरोरिज्म फोरम' (जीसीटीएफ) संगठन 2011 में स्थापित किया गया था तथा भारत इसका संस्थापक सदस्य के रूप में हमेशा इस बैठक में भाग लेता रहा है।

इसके साथ ही भारत–इजराइल द्विपक्षीय संबंध साइबर सुरक्षा तथा अंतरिक्ष जैसे नए क्षेत्रों में विस्तारित होने के साथ–साथ रक्षा तथा कृषि जैसे सहयोग के परंपरागत क्षेत्र में भी सहयोग प्रदान कर रहे हैं। 13–15 अक्तूबर, 2015 तक राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी इजराइल की पहली राजकीय यात्रा की। इजराइल के राष्ट्रपति रूवेन रिवलिन तथा प्रधान मंत्री बेंजामिन नेंतान्याहू के साथ बैठक के अतिरिक्त राष्ट्रपति ने इजराइली संसद के एक सत्र को संबोधित किया तथा भारत–इजराइल संबंधों पर एक नीति–परक वक्तव्य दिया था। इस यात्रा के दौरान विश्वविद्यालयों के बीच 8 करारों सहित कई अन्य करारों पर हस्ताक्षर किए गए थे। जैसे एयर स्टाफ वार्ता तथा यात्राओं के आदान–प्रदान जैसे संस्थागत तंत्रों के माध्यम से रक्षा सहयोग में प्रगति हुई। आई0एन0एस0 त्रिकंद ने अगस्त में हाइफा में रुकने की अनुमति मांगी थी। संयुक्त रूप से विकसित बराक–8 मिसाइल का नवंबर में इजराइल में सफलतापूर्ण प्रक्षेपण किया गया था। नियमित उच्च–स्तरीय रक्षा आदान–प्रदान के तौर पर इजराइल के नौ–सेना तथा वायु–सेना प्रमुखों ने भारत की यात्रा की। अंतर–सरकारी करार के कार्यान्वयन के माध्यम से स्वदेशी सुरक्षा में सहयोग को मजबूत किया गया था। पुलिस आधुनिकीकरण, क्षमता निर्माण तथा सीमा प्रबंधन संबंधी कार्य समूहों ने इस अवधि के दौरान इजराइल में मुलाकात की थी तथा इन क्षेत्रों में सहयोग के विशेष क्षेत्रों का आकलन किया था। अन्य क्षेत्रों में, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन तथा इजराइल अंतरिक्ष एजेंसी के बीच द्विपक्षीय बैठक अक्तूबर में जेरूसलम में हुई। साइबर के क्षेत्र में कॉनफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज (सी०आई०आई०) तथा तेल अवीव विश्वविद्यालय के बीच जून में चौथी साइबर गोलमेज बैठक हुई थी। इस गोलमेज बैठक में दोनों पक्षों के उद्योग तथा

[6] ibid

शिक्षा से विशेषज्ञ शामिल थे। इसके बाद, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई0आई0टी0) कानपुर ने इजराइली विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग व विभिन्न मॉडलों पर चर्चा कर रहा है। इस अवधि के दौरान भारतीय संस्थानों और इजराइली विश्वविद्यालयों के बीच अकादमिक संबंधों में वृद्धि हुई है। कृषि के क्षेत्र में, भारत–इजराइली कृषि सहयोग (2015–18) का तीसरा चरण सितंबर में आरंभ हुआ। 2015 में कृषि में उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन गुजरात में किया गया था।

अक्तूबर, 2015 में इजराइल में 8वां भारत–इजराइल मंच का आयोजन किया गया था। विविध चर्चाओं में अन्य बातों के साथ–साथ द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश, विविध वस्तुओं तथा रक्षा साझेदारी में नए आयाम जैसे विषय शामिल थे। भारतीय यहूदी समुदाय तक मिशन की पहुंच में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। भारतीय यहूदियों के लिए तीसरा सम्मेलन 2015 में हुआ था। जिसमें समुदाय के सभी वर्गों ने भाग लिया था। माननीय विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने 17–18 जनवरी, 2016 तक इजराइल की द्विपक्षीय यात्रा की थी। यह विदेश मंत्री की पहली इजराइल यात्रा थी जिसने इजराइल के साथ भारत के बहुमुखी संबंधों को और आगे बढ़ाया गया था।[7]

भारत और सीरिया ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अधिकांश वैश्विकमुद्दों पर सामान्य स्थिति है। सीरिया भारत की स्थिति की भी सराहना करता है एवं आग्रह करता है कि अरब राष्ट्र के आंतरिक मामलों में कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। भारत में सीरिया के राजदूत, रियाद अब्बास, कई वर्षों से बशर अल–असद शासन के लिए अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, जोकि भारत में एक लोकप्रिय व्यक्ति के साथ साथ राजनयिक और अन्य व्यस्तताओं में सबसे प्रमुख चेहरों में से एक है, जहां वह अक्सर अपने देश के सभी नवीनतम घटनाक्रमों की व्याख्या करते हुए पाये जाता है।[8] कई साल की उपेक्षा के बाद, सीरिया एक बार फिर भारत के विचारो पर अपना ध्यान आकर्षित किया है। भारत में सीरिया के राजदूत, रियाद कामेल अब्बास ने भारत को सीरिया के मित्र के रूप में संदर्भित किया, और कहा कि दमस्कुस

[7]वार्षिक रिपोर्ट (2015-16). नीति नियोजन एवं अनुसंधान प्रभाग, विदेष मंत्रालय. नई दिल्ली

[8]Syria always supports India. (February 18, 2018). The Statesman. Retrieved on 16 Oct 2018 from https://www.thestatesman.com/exclusive-interviews/syria-always-supports-india-1502587900.html

(Damascu) भारत को वार्ता में भाग लेना पसंद करेगा।[9] द हिंदू अखबार के एक साक्षात्कार में, अब्बास ने दोहराया कि ''शासन परिवर्तन के लिए कोरस में शामिल नहीं होने के भारत के रुख की सराहना की। सच कहूं, तो मैंने पहले ही यह कहा है कि अगर भारत ने जो किया है वह हर किसी ने किया है, तो सीरिया में कोई समस्या नहीं होगी।'' प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोई आतंकवाद अच्छा या बुरा नहीं होता केवल आतंकवाद होता है।[10]

भारत के साथ आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी प्रयास में ईरान एक आकर्षक भागीदार हो सकता है मार्च 2001 में भारतीय रक्षा सचिव की तेहरान यात्रा के दौरान, एक सुरक्षा वार्ता समझौता हुआ। जिसमें सुरक्षा एक अहम मुद्दा रहा भारत ने पाकिस्तान की धरती से कथित तौर पर शुरू की गई आतंकवादी गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए ईरान के साथ अपनी आतंकवाद–रोधी साझेदारी के विस्तार की संभावना तलाश रही है। पिछले कुछ दिनों में दो "जघन्य" आतंकवादी हमलों (पुलवामा एवं तेहरान) से पीड़ित होने के बाद, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने उप विदेश मंत्री सय्यद अब्बास अरघची से मुलाकात की और दोनों देश आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए करीबी सहयोग पर सहमति व्यक्त की है।[11]

7.3 वैश्विक दौर में भारत–चीन प्रतिस्पर्धा

21वीं सदी को एशियाई सदी के रूप में उल्लेखित किया जाता है[12] क्योंकि एशिया में पिछले पचास वर्षों में काफी प्रगति हुई है जैसे– आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक इत्यादि। इस क्षेत्र में प्रमुख खिलाड़ियों में जापान और चीन संभावित शक्तियाँ के रूप में अपनी पहचान हासिल की है। जिसमे भारत भी प्रयासरत है भारत अपनी आंतरिक सुधारों को पूरा कर रहा है और क्षेत्रीय देशो के साथ अपने सम्बन्ध मजबूत कर रहा है ताकि महान शक्ति बनने की क्षमता हासिल कर सके। भारत और चीन स्वतंत्र परिदृश्य के रूप में विश्व पटल पर उभर रहे है और इसके

[9] https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/india-looks-to-deepen-security-ties-with-syria/articleshow/50524788.cms
[10] https://thediplomat.com/2015/09/india-and-the-syrian-civil-war/
[11] India, Iran agree on close cooperation to fight terrorism. *The Economic Time.* Retrieved on 13 May 2019 from https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/india-iran-agree-on-close-cooperation-to-fight-terrorism/articleshow/68038205.cms
[12] Upadhyay, A. K. (2014). *Evolving Sino- Indian Relations in the 21stCentury*. International Journal of applied Social Science. 1 (2&3).72-81

साथ ही दोनों देशो की एक गहरी ऐतिहासिक यादों के साथ प्राचीन सभ्यता भी है।[13] प्राकृतिक वातावरण ने दोनों देशों को शांति से अलग रखा, लेकिन आधुनिक संचार ने भौतिक बाधाओं को तोड़ दिया। भारत की विदेश नीति में, चीन का संबंध एक महत्वपूर्ण कारक रहा है। स्वतंत्रता के पश्चात, भारत विभाजन की समस्याओं से जूझ रहा था और चीन अपने गृहयुद्ध की समस्याओं में लगा रहा। जिसके कारण एक–दूसरे के साथ निकट संबंध नहीं बन पाये। वर्तमान में भारत और चीन के सम्बन्ध को नियो रियलिस्ट स्टीफन एम वॉल्ट (1985) के द्वारा प्रतिपादित "थ्रेट ऑफ़ थ्रेट" की धारणा के द्वारा इसे अच्छी तरह से समझा जा सकता है, जहाँ उन्होंने एक दूसरे के गठबंधन को बेहतर ढंग से समझाने के लिए पहले से ही स्थापित "बैलेंस ऑफ़ पावर" सिद्धांत को संशोधित किया है।[14]

भारत–चीन की नीति में एक बड़ी समस्या पाकिस्तान है। जिसके कारण भारत की महत्वाकांक्षाओं को विफल करने और दक्षिण एशिया में अपनी पैठ बनाये रखने में चीन पाकिस्तान को एक मोहरा के रूप में उपयोग कर रहा है। और भारत इस कूटनीति का दुष्प्रभाव सीधे अपने संघर्ष के रूप में देखा रहा है। यह कूटनीति न केवल एक संघर्ष बल्कि भारत के खिलाफ खुली दुश्मनी का माहौल पैदा कर रहा है। जिसकी वजह से भारतीय उन्नति में रुकावट व अशांति का माहौल बना रहने का डर बना रहता है। बल्कि की दोनों देशो के बीच आर्थिक संबंध पर असर पड़ता है।

चीन ने पाकिस्तान को परमाणु उपलब्ध करवाने और हथियार वितरण क्षमता प्रदान करके चीन ने दक्षिण एशिया के भीतर भारत को रणनीतिक रूप से निष्प्रभावी कर दिया है।[15] चीन ने पाकिस्तान को बिना किसी संघर्ष के, भारत के खिलाफ अपनी राजनीति जारी रखने का साधन बना दिया है, किसके कारण वह भारत को सैन्य रूप में जवाबी कार्रवाई कर सके चाहे वह आन्तरिक रूप से कमजोर ही क्यों न हो। चीन ने काफी वर्षों से पाकिस्तान के साथ एक घनिष्ठ सम्बन्ध बनाये हुये है

[13]Gonsalves, Eric. (1998). *Positive Agenda for Positive Action: Better India-China Understand.* Gyan Publishing House, New Delhi.
[14]Upadhyay, A. K (2014). Evolving Sino- Indian Relations in the 21stCentury. *International Journal of Applied Social Science*. 1 (2&3). 72-81.
[15]The Sino- Pakistan Defence Deals: A Factfile. (2011). IIT Madras China Studies Centre. Retrieved on 11 Feb 2019 froom https://csc.iitm.ac.in/articles/sino-pakistan-defence-deals-factfile

और इसे लगातार सैन्य व आर्थिक मदद भी करता रहा है और राजनीतिक सम्बन्ध को लगातार विकसित किया है। एफ०ए०एस०रिपोर्टों के अनुसार, चीन ने पाकिस्तान को मिसाइल–3, एम–11 का चीनी संस्करण और एम–9, एम–18 का संस्करण उपलब्ध किया है।[16] उपयुक्त हथियार पाकिस्तान को उच्च तकनीक वाले हथियारों की आपूर्ति से संबंधित है जो की कश्मीर और आतंकवादी घटनो में उपयोग किए जाते हैं। चीन हमेशा से भारत के खिलाफ अपनी राजनीतिक रोटी सेकता रहा है। राष्ट्रपति जियांग ने कश्मीर के मुद्दे को एक हवा दे दिया। जिसके कारण दक्षिण एशिया में अपना ध्यान आर्थिक सहयोग पर केंद्रित करना चाहा।

चीन अपनी पहुँच पश्चिम एशिया में मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मुशर्रफ से ग्वादर बंदरगाह का निर्माण करने के लिए समझौता किया। इस समझौते के द्वारा चीन पश्चिम एशिया में आसानी से अपनी पंहुच स्थापित कर सकता है इसलिए यह समझौता चीन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था जो कि आधुनिक युग में चीन इस बंदरगाह का पूर्ण रूप से उपयोग कर रहा है। द इकनोमिक टाइम्स (22 जनवरी 2019) के संस्करण में उल्लेखित किया है कि पाकिस्तान और चीन दोनों देश मिल कर "चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा" (CPEC) बनाने की कोशिशो में लगे हुये है। यह आर्थिक गलियारा भारत के लिए सिरदर्द हो सकता है क्योंकि यह पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के साथ ओवरलैप करता है।[17] इसके अलावा, चीन, पाकिस्तान का उपयोग करते हुये भारत के पड़ोस में एक प्रतिपक्ष सैन्य शक्ति का निर्माण करते हुये दक्षिण एशिया के भीतर भारतीय शक्ति पर रोकने का काम कर रहा है।

चीन वैश्विक चिंताओं को नजर अंदाज करते हुये पाकिस्तान का हर परिस्थिति में साथ निभाता रहा है। इसके साथ ही अन्य दक्षिण एशियाई देश अक्सर चीन से अधिकतम लाभ लेने के प्रयास से दांव पेच खेलते रहते हैं। लेकिन ऐसी अस्थिर कूटनीति उनके राष्ट्रीय हितों के लिहाज से ठीक नही है अर्थात अल्पकालीन कूटनीति है या क्षेत्रीयता को नुकसान पंहुचा सकती है, यह सोच

[16]Ibid
[17] Chaudhury D. R. (Jan 22, 2019). The Economic Times. China Pakistan expand busisness at Economic Corridor. Retrived on 12 April 2019 from https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/china-pakistan-expand-business-at-economic-corridor/articleshow/67634046.cms?from=mdr

भारतीय सुरक्षा और राष्ट्रीय हितो को सीधे रूप में नुकसान पहुचाती है। इसीलिए भारत को इस उपक्षेत्र में दबाकर रखने वाली किसी प्रमुख शक्ति के बिना किसी दबाव के क्या हमारा कोई भी पड़ोसी मित्र राष्ट्र इस तरह की अवज्ञा कर सकता है।

भारतीय विदेश नीति में यह सबसे बड़ी चुनौतियों के रूप में है भारत की सबसे बड़ी चुनौती केवल यह नहीं होगी कि अपने पड़ोसियों तथा आसियान एवं पश्चिम एशिया समेत दूरवर्ती पड़ोसियों को किस तरह संभाला जाए बल्कि विश्व की प्रमुख शक्तियों के साथ अपने संबंधों को दुरुस्त करना भी चुनौती साबित हो रही है क्योंकि वे शक्तियां अपना–अपना प्रभाव जमाने के लिए होड़ करती रहती हैं तथा किसी न किसी के जरिये यह काम करना चाहती हैं जबकि इतने बड़े आकार, आर्थिक एवं सैन्य शक्ति, मानव संसाधन तथा रणनीतिक लाभ के कारण भारत ऐसी भूमिका में नहीं आ सकता। ऐसी परिस्थितियों में कोई अपने सिर पर मंडराते सायों से छुटकारा कैसे पाए यह एक बहुत बड़ी समस्या है।

चीन की वैश्विक महत्वाकांक्षाएं तो हैं ही, उसके साथ संबंध बनाए रखना बाकी सभी संबंधों की तुलना में सबसे अधिक कठिन रहा है। चीन ने अपनी वित्तीय एवं सैन्य ताकत के जरिये तथा दरियादिली से खैरात बांटकर भारत के पड़ोस में अपना मजबूत प्रभाव जमा लिया है, जो हमारी विदेश नीति के उद्देश्यों की राह में बाधक बन सकता है। चीन की 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल' रणनीति[18] उसकी चीन–पाकिस्तान आर्थिक गलियारा परियोजना[19] और बेल्ट एंड रोड परियोजनाओं के लिए सटीक बैठती है। वास्तव में इससे चीन का प्रभाव और भी आगे तक चला जाता है, जो रणनीतिक रूप से हमारे लिए असहजता भरा हो सकता है। चीन ने नेपाल और श्रीलंका के साथ अपने रक्षा संबंध और भी मजबूत किए हैं। इसका मुकाबला करना है तो क्षेत्र में हितधारकों को उसी प्रकार का आकर्षक तथा व्यावहारिक प्रोत्साहन देना होगा।

[18] Khurana, Gurpreet. (2008). China's String of Pearls in the indina ocean and its Sceurity Implictions. Strategic Analysis. Strategic Analysis, 32:1), 1-39.
[19] Opportunities and risks- the China-Pakistan Trade Corridor. World Economic Forum. Retrieved on 12 April 2019 from https://www.weforum.org/agenda/2018/07/opportunities-and-risks-the-china-pakistan-economic-corridor/.

जहां तक चीन–भारत संबंध हैं तो प्रत्यक्ष तौर पर सब कुछ 'सहयोग–प्रतिस्पर्द्धा' का नमूना लग रहा है। लेकिन चीन मौके की ताक में भारत की तरफ देख रहा है और रूस जैसे भारत के पारंपरिक साझेदारों को दूर ले जाने की कोशिश भी कर रहा है। रणनीतिक वैश्विक मंच पर जगह पाने के भारत के दावे का चीन द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है, जैसे–परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में शामिल होने तथा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता पाने में भारत के हर प्रयासों को विफल करता रहेगा। चीन–पाकिस्तान–रूस के बीच कुछ समय पहले रूस–पाकिस्तान सैन्य अभ्यास इसका उदाहरण हैं।

रूस के साथ भारत के रिश्ते बहुत पुराने और विविधता भरे हैं, लेकिन अमेरिकी प्रशासन के साथ भारत की बढ़ती निकटता ने रूस को तालिबान और अफगानिस्तान के कारण ही सही, पाकिस्तान के साथ रिश्ते बढ़ाने का बहाना दे दिया है। इसके संकेत कम से कम सात–आठ वर्ष से मिल रहे थे। लेकिन क्या अब मामला ऐसी जगह पहुंच गया है, जहां से वापसी नहीं हो सकती। कुछ वर्ष पहले तक यह मान लिया गया था कि रूसी प्रशासन पाकिस्तान की बातों में नहीं आएगा। लेकिन हकीकत यह है कि ऐसा हो चुका है और अब उसका सामना करने और उन्हें अलग करने की जरूरत है। यह भी सच है कि "भरोसेमंद और पुराने दोस्त" या "रूसी–हिंदी भाई भाई" जैसे भावनात्मक जुमलों से स्थिति पहले की तरह नहीं की जा सकती, लेकिन भारत के साथ सख्त आर्थिक रिश्ते उन्हें ऐसा करने पर मजबूर कर सकते हैं क्योंकि खनिजों तथा हीरों के अलावा सैन्य उपकरणों तथा असैन्य परमाणु प्रतिष्ठानों के लिए भारत अब भी उसके सबसे बड़े बाजारों में शामिल है।

कारोबार से ज्यादा समझ आने वाली भाषा कोई नहीं। इसके अलावा यदि ट्रंप–पुतिन समीकरण आगे जाकर कारगर साबित होते हैं तो चीन और पाकिस्तान दोनों के मामले में भारत के साथ रूसियों की भावनात्मक दूरी कम हो सकती है। लेकिन संबंधों के बारे में अपने प्रयासों के लिए इन कल्पनाओं के भरोसे नहीं बैठ सकते। अगर रूसियों के साथ कहीं भी भरोसे की कमी और गलतफहमी है तो हमें

कूटनीतिक संकेतों के फेर में पड़कर मामला बिगाड़ने के बजाय सीधे उनके नेतृत्व से बात कर उसे दूर करना होगा।

जहां तक अमेरिका की बात है, हालांकि भारत के साथ रणनीतिक रिश्ते और भी मजबूत करने के लिए दोनों पक्षों का समर्थन है, लेकिन ट्रंप प्रशासन की आसक्ति और प्रतिबद्धता 'कोरे पन्ने' की तरह यानी पूर्वाग्रह रहित है और अमेरिका में भारतीय समुदाय का मजबूत प्रभाव तथा राष्ट्रपति ट्रंप की कारोबारी रुख रखने वाली टीम उसे भारत की ओर केंद्रित रखने में सहायक हो सकती है। रोजगार और विनिर्माण वापस अमेरिका में लाने तथा कर ढांचों में प्रस्तावित बदलावों की नीतियों से भारत में अमेरिकी वित्तीय निवेश में कमी आने की आशंका तो है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को कुछ दिक्कत हो सकती है। यहां एक बार फिर वही बात आती है कि प्रतिस्पर्द्धा भरा तथा दूसरों की तुलना में अधिक फायदे एवं प्रोत्साहन भरा बाजार बने रहना हमारे लिए आवश्यक है और इसके लिए हमें नियमों को पिछली तिथि से लागू करने से बचना होगा क्योंकि इससे विदेशी निवेशकों के मन में शंकाएं उत्पन्न हो गई हैं।

चीन के बढ़ते प्रभाव का उत्तर देने के लिए यदि अमेरिकी एशिया प्रशांत एवं हिंद महासागर क्षेत्रीय सहयोग की अपनी रणनीतिक योजना के अनुरूप भारत में अधिक स्थान चाहते हैं तो लघु अवधि में यह फायदेमंद हो सकता है। अमेरिका के साथ भारत के रक्षा संबंध बढ़ते रहेंगे क्योंकि अमेरिका में सैन्य–औद्योगिक तालमेल इसके पीछे प्रमुख शक्ति है, लेकिन टकराव होने पर किसी भी प्रकार का झटका नहीं लगे, इसके लिए विशेष रूप से पुर्जों की विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी। भारत–अमेरिका–जापान त्रिपक्षीय संवाद के साथ संपर्क और भी बढ़ाना बेहतर होगा कि समान क्षेत्रीय उद्देश्यों वाले समूह में ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल कर चतुर्पक्षीय संपर्क बढ़ाया जाए।

पाकिस्तान प्रायोजित आंतकी समूहों की ओर से आतंकवाद दशकों से भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा रहा है। संयुक्त राष्ट्र में अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर समग्र संधि (सी0सी0आई0टी) कराने के भारत के प्रयास प्रमुख देशों की प्रतिबद्धता कम होने के कारण विफल रहे हैं। आई0एस0आई0एस, अलकायदा और उसकी विभिन्न

शाखाओं तथा चरमपंथी इस्लामी गुटों के खिलाफ लड़ाई विशेष रूप से पश्चिम एशियाई देशों के साथ खुफिया जानकारी की अधिक साझेदारी तथा सहयोग के जरिये ही करनी होगी और इसके लिए "लुक वेस्ट" नीति को "एक्ट वेस्ट" नीति में बदलव किया[20], जिससे पाकिस्तान के साथ उनकी नजदीकी और समर्थन कम हो सकता है।

चीन जैसे देश स्वयं भी आतंकवाद से पीड़ित होने के बावजूद मसूद अजहर जैसे पाकिस्तानी आतंकवादियों को बचाते रहते हैं और रूस का इरादा पाकिस्तान को आतंकवाद का प्रायोजक देश घोषित करने का नहीं है। इससे भारत विरोधी आतंकी हरकतों को जारी रखने की पाकिस्तान की मंशा और भी मजबूत हो गई है, जिसका सामना करने के लिए व्यापक और सार्थक अंतरराष्ट्रीय गठबंधन जरूरी हैं। आने वाले दिनों में दुनिया बदलेगी और विशेष रूप से प्रमुख शक्तियों के बीच नए द्विपक्षीय समीकरण बन सकते हैं, जिनका आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, वैश्विक अर्थव्यवस्था एवं व्यापार, संघर्षों या धीमे–धीमे सुलग रहे टकरावों पर प्रभाव सकारात्मक हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन होगा जरूर। भारत को प्रासंगिक बने रहने के लिए जोखिमों की थाह लेनी होगी और अपना रुख तय करना होगा।[21]

पूर्व–पश्चिम धुरी पर एक विशेषाधिकार प्राप्त गलियारे के रूप में इसकी भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, मध्य एशिया के भूमि व्यापार जोड़ने के लिए कोशिश कर है। हालाँकि, मध्य एशियाई कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने की क्षमता रखने वाला चीन एकमात्र क्षेत्रीय खिलाड़ी नहीं है। भारत में अन्य एशियाई दिग्गज भी इस दिशा में कदम बढ़ाने लगे हैं। ऐसा करने में, भारत ने कई क्षेत्रीय खिलाड़ियों के हित को आकर्षित किया है, जो अपने पड़ोस में चीन की बढ़ती भागीदारी को संतुलित करने में सक्षम, अन्य बाहरी भागीदारों को खोजने के प्रयास से प्रेरित है। नई दिल्ली की प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजना, इंटरनेशनल

[20] वर्तमान में 'लुक वेस्ट' नीति बेहतर– https://gshindi.com/category/india-world/look-west-policy
[21] https://bharatshakti.in

नॉर्थ–साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर (INSTC) की रूपरेखा के भीतर भारत की रणनीति को स्पष्ट किया गया है।[22]

इसका उद्देश्य भारतीय और रूसी क्षेत्र के बीच एक तेज़ मार्ग की गारंटी देना है, जिससे भारतीय सामान (जैसे कपड़े, रसायन और कृषि उत्पाद) ईरान, मध्य एशिया और यूरोप के कुछ हिस्सों में पहुँच सकते हैं, जबकि पाकिस्तान, भारत के ऐतिहासिक प्रतिद्वंद्वी को दरकिनार कर सकता है। मध्य एशियाई और ईरानी प्राकृतिक गैस, तेल और यूरेनियम का भारतीय आयात बढ़ना भी इस संबंध में एक प्रमुख लक्ष्य है। एक पूर्ण INSTC भारत और मध्य एशिया (ईरान सहित) के बीच व्यापार आदान–प्रदान को बढ़ावा दे सकता है, अनुमानों के साथ मौजूदा 1 बिलियन से 170 बिलियन डॉलर की वृद्धि हुई है। तुलना के माध्यम से, 2016 में, चीन और मध्य एशिया के बीच व्यापार 30 बिलियन यूरो का था।

चीन और भारत के बीच चल रहे बुनियादी ढांचे की प्रतियोगिता का सबसे स्पष्ट प्रतिनिधित्व पाकिस्तान में ग्वादर (चीन द्वारा समर्थित) और चाबहार के ईरानी बंदरगाह (भारत द्वारा समर्थित) के बंदरगाह हैं। ओमान की खाड़ी के पास और एक–दूसरे से लगभग 150 किमी दूर स्थित, वे दो अलग और प्रतिस्पर्धी व्यापार पहुंच का प्रतिनिधित्व करते हैं। ग्वादर बंदरगाह चीन द्वारा चीन–पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) के ढांचे के भीतर विकसित किया गया है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) की एक शाखा जिसमें पाकिस्तान के बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए कई पहल शामिल हैं– और हिंद महासागर में बीजिंग के दरवाजे का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरी ओर, चाबहार नई दिल्ली का ईरान और मध्य एशिया का प्रवेशद्वार है, विशेष रूप से जब ईरान की सीमा पर एक नियोजित रेलगाड़ी जो अफगानिस्तान की सीमा पर है।

7.4. वैश्विक परिदृश्य में भारत

भारत के संदर्भ में देखा जाए तो शीत युद्ध की समाप्ति के बाद इसकी विदेश नीति शिथिल पड़ने लगी क्योंकि कुछ अन्तर्निहित प्राथमिकताओं के दबाव के

[22]China, India and the Crossroads of 21st Century Infrastructure Competition (2019). Retrived from https://www.academia.edu

कारण भारत की विदेश नीति में अन्तर्विरोधों की श्रृंखला तेजी से बढ़ने लगी। भारत में अपनी योग्यता और स्वायत्तता को एक संतुलित अवस्था में बनाए रखा। इसी कारण महाशक्तियों ने भारत को उसकी योग्यता और क्षमता के अनुरूप प्रतिष्ठा प्रदान की है, परंतु 1990 के बाद वैश्विकृत दौर में भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिष्ठा को बनाने में भली–भाँति सफल होने लगा है। उदाहरण के लिए भारत जापान की तुलना में बहुत ही कम निवेश के साथ वैश्विक स्तर पर अपने पद की गरिमा बनाने में प्रभावी रहा है। आधुनिक दौर में भारत बहुपक्षीय सगठनों के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से प्रभावशाली देशों के उच्चाधिकार प्राप्त विभिन्न समूहों का सदस्य बन चुका है जैसे विश्व व्यापार संगठन, (WTO) और संयुक्त राष्ट्र, (UN) के जलवायु परिवर्तन ढ़ाँचे आदि। अपवाद स्वरूप अमेरिका और चीन के अतिरिक्त आज अनेक देश देश नई दिल्ली के साथ साझेदारी करने में सर्वाधिक उत्सुक है। इनमें इजराइल ईरान अग्रणी भूमिका में हैं।

भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाने के बाद भी व्यापारिक अवसरों के लिए नई दिल्ली द्वारा कुछ अह्म मुददों पर विश्व के समक्ष अपनी विशेष प्रस्तुति रखनी होगी। इनमें कुछ प्रमुख मुददे हैं जैसे–कार्बन उत्सर्जन, व्यापार दरों की कमी के संबंध, विश्व में शांति और सुरक्षा बनाएं रखने में भारत की भूमिका? वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा में निरन्तर बदलाव आँका जा रहा है। इस प्रतिष्ठात्मक गतिशीलता को बनाए रखना भारत के लिए आवश्यक होता जा रहा है, क्योंकि अन्य देशों की अपेक्षाएँ भारत की पद गरिमा को लेकर निरन्तर बढ़ती जा रही हैं। अन्य शक्तियाँ भारत से यह भी अपेक्षा करती हैं कि जिस प्रकार व शासन व्यवस्था को सुचारू से बनाए रखने के लिए जिम्मेदार रहे हैं, ठीक उसी प्रकार भारत भी इस प्रक्रिया में हिस्सा लें और अन्य देशों के साथ मिलकर अपनी भूमिका उचित रूप से निर्वहन करें। नई दिल्ली के नीति निर्माता समझते हैं कि भारत को अपने योगदान में किसी एक पृष्ठभूमि को चुनना होगा या तो वह स्विटजरलैंड की तरह अपनी भूमिका निभाएं या फिर अमेरिका की तरह। वह एक बार में दो अलग–अलग देशों के समान दो भूमिकाओं का निर्वहन नहीं कर सकता। भारत को

अपनी योग्यता व प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए किसी एक पक्ष का सहायक बनना होगा।

7.5. आधुनिक युग में भारत ईरान के दृष्टिकोण की समीक्षा

1990 के बाद से भारत आर्थिक वैश्विकरण के दौर में अपने आप को इस साँचे में ढलने की कोशिश करने लगा। इसके चलते इसने अपनी आंतरिक और बाहरी आर्थिक नीतियों में परिवर्तन भी किया। भारत में उदारीककण की नीतियों ने भी विदेश नीति को प्रभावित किया है। इसके आर्थिक प्रदर्शन के रणनीतिक परिणाम स्वतः स्पष्ट हैं। इसलिए आर्थिक विकास और ब्राहय अभिविन्यास में एशिया में अपने देशों एंव प्रमुख शक्तियों के साथ नए संबंधों को बनाने में सफल रहा। कुछ समय पहले राजनीति विश्लेषकों ने भविष्यवाणी की थी कि भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को भू–राजनीतिक वातावरण के तहत अपनी जरूरतों को पूरा कर सकता है। नतीजतन, भारत ने अपने उच्च आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने व नई ऊर्जा संपत्ति की तलाश में अपनी एकीकृत ऊर्जा नीति और तेल कूटनीति शुरू की है। ऊर्जा सुरक्षा को भारत ने अपनी विदेश नीति के' महत्वपूर्ण घटक के रूप में जोड़ा है। जवाहरलाल नेहरू ने दिसंबर 1947 में विदेश नीतियों के बारे में बात करते हुए तर्क दिया था कि सदन को यह याद रखना चाहिए कि, यह केवल एक शतरंज बोर्ड पर किया जाने वाला संघर्ष नहीं हैं। विदेश नीति आर्थिक नीति का परिणाम है और जब तक भारत अपनी आर्थिक नीति को ठीक से विकसित नहीं करता है, तब तक विदेश नीति अस्पष्ट रहेगी और हम इसे अंधे की तरह खोजते रहेंगे।

शीत युद्ध की समाप्ति के बाद ईरान भारत की विदेश नीति का संबंध महत्वपूर्ण रहा है। द्विपक्षीय ऊर्जा व्यापार के बढ़ने के अलावा दोनों देश मध्य एशिया में आर्थिक और वाणिज्यिक हितों के साथ–साथ समान रणनीतिक चुनौतियों को साझा करते हैं, विशेष रूप से अफगानिस्तान में। फिर भी भारत और अमेरिका के बीच मधुर संबंधों के आलोक में ईरान के साथ बढ़ता संबंध समस्याग्रस्त हो गया, विशेष रूप से ईरानी परमाणु मुद्दे के संदर्भ में। भारत की अपनी सामरिक स्वायत्तता की रक्षा की क्षमता पर सवाल उठता है। मई 2012 में ईरान व्यापार प्रतिनिधिमंडल

भारत की यात्रा पर आये, तो भारतीय विदेश मंत्री एस.एम. कृष्णा ने ईरान के खिलाफ अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंधों की निंदा की। वाशिंगटन और तेल अवीव दोनों के साथ अपने घनिष्ठ संबंध के बावजूद, ईरानी परमाणु मुद्दे के कारण बढ़ते अंतरराष्ट्रीय तनावों की परवाह किए बिना, भारत ने ईरान के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी बनाए रखी है। दोनों देशों के बीच शास्त्रीय पुरातनता से लेकर व्यापक प्राचीन वाणिज्यिक और सांस्कृतिक आदान–प्रदान का इतिहास समृद्ध है। जबकि ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना ने दोनों देशों के घनिष्ठ संबंधों को तोड़ने का नेतृत्व किया था, शीत युद्ध युग के बदलते रणनीतिक संदर्भ में उनके संबंधों को एक बार फिर से जोड़ दिया गया है।

दरअसल, शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात भारत की नीतियों में एक महत्वपूर्ण बदलाव देखा जा सकता है। इस बदलाव को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर चिह्नित किया जा सकता है। सोवियत संघ के पतन के बाद भारत ने अपना मुख्य आर्थिक और सैन्य साथी खो दिये। शीत–युद्ध के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा स्थपित एकीकृत साम्राज्य होने के बावजूद भारत विश्व मामलों में अधिक प्रभावशाली भूमिका निभाने के लिए इच्छुक रहा है। इस प्रकार एकध्रुवीय प्रणाली के पदानुक्रम का मुकाबला करने के लिए भारत सामने आया है साथ ही चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका इत्यादि देशो ने भारत की विशिष्ट विदेश नीति व्यवस्था का समर्थन भी किया है। अमेरिका के नेतृत्व वाली सरकार ने केवल संस्थागत संरचनाओं और सैन्य गठबंधनों के क्षेत्र पर ध्यान दिया जबकि भारत ने तकनीकी रणनीतियों की एक विस्तृत श्रृंखला के आधार पर एक मूल राजनयिक मॉडल का समर्थन किया है। इस प्रकार भारत की विदेश नीति सामरिक स्वायत्तता के प्रचार का एक केंद्रीय निर्धारक बन गयी है।

यह नई अवधारणा रणनीतिक स्वायत्तता में एक स्पष्ट परिभाषा का अभाव है परिणामस्वरूप भारतीय राजनीतिक और रणनीतिक समुदाय के बीच इस व्याख्या को हटा दिया गया है। फिर भी इसके मुख्य सिद्धांतों को संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है। रणनीतिक स्वायत्तता की खोज भारत की गुटनिरपेक्षता की पारंपरिक नीति के साथ समान लक्ष्यों को साझा करती है जैसे कि एक स्वतंत्र विदेश नीति

का अनुसरण, किसी भी गठबंधन की अस्वीकृति, भारत की संप्रभुता की रक्षा और अंतरराष्ट्रीय क्रम में एक प्रभावशाली भूमिका का अधिग्रहण। फिर भी, उनके साधन अलग हैं। नेहरू से विरासत में मिली गुटनिरपेक्ष नीति दक्षिणी नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों के प्रचार पर आधारित थी। इस विचार पर कि भारत विचारों की शक्ति के माध्यम से दुनिया को जीत सकता है। इसके विपरीत भारत के वर्तमान नेतृत्व द्वारा रणनीतिक स्वायत्तता नीति को आगे लाया गया, जो यथार्थवाद और आदर्शवाद की प्रतिस्पर्धा के बीच की दुविधा को दूर करने का प्रयास करती है। यह भारत की राष्ट्रीय शक्ति को अधिकतम करने के लिए कई देशों के साथ विभिन्न रणनीतिक साझेदारी की स्थापना पर आधारित एक बहुत ही व्यावहारिक नीति है। भारत ने लुक ईस्ट पॉलिसी या पूर्व की ओर देखो नीति पूर्व एशियाई क्षेत्र में अपना सामरिक आर्थिक नीतियों में सफलता प्राप्त करने के उदेश्य से अस्तित्व में लाया। इस नीति के तहत भारत का प्रयास इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकना है। दूसरे शब्दों में, लुक ईस्ट पॉलिसी दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापक आर्थिक और सामरिक संबंधों को विकसित करने का एक विशिष्ट प्रयास है जिससे इस क्षेत्र में क्षेत्रीय शक्ति के रुप में खुद को स्थापित कर सके।

इस नीति की शुरुवात 1991 में हुई और इसे लागू करने का श्रेय प्रधानमंत्री पी वी नरसिंह राव के शासन को जाता है। हालांकि,प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार ने इसे रूचि पूर्ण तरीके से अपनाया। इस नीति के तहत भारत ने एशियन टाईगर अर्थव्यवस्थाओं के साथ अच्छे संबंध स्थापित किए हैं। भारत ने इसके अंतर्गत श्रीलंका, थाईलैंड और अन्य पूर्व एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के साथ शीघ्र फसल योजना शामिल की हैं। 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने आर्थिक उदारीकरण और मुक्त व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किये जिनमें सिंगापुर और थाईलैंड के साथ के साथ व्यापक आर्थिक सहयोग करार लागू करने पड़े थे क्योंकि भारत की आर्थिक स्थित लगभग ख़राब हो रही थी भारत अपना सोना विदेशी मुद्रा भंडारण में गिरवी रखना पड़ा था।

उदारीकरण के उपायो ने न सिर्फ देश की घरेलू आर्थिक नीतियों में आमूलचूक परिवर्तन किये बल्कि इन बदलावों के माध्यम से पूर्व में स्थित हमारे

पड़ोसी देशो की आर्थिक गतिशीलत के साथ तालमेल बिठाने में भी सहयता की थी। अतः यह तार्किक रूप में है की विदेश नीति के इस नए पहलू को लुक ईस्ट अर्थात पूरब की ओर देखो का नाम दिया गया। इस दौरान भारत ने पश्चिमी देशो के साथ अपना पुराना सम्बन्ध कायम रखा और इस क्षेत्र में अपने सम्बन्ध और अधिक मजबूत किये।

लुक ईस्ट नीति के अपनाने के पच्चीस साल बाद और अनेक देशो में नये तटीय गैस और तेल भंडारों की खोज होने के बाद विश्व के भ–ूराजनीतिक समीकरणों को बदल दिया, परिणामस्वरूप भारत ने भी उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाया इस क्षेत्र की समस्या यह थी की तेल निर्यात देश अपनी सुविधा के अनुसार तेल का उत्पादन कम या ज्यादा करते हुए इनकी कीमतें बढा या घटा कर पूरी दुनिया के देशो को अपना बंधक बना रखा था। लेकिन उत्तरी और दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप के अलावा ऑस्ट्रेलिया और यहां तक कि पश्चिम एशिया के कुछ अन्य देशों में तेल और गैस के नए भंडारण मिलने के बाद दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में भारी कमी आई थी। इस बदलती हुई परिस्थिति ने बड़े गैस उपभोक्ता जैसे कि जापान चीन और भारत को यह मौका सुलभ करा दिया की वे अपनी बड़ी खपत के बल पर आसपास स्थित तेल उत्पादक देशों से ज्यादा आकर्षक दरों पर मोलभाव कर सकें। भारत ने इस मौके लाभ उठाते हुए अपने सम्बन्ध खाड़ी में स्थित तेल उत्पादक देशों के साथ सक्रिय कर लिये।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण देशो के साथ सामरिक हितो को स्थापित किया जैसे– सऊदी अरब, यू0ए0ई0 और कतर एयर वही ईरान के साथ भी उर्जा और संचार के क्षेत्र में सहयोग करने वाले सम्बन्ध कायम किये. ईरान भारत के व्यापारिक और सामरिक हितो के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण गतव्य है। विशेष रूप से अफगानिस्तान एयर मध्य एशियाई देशो के सम्बन्ध में।

भारत सरकार ने ईरान से प्राकृतिक गैस खरीदने में गहरी रुचि दिखाई है, लेकिन भारत के सामने एक समस्या परिवहन अर्थात आवागमन की है। किन्तु इस समस्या को भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए ईरान और भारत ने 1993 में एक भूमिगत प्राकृतिक गैस पाइपलाइन

के महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किये। इस परियोजना से ईरान से गैस निर्यात को बढ़ाने और भारत की उच्च ऊर्जा मांगों को पूरा करने में सहयता मिलेगी। इसके साथ ही कराची को दक्षिण पारस प्राकृतिक गैस क्षेत्र से जोड़ने वाली प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के निर्माण के लिए पाकिस्तान और ईरान ने 1995 में एक प्रारंभिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद ईरान पाकिस्तान और भारत के बीच समझौते हुये जिसे ईरान–पाकिस्तान–भारत (आई0पी0आई0) परियोजना के नाम से भीं जाना जाता है इस परियोजन से भारत और पाकिस्तान की उर्जा समस्या पूरी तरह से ख़त्म तो हो सकती है साथ ही ईरान के एक बड़ा उर्जा व्यापारी मिल जायेगा। लेकिन फिलहाल यह परियोजना ठंडे बस्ते में चली गयी है।

अध्याय–अष्टम्

निष्कर्ष

8.1. निष्कर्ष

इस प्रकार उपरोक्त विश्लेषणों से स्पष्ट होता है कि 1990 के बाद ऐसा कोई देश नहीं है जिसने प्राकृतिक संसाधन के महत्व को न समझा हो और यह महत्व कई राष्ट्रो के नीतियों में अपना केंद्रीय स्थान हासिल किया है। विकास एक ऐसी प्राकिया है जिसके अनुभव से दुनिया के कई देश अछूते हैं, और अभी भी संघर्ष की अवस्था में हैं। विश्व के अनेक राष्ट्र अपने नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने और उनका जीवन स्तर सुधारने के लिए निरंतर असमर्थ है। ऐसे मोड़ पर विकास प्रक्रिया में सहायता देने के लिए ऊर्जा एक महत्वपूर्ण कारक बन गया है। पृथ्वी पर ऐसे कई संसाधन उपलब्ध हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है, उनमें से तेल और गैस सबसे महत्वपूर्ण हैं।

आधुनिक युग में विभिन्न (खास तौर पर तेल व गैस उत्पादक) देशों के बीच जब कोई सौदा या समझौता होता है तो तेल व गैस का स्थान सर्वोपरि होता है। चाहे वह विकसित और विकासशील देश ही क्यों न हो सभी को इसकी जरूरत होती है। जिसकी वजह से कुटनीतिक षड़यत्र रचे जाते हैं और ये नीतियां विश्व पटल पर अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। ऊर्जा उन देशों को जोड़ने में लगी है जिन्हे भौगोलिक दृष्टि से बिल्कुल उल्टा या नगण्य कहा जाता रहा है। परन्तु उनके विशाल संसधानों के कारण तेल और गैस संपन्न क्षेत्रों की कीमतों में इजाफा हुआ है। इस प्रकार, ऊर्जा और राजनीतिक सम्बन्ध एक दूसरे के निकट हैं और इस राजनीतिक सम्बन्ध में भू–राजनीतिक खेल के साथ–साथ गैर राजनीतिक संगठन भी अपनी भूमिका निभा रहे है। जैसा की इस शोध कार्य में भारत–ईरान के द्विपक्षीय संबंधों व भारत की ऊर्जा जरूरतों को ईरान पूरा करने में सक्षम है, साथ ही धार्मिक कट्टरपंथी, आतकंवाद, भारत–चीन प्रतिस्पर्धा व भारत–अमेरिका सम्बन्ध

से ईरान और भारत के बीच ऊर्जा सुरक्षा पर प्रभाव इत्यादि बिन्दुओं को उल्लेखित किया गया है।

भूमंडलीकरण के दौर में आर्थिक विकास के लिए दो राज्यों के बीच नजदीकी व प्रतियोगिता होना महत्वपूर्ण उन्नती का कारक माना जाता है लेकिन इसका प्रभाव आमतौर पर कुछ कमजोर अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ता है। इस दौर में पूरी तरह से एक स्वतंत्र अर्थव्यस्था विकसित करना असंभव है। सोवियत संघ के विघटन के बाद वैश्विक स्तर पर सहयोग का रास्ता शुरु हो गया था विश्व के अविकसित देश आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे जिसमें भारत और चीन भी सम्मिलत है, दोनों देशों की आर्थिक स्थिति के समान होने के कारण पुरानी समस्याओं से उबरने के लिए प्रयासरत थे।

भारत 1990 के दशक में अपनी नाजुक अर्थव्यस्था के चलते दिवालिया की स्थिति में पहुंचा गया था जिसके चलते भारत ने 1991 में नयी अर्थव्यस्था वाली नीति को अपनाया इसका परिणाम यह हुआ कि समाजवादी विचारधारा को छोड़कर पूँजीवादी रास्ते पर चल पड़े। जिसमें निजीकरण और उदारीकरण अहम थे, भारत ने अपनी आर्थिक नीति को एक नए दौर में पहुंचा दिया। जिसका परिणाम यह हुआ कि विश्व के अनेक विकसित देशों से ज्यादा से ज्यादा निवेश भारत में होने लगा। भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में ऊर्जा जरूरतों के लिए तेल और गैस को सुरक्षित करने एंव विश्व के ऊर्जा उत्पादक देशों के साथ राजनीतिक संबंधों को प्रगाढ़ करने की कोशिश में लग गया क्योंकि भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। इसका परिणाम यह हुआ कि भारत विश्व के सर्वोत्तम संस्थानों जैसे–डब्लू0टी0ओ0 और ओ0ई0सी0डी में अपनी जगह हासिल की।

भारत की आर्थिक व्यवस्था में सुधार करने के लिए विदेश नीति को तेल की कूटनीति में तब्दील कर दिया गया। यह परिवर्तन वर्ष 1991 के बाद किया गया तथा इन 4 से 5 वर्षों में भारत, विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा की संभावनाएं तलाशने लगा। वैश्वीकरण के दौर में भारत की विदेश नीति में ऊर्जा सुरक्षा सबसे प्रमुख है। ऊर्जा सुरक्षा के मामले में भारत उच्च स्तरीय कूटनीति का इस्तेमाल कर रहा है, 1960–1982 तक भारत तकनीकी यातायात के मामले में पूरी तरीके से रूस

पर निर्भर था। भारत ऊर्जा तकनीकी के मामले में बहुत पिछड़ा था इसके चलते पश्चिमी तेल रिफाइनरी कंम्पनियॉ रूस से आयात तेल का शोधन करने से माना कर देती थी तब भारत सरकार ने रूस और रोमानिया सरकार के सहयोग से अपने रिफाइनरी कंपनी की स्थापना करने का निर्णय लिया।

भारत ऊर्जा सुरक्षा की जरूरत को ध्यान में रखते हुये अपनी विदेश नीति में भू–राजनीति को अधिक महत्व दिया है। क्योंकि 1991 में सोवियत संघ का विघटन होने के पश्चात भारत के ऊर्जा आयातक देश हमेशा बदलते रहे हैं। साथ ही भारत वैश्विक बाजार में नये तेल उत्पादक देशों की तलाश के साथ–साथ इस क्षेत्र में भारतीय तेल कंपनियों ने निवेश को बढावा दिया। आधुनिक युग में भारत ऊर्जा सुरक्षा को लेकर बहुत ही चिन्तित है भारत का ऊर्जा स्रोत्र मुख्य रूप में कोयला, तेल, गैस, और सौर ऊर्जा आदि हैं जो ऊर्जा जरूरतों के मुताबिक बहुत ही कम है। भारत में लगभग एक करोड़ से ज्यादा लोग अभी भी बिजली की आपूर्ति से वंचित है। लगभग 10 प्रतिशत गॉव के लोग अभी भी परम्परागत ऊर्जा पर निर्भर है। इसके चलते आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न हो रही है।

भौगोलिक दृष्टि से भारत विश्व का सातवां बड़ा देश है और इसकी जनसँख्या एक अरब 20 करोड़ है जो चीन के बाद विश्व में दूसरा सबसे बड़ा देश है। इसकी सकल घरेलू उत्पाद लगभग 7 से 8 प्रतिशत है जबकि 2008 में आर्थिक संकट भी आया था लेकिन देश की अर्थव्यस्था को ज्यादा नुकसान नहीं सहना पड़ा। भारत के पास परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा उपलब्ध है, लेकिन आवश्कता के अनुसार उपलब्ध ऊर्जा को पूरा नही किया जा सकता है। इसलिए भारत 80 प्रतिशत ऊर्जा का आयत विश्व के अनेक देशों से करता है। भारत ने 1990 में 40 प्रतिशत तेल का आयत किया था जो की वर्ष 2011 में बढ़कर 70 हो गया और 2017–18 में 80 प्रतिशत है।

उपर्युक्त आकड़ो से पता चलता है की भारत को ऊर्जा आवश्यकता दिन प्रति दिन बढ रही है यदि इसी रफ तार से बढती रहेगी तो आने वाले दिनों में उर्जा का आयत 90–95 प्रतिशत हो जायेगा। इस आवश्कता को मद्दे नजर रखते हुये भारत को सस्ती और अच्छी ऊर्जा स्त्रोतों को ढूँढना होगा। इसके चलते

भारतीय सरकार ने विभिन्न देशों के साथ सन्धि किये हैं साथ ही भारतीय तेल कंपनियों को भी ऊर्जा उत्पादक देशों (सऊदी अरब, अफ्रीका, इराक, ईरान, यू0ए0ई0) में निवेश करने के लिये प्रेरित किया है जैसे–ओ0एन0जी0सी0, गेल इत्यादि।

भारत अधिकतम ऊर्जा की पूर्ति खाड़ी के देशो से पूरा करता है क्योंकि इस क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में तेल व प्राक्रतिक गैस का भण्डार है। जिसमें से सऊदी अरब, इराक और ईरान प्रमुख हैं। ईरान–भारत को सबसे अधिक तेल निर्यात करता है। ईरान विश्व में चौथे तेल भंडारण में अपना स्थान प्राप्त किया है और वहीं गैस के मामले में दूसरे स्थान पर है। उपलब्ध ऊर्जा को मद्दे नजर रखते हुये भारत–ईरान से प्रगाढ़ संबध बनाये हुये हैं दूसरी तरफ ईरान को भी एक सबसे बड़ा बाजार मिला हुआ है। जिससे दोनों देश एक दूसरे से जुड़े हुये है। दोनों देशों के बीच ऊर्जा सम्बन्धों में उतार–चढ़ाव का इतिहास रहा है लेकिन दोनों देशों ने कभी भी व्यापारिक रिश्ता ख़राब नहीं किये। इसके साथ ही दोनों देशों ने प्राकृतिक गैस खोज और उत्पादन में हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है।

भारतीय तेल कंपनी ईरान के फरजाद–बी गैस क्षेत्र कि खोज करने में शामिल था, लेकिन 2012 में पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण यह कार्य रुक गया। लेकिन फिर 2016 के अंत में ईरान ने भारतीय निवेश के लिए विशेष रूप से गैस क्षेत्र शामिल करने पर सहमति व्यक्त किया परन्तु यह मौका रूस को दे दिया जिसकी वजह से भारत और ईरान के बीच एक दरार पैदा कर दिया। ईरान ने पहली बार तेल निर्यात में एक तिहाई की कटौती करके जवाबी हमला किया। हालांकि बार–बार असहमति और संबंधों के टूट जाने के बाद जुड़ना काफी समस्या हो जाती है जिसके वजह से अनुबंध नहीं हुआ। मई 2017 में, ईरान ने रूस को फर्जाद–बी गैस क्षेत्र विकसित करने की अनुमति दे दी। ईरानी अधिकारियों ने भारत को कहा कि इस क्षेत्र में एक साथ कई विकल्प है जो आप को बाद में उपलब्ध कराई जाएंगी और इसके बाद दोनों देशों में बातचीत जारी रही। इसके पश्चात् रूस की तानाशाही को कम करने के लिए ईरानी तेल मंत्री बिजन नामदार जंगानेह ने वियना में आर्गस से बात करते हुए गाजप्रॉम के साथ समझौते पर

हस्ताक्षर किया। इसी बीच भारतीय फर्मों ने कहा कि वे भी तेल और गैस की संपत्ति खरीदने के लिए कहीं और देख रहे हैं। कुछ समय पश्चात कच्चे तेल की कीमत में बदलाव के कारण दोनों को फिर से संगठित होना पड़ा। ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने के भारत के प्रयासों के बावजूद भारत–ईरान और अन्य प्रमुख ऊर्जा आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर है। तेल खरीदने के अलावा दिल्ली अपनी ऊर्जा सुरक्षा को बचाना चाहती है, और इसके लिये यह आपूर्तिकर्ताओं के साथ दीर्घकालिक निवेश कर रही है और राजनयिक सम्बन्ध भी बना रही है।

इसके साथ ही ऊर्जा के द्वारा भारत के विभिन्न आयामों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। वैश्विक युग में ऊर्जा उपलब्धता होने की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था में उन्नति हुई है, वर्ष 2001–02 में जीडीपी 5.81% थी और वही 2013–14 मे घट कर 4.7% हो गयी तथा 2018 में जीडीपी 7.2% है इस तथ्य से पता चलता है की ऊर्जा के अर्न्तगत आर्थिक उन्नति बहुत तेजी के साथ होती है। कुछ राजनीतिक चिन्तक यह भी कहते हैं कि जैसे–जैसे आर्थिक उन्नति होगी वैसे–वैसे ऊर्जा की आवश्यकता भी जरूरत पड़ेगी। भारत–ईरान दोनों देश विश्व पटल पर एक नए रस्ते पर चल पड़े और दोनों देश एक दूसरे के महत्व को समझने लगे। भारतीय अर्थव्यवस्था की बढ़ती विकास दर ने भारत–ईरान संबंधों में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। इसका प्रभाव न केवल आर्थिक जगत पर पड़ा है बल्कि सांस्कृतिक राजनीतिक व सामरिक क्षेत्रों पर भी पड़ा है।

अमेरिका व चीन यह कभी भी नहीं चाहते हैं कि भारत ईरान से उर्जा आयात करें। क्योंकि अमेरिका और ब्रिटिश शासन दुनिया में सबसे सस्ता और सबसे आसानी से उपलब्ध तेल भंडारों पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश शुरू से ही कर रहे थे। अमेरिका और ब्रिटिश तेल कंपनियां इराक के खिलाफ वर्ष 2003 में युद्ध किया जिसमें बीपी, एक्शन मोबिल, शेवरान टेक्साको इत्यादि कंपनियां सम्मलित थी। जिसका मुख्य उद्देश्य था कि इस क्षेत्र में उपलब्ध तेल सुविधाओं को सुरक्षित करना। क्योंकि अमेरिका में तेल की खपत दुनिया के खपत का लगभग 26 प्रतिशत है। यह खपत आने वाले दिनों में भी बढ़ेगा। अमेरिका में ऊर्जा भंडार दुनिया की तुलना में लगभग 2.8 प्रतिशत ही उपलब्ध है। जिसकी वजह से इराक,

सऊदी अरब, व ईरान जैसे महत्वपूर्ण ऊर्जा क्षेत्रों पर अपनी निगाहें लगाये बैठा हुआ है। जिसे अमेरिका अधिकतम दोहन करना चाहता है और समुद्री मार्गो को सुरक्षित करने का प्रयास भी कर रहा है। खाड़ी देशों को अपने खेमे में लेने के लिए दबाव डालता है क्योंकि 1973 में तेल की कीमतों में वृद्धि के बाद अमेरिकी अधिकारियों ने इस क्षेत्र में सैन्य शक्ति के द्वारा आर्थिक संपदा को भी हासिल करना चाहा था। यह नियंत्रण की प्रवृत्ति समय समय पर बदलती रहती है प्रायः अमेरिकी अधिकारी सैन्य शक्ति के द्वारा अरब खाड़ी देशों में अपना आधिपत्य स्थापित करने में सफल रहे हैं। एंव अरब खाड़ी के देश इस षड्यंत्र का शिकार बने हुए हैं। वैश्विक राजनीति में तेल की राजनीति पूर्ण रूप से हावी हो गई है। वर्तमान समय में करीब दुनिया में समुद्र जनित कच्चे तेल का 35 फीसदी पश्चिम एशिया के देशों से निकाला जाता है तथा होरमुज के जलडमरूमध्य और ईरान के बीच जलडमरूमध्य के उत्तर पूर्ब किनारे से और यूनाइटेड अरब अमिरत के ओमानी इन्क्लेव के मौसदम पर जलडमरूमध्य दक्षिण पश्चिम किनारे के माध्यम से होकर वैश्विक बाजार तक लाया जाता है। अमेरिका खाड़ी देशों से लगभग 17 प्रतिशत तेल का आयात करता है यद्यपि आज भी अमेरिका कच्चे तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इस आयात को अमेरिका बरकार रखना चाहता है। खाड़ी देशों के बीच आपसी कूटनीति व् गृहयुद्ध के चलते तेल के आयात पर न केवल अमेरिकी देशों पर पड़ता है बल्कि इसका प्रभाव विश्व में भी पड़ता है। जिसके चलते विश्व में एक देश दूसरे देश से आपसी समझौते व ऊर्जा कूटनीति में एक दूसरे का सहारा ले रहे हैं।

यदि भारत और अमेरिका के संबंधो का उल्लेख करते हैं तो दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंध अच्छे थे लेकिन यदा–कदा दोनों देशों के बीच उतार–चढ़ाव का भी दौर रहा है, भारत के आर्थिक, राजनीतिक व ऊर्जा संबंधों पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। यही वजह हैं कि भारत का खाड़ी देशों के साथ व अन्य ऊर्जा उत्पादक देशों से आर्थिक और राजनीतिक संबंधों में भी खटास आ जाती हैं क्योंकि अमेरिका अपने बदलते समीकरण के अनुसार विश्व जगत में सैन्य प्रतिबंध व पर्यावरण मुद्दों के द्वारा विश्व में कानूनी दांवपेच खेलता रहता है। जिसके द्वारा विश्व राजनीति में एक हलचल सी स्थिति बन जाती है। उदाहरण के तौर पर अमेरिका ने

ईरान पर परमाणु प्रतिबंध लगाया तो कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा हो गया और भारत इस रणनीति का शिकार बन गया। वर्तमान समय में अमेरिकी प्रशासन ने ईरान पर प्रतिबंध लगा दिया। जिसमें कहा गया कि ईरान परमाणु समझौता पी0 फाइव प्लश वन के नियमों का उल्लंघन कर रहा है जिसकी वजह से ईरान के तेल उत्पादन में कमी आयी है साथ ही ईरानी अर्थव्यवस्था पर भी गहरा प्रभाव पड़ा है। भारत में सऊदी अरब के बाद ईरान दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश रहा हैं।

यदि भारत–ईरान सम्बन्धों का विश्लेषण दक्षिण एशिया व पश्चिम एशिया से करते हैं तो दोनों देश क्षेत्रीय समीकरण को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं चाहे वह आर्थिक हो या राजनीतिक। पश्चिम एशिया में भारत अपने सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक संबंधों को और अधिक मधुर करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहा हैं। भारत जी0सी0सी0 देशों के साथ अपनी ऊर्जा सुरक्षा पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है इसके अलावा, व्यापार, निवेश, सुरक्षा व भारतीय कामगार और उनसे मिलने वाली रकम सबसे महत्वपूर्ण है जिसके कारण भारत को एक सम्बल प्राप्त हो रहा है। वैश्विक दौर में भारत का मुख्य उद्देश तेल व गैस की आपूर्ति करना हैं ताकि उच्च आर्थिक उन्नति की जा सके। वहीं दूसरी तरफ ईरान दक्षिण एशियाई देशों के साथ अपने आर्थिक, राजनीतिक, संबंधों को भी मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। जिससे भारत को दक्षिण एशिया में सामरिक, आर्थिक व राजनीतिक सफलता मिलने में आसानी होगी जैसे ईरान ने भारत–अफगानिस्तान के बीच कई समझौते किये .जिससे आर्थिक उन्नति ही नही बल्कि ऊर्जा के क्षेत्रों में भी उन्नति होगी।

भारत हमेशा से ही विश्व पटल पर गुटनिरपेक्षता का रास्ता अपनाया है जिससे किसी भी राष्ट्र को कोई नुकसान पहुंचाये बिना अपनी उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। इसका उद्देश्य संघर्ष की जगह शांति के क्षेत्र को विस्तारित करना। सभी गुट निरपेक्ष राज्य अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका में स्थित है इस क्षेत्र के सभी देश पहले शोषित और उत्पीड़न का शिकार हो चुके थे और भारत भी इसका अभिन्न अंग रहा है भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को समझने के साथ–साथ

अपनी आर्थिक, राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्ति करने के लिए विश्व जगत में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है।

8.2. सुझाव

- भारत को अपनी ऊर्जा आवश्यकता पूरा करने के लिए ईरान में भारतीय कंपनियों का निवेश और बढ़ाना चाहिए जिससे विपरीत परिस्थितियों में भारत को फायदा हो सकेगा।
- आई0पी0आई0 पाइपलाइन के लिए भारत को पाकिस्तान के रास्ते से न होकर, ईरान–अफगानिस्तान–भारत के रास्ते को अपनाना चाहिए।
- भारत–ईरान के सम्बन्धों को मजबूत करने के लिए रूस का भी सहारा लेना चाहिए जिससे भारत मध्य एशिया में भी अपनी पैठ बना सकता है और एक नये विकल्प के रूप में भारत व मध्य एशिया दोनों को फयदा होगा।
- भारत को अपनी ऊर्जा जरुरतों को पूरा करने के लिए सौर और पवन ऊर्जा के अलवा समुद्री तरगों के माध्यम से भी बिजली के उत्पादन करने पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि आने वाले दिनों में जलवायु परिवर्तन को भी सुरक्षित रखना होगा।
- भारत–ईरान सम्बन्धों को मजबूत करने के लिए ईरान में आर्थिक निवेश को बढ़ावा देना चाहिए।
- भारत को इजरायल के साथ को अपने सम्बन्धों अधिक मजबूत करने चाहिए इससे पश्चिम एशियाई देशों व क्षेत्रीय विकास के लिए तकनीकि मदद मिल सकेगी।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. प्राथमिक स्रोत (समाचार पत्र, सरकारी दस्तावेज इत्यादि।)

- The Hindu
- BBC
- Times of India
- Amar Ujala
- The Time
- Dainik Bhaskar
- The Indian Express
- Hindustan Time
- The Pioneer
- The Economic Times
- Indian Government Report
- Iran: Internal Politics and U.S Policy and Options. (April 30, 2019). Congressional Research Service Report.
- Ministry of the External Affairs, government of India

2. Books

1. Ahmad, T. (2015). The Gulf Region. In *The Oxford Handbook of Indian Foreign Policy* (p. 437). Oxford Handbooks.
2. Ashwarya, S. (2017). *India-Iran relations: progress, problems and prospects*. Routledge.

3. Bhat, M. A. (2018). *India and Iran Relations in Twenty First Century*. eren gündogan.
4. Hock, H. H., & Joseph, B. D. (2009). *Language history, language change, and language relationship: An introduction to historical and comparative linguistics* (Vol. 218). Walter de Gruyter.
5. Sullivan, K. (2015). *Competing Visions of India in World Politics: India's Rise Beyond the West*. Springer.
6. Pethiyagoda, Kadira (2018). India's Pursuit of Strategic and Economic Interests in Iran. THE Brookings Institution, N.W. Washington, D.C.
7. Goud, R. S., & Mookherjee, M. (Eds.) (2014). India and Iran in Contemporary Relations 1Vol.1). Allied Publishers.
8. Does US road to better relations with Iran pass through India\, Christian Science Monitor, 18 July 2009.
9. Cordesman, A. H. (2007). *Iran, oil, and the Strait of Hormuz* (pp. 2-4). Center for Strategic and International Studies.
10. Kalicki, J. H., & Goldwyn, D. L. (Eds.). (2013). *Energy and security: strategies for a world in transition*. JHU Press.
11. Lahiri-Dutt, K. (2003). Energy resources in South Asia: The last frontier?.
12. Dyer, H., & Trombetta, M. J. (Eds.). (2013). *International handbook of energy security*. Edward Elgar Publishing.
13. Goud, R. S., & Mookherjee, M. (Eds.). (2014). *India and Iran in Contemporary Relations* (Vol. 1). Allied Publishers.

3. Article and Web Sources

Agarwal, R. (2014). Persian Gulf 2013: India's Relations with the Region. *Indian Foreign Affairs Journal*, *9*(1), 72.

Ahmed, Z. S., & Bhatnagar, S. (2018). The India-Iran-Pakistan Triad: Comprehending the Correlation of Geo-economics and Geopolitics. *Asian Studies Review*, *42*(3), 517-536.

Alam, S. (2004). Iran-Pakistan relations: Political and strategic dimensions. *Strategic Analysis*, *28*(4), 526-545.

Athwal, A. (2007). *China-India Relations: Contemporary Dynamics*. Routledge.

Baidya, S. (2017). India's Policy towards Iran: Reflection of Intentions, Ambiguities and Complexities. *International Studies*, *54*(1-4), 144-161.

Belal, K. (2017). Pak-Iran Relations: Evolving Dynamics, Prospects and Approaches. *Policy Perspectives: The Journal of the Institute of Policy Studies*, *14*(1), 83-104.

Fair, C. C. (2007). India-Iran security ties: Thicker than oil. *Gauging US-Indian Strategic Cooperation, Carlisle, PA: Strategic Studies Institute, US Army War College*, p271.

Ganguly, S., & Scobell, A. (2005). India and the United States. *World Policy Journal*.

Nasirpour, G. Iran-India Relations with Future Prospects.

Pant, H. V. (2004). India and Iran: An ""Axis"" in the Making?. *Asian Survey*, *44*(3), 369-383.

Pant, H. V. (2008). India and Iran Too Close for Comfort. In *Contemporary Debates in Indian Foreign and Security Policy* (pp. 113-129). Palgrave Macmillan, New York.

Purushothaman, U. (2012). American Shadow over India–Iran Relations. *Strategic Analysis*, *36*(6), 899-910.

Rafique, N. (2016). Prospects of Pakistan-Iran Relations: Post Nuclear Deal. *Strategic Studies*, *36*(3).

Ramana, S. (2012). The Pakistan Factor in the India–Iran Relationship. *Strategic Analysis*, *36*(6), 941-956.

Tripathi, A. K. (2012). Contemporary Challenges to India's Foreign Policy. *International Journal of Social Science & Interdisciplinary Research*, *1*(7).

Verma, S. K. (2007). Energy geopolitics and Iran–Pakistan–India gas pipeline. *Energy Policy*, *35*(6), 3280-3301. Pandian, S. (2005). The political economy of trans-Pakistan gas pipeline project: assessing the political and economic risks for India. *Energy Policy*, *33*(5), 659-670.

Sajjanhar, A. (2018). India and Iran resolve to focus on Connectivity and Economic Cooperation. Institute for defence studies and Analyses. Retrieved form https://idsa.in/idsacomments/india&and&iran&resolve&to&focus&on&connectivity&and&economic&cooperation_asajjanhar_200218

BP Statistical Review 2018. Retrived from https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2018-india-insights.pdf

Kumar, Mukul . (March 2018). Tkkiku vkSj :l dks ihNs NksM+ Hkkjr cuk nqfu;k dk rhljk lcls cM+k fctyh mRiknd Retrieved 12 December 2018 from https://inextlive.jagran.com/now-india-is-the-third-largest-electricity-producer-ahead-of-russia-and-japan-201803260001

Oil & Gas Journal, Worldwide look at reserves and production (December 2017).

Facts Global Energy, Iran's Oil and Gas Annual Report 2017 (December 2017).

Beaver, B., Beaver, Jeffrey., Wilsey, M. (2007). The Middle East: United States Policy and Relations in the Latter Half of the 20th Century. Retrieved on June 17, 2016 from https://web.stanford.edu/class/e297c/war_peace/middleeast/hcentury.html

Tharoor, Ishaan. (June 16 2014). Iraq's Crisis: Don't forget the 2003 U.D invasion. The Washington Post. Retrieved on 13 May 2017 from https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2014/06/16/iraqs-crisis-dont-forget-the-2003-u-s-invasion/?noredirect=on&utm_term=.4ea49c8d09cd.

Violatti, C., (2008). Aryan. Retrieved on 27 Jan 2018 from https://www.ancient.eu/Aryan/.

Singh Roy, M. (2012). Iran: India's Gateway to Central Asia. *Strategic Analysis*, *36*(6), 957-975.

S. Mehdudia (March 2013). "India not to halt imports from Iran". The Hindu

Hillebrand, Evan (March3, 2016). What is energy Security? Definitions and Scenarios. Climate Etc. Retrieved 28 December 2019 from https://judithcurry.com/2016/03/03/what-is-energy-security-definitions-and-scenarios/.

माथुर, रितु (मई 2014). भारतीय उर्जासुरक्षा–चुनौतियाँ एवंसंभावनाए. योजना.

मिश्रा, रंजना (जनवरी 2017) जोड़ने वाला चाबहरः भारत ईरान और अफगानिस्तान और मध्य एशिया। भारत की विदेश नीति. वर्ल्ड फोकस 58 पेज नंबर 25 भाग 1

Fallahi, Ebrahim, (March 13, 2019). Iran, India Stress enhancement of economic relations. Tehran Times.

Pattanayak, S. (2001). Oil as a factor in indo-gulf relations. *Strategic Analysis*, *25*(3), 465-480.

Bhattacharjee, Dr. Dhrubajyoti (7 July 2017). Pakistan and Iran – Changing Dynamics and Challenges. *Indian Council of world Affairs.* Retrieved on 16 Sep 2018 from https://icwa.in/pdfs/VP/2014/PakistanandIranChangingVP07072017.pdf .

Hussain, M. (2012). Indo-Iranian Relations During the Cold War. *Strategic Analysis*. 36 (6), 859-870. Retrieved on 13 March 2018 from https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/09700161.2012.728868?needAccess=true&.

Hathaway, R. M. (2004).The "Strategic Partnership" Between India and Iran. *Asia Program Special Report.* Retrieved on 11 Oct 2017 From https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/asia_rpt_120rev_0.pdf

Ganai Mushtaq Ahmad & Pandey A.P .(2016). A case of India and Iran, Political Relations since gulf war to 2001. International Journal of Political Science and Development, 4 (5).

Wagay Shamin Ahmad (2018). Indo Iranian Relation Travelling Through Ages. Innternational Journal of Resarch in Humanities, Art and Literature 6 (2), 33-52.

Pant, H. V. (2004). India and Iran: An "Axis" in the Making?. *Asian Survey*, *44*(3), 369-383.

Chaudhury N. R. (2018). India and Iran: Historical ties attain Strategic dimensions retrieved on 12 Nov 2018 from http://www.indiandefencereview.com/india-and-iran-historical-ties-attain-strategic-dimensions/

Chaudhury, D. R. (Jan 10, 2019). Iran Can be a Bridge between India and Guld Foreign Minister. The Economic Times. Retrieved on 12 Sep from https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/iran-can-be-a-bridge-between-india-and-gulf-foreign-minister/articleshow/67465844.cms

प्रभा साक्षी तरण विजय 6 जुलाई 2018। www.prabhasakshio.com/ अपेपजमक वद December 2018

ऊमा पुरुषोतमन, (2012) रुटलेग, टेलर एंड फ्रांसिस ग्रुप

प्रो. मो. बदरुल आलम, वर्ल्ड फोकस फरवरी 2015, भारत की ऐतिहासिक समीक्षा और मोदीमय अमेरिका

ईरान के संबंध में भारत पर बढ़ता अमेरिकी दबाव, क्या भारत अमेरिका के आगे झुकेगा? या देशहित में लेगा फैसला? 7 सितंबर 20182

अमेरिका ने 2+2 वार्ता के बीच चाबहार पेमेंट मैकेनिज्म पर काम करने में जुटे भारत ईरान 7 सितंबर 2018

भारत–अमेरिका सम्बन्ध : इतिहास के आइने में–ठठब छमू हिन्दी, पृ0सं0 2

सिसोदिया, एन० एस, दोलतयार, मुस्तफा (5 जुलाई 2010). भारत ईरानः एक स्थाई सम्बन्ध विषय पर आई० डी० एस० ए०– आई० पी० आई० एस० सामरिक सवाद, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार।

पन्त पुष्पेश (2010). भारत की विदेश नीति पेज न 7.2 मैक्ग्रहिल एडुकेशन इंडिया।

तुलशीराम (1985). पर्सिय टू ईरान वन स्टेप फोरवर्ड टू स्टेप बैक, महजान पब्लिसिग हॉउस।

बेखरद जुबानी (26 जून 2018). ईरान का वो प्रचीन कार नामा जिसकी दुनिया कर्जदार है।

त्रिपाठी, राम प्रसाद (1988). विश्व का इतिहास उत्तर प्रदेश हिंदी सस्थान लखनऊ पेज न 311।

News 18 Hindi November 19, 2018, 12 :35 PM IST

NDTV May 18, 2017, 11:32 IST

वर्ल्ड फोकस, जनवरी 2017, डॉ० मनन द्विवेद्धी "भारत–अमेरिका द्विपक्षीय इतिहास का नया तारा : तेजी से बढ़ते लक्षण–निर्यात, पेज न. 103

भारत में अमेरिकी दूतावास और वाणिज्य दूतावास, भारत में अमेरिकी राजदूत केनेथ आई. नेता ई जस्टर का भाषण।

Harsh V. Pant India's relation with Iran: much ado about nothing; the washing Quaterly, 34(1), P.1

www.jansatta.com visited on September, 24, 2018

नवभारत टाइम्स. इंडिया। www.navbharattimes.com visited on 13 November 2018

http://www.bbc.comcdn.ampproject.org/ visited on 25 December 2018

Sansarloachan.in/ Iran-nuclear deal- P5 hindi

भारत–अमेरिका सम्बन्ध : इतिहास के आइने में–BBC News हिन्दी, पृ0सं0 2

Koepke, B. (2013). *Iran's Policy on Afghanistan: The Evolution of Strategic Pragmatism*. Stockholm International Peace Research Institute.

पंत पुष्पेश (2010). भारत की विदेश नीति, Mc Graw hill publication, India

Power, P. F. (1964). Indian foreign policy: The age of Nehru. *The Review of Politics*, *26*(2), 257-286.

Abhyankar, R., & Pourzand, A. (2013). Protests and Possibilities: West Asia and India. *Gateway House Research Paper*, (8).

Berlin, D. L. (2004). *India-Iran Relations: A Deepening Entente*. Asia-Pacific Center For Security Studies Honolulu Hi.

Kronstadt, K. A., & Katzman, K. (2006, August). India-Iran relations and US interests. Library of Congress Washington DC Congressional Research Service.

Pant, H. V. (2004). India and Iran: An ““Axis”” in the Making?. *Asian Survey*, *44*(3), 369-383.

Pant, H. V. (2011). India's Relations with Iran: Much Ado about Nothing. *The Washington Quarterly*, *34*(1), 61-74.

Cheema, S. A. (2010). India–Iran Relations: Progress, Challenges and Prospects. *India Quarterly*, *66*(4), 383-396.

Siddique, A., Selvanathan, E. A., & Selvanathan, S. (2012). Remittances and economic growth: empirical evidence from Bangladesh, India and Sri Lanka. *Journal of development studies*, *48*(8), 1045-1062.

Gunasinghe, N. (2004). The open economy and its impact on ethnic relations in Sri Lanka. *Economy, culture and civil war in Sri Lanka*, 99-114.

Dash, K. C. (1996). The political economy of regional cooperation in South Asia. *Pacific Affairs*, 185-209.

Baral, L. R. (1992). India-Nepal Relations: Continuity and Change. *Asian Survey*, *32*(9), 815-829.

Caplan, L. (2013). *Land and social change in east Nepal: a study of Hindu-tribal relations*. Routledge.

Subedi, S. P. (1994). India-Nepal security relations and the 1950 treaty: time for new perspectives. *Asian Survey*, *34*(3), 273-284.

Murthy, P. (1999). India and Nepal: Security and economic dimensions. *Strategic Analysis*, *23*(9), 1531-1547.

Rana, P. S. J. (1971). India and Nepal: The political economy of a relationship. *Asian Survey*, 645-660.

Swami, Parveen (May 23, 2016). In a first Modi invites SAARC Leaders for his Swearing in. The Hindu. Retrieved on 23 march 2018 from https://www.thehindu.com/news/national/in-a-first-modi-invites-saarc-leaders-for-his-swearingin/article6033710.ece

Ramana, S. (2012). The Pakistan Factor in the India–Iran Relationship. *Strategic Analysis*, *36*(6), 941-956.

Balooch, M. (2009, July). Iran and India's cooperation in Central Asia. In *China and Eurasia Forum Quarterly* (Vol. 7, No. 3, pp. 25-29).